दैनिक
जलते दीप

जोधपुर, शनिवार 27 अप्रैल 2024

भूख और कुपोषण की गहराती समस्या

यह अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है कि जिस दौर में दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों के जरिए लगातार विकास का हवाला दिया जाता है, उसमें करोड़ों लोगों को पेट भरने के लिए खाना तक नहीं मिलता है। यह अफसोसनाक हकीकत एक तरह से विकास के दावों के सामने आईना है, जो इस बात पर विचार करने जरूरत को रेखांकित करता है कि इसकी दिशा क्या है और आखिर यह किसके लिए है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने 'ग्लोबल रिपोर्ट आन फूड क्राइसिस' यानी खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि विश्व के उनसठ देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग सन 2023 में भूख से तड़पने को लाचार हुए। भूख का सामना करने वाले लोगों की तादाद 2022 के मुकाबले 2.4 करोड़ ज्यादा रही।रिपोर्ट के मुताबिक, भूखे रहने वालों में बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा, बत्तीस देशों में पांच वर्ष से कम उम्र के 3.6 करोड़ अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। साथ ही युद्ध और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बढ़ते विस्थापन के बीच पिछले वर्ष कुपोषण की समस्या और ज्यादा गहरी हो गई। सवाल है कि दुनिया भर में और खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अगर भूख सहित कई बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात की जाती है तो इस त्रासदी के लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बीस देशों में भूख की मुख्य वजह वहां चल रहे हिंसक संघर्ष थे। दूसरा बड़ा कारण यह था कि बढ़ते तापमान या मौसम से संबंधित आपदाओं, कीटों के हमले और महामारी के बीच करीब सात करोड़ सत्तर लाख से ज्यादा लोगों को उच्च स्तर की गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। इसी तरह, खाने-पीने की चीजों की महंगाई, आयातित खाद्य वस्तुओं पर निर्भरता, उच्च ऋण स्तर आदि वजहों से भी लोगों को भूख की समस्या से रूबरू होना पड़ा। सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से या वैश्विक स्तर पर भुखमरी के लिए जिन कारणों को चिह्नित किया गया है, उसका हल निकालने की कोशिश किसे करनी है और वह कब होगा! यह एक जगजाहिर तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र या फिर अन्य संस्थाओं की ओर से विश्व भर में भूख के संकट पर अक्सर अध्ययन रपटें जारी की जाती हैं। उसमें कारण भी बताए जाते हैं। मगर उन्हें दूर करने को लेकर बात औपचारिकताओं से आगे नहीं बढ़ पाती। अन्यथा क्या वजह है कि वर्षों से भुखमरी के हालात कायम रहने के बावजूद इस दिशा में अब तक कोई ठोस हल सामने नहीं आ सका है। उल्टे आर्थिक और सामरिक स्तर पर दुनिया के ताकतवर देश भुखमरी की त्रासदी की ओर ध्यान दिलाए जाने पर भी उसके समाधान को लेकर शायद ही कोई रुचि दिखाते हैं। गरीबी, जलवायु परिवर्तन आदि से उपजी समस्याओं से अगर कोई देश ज्यादा प्रभावित होता है तो सक्षम देश उनकी मदद के लिए क्या करते हैं? संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि युद्धग्रस्त गाजा में सबसे ज्यादा लोगों ने अकाल की गंभीर स्थिति का सामना किया। सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के होते हुए भी युद्धग्रस्त इलाकों में ऐसे हालात कैसे लंबे समय तक बने रहते हैं और युद्ध को खत्म कराने के प्रयास महज दिखावे के क्यों साबित होते हैं कि लोगों के सामने भूख से तड़पने की नौबत आती है!

आंदोलन किसानों का, सजा भुगत रहे हैं रेल यात्री

पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू रेलवे स्टेशन में जारी किसानों के आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को बिना किसी अपराध के सजा भुगतनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर रेलवे को भी भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से रोज 40 से 50 ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। यात्रियों को ज्यादा समय व पैसा लगाकर अपने गंतव्य स्थानों तक जाना पड़ रहा है। रेलवे के पार्सल बुकिंग केंद्र में भी पचास फीसदी की कमी आने की बात बतायी जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि किसानों की न्यायसंगत मांगों को पूरा किया ही जाना चाहिए। वे लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं। ऐसे में सत्ताधीशों का भी नैतिक दायित्व बनता था कि वे किसानों से बातचीत की टेबल पर बैठकर बात करते। जिससे सड़क व रेल यातायात बाधित भी नहीं होता। वैसे किसानों को भी आंदोलन करने से पहले देशकाल-परिस्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए था। देश इस समय चुनावी मूड में है। कोई भी सरकार किसानों से जुड़े किसी मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने में सक्षम नहीं है। किसानों को नये जनादेश का इंतजार करके किसान आंदोलन को दिशा देनी चाहिए थी। किसानों को देश व समाज के अहसासों का भी ध्यान रखना चाहिए। कल्पना कीजिए कि रेल यात्रा करने वाले लोगों को जब अचानक सूचना मिलती है कि उनकी ट्रेन रद्द हो गई है तो उन पर क्या बीतती होगी? लोग घंटों रेलवे टिकट बुकिंग केंद्रों पर खड़े होकर अपने लिये टिकट आरक्षित करवाते हैं। कई महीने पहले एडवांस में रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। फिर एक दिन यात्रा से ठीक पहले पता चलता है कि उनकी ट्रेन रद्द हो गई है। आंदोलनकारियों को सोचना चाहिए कि उस ट्रेन से कोई मरीज कहीं दूर उपचार हेतु जा रहा होगा। कहीं कोई बेरोजगार नौकरी के लिये साक्षात्कार देने जा रहा होगा। हो सकता है कि सही समय पर न पहुंच पाने के कारण कई छात्र परीक्षा या नौकरी पाने से वंचित हो गए होंगे। समय-समय पर देश की शीर्ष अदालत के मार्गदर्शक फैसले आते रहे हैं कि हमें किसी आंदोलन के नाम पर नागरिक जीवन को बंधक नहीं बनाना चाहिए। यदि आंदोलनकारियों के अधिकार हैं तो आम नागरिकों के भी अपने अधिकार हैं। एक पुरानी कहावत है कि जहां से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है, वहां पर पहले व्यक्ति की आजादी खत्म हो जाती है। यानी हमारी किसी भी तरह की आजादी का मतलब किसी की आजादी का अतिक्रमण करना नहीं हो सकता। वैसे भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी हमें सोचना चाहिए कि यातायात के साधनों, वह चाहे बस हो या ट्रेन, के परिचालन में बाधा डालना एक अपराध जैसा है। ट्रेन को थामना देश के विकास के पहिये थामने जैसा ही है। हमारे कारोबार, जीवन व्यवहार, तीर्थाटन तथा सेना के आवागमन को गति देने वाली ट्रेनों को रोकना निस्संदेह, दुर्भाग्यपूर्ण ही है। निश्चित रूप से इसमें हमारे देश के नीति-नियंताओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों किसानों को अपनी मांगें मनवाने के लिये रेल रोकने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे सत्ताधीशों के व्यवहार में व्याप्त दंभ और किसानों की मांगों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव भी इस तरह के आंदोलनों के लिये ईंधन का काम करता है। ऐसे हालात में किसानों को अभी अपने आंदोलनों के तौर-तरीकों को बदलना पड़ेगा। उन्हें हक है कि वे अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करें। लेकिन उन्हें यह हक कदापि नहीं दिया जा सकता है कि वे देश के रेल तंत्र को ठप कर दें। यह देश की लोकतांत्रिक सहिष्णुता का अपमान करने जैसा भी है। अब समय आ गया है कि सभी लोग सुनिश्चित करें कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन से देश के सड़क व रेल परिवहन में कोई बाधा न उत्पन्न हो। हमें अपने निहित स्वार्थों की अनदेखी करके राष्ट्रीय हितों व सरोकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रसंगतः सत्य की जगह

पुराने जमाने की बात है। सत्यदेव काफी धर्मनिष्ट राजा थे। वह हर समय लोगों की भलाई में लगे रहते थे। वे सत्य धर्म के कठोर उपासक थे और सत्य को ही सर्वस्व समझते थे। सत्य के लिए वे अपना सब कुछ छोड.देने को भी तत्पर रहते थे। एक दिन प्रातः उठकर वह सूर्य को प्रणाम कर ही रहे थे कि उन्होंने एक सुन्दरी को राजमहल से बाहर जाते देखा। राजा के पूछने पर सुन्दरी ने कहा, 'मैं लक्ष्मी हूं, बहुत समय तक तुम्हारे यहां रह चुकी, लेकिन अब मैं जा रही हूं।' सुन्दरी के पीछे-पीछे एक व्यक्ति भी दरवाजे से बाहर निकला। राजा के पूछने पर उसने बताया 'मैं दान हूं। जब लक्ष्मी ही यहां से जा रही हैं तो तुम दान कहां से दोगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूं।' कुछ क्षणों के बाद तीसरा व्यक्ति महल से बाहर निकला। राजा के पूछने पर उसने बताया, 'मैं सदाचार हूं। जब लक्ष्मी और दान ही नहीं रहेंगे तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूं।' चौथा व्यक्ति भी बाहर जाने लगा तो पूछने पर उसने बताया, 'मैं यश हूं। जब लक्ष्मी, दान और सदाचार सभी जा रहे हैं तो मेरा यहां क्या काम, इसलिए मैं भी जा रहा हूं।' अंत में पांचवां व्यक्ति बाहर जाने लगा तो राजा ने पूछा, 'आप कौन हैं?' वह बोला, 'मैं सत्य हूं। जब ये चारों यहां नही रहेंगे तो मैं भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूं।' इस बार राजा सत्यदेव पांचवें व्यक्ति के चरणों में हाथ जोडक़र गिर पडे.और प्रार्थना करने लगे, 'भगवान, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं। दिन-रात आपकी आराधना करता हूं। लोग मुझे सत्यदेव कहते हैं, ये चारों जाएं तो जाएं मुझे दुख नहीं, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं।' राजा की सत्य के प्रति गहरी निष्ठा देखकर पांचवां व्यक्ति मुस्कराते हुए अंदर जाने लगा तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी महल में लौट आए। राजा की सत्य के प्रति आस्था और भी बढ.गई।

अब मालदीव से सतर्क रहने का वक्त

– पुष्परंजन

मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव परिणाम को 'सुपर मेजोरिटी' कहा है। दो लाख 84 हज़ार 887 मालदीवियन वोटरों में से 84.14 फीसद ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लिया था। मुइज़्ज़ू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने संसद की 93 सीटों में से 71 पर फतह की है। पीएनसी के पास अपने गठबंधन दलों के साथ कुल मिलाकर 75 सीटें हैं, जबकि मुख्य विपक्षी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) पहले की 65 सीटों से घटकर केवल 12 सीटों पर रह गई है। पीएनसी ने 90 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि एमडीपी ने 89 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ा। 130 स्वतंत्र उम्मीदवारों से अलहदा जम्हूरी पार्टी (जेपी) के 10 और डेमोक्रेट्स के 39 कैंडिडेट्स थे।

जीत-हार का फ़ासला सुनकर हैरान होइएगा। पचास-सौ वोट से भारत के किसी गली-मोहल्ले और हाउसिंग सोसायटी चुनाव में लोग हारते-जीतते हैं। दुनिया मॉमून मालदीव की विदेशमंत्री रह चुकी हैं। अहमद फारिस मॉमून उनके भाई हैं, जो कभी अर्थ मंत्रालय संभालते थे। पूर्व राष्ट्रपति मॉमून अब्दुल गयूम की दोनों संतानें इस बार चुनाव हार चुकी हैं। 1978 से 2008 तीस साल तक अखंड राज किया था मॉमून अब्दुल गयूम ने। उस कालखंड में इनकी संतानों के जलवे थे। जनमत की ताक़त ने चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। यह बात सफलता के नशे में चूर राष्ट्रपति मुइज्जू की समझ में शायद देर से आये।

अभी सबको यही लग रहा है कि मुइज्जू ने 'इंडिया आउट' का जो नारा दिया था, उसका असर संसदीय चुनाव पर भी पड़ा है। बेशक पड़ा होगा। लेकिन अमेरिकी फैक्टर सबकी आंखों से ओझल है। इस परिणाम से अमेरिका को भी झटका लगा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हमने चुनाव परिणामों पर बारीकी से नजर रखी है। हमें यह सुनकर खुशी हुई कि पर्यवेक्षकों ने कोई बड़ा मुद्दा या अनियमितता नहीं बताई है और नतीजे लोगों की इच्छा के अनुरूप हैं। हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय प्रभाव को विस्तार देने और चीन को बेअसर करने के लिए अमेरिका ने 2023 में माले में दूतावास खोला था। यों, अमेरिका ने मालदीव की स्वतंत्रता के बाद 1966 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने के मकसद से अमेरिका ने सितंबर, 2020 में मालदीव से सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्या मालदीव में अमेरिकी रणनीति विफल हो गई? दिल्ली पर सवाल दरपेश करने से पहले इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

मालदीव ने 1965 में इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। उस समय इस्राइल, मालदीव को मान्यता देने वाला तीसरा देश था, और इस्राइली राजदूत मालदीव के राष्ट्रपति को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करने वाले पहले कूटनीतिक थे। 2009 में राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद के नेतृत्व में मालदीव ने इस्राइल के साथ पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। मालदीव इस्राइली पर्यटकों के बीच लोकप्रिय डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन गाज़ा युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया।

वर्ष 2023 में फलस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मालदीव में 'इस्राइल आउट' जैसे प्रदर्शन आयोजित किये गये। मालदीव के सांसद सऊद हुसैन ने इस्राइली पासपोर्ट धारकों को देश में आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पेश किया था। साथ में इस्राइली युद्ध का समर्थन करने वाली कंपनियों के बहिष्कार का आह्वान किया था। इन सबका फायदा मुइज्जू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) को इस बार के संसदीय चुनाव में मिला है। भारत ने जिस तरह नेतन्याहू के प्रति सहानुभूति दिखाई, उसने भी चुनाव प्रचार के समय पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के लिए ईंधन का काम किया था। पीएनसी की विजय और मुख्य विपक्षी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की पराजय के पीछे पंचतंत्र की तरह कहानी के पीछे कहानियों के जाल बिछे हैं।

इस समय सबसे गद्गद चीन है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हम सफल संसदीय चुनावों के लिए मालदीव को बधाई देते हैं, और मालदीव के लोगों की पसंद का पूरा सम्मान करते हैं। हमें साझा भविष्य तय करना है। मालदीव के साथ काम करने को हम तैयार हैं।' अब जिस तरह मालदीवियन संसद 'मजलिस' में सुपर मेजोरिटी मुइज्जू की पार्टी को हासिल हुई है, चीन के सोये अरमान जग चुके हैं।

शिन्हुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीति अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग ने कहा, 'चुनाव से पहले, विपक्षी दल ने संसद को नियंत्रित किया था, इसलिए मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति पद को काफी दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब हासिल चुनावी जीत मुइज़्ज़ू को काफी मजबूत करती है, जो उनकी वर्तमान घरेलू और विदेशी नीतियों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए फायदेमंद है।'

थिएनक्वांगछिंग चाइनिज अकादमी ऑफ सोशल साइंस में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। उनके बयान पर ग़ौर करें, तो चीनी मंशा साफ हो जाती है। थिएनक्वांगछिंग ने कहा, 'आकार और जनसंख्या के मामले में एक छोटे राष्ट्र के रूप में मालदीव की प्राथमिक चिंताएं स्वतंत्रता बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए ख़तरा है। मुइज़्ज़ू का अभियान आर्थिक विकास पर काफी हद तक केंद्रित है। यह चुनाव राष्ट्रपति के विकास एजेंडे के लिए जनता के समर्थन को दर्शाता है।'

मतलब साफ़ है कि चीनी बंदूक प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू के कंधे पर है। वो संसद में मालदीव के आर्थिक विकास के नाम पर 'वन बेल्ट रोड इनीशिएटिव' की कई सारी लंबित योजनाएं पास कराएंगे। संसद से रक्षा समझौतों की पुष्टि कराएंगे। इस इलाके में भारत के रणनीतिक असर को कैसे कम करना है, उसकी कवायद शुरू हो जाएगी। इसे काउंटर करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। मालदीव भौगोलिक रूप से एक ओर अदन की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर के होर्मुज जलडमरूमध्य के चोकप्वाइंट पर टिका है, दूसरी ओर पूर्वी हिंद महासागर के मलक्का जलडमरूमध्य के चोकप्वाइंट के बीच एक 'टोल गेट' की तरह अवस्थित है। ऐसे सामरिक महत्व के मुल्क की हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते।

भारत और मालदीव के बीच 545 नॉटिकल माइल्स वाली समुद्री सीमा को एक द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से सीमांकित किया गया था, जिस पर 28 दिसंबर, 1976 को हस्ताक्षर किए गए थे, और 8 जून, 1978 को लागू हुआ था। हमारी प्राथमिकता 'सतर्कता गई, दुर्घटना हुई' वाली स्थिति से बचने की होनी चाहिए। यों, भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को उन्नत करने के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक नया नौसैनिक अड्डा 'आईएनएस जटायु' स्थापित किया है। यह बेस मालदीव का निकटतम नौसैनिक अड्डा होगा। लेकिन, इसे काफ़ी मत मानिये। **(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)**

सच जानने के लिये सर्वे और दावे-प्रतिदावे

https://t.me/AllNewsPaperPaid

– हेमंत पाल

अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व की प्रामाणिकता के लिए कोर्ट के निर्देश पर ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (एएसआई) ने साइंटिफिक सर्वे किया था। अपनी प्रमाणिक रिपोर्ट से एएसआई ने जो साबित किया, वो दुनिया के सामने है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर इसी तरह का सर्वे धार की भोजशाला में किया जा रहा है। एएसआई को अपने सर्वे से साबित करना है कि भोजशाला वास्तव में राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर है या मौलाना कमालुद्दीन की बनाई मस्जिद! दोनों पक्षों के बीच सौ सालों से ज्यादा समय से यह विवाद है। एक महीने से एएसआई भोजशाला में सर्वे कर रही है।

हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वे करके और अपनी रिपोर्ट अगले 45 दिन में उसे सौंपने का निर्देश दिया था। लेकिन, अब एएसआई ने इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा है। क्योंकि, निर्धारित अवधि में काम पूरा संभव नहीं है। सर्वे की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए कोर्ट के निर्देश पर हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी सर्वे टीम के साथ अंदर जाने की इजाजत मिली है। पहले दिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम के साथ परिसर में जाना टाला, उसके बाद से दोनों पक्षों के प्रतिनिधि सर्वे टीम के साथ सुबह से शाम तक मौजूद रहते हैं। हालांकि, एएसआई को सर्वे पर किसी भी तरह का बयान देने की इजाजत भी नहीं है क्योंकि, रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करानी है। मगर सर्वे टीम के साथ अंदर जाने वाले दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अंदर जाते हैं, तो वे मीडिया के सामने कोई न कोई ऐसी बात जरूर करके जाते हैं, जो इस सर्वे की गोपनीयता को भंग करने जैसी होती है।

मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा लगाई गई आपत्तियों का जिक्र करने के साथ यह भी बताते हैं कि बीते सौ सालों से ज्यादा समय में भोजशाला विवाद में क्या कुछ हुआ! वे उन तर्कों को भी नकारते हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि मुखरता से बताते हैं कि सर्वे के दौरान अंदर मिलने वाले प्रमाण संकेत दे रहे हैं, कि यह सरस्वती मंदिर रहा है। वास्तव में तो सीधे-सीधे इस बात की मार्केटिंग करने की भी कोशिश की जा रही है कि एएसआई का यह सर्वे हिंदू धर्मावलंबियों की याचिका पर ही किए जाने के निर्देश हुए हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के हाईकोर्ट में पेश किए जाने से पहले ऐसी बयानबाजी गोपनीयता भंग करने जैसा कृत्य कह सकते हैं। सर्वे के दौरान जब भी मंगलवार या शुक्रवार आता है, तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भोजशाला परिसर में जाकर अपनी आराधना करते हैं। शुक्रवार को मुस्लिम नमाज़ अता करने और मंगलवार को हिंदू परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कई साल पहले केंद्र सरकार ने दोनों पक्षों को यह व्यवस्था दी थी, तब से प्रशासन की देखरेख में इसका पालन किया जा रहा है। देखा गया कि सर्वे के दौरान हर मंगलवार को जब हिंदू पक्ष भोजशाला में पूजा-अर्चना के लिए जाते हैं, उस दिन हिंदू पक्ष की तरफ से भोजशाला आंदोलन से जुड़ा कोई बड़ा हिंदूवादी नेता मीडिया के सामने कोई न कोई ऐसी बात जरूर करता है, जो सुर्खी बनती है। उन्हें एएसआई सर्वे पर न कोई बयान देने की जरूरत है, न इजाजत।

हिंदू पक्ष के लोग बार-बार मथुरा, ज्ञानवापी और अयोध्या के एएसआई सर्वे के नतीजे को आधार बनाकर भोजशाला में भी उसी तरह के प्रमाण मिलने का दावा करते हैं। जबकि, मुस्लिम प्रतिनिधि का दावा रहता है कि 1902 और 1903 में भी इसी तरह का सर्वे हुआ था और उस समय यह मान लिया गया था कि यह मंदिर नहीं है। आज भी उनका दावा है कि 1300 ईस्वी में जब मौलाना कमालुद्दीन यहां आए थे और उन्होंने मस्जिद बनाई थी। उस समय यहां कई तरह का रॉ-मैटेरियल मस्जिद के निर्माण के लिए लाया गया था। संभवतः उस समय लाए गए रॉ-मैटेरियल में कुछ ऐसी सामग्री आ गई होगी जो यहां हिंदू धर्म का प्रमाण दे रही है।

भोजशाला में बनी एक अक्कल कुईया को लेकर भी दोनों पक्षों के पास ऐसे दावे हैं, जो सर्वे को प्रभावित कर सकते हैं। हिंदुओं का कहना है कि इस तरह की अक्कल कुईया आर्यावर्त में 7 जगह है जिसमें से तीन जगह भारत में है। एक इलाहाबाद में, एक तक्षशिला और तीसरी भोजशाला में। धार की भोजशाला की अक्कल कुईया के बारे में उनका कहना है कि यह सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ जल स्रोत था। माना जाता है कि जहां भी शिक्षा के विकसित केंद्र रहे, वहां विद्यार्थियों को ज्ञान देने के लिए इस तरह की कुईया का निर्माण किया गया। इसमें वे पत्थर पाए गए, जो विलुप्त हुई सरस्वती नदी में होते थे। इसके प्रमाण में हिंदू पक्ष विष्णु श्रीधर वाकणकर की किताब का हवाला देते हैं। जबकि, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वास्तव में यह अक्कल कुईया नहीं, बल्कि मस्जिदों के पास पाए जाने वाला जल कुंड है। वास्तव में इसकी सच्चाई एएसआई के सर्वे से ही पता चलेगी। लेकिन दोनों पक्षों की बयानबाजी सामाजिक सामंजस्य के लिए उचित नहीं है।

कैदियों में टकराव रोकने को बने प्रभावी तंत्र

उन्नीस अप्रैल को संगरूर जेल में बंदियों के दो समूहों के बीच झड़प में दो कैदियों की मौत हो गई और दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। इससे लगभग एक सप्ताह पहले भी गुरदासपुर की केंद्रीय जेल में एक झड़प को रोकने की कोशिश करते हुए थाना प्रबंधक सहित कम से कम चार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पंजाब की जेलों में पिछले एक दशक में हिंसा और दंगों की कई घटनाएं हुईं। फरवरी, 2023 में तरनतारन जिले की गोइंदवाल साहिब केन्द्रीय जेल के अन्दर लड़ाई में दो गैंगस्टर मारे गए थे। जून, 2019 में लुधियाना जेल में दंगाई कैदियों ने पुलिस से झड़प की थी। जिसमें एक कैदी की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे। मार्च, 2017 में भी गुरदासपुर जेल में कैदियों के दंगे में तीन जेल कर्मचारी घायल हो गए थे।

जेलों में हिंसा के अपराधशास्त्र को जेल की सामाजिक संरचना और शासन व्यवस्था को सामने रखकर समझा जा सकता है, जो अक्सर संसाधनों के अभाव में आपसी खींचतान के कारण उत्पन्न होता है। यही नहीं, जेलों का माहौल ही शोषणकारी है और अन्याय होने पर कैदियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हिंसा ही होती है। मानसिक बीमारी, जातीय और धार्मिक समीकरण, बन्दियों और जेल कर्मचारियों के बीच की सांठ-गांठ, सांस्कृतिक मतभेद और जेल में बंदी गैंगस्टरों से सांठ-गांठ अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जो जेलों में दंगों के मूल कारण बन जाया करते हैं।

पंजाब की जेलों में अधिकांश झगड़े भौतिक वस्तुओं को लेकर नहीं बल्कि प्रभुत्व, सम्मान, निष्पक्षता, वफादारी, गिरोहों की दुश्मनी व वर्चस्व जैसे गैर-भौतिक हितों को लेकर होते हैं। यही कारण है कि वे पूर्व-नियोजित होते हैं और पुलिस हस्तक्षेप के बिना उन्हें सुलझाना कठिन होता है।

कुछ साल पहले 'कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन से पता चला कि पंजाब की 24 में से 18 जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई थीं, 25 प्रतिशत पद खाली थे, 17 जेलें कल्याण अधिकारियों के बिना काम कर रही थी, बाहरी निरीक्षण तंत्र आमतौर पर नदारद था क्योंकि केवल एक जेल में ही 'बोर्ड आफ विजिटर' था जो जेलों पर स्वतंत्र निगरानी के लिए एक वैधानिक निकाय है। 660 कैदियों में से 12 प्रतिशत ने जेल-हिरासत में हिंसा का आरोप लगाया था। 15 कारागारों में कैदियों ने जेलों के अंदर नशे की तस्करी और प्रतिबन्धित सामग्री की आपूर्ति की भी बात का जिक्र किया था।

ये सभी तथ्य मिलकर पंजाब की जेलों में संसाधनों, पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी की गवाही देते हैं, जिसका जेलों के अन्दर के जीवन और सुरक्षा पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। ऐसी जमीनी हकीकतों के प्रकाश में जेलें ख़तरनाक, अमानवीय और दर्दनाक जगह बन जाती हैं, जहां हिंसा अपरिहार्य है। जुलाई, 2022 में राज्य सरकार ने जेलों में 'ड्रग स्क्रीनिंग' सर्वेक्षण शुरू किया जिसमें 30,000 बन्दियों को शामिल किया गया था। यह बात सामने आई कि सर्वेक्षण में शामिल 47 प्रतिशत से अधिक कैदी नशे के आदी हैं। एक छोटी-सी जगह में इतनी बड़ी संख्या में मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की मौजूदगी स्वयं में एक विस्फोटक है जो फूटने का इंतजार कर रहा है।

नशे का आदी व्यक्ति नशीली दवाओं के बिना जीवित नहीं रह सकता है और कैदी इसकी व्यवस्था जेलों के अन्दर गिरोहों के माध्यम से करते हैं। नशे की आपूर्ति जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बिना सम्भव नहीं है। जेल के अन्दर जब ऐसे गिरोह हों तो हिंसा स्वाभाविक है। मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों के इलाज के लिए जेलों में बहुआयामी नशा मुक्ति कार्यक्रमों की आवश्यकता है, वर्तमान में किए जा रहे उपाय अपर्याप्त और अप्रभावी साबित हो रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की जेलें उत्तर भारत में गैंगस्टरों के लिए पसंदीदा जगहों के रूप में भी उभरी हैं। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी ने रूपनगर जेल में सुरक्षित और आरामदायक पनाह पाई थी। पिछले साल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब की एक जेल से एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था और अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। सलाखों के पीछे से बदमाशों द्वारा धमकी भरे संदेश और फिरौती के लिए टेलीफोन पर्याप्त संकेत हैं कि जेल प्रशासनिक मशीनरी में सब कुछ ठीक नहीं है।

कारागार अत्यधिक अस्थिर और चंचल प्रवृत्ति के लोगों की बस्तियां हैं, जो निठल्ले रहते हैं। कठोर कारावास की सज़ा पाने वाले केवल 20 प्रतिशत दोषियों को ही जेल कारखानों में काम दिया जा सकता है। 75 प्रतिशत से अधिक बन्दी विचाराधीन कैदी हैं जिन्हें कानूनन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जेल के छोटे से क्षेत्र में इस तरह का निठल्ला कार्यबल शांति के लिए ख़तरा है। इसके लिए कानूनों में बदलाव करने और कैदियों के लिए पर्याप्त काम के अवसर पैदा करने की जरूरत है।

तर्कसंगत स्थानांतरण नीति के अभाव में दागी जेल अधिकारी अपने पसंदीदा स्थानों पर अपनी नियुक्ति का प्रबन्ध करते रहते हैं। इसके कारण बंदी बदमाशों के गिरोहों के साथ सांठ-गांठ विकसित करना आसान हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप जेलों में भेदभावपूर्ण, अवैध और भ्रष्ट आचरण पनपता है जो कैदियों के बीच टकराव बढ़ाता है।

अपेक्षाकृत छोटा राज्य होने के कारण पंजाब की जेलों में किसी भी जेल अधिकारी को एक स्थान पर दो साल से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार समय-समय पर समीक्षा करके अवांछित तत्वों को सेवा से बाहर किया जाना चाहिए। जेल में अन्दर की ड्यूटियों को भी एक उचित अवधि के बाद बदलते रहना चाहिए।

– डॉ. केपी सिंह

सम्पादकीय

बार-बार सिस्टम को चुनौती दे रहे साइबर अपराधी

जयपुर के अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को चार माह में तीन बार उड़ाने की धमकी दी गई है। ताजा धमकी तो शुक्रवार को ईमेल पर आई है। ये सीधे-सीधे साइबर अपराधियों की पुलिस प्रशासन को चुनौती है कि लो हमने आपका सिस्टम हिला दिया और आप बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। पूर्व में तीन बार की धमकियां देने वालों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। यही कारण है कि बार-बार ऐसे अपराधियों का हौंसला बुलन्द हो जाता है। पुलिस की कार्यप्रणाली की कमजोरी मानो या फिर कामकाज का दबाव कि धमकी देने के बाद जब कुछ नहीं निकलता तो पुलिस भी उदासीन हो जाती है। यही कारण है कि अपराधियों के हौंसले बुलन्द होते ही चले जाते हैं। शुक्रवार को भी एयरपोर्ट के ऑफिशियल फीडबैक आईडी पर शुक्रवार दोपहर धमकी भरा ईमेल आया। मेल के बाद जो होना था वह हुआ। पुलिस बुलाई, बम निरोधक दस्ते भी आए। सिस्टम को बाधित रखा गया। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री और उनके परिजन इन सबमें बड़े परेशान हुए। सर्च के चक्कर में गहन जांच से लोगों को गुजरना पड़ा। यात्रियों को फीडबैक के लिए दी गई आईडी पर आज दोपहर में ईमेल आया था। ईमेल करने वाले ने खुद को बेंगलूरु का होने की बात लिखी है। ईमेल में आरोपी ने एयरपोर्ट के एंट्रेंस गेट पर बम रखा होने की धमकी दी। इसके बाद डॉग स्क्वॉड, एंटी बम स्क्वॉड और एयरपोर्ट की सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर जांच शुरू की। लगभग डेढ़ घंटे की जांच में एयरपोर्ट एरिया में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मामले में एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है। पिछले चार महीने में यह तीसरी बार है, जब जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले इसी साल 16 फरवरी और 2023 में 27 दिसंबर को एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। दोनों बार ऑफिशियल कस्टमर केयर आईडी पर ईमेल आया था। जांच में सुरक्षा एजेंसी और पुलिस को कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला था।

दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है गंभीर चुनौती

18वीं लोकसभा चुनाव में हर राजनैतिक दल अपने स्वार्थ की बात सोच रहा है तथा येन-केन-प्रकारेण ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने की अनैतिक तरकीबें निकाल रहा है। एक-एक प्रत्याशी चुनाव का प्रचार-प्रसार करने में करोड़ों रुपयों का व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, राजनीतिक दलों एवं प्रायोजकों से मिलता है। चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार उनके अनुचित दबाव के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनैतिकता एवं आर्थिक अपराध की परम्परा को सिंचन मिलता रहता है।

ललित गर्ग।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव 2024 अनेक दृष्टियों से यादगार, चर्चित, आक्रामक एवं ऐतिहासिक होने के साथ-साथ अब तक का सबसे महंगा एवं दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार का चुनावी खर्च एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये के खर्च के साथ दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च की तुलना में इस बार दुगुना खर्च होगा। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक महंगी एवं धन के वर्चस्व वाली होने से राजनीतिक मूल्यों का विसंगतिपूर्ण एवं लोकतंत्र की आत्मा का हनन होना स्वाभाविक है। चुनाव जनतंत्र की जीवनी शक्ति है। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है। जनतंत्र के स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता, पारदर्शिता, मितव्ययता और उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत होने पर लोकतंत्र की जड़े खोखली होती चली जाती हैं। करोड़ों रुपए का खर्चीला चुनाव, अच्छे लोगों के लिये जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता बन्द करता है और धनबल एवं धंधेबाजों के लिये रास्ता खोलता है। इन चुनावों में अर्थ का अनुचित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण खर्च का प्रवाह जहां चिन्ता का कारण बन रहा है, वहीं समूची लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का सबब भी बन रहा है। इस तरह की बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलियां डालना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके विरोध में व्यापक जनचेतना को जगाना जरूरी है। यह समस्या या विकृति किसी एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया के समूचे लोकतांत्रिक राष्ट्रों की समस्या है।

यथार्थ में देखा जाए तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। लेकिन इस तरह लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन होता है, इस सबसे उन्नत एवं आदर्श शासन प्रणाली पर अनेक प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं।

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर चुनाव अभियान के लिए धन अलग-अलग स्रोतों से अलग-अलग तरीको से उम्मीदरवारों और राजनीतिक दलों के पास आता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए मुख्य रूप से रियल इस्टेट, खनन, कारपोरेट, उद्योग, व्यापार, ठेकेदार, चिटफण्ड कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, परिवहन ठेकेदार, शिक्षा उद्यमकर्ता, एनआआई, फिल्म, दूरसंचार जैसे प्रमुख स्रोत है। इस साल डिजिटल मीडिया द्वारा प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दल पेशेवर एजेंसिया की सेवाएं ले रहे हैं। इनसे सबसे अधिक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान, रैली, यात्रा खर्च के साथ-साथ सीधे तौर पर गोपनीय रूप से मतदाताओं को सीधे नकदी, शराब, उपहारों का वितरण भी शामिल है। देश में 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 2024 में 500 गुणा अधिक खर्च होने का अनुमान है। प्रति मतदाता 6 पैसे से बढ़कर आज 52 रुपये खर्च होने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में होने वाले वास्तविक खर्च और अधिकारिक तौर पर दिखाए गए खर्चे में काफी अंतर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 32 राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों द्वारा आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2,994 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया। इनमें दिखाया गया कि राजनीतिक दलों ने 529 करोड़ रुपये उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग में पेश खर्च का ब्यौरा और वास्तविक खर्च के साथ-साथ उम्मीदवारों द्वारा अपने स्तर पर किए जा रहे खर्चे में काफी अंतर है।

अमेरिकी चुनाव पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने कहा कि यह 2020 के अमेरिकी चुनावों पर हुए खर्च के लगभग बराबर है, जो 14.4 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख 20 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित होगा। भारत में होने वाले चुनाव में हो रहे बेसुमार खर्च की तपीश समूची दुनिया तक पहुंच रही है। समूची दुनिया के तमाम देशों में भारत के चुनाव को न केवल दम साध कर देखा जा रहा है बल्कि इन चुनाव के खर्चों एवं लगातार महंगे होते चुनाव की चर्चा भी पूरी दुनिया में व्याप्त है। लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों एवं उनके उम्मीदावारों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये तिजोरियां खोल दी है। यह चुनाव राष्ट्रीय मसलों के मुकाबले राजनीतिक दलों के हित सुरक्षित रखने के वादे पर ज्यादा केंद्रित लग रहा है और टकराव के मुद्दे थोड़े ज्यादा तीखे हैं। लेकिन अगर मुद्दों से इतर अभियानों की बात करें तो यह खबर ज्यादा ध्यान खींच रही है कि इस बार चुनाव अब तक के इतिहास में सबसे खर्चीला साबित होने जा रहा है। इस चुनावों के अत्यधिक खर्चीले होने का असर व्यापक होगा। चुनाव के तवे को गर्म करके अपनी रोटियां सेंकने की तैयारी में प्रत्याशी वह सब कुछ कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करता है। काफी लंबे और जटिल प्रक्रिया के तहत चलने वाले चुनाव में जनता के बीच समर्थन जुटाने के लिए उम्मीदरवार जितने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हैं, उसमें उन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर सामग्रियों और जनसंपर्कों तक के मामले में कई स्तरों पर खर्च चुकाने पड़ते हैं। यों किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले चुनावों में ऐसा ही होता है, लेकिन भारत में इसी कसौटी पर खर्च में कई गुना ज्यादा होना चिन्ता का सबब बनना चाहिए। दुनिया की आर्थिक बदहाली एवं युद्ध की विभीषिका से चौपट काम-धंधों एवं जीवन संकट में लोकसभा के चुनाव कहां कोई आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जो लोग चुनाव जीतने के लिए इतना अधिक खर्च कर सकते हैं तो वे जीतने के बाद क्या करेंगे, पहले अपनी जेब को भरेंगे, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बनायेंगे। और मुख्य बात तो यह है कि यह सब पैसा आता कहां से है? कौन देता है इतने रुपये? धनाढ्य अपनी तिजोरियां तो खोलते ही है, कई कम्पनियां हैं जो इन सभी चुनावी दलों एवं उम्मीदवारों को पैसे देती है, चंदे के रूप में। चन्दा के नाम पर यदि किसी बड़ी कम्पनी ने धन दिया है तो वह सरकार की नीतियों में हेरफेर करवा कर लगाये गये धन से कई गुणा वसूल लेती है। इसीलिये वर्तमान देश की राजनीति में धनबल का प्रयोग चुनाव में बड़ी चुनौती है। सभी दल पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान के नाम पर नहीं। कोई भी ईमानदारी और सेवाभाव के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। राजनीति के खिलाड़ी सत्ता की दौड़ में इतने व्यस्त है कि उनके लिए विकास, जनसेवा, सुरक्षा, महामारियां, युद्ध, आतंकवाद की बात करना व्यर्थ हो गया है। सभी पार्टियां जनता को गुमराह करती नजर आती है। सभी पार्टियां नोट के बदले वोट चाहती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

आज का इतिहास

27 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- मुगल साम्राज्य का शासक बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर नया बादशाह बना।
- नीदरलैंड और फ्रांस ने 1662 में सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किये।
- मुगल शासक मुहम्मद शाह का 1748 में दिल्ली में निधन हुआ।
- अमेरिकी नौसैनिकों ने 1805 में त्रिपोली के तटीय क्षेत्रों में हमला किया।
- कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिये 1878 में पहली मंजूरी दी।
- सन 1908 में लंदन में चौथे ओलंपिक खेल शुरू हुए।
- नाजियों ने 1940 में पोलैंड के ओस्वीसिम में यातना शिविर का निर्माण शुरू किया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने 1941 में एथेंस में प्रवेश किया।
- अमेरिका के ओकलाहोमा प्रांत में 1942 में आये तूफान के कारण 100 लोग मारे गये।
- नेशनल डिफेंस कॉलेज की 1960 में नयी दिल्ली में स्थापना।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गामा किरणों के अध्ययन के लिये 1961 में पृथ्वी की कक्षा में 'एक्सप्लोरर 11' लांच किया।
- सिएरा लियोन ने 1961 में ब्रिटेन से स्वाधीनता की घोषणा की।
- क्यूबा के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो 1963 में रूस की अपनी यात्रा के दौरान राजधानी मॉस्को पहुंचे।
- अमेरिका ने 1967 में नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।
- अंतरिक्ष यान 'अपोलो 16' 1972 में पृथ्वी पर वापस लौटा।
- सन 1989 में बांग्लादेश में आये तूफान से 500 लोगों की मौत।
- अफगानिस्तानी विमान 'एएनएस 32' 1993 में दुर्घटनाग्रस्त होने से 76 लोगों की मौत।
- 1994 को दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता दिवस।
- टुलुज (फ्रांस) में एयरबस निर्मित दुनिया के सबसे बड़े विमान ए-380 ने 2005 में पहली परीक्षण उड़ान भरी।
- पाकिस्तान ने 2008 में अपने विदेश सचिव रियाज मुहम्मद ख़ान को बर्ख़ास्त कर उनके स्थान पर चीन में पाकिस्तान के राजदूत सलमान बशीर को विदेश सचिव नियुक्त किया।
- यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने 2010 में भारत के नागरिकों की पहचान का एक बड़ा सबूत बनने जा रहे यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अब नया ब्रांड नाम 'आधार' तथा नया लोगो पेश किया।
- अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने जन्म को लेकर हुए विवाद के बाद 2011 में सार्वजनिक तौर पर जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी की।

27 अप्रैल जन्मे व्यक्ति

- प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक तथा समाजशास्त्री हरबर्ट स्पेन्सर का 1820 में जन्म हुआ।
- महान अभिनेत्री जोहरा सहगल का 1912 में जन्म हुआ।
- प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मनीभाई देसाई का 1920 में जन्म हुआ।

विशेष आलेख

वन प्रबंधन के लिए सही योजनाएं नहीं बनाई गई तो हमें भविष्य में भयंकर परिणाम झेलने होंगे

अशोक भाटिया

गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं. एक नवंबर, 2023 से 22 अप्रैल 2024 तक वनाग्नि की 431 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं और इनसे 516.92 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। खास बात यह है कि 31 मार्च तक जंगलों में आग लगने की सिर्फ 34 घटनाएं हुई थीं और इनसे 35.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र ही प्रभावित हुआ था। लेकिन अप्रैल के 22 दिन में वनाग्नि और उससे होने वाला नुकसान करीब 13 गुना बढ़ गया।

दरअसल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर इस साल की शुरुआत में ही दिखने लगा है। देश के बड़े हिस्से में तापमान औसत से अधिक दर्ज किया गया है और इस बार तीन मार्च से ही लू या हीटवेव का प्रकोप शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 19 अप्रैल, को जारी अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 18 अप्रैल, को भारत के 60 प्रतिशत से अधिक या 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। 2023 की तुलना में इस बार हीटवेव ने देश में 10 दिन पहले दस्तक दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 तक, तीन राज्यों में लू या हीटवेव का सितम रहा। तीन मार्च से 18 अप्रैल, 2024 तक अब यह संख्या बढ़ कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गई, जिन्हें गर्म हवाओं ने अपने आगोश में ले लिया था।भारत में लू या हीटवेव इस सप्ताह सुर्खियां बना रहा है, 16 अप्रैल को कथित तौर पर हीटस्ट्रोक से 13 लोगों की मौत हो गई। 20 अप्रैल को प्रकाशित, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने बताया कि देश के 90 प्रतिशत लोगों को गर्मी के कारण आजीविका क्षमता, खाद्यान्न उपज, वेक्टर जनित रोग फैलने और शहरी स्थिरता में नुकसान होने का खतरा है।

यहां बताते चले कि, जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसे हीटवेव घोषित किया जाता है।कर्नाटक में साल का पहला लू का प्रकोप तीन मार्च को दर्ज किया गया था। नौ मार्च तक राज्य में चार दिन लू का कहर दर्ज किया गया था। गोवा में लू के चार दिन और गुजरात में दो दिन रहे। महीने की आखिरी लू 12 मार्च को दर्ज किया गया था।देश में 12 अप्रैल, को पश्चिम बंगाल में गंगा के अलग-अलग इलाकों में लू ने दस्तक दी। आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब और पश्चिम बंगाल में 12 से 18 अप्रैल तक लू का प्रकोप दर्ज किया गया।वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इससे निपटने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है, विशेष रूप से क्योंकि लू के सितम के जारी रहने के आसार हैं और यह लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।मौसम विभाग द्वारा 2 7 अप्रैल, 2024 तक लू या लू जैसी चरम स्थितियों पर कम से कम आठ राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में 30 अप्रैल, 2024 तक इन चरम स्थितियों के जारी रहने की आशंका जताई गई है।लोगों के स्वास्थ्य पर लू के प्रभाव को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली ऐसी चरम घटनाएं घातक भी हैं और इनसे निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की जरूरत है। देश के कई राज्यों में जंगल में आग लगने से हजारों हैक्टेयर का जंगल तबाह हो गया वहीं वन्य संपदा और वन्य जीवों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। जंगलों से उठी आग की लपटों ने जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड को आग की तपती भट्ठी बना दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल की स्थिति चीड़ की पत्तियों के कारण काफी विकराल है। 70 के दशक में ही पर्वतीय राज्यों में चीड़ उगाने के अभियान ने एक तरह का जंगल राज पैदा कर दिया। चीड़ उगाने की मुहिम में पर्वतीय राज्यों में न केवल चारागाहें छीन ली बल्कि मनुष्य को भी वनों से दूर कर दिया। वनाग्नि से हिमालीय राज्यों में कहर बरप रहा है, जहां तापमान सामान्य से दो से लेकर चार डिग्री तक बढ़ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बर्फ का सागर और एशिया की जलवायु के नियंत्रक हिमालय की क्या दशा होगी? तापमान बढ़ने से जंगलों में सूखे पत्ते और टहनियां ईंधन का काम करती हैं। एक छोटी सी चिंगारी हीट का काम करती है। ऐसे में अगर तेज हवायें चल रही हों तो यह आग पूरे जंगल को तबाह कर देती है। इंसानों की लापरवाही के चलते भी आगजनी की घटनायें बढ़ रही हैं। जम्मू के रियासी जिले के जंगल, हिमाचल के पार्वती घाटी में, राजस्थान के अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में बमराडी से लेकर सीमार के जंगलों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग से प्रकृति तबाह हो चुकी है। गर्मियों में तापमान के कहर ढाने के कारणों में ग्लोबल वार्मिंग तो है ही लेकिन भारत में बढ़ते तापमान का कारण वनों का क्षरण भी है। यही कारण है कि देहरादून, मंसूरी, पंतनगर, रुड़की का अधिकतम तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। पिछले दिनों मुक्तेश्वर और मसूरी जैसे ठंडे स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वनाग्नि की आंच उत्तराखंड हिमालय के लगभग 14 ग्लेशियरों तक पहुंच रही है। कौन नहीं जानता कि राज्यों में अवैध खनन माफिया की तरह वन माफिया भी सक्रिय हैं। हर बार जंगल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनाकर जंगल को बचाने का ढिंढोरा पीटा जाता है लेकिन आग से बचाने के लिए जंगल की प्रवृत्ति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। मानव और व्यवस्था सब तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। मौसम परिवर्तन के चक्र ने अपने पंजे भयंकर रूप से फैला दिए हैं। जंगल अपनी ही हवाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। पंजाब और हरियाणा जंगलों की आग से बचे हुए हैं क्योंकि पंजाब में 3.65 प्रतिशत और हरियाणा में 3.53 प्रतिशत जमीन पर ही जंगल है। अगर मनुष्य को भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से अपना बचाव करना है तो उसे प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करना होगा और जंगलों को आग से बचाने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। वन प्रबंधन के लिए सही योजनाएं नहीं बनाई गई तो हमें भयंकर परिणाम झेलने होंगे।

कार्यस्थल सुरक्षा और समावेशिता का पोषण करें

विजय गर्ग

प्रभावी कार्यस्थल सुरक्षा और समावेशिता पहल एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करती है, जो उच्च आकांक्षाओं का पोषण करते हुए मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित करती है। कार्यस्थल सुरक्षा और समावेशिता के लगातार बदलते परिदृश्य में, इस यात्रा की तुलना अक्सर मास्लो के सिद्धांत से की जाती है जहां मूलभूत घटक उच्च आकांक्षाओं के लिए मंच तैयार करते हैं। मास्लो के पदानुक्रम की तरह जो शारीरिक आवश्यकताओं से आत्म-प्राप्ति की ओर बढ़ता है, हमारे आधुनिक दृष्टिकोण को अधिक महत्वाकांक्षी आकांक्षाओं तक जाने से पहले बुनियादी आवश्यकताओं से निपटना होगा। आज की मांग संगठनों की आकांक्षाओं से कहीं आगे जाती है, बल्कि उस पर ध्यान देती है जो विशेष क्षण में सबसे जरूरी है। आंकड़े एक्स-जेन्स, मिलेनियल्स, जेन जेड और जल्द ही जेनरेशन अल्फा सहित विविध कार्यबल संरचना का संकेत देते हैं। जैसे ही यह जनसांख्यिकीय बदलाव आएगा, क्या हम तैयार हैं? इस नये युग के लिए किस प्रकार की नीतियों और प्रथाओं पर विचार किया जाना चाहिए? वेतन समानता- नौकरी विवरण को वास्तविक भूमिकाओं या संभावित नियुक्तियों के साथ जोड़ने के लिए विवरण पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ऑडिट महज़ नीति निर्माण से आगे जाता है; इसके लिए विभिन्न परिदृश्यों में वेतन वार्ता और प्रतिधारण रणनीतियों पर चर्चा की आवश्यकता होती है। सुरक्षित कार्यस्थल- संगठन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने में तेजी से निवेश कर रहे हैं। पहल में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीतियां शामिल हैं, जो न केवल कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं बल्कि उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए एक चुंबक के रूप में भी काम करती हैं। सामाजिक योगदान पर ईएसजी का जोर मौद्रिक लाभ से परे उद्देश्य चाहने वाले व्यक्तियों के अनुरूप है। सम्मानजनक कार्यस्थल: मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण स्थापित करने के लिए स्पष्ट नीतियों को अनिवार्य किया गया है, जिसमें व्यावसायिक आचरण संहिता, शिकायत निवारण प्रोटोकॉल और कार्यस्थल उत्पीड़न दिशानिर्देश (यौन उत्पीड़न की रोकथाम सहित) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समर्पित समितियों को रोकथाम की पहल पर सक्रिय रूप से काम करते हुए मुद्दों का तुरंत समाधान करना चाहिए। विविधता और समावेशन- प्रासंगिक बने रहने के लिए, संगठनों को समान रोजगार नीतियां अपनानी होंगी, संचार प्रथाओं को परिष्कृत करना होगा, कर्मचारी संसाधन समूहों को बढ़ावा देना होगा और विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई) परिषदों की स्थापना करनी होगी। इन पहलों को प्राथमिकता देने में विफलता संभावित उम्मीदवारों और भागीदारों को हतोत्साहित कर सकती है, जो आज के परिदृश्य में उनके महत्व को रेखांकित करती है। लचीलापन- कर्मचारियों की विविध आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता सर्वोपरि है। विशेष परिस्थितियों के लिए आवास, अलग-अलग-सक्षम व्यक्तियों के लिए पहुंच, लिंग-तटस्थ सुविधाएं और नर्सिंग स्थान जैसी सुविधाएं आवश्यक हैं।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

वृष

व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

मिथुन

किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

कर्क

मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

सिंह

अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

कन्या

सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला

स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

वृश्चिक

मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

धनु

आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

मकर

आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

कुंभ

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

मीन

दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है गंभीर चुनौती

-ललित गर्ग

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव 2024 अनेक दृष्टियों से यादगार, चर्चित, आक्रामक एवं ऐतिहासिक होने के साथ-साथ अब तक का सबसे महंगा एवं दुनिया का सबसे खचीर्ला चुनाव है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार का चुनावी खर्च एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये के खर्च के साथ दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च की तुलना में इस बार दुगुना खर्च होगा। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक महंगी एवं धन के वर्चस्व वाली होने से राजनीतिक मूल्यों का विसंगतिपूर्ण एवं लोकतंत्र की आत्मा का हनन होना स्वाभाविक है। चुनाव जनतंत्र की जीवनी शक्ति है। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है। जनतंत्र के स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता, पारदर्शिता, मितव्ययता और उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत होने पर लोकतंत्र की जड़े खोखली होती चली जाती हैं। करोड़ों रुपए का खचीर्ला चुनाव, अच्छे लोगों के लिये जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता बन्द करता है और धनबल एवं धंधेबाजों के लिये रास्ता खोलता है। इन चुनावों में अर्थ का अनुचित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण खर्च का प्रवाह जहां चिन्ता का कारण बन रहा है, वहीं समूची लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का सबब भी बन रहा है। इस तरह की बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलियां डालना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके विरोध में व्यापक जनचेतना को जगाना जरूरी है। यह समस्या या विकृति किसी एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया के समूचे लोकतांत्रिक राष्ट्रों की समस्या है।

18वीं लोकसभा चुनाव में हर राजनैतिक दल अपने स्वार्थ की बात सोच रहा है तथा येन-केन-प्रकारेण ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने की अनैतिक तरकीबें निकाल रहा है। एक-एक प्रत्याशी चुनाव का प्रचार-प्रसार करने में करोड़ों रुपयों का व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, राजनीतिक दलों एवं प्रायोजकों से मिलता है। चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार उनके अनुचित दबाव के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनैतिकता एवं आर्थिक अपराध की परम्परा को सिंचन मिलता रहता है। यथार्थ में देखा जाए तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। लेकिन इस तरह लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन होता है, इस सबसे उन्नत एवं आदर्श शासन प्रणाली पर अनेक प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं।

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर चुनाव अभियान के लिए धन अलग-अलग स्त्रोतों से अलग-अलग तरीको से उम्मीदरवारों और राजनीतिक दलों के पास आता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए मुख्य रूप से रियल इस्टेट, खनन, कारपोरेट, उद्योग, व्यापार, ठेकेदार, चिटफण्ड कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, परिवहन ठेकेदार, शिक्षा उद्यमकर्ता, एनआआई, फिल्म, दूरसंचार जैसे प्रमुख स्त्रोत है। इस साल डिजिटल मीडिया द्वारा प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दल पेशेवर एजेंसिया की सेवाएं ले रहे हैं। इनसे सबसे अधिक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान, रैली, यात्रा खर्च के साथ-साथ सीधे तौर पर गोपनीय रूप से मतदाताओं को सीधे नकदी, शराब, उपहारों का वितरण भी शामिल है। देश में 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 2024 में 500 गुणा अधिक खर्च होने का अनुमान है। प्रति मतदाता 6 पैसे से बढ़कर आज 52 रुपये खर्च होने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में होने वाले वास्तविक खर्च और अधिकारिक तौर पर दिखाए गए खर्चे में काफी अंतर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 32 राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों द्वारा आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2,994 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया। इनमें दिखाया गया कि राजनीतिक दलों ने 529 करोड़ रुपये उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग में पेश खर्च का ब्यौरा और वास्तविक खर्च के साथ-साथ उम्मीदवारों द्वारा अपने स्तर पर किए जा रहे खर्चे में काफी अंतर है। अमेरिकी चुनाव पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने कहा कि यह 2020 के अमेरिकी चुनावों पर हुए खर्च के लगभग बराबर है, जो 14.4 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख 20 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित होगा।

भारत में होने वाले चुनाव में हो रहे बेसुमार खर्च की तपीश समूची दुनिया तक पहुंच रही है। समूची दुनिया के तमाम देशों में भारत के चुनाव को न केवल दम साध कर देखा जा रहा है बल्कि इन चुनाव के खर्चों एवं लगातार महंगे होते चुनाव की चर्चा भी पूरी दुनिया में व्याप्त है। लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों एवं उनके उम्मीदावारों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये तिजोरियां खोल दी है। यह चुनाव राष्ट्रीय मसलों के मुकाबले राजनीतिक दलों के हित सुरक्षित रखने के वादे पर ज्यादा केंद्रित लग रहा है और टकराव के मुद्दे थोड़े ज्यादा तीखे हैं। लेकिन अगर मुद्दों से इतर अभियानों की बात करें तो यह खबर ज्यादा ध्यान खींच रही है कि इस बार चुनाव अब तक के इतिहास में सबसे खचीर्ला साबित होने जा रहा है। इस चुनावों के अत्यधिक खचीर्ले होने का असर व्यापक होगा। चुनाव के तवे को गर्म करके अपनी रोटियां सेंकने की तैयारी में प्रत्याशी वह सब कुछ कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करता है। काफी लंबे और जटिल प्रक्रिया के तहत चलने वाले चुनाव में जनता के बीच समर्थन जुटाने के लिए उम्मीदरवार जितने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हैं, उसमें उन्हें स्थानीय कार्यकताओं से लेकर सामग्रियों और जनसंपर्कों तक के मामले में कई स्तरों पर खर्च चुकाने पड़ते हैं। यों किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले चुनावों में ऐसा ही होता है, लेकिन भारत में इसी कसौटी पर खर्च में कई गुना ज्यादा होना चिन्ता का सबब बनना चाहिए।

दुनिया की आर्थिक बदहाली एवं युद्ध की विभीषिका से चौपट काम-धंधों एवं जीवन संकट में लोकसभा के चुनाव कहां कोई आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जो लोग चुनाव जीतने के लिए इतना अधिक खर्च कर सकते हैं तो वे जीतने के बाद क्या करेंगे, पहले अपनी जेब को भरेंगे, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बनायेंगे। और मुख्य बात तो यह है कि यह सब पैसा आता कहां से है? कौन देता है इतने रुपये? धनाढ्य अपनी तिजोरियां तो खोलते ही है, कई कम्पनियां हैं जो इन सभी चुनावी दलों एवं उम्मीदवारों को पैसे देती है, चंदे के रूप में। चन्दा के नाम पर यदि किसी बड़ी कम्पनी ने धन दिया है तो वह सरकार की नीतियों में हेरफेर करवा कर लगाये गये धन से कई गुणा वसूल लेती है। इसीलिये वर्तमान देश की राजनीति में धनबल का प्रयोग चुनाव में बड़ी चुनौती है। सभी दल पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान के नाम पर नहीं। कोई भी ईमानदारी और सेवाभाव के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। राजनीति के खिलाड़ी सत्ता की दौड़ में इतने व्यस्त है कि उनके लिए विकास, जनसेवा, सुरक्षा, महामारियां, युद्ध, आतंकवाद की बात करना व्यर्थ हो गया है। सभी पार्टियां जनता को गुमराह करती नजर आती है। सभी पार्टियां नोट के बदले वोट चाहती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है। सभी जीवन मूल्य बिखर गए है, धन तथा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का अर्जन सर्वोच्च लक्ष्य बन गया है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि यह चुनाव आर्थिक विषमता की खाई को पाटने की बजाय बढ़ाने वाले साबित होने जा रहे हैं। आखिर कब तक चुनाव इस तरह की विसंगतियों पर सवार होता रहेगा?

अशोक भाटिया

गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं. एक नवंबर, 2023 से 22 अप्रैल 2024 तक वनाग्नि की 431 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं और इनसे 516.92 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। खास बात यह है कि 31 मार्च तक जंगलों में आग लगने की सिर्फ 34 घटनाएं हुई थीं और इनसे 35.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र ही प्रभावित हुआ था। लेकिन अप्रैल के 22 दिन में वनाग्नि और उससे होने वाला नुकसान करीब 13 गुना बढ़ गया।

दरअसल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर इस साल की शुरूआत में ही दिखने लगा है। देश के बड़े हिस्से में तापमान औसत से अधिक दर्ज किया गया है और इस बार तीन मार्च से ही लू या हीटवेव का प्रकोप शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 19 अप्रैल, को जारी अखिल भारतीय मौसम पूवार्नुमान के अनुसार, 18 अप्रैल, को भारत के 60 प्रतिशत से अधिक या 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। 2023 की तुलना में इस बार हीटवेव ने देश में 10 दिन पहले दस्तक दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 तक, तीन राज्यों में लू या हीटवेव का सितम रहा। तीन मार्च से 18 अप्रैल, 2024 तक अब यह संख्या बढ़ कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गई, जिन्हें गर्म हवाओं ने अपने आगोश में ले लिया था।भारत में लू या हीटवेव इस सप्ताह सुर्खियां बना रहा है, 16 अप्रैल को कथित तौर पर हीटस्ट्रोक से 13 लोगों की मौत हो गई। 20 अप्रैल को प्रकाशित, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने बताया कि देश के 90 प्रतिशत लोगों को गर्मी के कारण आजीविका क्षमता, खाद्यान्न उपज, वेक्टर जनित रोग फैलने और शहरी स्थिरता में नुकसान होने का खतरा है। यहां बताते चले कि, जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसे हीटवेव घोषित किया जाता है। कर्नाटक में साल का पहला लू का प्रकोप तीन मार्च को दर्ज किया गया था। नौ मार्च तक राज्य में चार दिन लू का कहर दर्ज किया गया था। गोवा में लू के चार दिन और गुजरात में दो दिन रहे। महीने की आखिरी लू 12 मार्च को दर्ज किया गया था।देश में 12 अप्रैल, को पश्चिम बंगाल में गंगा के अलग-अलग इलाकों में लू ने दस्तक दी। आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब और पश्चिम बंगाल में 12 से 18 अप्रैल तक लू का प्रकोप दर्ज किया गया।वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इससे निपटने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है, विशेष रूप से क्योंकि लू के सितम के जारी रहने के आसार हैं और यह लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।मौसम विभाग द्वारा 2 7 अप्रैल, 2024 तक लू या लू जैसी चरम स्थितियों पर कम से कम आठ राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में 30 अप्रैल, 2024 तक इन चरम स्थितियों के जारी रहने की आशंका जताई गई है।लोगों के स्वास्थ्य पर लू के प्रभाव को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली ऐसी चरम घटनाएं घातक भी हैं और इनसे निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की जरूरत है।

देश के कई राज्यों में जंगल में आग लगने से हजारों हैक्टेयर का जंगल तबाह हो गया वहीं वन्य संपदा और वन्य जीवों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। जंगलों से उठी आग की लपटों ने जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड को आग की तपती भट्ठी बना दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल की स्थिति चीड़ की पत्तियों के कारण काफी विकराल है। 70 के दशक में ही पर्वतीय राज्यों में चीड़ उगाने के अभियान ने एक तरह का जंगल राज पैदा कर दिया। चीड़ उगाने की मुहिम में पर्वतीय राज्यों में न केवल चारागाहें छीन ली बल्कि मनुष्य को भी वनों से दूर कर दिया। वनाग्नि से हिमालीय राज्यों में कहर बरप रहा है, जहां तापमान सामान्य से दो से लेकर चार डिग्री तक बढ़ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बर्फ का सागर और एशिया की जलवायु के नियंत्रक हिमालय की क्या दशा होगी?

तापमान बढ़ने से जंगलों में सूखे पत्ते और टहनियां ईंधन का काम करती हैं। एक छोटी सी चिंगारी हीट का काम करती है। ऐसे में अगर तेज हवायें चल रही हों तो यह आग पूरे जंगल को तबाह कर देती है। इंसानों की लापरवाही के चलते भी आगजनी की घटनायें बढ़ रही हैं। जम्मू के रियासी जिले के जंगल, हिमाचल के पार्वती घाटी में, राजस्थान के अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में बमराडी से लेकर सीमार के जंगलों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग से प्रकृति तबाह हो चुकी है। गर्मियों में तापमान के कहर ढाने के कारणों में ग्लोबल वार्मिजा तो है ही लेकिन भारत में बढ़ते तापमान का कारण वनों का क्षरण भी है। यही कारण है कि देहरादून, मंसूरी, पंतनगर, रुड़की का अधिकतम तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। पिछले दिनों मुक्तेश्वर और मसूरी जैसे ठंडे स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वनाग्नि की आंच उत्तराखंड हिमालय के लगभग 14 ग्लेशियरों तक पहुंच रही है।

वन्य जीवन अपने आप में एक दुनिया होता है। वनों में जीवधारियों को पर्याप्त भोजन के साथ-साथ सुरक्षित आश्रय भी मिल जाता है इसलिए वन सभी तरह के जीवधारियों का प्राकृतिक आवास होते हैं। तमाम वनस्पतियां और वन्य जीव एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब हालात यह है कि जंगलों की आग वनस्पति और वन्य जीवों का अस्तित्व राख में बदल रही है। बाघ और हिरन जैसे वन्य जीवन तो जान बचाकर सुरक्षित क्षेत्र की ओर भाग सकते हैं। तभी तो बाघों और मनुष्य के लिए खतरनाक जीवों को शहरों की सड़कों पर घूमते देखा जाता है। मगर उन निरीह जीवों और कीट-पतंगों का क्या हाल होगा जो आग की गति से भाग भी नहीं सकते। जंगलों की आग मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन चुकी है। इस आग के धुएं में अलग-अलग तरह के कण होते हैं जिनमें कार्बन मोनोआक्साइड भी शामिल है। स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों को लगातार नुक्सान पहुंचा रहे हैं। ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो इस पर जमा ब्लैक कार्बन भी बहेगा इससे जल प्रदूषित हो जाएगा। यह विडम्बना ही है कि किसी पेड़ के कटने से वन विभाग आम आदमी का जीना हराम कर देता है।

कौन नहीं जानता कि राज्यों में अवैध खनन माफिया की तरह वन माफिया भी सक्रिय हैं। हर बार जंगल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनाकर जंगल को बचाने का ढिंढोरा पीटा जाता है लेकिन आग से बचाने के लिए जंगल की प्रवृत्ति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। मानव और व्यवस्था सब तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। मौसम परिवर्तन के चक्र ने अपने पंजे भयंकर रूप से फैला दिए हैं। जंगल अपनी ही हवाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। पंजाब और हरियाणा जंगलों की आग से बचे हुए हैं क्योंकि पंजाब में 3.65 प्रतिशत और हरियाणा में 3.53 प्रतिशत जमीन पर ही जंगल है। अगर मनुष्य को भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से अपना बचाव करना है तो उसे प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करना होगा और जंगलों को आग से बचाने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। वन प्रबंधन के लिए सही योजनाएं नहीं बनाई गई तो हमें भयंकर परिणाम झेलने होंगे।

तीसरा चरणःब्रज से रूहेलखंड तक 10 सीटों पर मुकाबला

-अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में अब 07 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रस्साकशी तेज हो गई है। तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, एटा एवं आंवला की सीटें शमिल हैं। इस चरण में मुलायम और कल्याण के गढ़ में मुख्य मुकाबला होगा। डिंपल यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव की सियासी किस्मत इसी चरण में तय होगी। डिंपल जीत जारी रखने और अक्षय यादव और आदित्य यादव सपा की खोई सीट वापस पाने की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह के सामने भी हैट्रिक लगाने की चुनौती होगी। वह, एटा से उम्मीदवार हैं। इस चरण की 10 में 8 सीटों पर इस समय भाजपा काबिज है। संभल और मैनपुरी सपा के खाते में हैं, बाकी 8 सीटों पर 2019 में भाजपा जीती थी। मुस्लिम बहुल संभल सीट से सांसद शफीकुर्रहमान बर्क का निधन होने के चलते सपा ने उनके पोते और कुंदरकी से विधायक जियाउर्रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में यह सीट भाजपा जीती थी, लेकिन पिछले चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन ने उसकी राह रोक दी थी। संभल में 2019 में हार का सामना करने वाले परश्मेवर लाल सैनी इस बार भी भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि बसपा ने शौलत अली को टिकट दिया है। हाथरस, फतेहपुर सीकरी और बरेली में भाजपा हैट्रिक और आगरा एवं आंवला में लगातार चौथी जीत दर्ज करने की उम्मीद लिए मैदान में है। वहीं, सपा एवं कांग्रेस इस बार साथ हैं, जबकि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। इसलिए, अधिकतर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की ही उम्मीद है। सिलसिलेवार इन सीटों की समीक्षा की जाये।

https://t.me/AINewsPaperPaid

आगरा लोकसभा सीट पर किसके सिर ताज सजेगा, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बतौर भाजपा प्रत्याशी हैं। बसपा ने कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रहीं सत्या बहन की पुत्री पूजा अमरोही को टिकट थमाया है। सपा ने पुराने बसपाई रहे जूता कारोबारी सुरेश चंद कर्दम पर भरोसा जताया है। बघेल पर अपना दबदबा बराकरार रखने तो सुरेश चंद कर्दम पर सपा के लिए पिछले तीन लोकसभा चुनावों में इस सीट पर पड़ा सूखा खत्म करने की चुनौती है। पूजा अमरोही के समक्ष पर बसपा का खाता खोलने की चुनौती होगी। मोहब्बत की नगरी आगरा चुनाव में किस पर प्रेम वर्षा करेगी, इस पर निगाहें लगी हैं।

बरेली लोकसभा सीट पर भाजपा ने आठ बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर भाजपा ने पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया । इसे लेकर पार्टी कार्यकताओं में नाराजगी जरूर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रुहेलखंड में हुईं अपनी जनसभाओं के मंच पर संतोष गंगवार को स्थान देकर इस नाराजगी को दूर कर दिया है। 2009 में भाजपा के इस मजबूत किले को मामूली जीत के अंतर से ढहाने में कामयाब हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को सपा ने फिर इसी उम्मीद से मैदान में उतारा है। यहां भाजपा-सपा की सीधी लड़ाई है।

संभल लोकसभा सीट के सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के निधन के बाद इस सीट पर उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए कुंदरकी के सपा विधायक जियाउर्रहमान यहां समाजवादी उम्मीदवार हैं। पहले सपा ने शफीकुर्रहमान बर्क को टिकट थमाया था, लेकिन उनका निधन होने पर उनके पोते को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर जियाउर्रहमान के कंधों पर अपने परिवार का वर्चस्व बरकरार रखने का दारोमदार होगा। बतौर भाजपा प्रत्याशी पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी के सामने इस सीट पर भाजपा को 2014 में मिली एकमात्र सफलता को दोहराने के साथ पिछले चुनाव में खुद को मिली हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती है। बसपा के लिए पिछले दो चुनावों में यह सीट बंजर साबित हुई है। ऐसे में बसपा प्रत्याशी सौलत अली के लिए हाथी कितना प्रभावी होगा, यह देखना होगा।

मैनपुरी लोकसभा सीट सपा ने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए पार्टी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा हैं। मुलायम सिंह के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंद्वियों को हतप्रभ कर उन्होंने यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला था। अब उन पर इस विरासत को सहेजने और संजोये रखने की जिम्मेदारी है। सपा इस सीट पर 1996 से काबिज है। वहीं अब तक अजेय साबित हुई मैनपुरी सीट पर भगवा परचम लहराने के लिए भाजपा ने स्थानीय विधायक और योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। यादव और शाक्य बिरादरियों की बड़ी आबादी वाली इस सीट पर बसपा ने पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है।

बदायूं लोकसभा सीट पर भी यादव परिवार की साख का परीक्षा होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले यहां चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। धर्मेन्द्र 2009 व 2014 में बदायूं से बतौर सपा प्रत्याशी सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में चुनाव हार गए थे। अखिलेश ने इस बार फिर उन्हें यहां से टिकट थमाया, लेकिन बाद में उन्हें आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाकर चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं के चुनाव मैदान में उतार दिया। बाद में स्थानीय इकाई की मांग पर अखिलेश ने चाचा शिवपाल की जगह उनके पुत्र आदित्य यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा ने यहां वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीवार बनाया है तो बसपा ने मुस्लिम खां पर भरोसा जताया है। भाजपा यहां अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जोर लगाएगी।

आंवला लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद और प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप जीत की तिकड़ी लगाने के इरादे से फिर मैदान में हैं। उनकी राह रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को मैदान में उतारा है जो शाहजहांपुर के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2007 व 2012 में बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बसपा ने इस सीट पर सपा छोड़कर आए आंवला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सैयद आबिद अली को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर भी सभी दल जातियों के जरिये अपने समीकरण बैठाने में लगे हैं। वैसे आंवला सीट पर ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो चार जून को चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

हाथरस लोकसभा सीट बाहरी प्रत्याशियों को सुहाती रही है। भाजपा ने यहां अपने सांसद राजवीर सिंह दिलेर का टिकट काटकर अलीगढ़ की खैर सीट के विधायक और योगी सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। उन पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखने की जिम्मेदारी होगी। वहीं बसपा ने साफ्टवेयर इंजीनियर हेमबाबू धनगर और सपा ने जसवीर वाल्मीकि को प्रत्याशी घोषित किया है। सपा और बसपा प्रत्याशी सहारनपुर के निवासी हैं। भाजपा को अपनी केंद्रीय योजनाओं और मोदी-योगी पर भरोसा है तो विपक्ष को अपने समीकरणों का। देखना होगा कि इस सीट पर फिर कमल खिलता है या सपा-बसपा अपना खाता खोल पाने में कामयाब होती हैं। एटा लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र और वर्तमान भाजपा सांसद राजवीर सिंह यहां बीजेपी की तरफ से हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर चुनाव मैदान में हैं। राजवीर लोध बिरादरी से हैं तो सपा ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य पर भरोसा जताया है। देवेश शाक्य औरैया से दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। बसपा ने कांग्रेस छोड़कर आए पेशे से वकील मोहम्मद इरफान को उम्मीदवार बनाकर चुनाव का तीसरा कोण उभारने की कोशिश की है। बसपा अभी तक एटा सीट नहीं जीत सकी है। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रभाव वाला माना जाता है जिसे बरकरार रखने में राजवीर सिंह भी सफल रहे हैं। लोध मतदाता इसकी धुरी हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी शाक्य बिरादरी को साथ लेते हुए मुस्लिमों के साथ अपना समीकरण इस चुनाव में देख रही है।

फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर फिलहाल दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 4.95 लाख वोटों से जीतने वाले जाट बिरादरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर इस बार फिर यहां कमल खिलाने के इरादे से मैदान में हैं। बसपा ने चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण प्रत्याशी राम निवास शर्मा पर भरोसा जताया है तो कांग्रेस ने ठाकुर बिरादरी के रामनाथ सिकरवार को उतारा है। फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने निर्दल उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरकर यहां होने वाली लड़ाई को रोमांचक बना दिया है। रामेश्वर चौधरी भी जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं।

कर्नाटक में कांग्रेस ने साल भर में ऐसी कौन-सी गलतियां कर दीं जिसके चलते जनता इतनी नाराज है

हमने कर्नाटक के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना था कि बिजली के बिल में कटौती की जगह बिजली की कटौती होने लगी है। शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों ने कहा कि कमर्शियल यूज के लिए बिजली की दरों में बार-बार इजाफा किया जा रहा है जिससे हम पर भार पड़ रहा है।

लगभग एक साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 136 सीटों पर जीत हासिल कर-के प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई थी। लेकिन एक साल के भीतर ही कर्नाटक के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जिस तरह कांग्रेस के प्रति नाराजगी दिखने लगी है वह दर्शा रही है कि चुनावों में किये गये वादे पूरे नहीं किये जायें तो जनता सबक सिखाने को तैयार रहती है। खास बात यह है कि कर्नाटक में दी गयी गारंटियों को पूरा करने के दावे के आधार पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी अपने घोषणापत्र में तमाम तरह की गारंटियां दी हैं। लेकिन जब आप कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों के बारे में जनता से राय लेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली में जो दावे किये जा रहे हैं वह खोखले हैं।

हमने कर्नाटक के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना था कि बिजली के बिल में कटौती की जगह बिजली की कटौती होने लगी है। शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों ने कहा कि कमर्शियल यूज के लिए बिजली की दरों में बार-बार इजाफा किया जा रहा है जिससे हम पर भार पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमसे पैसा लेकर दूसरों को सब्सिडी दे रही है जोकि गलत है। गांवों में किसानों और दुग्ध उत्पादकों ने कहा कि हमसे किये गये वादे पूरे नहीं किये गये। शहरी क्षेत्रों में गैर-लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का उपयोग करने वाली महिलाओं ने कहा कि यह देश का चुनाव है इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से जब हमने मुफ्त यात्रा सुविधा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक तो बसें कम हैं और दूसरा जो बसें हैं वह खटारा जैसी हैं और प्रदूषण फैलाती हैं इसलिए ऐसी सुविधा का हमें कोई फायदा नहीं।

हमने गांवों और शहरों में एक चीज समान रूप से पाई कि लोग यह कहते दिखे कि हमें मुफ्त की सौगात नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कि हम कमा कर खाना चाहते हैं और सभी चीजों का बिल भी अपनी जेब से भरना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि हम सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहते इसलिए सरकार को मुफ्त रेवड़ियां बांटने की बजाय रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर जोर देना चाहिए। हमने पाया कि कर्नाटक में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास इस चुनाव में बड़े मुद्दे हैं। हमने पाया कि भाजपा से बेहतर बूथ प्रबंधन किसी अन्य पार्टी के पास नहीं है। हमने पाया कि महिला शक्ति का समर्थन सर्वाधिक भाजपा के साथ है। हमने पाया कि युवा शक्ति का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। हमने पाया कि पहली बार मतदान करने वाले से लेकर बच्चे तक की जुबान पर मोदी का नाम है।

2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 43 प्रतिशत मत हासिल किये थे। पिछले लोकसभा चुनावों में कर्नाटक उन राज्यों में शुमार था जहां भाजपा ने 51 प्रतिशत से अधिक मत हासिल किये थे। इस बार के चुनावों में भी वही स्थिति देखने को मिल सकती है। पिछले चुनावों में भाजपा ने राज्य की 28 में से 25 सीटों पर विजय हासिल की थी, ऐसा लगता है कि इस बार भी वही स्थिति रह सकती है या भाजपा और आगे भी जा सकती है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि का लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है और जिस तरह हाल ही में बेंगलुरु के एक कैफे में धमाका हो गया था उसको देखते हुए लोगों के मन में यह भावना प्रबल हुई है कि सुरक्षा हालात भाजपा के राज में ही बेहतर होते हैं।

2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 43 प्रतिशत मत हासिल किये थे। पिछले लोकसभा चुनावों में कर्नाटक उन राज्यों में शुमार था जहां भाजपा ने 51 प्रतिशत से अधिक मत हासिल किये थे। इस बार के चुनावों में भी वही स्थिति देखने को मिल सकती है। पिछले चुनावों में भाजपा ने राज्य की 28 में से 25 सीटों पर विजय हासिल की थी, ऐसा लगता है कि इस बार भी वही स्थिति रह सकती है या भाजपा और आगे भी जा सकती है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि का लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है और जिस तरह हाल ही में बेंगलुरु के एक कैफे में धमाका हो गया था उसको देखते हुए लोगों के मन में यह भावना प्रबल हुई है कि सुरक्षा हालात भाजपा के राज में ही बेहतर होते हैं।

कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के समय साइडलाइन किये गये पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भाजपा जिस तरह इस बार पूरा महत्व दे रही है उसका जातिगत असर होता भी दिख रहा है। भाजपा ने येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी है। येदियुरप्पा का लिंगायत समुदाय पर बड़ा प्रभाव है जोकि राज्य में बड़ा सामाजिक वर्ग है। वहीं जनता दल सेक्युलर का प्रभाव वोक्कालिगा समुदाय के बीच काफी अच्छा माना जाता है। इस समय कर्नाटक में जो सामाजिक समीकरण हैं उसके मुताबिक लिंगायत और वोक्कालिगा की ताकत के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जुड़ जायेगी तो इस गठबंधन का बेड़ा पार होना आसान हो जायेगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा राज्य में काफी सम्मानित नेता हैं। उन्होंने मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है और लगातार साक्षात्कारों और बयानों के जरिये वह जिस तरह मोदी के लिए समर्थन मांग रहे हैं उसका भी बड़ा असर कर्नाटक की राजनीति में देखा जा रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी कह चुके हैं कि जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही नहीं है बल्कि यह आगे तक के लिए है।

कर्नाटक में हमने एक चीज और पाई कि भाजपा जहां इस चुनाव को पूरी एकजुटता के साथ लड़ रही है वहीं कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की बजाय अपने-अपने खेमों के लोगों को जिताने के लिए ही प्रयास करते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि यह सब घटनाक्रम कांग्रेस के कई विधायकों को अखर रहा है। वह पहले से ही इस बात से नाराज हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि मुफ्त रेवड़ियां बांटने के चक्कर में कर्नाटक सरकार का खजाना ही खाली हो चुका है और विकास के लिए पैसा नहीं बचा है। यहां सवाल यह भी उठता है कि जब खजाना रेवड़ियां लुटाने में खाली कर दिया गया लेकिन जनता कह रही है कि उसे कुछ मिला ही नहीं तो यह पैसा आखिर गया कहां? -नीरज कुमार दुबे

संपादकीय

सत्य बसा है सीने में बहुत दर्द है जीने में!

सत्य सत्य है जो बसा है सीने में यह अनुभव की बातें हैं, कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन व ाह हारता नहीं।मानव के जन्म से लेकर अंत काल तक, सत्य का जो संबंध व्यक्ति से होता है, वह सदैव बना रहता है।लेकिन यह संसार है, जहां झूठ की भी चलती है, थोड़े ही दूर, थोड़ी देर के लिए। झूठ सदैव चलता नहीं, कुछ वक्त के लिये लाभ भले ही दे। आज के आधुनिक परिवेश में लोग झूठ को साबित करने में महारत हासिल करते दिखते हैं हैं।झुठ व्यक्ति को परेशान कर सकता है।पर सत्य सत्य होता है और वह व्यक्ति को निश्चित रूप से उसे सत्य से साक्षात्कार कराता दिखता है।आज लोग झूठ पर ही बुनियाद खडा कर रहे और इसी बुनियाद के बल पर मूंछ पर ताव देते हैं। लेकिन सत्य सत्य होता है।मानव रुपी इस नश्वर शरीर के विश्वास को पुख्ता करता है। इसके लिये अपने संकल्पों के साथ उस अदृश्य परमात्मा को जिन्होंने मनुष्य को इस धरा पर उतारा है, उन्हें अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपने को समर्पित करना होता है। लोक कल्याण के साथ अपने कल्याण की भी बातें इसमें निहित होती हैं और आज जब सर्वत्र घोर अंधेरा छाया हुआ है।हर जगह आत्मीयता खत्म होती जा रही है। लोग स्वार्थ के वशीभूत होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऊपर वाले का ही सहारा दिखता है ना समाज में न देश में नाही शासन प्रशासन में कोई स्पष्ट नीति दिखती है। तब ऊपर वाले ही दिखते हैं। मानवता की रक्षा के लिए। ऐसी स्थिति में हमारी धार्मिक आस्था निश्चित रूप से बलवती होती रहती है।भारतीयों का धार्मिक आस्था सदैव चरमोत्कर्ष पर रहता है।हम सभी सालों भर धार्मिकता के साथ दर्शन पूजन में व्यस्त रहते हैं। भारत में एक नहीं अनेकों ऐसे धर्म और धार्मिकता के लोग हैं। जो निरंतर अपने धर्म के प्रति सजग रहकर धार्मिकता को पुष्ट करते हैं।वही आस्था गंगा स्नान का है, जो धार्मिक भाव में उत्पन्न है। वह निश्चित रूप से भारतीय जनो का एक ऐसी पहचान है, जो अपने तन मन से धर्म को समर्पित करते हैं और हमारा धर्म निश्चित रूप से आपसी सद्भाव और एकता का प्रतीक है। विविधता में एकता, यह एक ऐसा मंत्र है, जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करता है।विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। भारत के इस प्रांण तत्व को समझना होगा। सवा सौ करोड़ देशवासियो की आपसी एकता, अखंडता, सदभाव और विश्वसनीयता को बनाए रखने में अहम धर्म भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे निभाते है।यह भी जानिए कि धर्म ने ही यह साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र में सभी का हक बराबर है। किसी भी तरह की जटिल समस्याओं का निदान, समाधान निकाला जा सकता है और एकता अखंडता को बनाए रखा जा सकता है।भारतीय लोकतंत्र जीवंत है और यह पूरे देश के लिये गौरव की बात है, कि हम सभी एकता और अखंडता में पूर्ण विश्वास रखते हैं।सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति ही, हम सभी के उद्धार का कारण भी बनता है। अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करे, कि साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना होगा, सबका विश्वास हासिल करना होगा। अब देश के हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण की जवाबदेही और एक नागरिक के तौर पर हम सभी समाज के साथ अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए, काम करना हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अनिवार्य है। हमारे बीच एकता, शांति, सद्भाव सबके साथ स्नेह देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भविष्य की ओर देखना है, भविष्य के भारत के लिए काम करना होगा। भारत के सामने चुनौतियां और भी है।मंजिलें और भी है।हम सब भारतीय साथ मिलकर, साथ चलकर ही लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तभी मंजिलों तक पहुंच पाएगें।आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए, आने वाले चुनौतियों का, आगे बढ़ने का, सभी भारतीयों को मिलजुल कर देश के विकास में, अपने योगदान को सुनिश्चित करने का संकल्प लेना है। हम सभी एकता और अनेकता की बातें सिर्फ जुबां से नहीं करें, बल्कि उसे सार्थक रूप में परिणत करते हुए एक दूसरे को साथ लेकर चलने का हर संभव प्रयास करें और यह तभी संभव है, जब हम अपने धर्म और कर्म को बरकरार रखते हुए एक साथ एकता में, बंधकर अनेकता का उदाहरण पेश कर, सदैव आगे बढ़ते रहें और धार्मिकता को अपनाकर अपने कर्म को सुधार कर निश्चित रूप से साथ चल कर धर्म-कर्म और समाज को सुदृढता प्रदान करना हम भारतीय जनों का कर्तव्य बनता है। धार्मिक आस्था हमारी पूंजी है, यानी मनुष्य की पूंजी है। जिसे हमें याद रखना होता है। इस पूंजी को संजो कर रखना होता है।अगर हम आप धर्म-कर्म में अपना योगदान करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है, देश का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, हर किसी का कल्याण इसी में निहित है।यह जानी-मानी सी बात है, कोई हमारी बात नहीं है।हम आपसे बस यही आग्रह करेंगे कि अपनी धार्मिकता को पुष्ट करते हुए, सामाजिकता में बने रहे, धर्म कर्म करते रहें। आपको और हमें यह निश्चित रूप से उस मुकाम पर पहुंचेगा, जिस मुकाम के लिए उस अदृश्य शक्ति भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। सबका कल्याण हो यह ध्यान रहे। तभी आपका हमारा कल्याण निहित है। अन्यथा जो हो रहा है, सब देख रहे हैं और क्या हो रहा है, यह दिख रहा है।अनैनिकता, व्यभिचार जैसे हर कार्य इस धरा पर हम देखते भोंगते रहते हैं। बस ऊपर वाले ही हैं जिनसे जुड कर कर्म धर्म के साथ अपने को पवित्र बनाते हैं। वही सबकुछ मनुष्य को देते हैं, कराते हैं, कि आप कितना कुछ करते हो उसमें उनका कितना योगदान है। यह समझने की बात होगी और वही समझ पाएंगे जो अपने हृदय से ऊपर वाले को जानते समझते पूछते हैं। वह दिखाई नहीं देते। लेकिन जीवन उन्होंने ही दिया है इसको देखते हैं, जानते हैं । आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा अपने अंदर होता है।जो हर एक मनुष्य में समाहित है। धर्म कर्म करके जीवन पथ पर आगे चलना ही जीवन की सार्थकता है। आज जीवन कितना कठिन हो गया है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस करोना काल में लोगों को जिस तरह से जीना पड़ रहा है, वह कितना कष्टकारी दिखता है, सोचने को मजबूर करता है कि क्या जीवन यही है? आज हर तरफ मजबूरी पांव पसारे दिखती है। हर कोई मजबूरी में जीवन को खेप रहा दिखता है।वेकारी बेरोजगारी और भूख की चपेट में कई लोग पडे हुए हैं।हर किसी को लगता है की जिंदगी जीने के लिए सिर्फ अपना बचाव करना ही काफी है। दूसरे के लिए सोचना भी कोरोना जैसी महामारी की चपेट में पड जाना होता है। अब जिंदगी को किस तरह लोग जिए लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कोरोना नित्य लोगों में दहशत पैदा करने में जुटी हुई है।लोग लोग खौफ जदा हैं। हर किसी को अपने जीवन की पड़ी है। बस ऊपर वाले पर भरोसा करके जीवन जान चलाया जा रहा है। इस काल में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है, तो वह है मजदूर वर्ग, जो रोज कमाता और खाता रहा है। छोटे-छोटे वे दुकान कर्मी, जो मासिक पगार पर अपने परिवार को आजिवीका चला रहे थे, या फिर रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग, जिनकी मेहनत के बल पर घर की रोटी दाल चलती थी। सब बेबस है, सब मजबूर है, पर जिंदगी जीने की लालसा तो बच्ची ही है। इसलिए ऊपर वाले का भरोसा कर जीना मरना उनके ऊपर छोड़ बस जीवन जिए जा रहे हैं लोग। जीवन है तो परेशानियां हैं अनेक परेशानियों के बीच व्यक्ति को जीना पड़ता है और तभी तो लोग कहते हैं जीना इसी का नाम है। बहुत दर्द है जीने में, पर जीना पड़ता है। आदमी चाहता कुछ है, होता कुछ है, पर इसी में जीना है।परेशानियों के बीच जीना आदमी को जीना होता है।

प्रभात वर्मा

पृथ्वी दिवस के अवसर पर

पेड़ हमारे सहचर एवं पूज्य

बाइस अप्रैल पृथ्वी दिवस है ।पृथ्वी दुखित होती है जब पेड़ कटते हैं। अतः पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्षों के संबंध में कुछ कहना, सबसे पहले जरूरी है ।वृक्ष-वनस्पतियों की उपयोगिता उसकी सार्थकता और औचित्य को गहराई से अनुभव करने के बाद ही लोगों ने उसे देवत्व की गरिमा प्रदान की। यह सोचकर कि लोक पूजित हो जाने पर उसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। कितनी ही सभ्यताएं विकसित हुई हैं और शून्य में विलीन हो गई है ।संस्कृतियों का उन्नयन हुआ, सबके केंद्र में वृक्ष एवं वनस्पति ही रहे ।लोग श्रद्धा भाव से पीपल को पानी देते हैं और तुलसी चौरा पर दीपक जलते हैं ।उनके अनेक मान्यताएं, टोटके जाने अनजाने बनती चली गई और घुलती चली गई। कहते हैं जिस कन्या के विवाह के लिए अडचने आ जाती हो, तब उसका विवाह यदि महुआ से कर दिया जाए तो दिक्कते नहीं होती ।विश्वसनीय तो नहीं लगता। इसी तरह यदि कन्या मंगली हो तो मंगलवार को महुआ वृक्ष के निकट दीपक जलाकर अनुष्ठान किया जाए, तो मंगल दोष कट जाता है। इतना नहीं घर में होने वाले शादी अनुष्ठान निर्विघ्न होने के लिए आम महुआ में विवाह कर देते हैं ।यह और कुछ नहीं, वृक्षों के प्रति युग युग से आ रही लोकमत में श्रद्धा एवं विश्वास है। प्रकृति में हर समय परिवर्तन होता रहता है ।सुख कारक एवं दुखद, लेकिन मनुष्य भी इसमें विकृति लाने में दोषी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर आज बहुत चिंता की जा रही है ।लेकिन यांत्रिक प्रदूषण से होने वाले खतरों से की भयावता बढ़ती जा रही है। आवश्यकता है प्रकृति की संरक्षण और भौतिक विकास में एक समन्वय का, जो अतिशय लालच पर नियंत्रण रखें बिना नहीं हो सकता ।भारतीय चिंतन में वृक्ष को दृष्टा भाव से साधना रत ऋषि के रूप में, मनुष्यों को हर प्रयास से सीख लेने वाला कहा गया है। भागवत कार कहते हैं "देखो यह वृक्ष भाग्यवान है, इसका शरीर दूसरे की छाया देने के लिए ही निर्मित हुआ है।" सारा जीवन परोपकार को अर्पित यह स्वयं हवा के झोंके वर्षा धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु इनसे हम लोगों की रक्षा करते हैं। सचमुच इनका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि इसके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है ।उनका जीवन निर्वाह होता है ।जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से सभी को कुछ ना कुछ मिल जाता है ।यह अपने पत्ते फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलो से लोगों की कामना पूर्ण करते हैं ।वैदिक ऋषियों का मन इसकी आश्रय दायिनी उदारता और औषधिय गुणकारी करुणा से आकृष्ट हुआ। वे आत्मा की गहराई में जाकर उनके दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदी के विद्वान प्रोफेसर रामप्रवेश सिंह जी ने अपनी उल्लेखनीय पुस्तक "लोक वृक्ष की छाया में" कहते हैं पेड़ों के नाम उनके स्वभाव एवं उद्धात चरित्र के अनुरूप दिए गए हैं। वृक्षों में लोक जीवन को ऊर्जा के स्रोत से ओत प्रोत कर देने की अप्रतिम क्षमता होती है ।इसके अर्थ एवं कार्य के आधार पर कई नाम से संबोधित किया जाता है ।वृक्ष का अर्थ है भूमि को विदीर्ण कर देने वाला ।विटप अर्थात दूर-दूर विस्तार पाने वाला ।पादप का अर्थ है पैर से पानी पीने वाला। महीन्ह अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला ।उन्हें चैत्य भी कहते हैं, जो चत्वर हो। अर्थात जिनमे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, प्रदान करने की शक्ति हो ।चेत्य शब्द उनके मंगल मय कल्याणकारी व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। हमारी संस्कृति में वर्षों से पूर्व में एवं आज भी श्रद्धा एवं अपनत्व भरा संबंध है। विभिन्न अवसरों पर वट, अश्वथ, महुआ, बेल, नीम, अशोक, आम, आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। लोक विश्वास में फैली इस आस्था में हरे पेड़ को काटना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। विष्णु पुराण में वृक्षारोपन को बहुत महत्व दिया गया है ।और पुण्य कारक माना गया है। कहा गया है कि अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा, सड़क के किनारे लगाया गया एकमात्र वृक्ष अधिक श्रेष्ठ है ।जिसके छाया के नीचे थके पथिक विश्राम करते हैं ।भगवान राम के वनवास का प्रसंग हो या पांडवों का वन गमन, वृक्षों की शीतल छाया ने ही उन्हें ब्रह्म ज्ञानी बनाया ।श्री कृष्ण से जुड़े कदम्ब, सीता से जुड़े अशोक, शिव से जुड़े बिल्व पत्र, कामदेव से जुड़े सहकार अशोक, बकुल, विष्णु से जुड़े अश्वत्थ, ब्रह्मा से जुड़े वट वृक्ष की विशेषता से हमारा साहित्य गौरवान्वित है। महाकवि कालिदास ने कर्णिकार, शेफाली, शिरीष का अपने साहित्य में अनूठा चित्र उकेरा है। बॉस की बांसुरी को कैसे भूल सकते जिनके मधुर ध्वनि में राधा सुध बुध खो बैठती थी एवं कृष्ण पर निछावर हो जाती थी। चाहे निर्माण का ऋण हो या अवसान की दारुण बेला दोनों स्थितियों में हमारे जीवन यात्रा को सहेज कर रख लेता है वृक्ष ।आज के समय में घटते हुए वन एवं बढ़ते हुए कंक्रीट के भवनो का बाहुल्य है। लेकिन बड़े अट्टालिकाओं एवं प्रसाद की गरिमा उसके आगे पीछे स्थित पुष्प वाटिका से ही आंकी जाती है। जहां उपवन है वहां स्वास्थ्यवर्धक वातावरण है, जीवन है, जीवंतता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां, जीवो के जीवन का आधार है। वृक्ष हैं तो पृथ्वी पर जीवन है।

दस्तक प्रभात/देवेंद्र कुमार

संस्मरण

"जहां चाह वहां राह"

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आप अगर अपने जीवन में किसी मकाम को हासिल करने की हार्दिक इच्छा, तमन्ना, सपना, ख़्वाहिश और चाहत रखते हैं तो वह मकाम आपको हासिल होता है। ऐसी मेरी सोच है और वह इसलिए कि अपनी जिंदगी में अपनी बदलती हुई इच्छाओं के अनुरूप किसी न किसी रूप में मैंने वह सारे मकाम हासिल करता गया। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से संकल्पित और समर्पित हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बात 70 के दशक की है जब पटना विश्वविद्यालय का क्रेज था। उन दिनों अगर छात्र आपस में बात करते हुए यह बताते थे कि मैं मगध विश्वविद्यालय का छात्र हूं तो सामने वाला किस कॉलेज में हो और कई प्रश्न कर देता था, वही पलट कर आप अगर पूछते कि आप किस विश्वविद्यालय में हैं तो जवाब मिलता था कि मैं तो पटना विश्वविद्यालय में हूं और आप आगे कुछ ना पूछे इस अंदाज में अपने वाक्य की समाप्ति करता था। मैं उन दिनों मगध विश्वविद्यालय के ए. एन कॉलेज का छात्र था। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने की इच्छा जागृत हुई स्नातक में मैं अपने विषय दर्शनशास्त्र में डिस्टिंक्शन मार्क लाया और मेरा दाखिला पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र (दरभंगा हाउस) विभाग में हो गया। विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करने के बाद मुझे बड़ी इच्छा हुई कि मोटरसाइकिल पर प्रेस लेकर चलने का अवसर मिले। मैंने स्वतंत्र पत्रकार के रूप में पत्रकारिता प्रारंभ किया। इस दौरान मेरी रचनाएं व रपट आर्यावर्त, प्रदीप (आज का हिन्दुस्तान), आज आदि कई अखबारों में प्रकाशित होने लगी और फिर पटना से प्रकाशित होने वाले अखबार अमृत वर्षा, जनादेश और लोकपत्र जैसे अखबारों का संपादकीय विभाग में मैं नौकरी करने लगा तब एक मोपेड गाड़ी खरीदी और उस पर प्रेस लिखाकर घूमना शुरू कर दिया। 80 के दशक में आकाशवाणी, पटना के युववाणी कार्यक्रम में भाग लेने के सिलसिले में आकाशवाणी में मेरा आना-जाना शुरू हुआ। उस समय युववाणी कार्यक्रम में मेरी पसंद, गीतों भरी कहानियां, 15 से 17 आदि कई कार्यक्रम का प्रसारण हुआ करता था। आकाशवाणी परिसर में ही मेरी मुलाकात बहुआयामी प्रतिभा के धनी और आकाशवाणी के तत्कालीन कार्यक्रम संयोजक श्री प्रभात वर्मा(वर्तमान में दस्तक प्रभात के संपादक एवं फिल्मी निमार्ता)से मुलाकात हुई जो आज भी मेरे अभिन्न मित्र के रूप में मेरे संपर्क में हैं। उन दिनों विजय कुमार सिंह उर्फ मंटू जी विविध भारती विज्ञापन प्रसारण सेवा प्रभाग के उद्घोषक के रूप में कार्यरत थे उन्हें हम लोग मंटू भैया संबोधित किया करते थे। एक दिन मैंने देखा कि मन्टू भैया स्टूडियो में मूविंग चेयर पर बैठकर एक अनाउंसमेंट किये और डेक पर लगे टेप ऑन कर बाहर निकले पड़े, यह सब मैं दरवाजे में लगे शीशे से देख रहा था ।यह सब मुझे लगा कि कितनी अच्छी नौकरी है ।काश! मुझे भी ऐसी नौकरी लग जाती तो कितना अच्छा होता। उन्ही दिनों आकाशवाणी में समाचार वाचक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन आया । मैंने आवेदन दिया और लिखित परीक्षा एवं वॉइस टेस्ट के बाद समाचार वाचक में मेरी अस्थाई नियुक्ति हो गई, परंतु समाचार वाचक में पद खाली नहीं रहने के कारण मुझे विविध भारती पर उद्घोषक के रूप में कार्य दिया गया और मैं विविध भारती का उद्घोषक बन गया। 90 का दशक आते-आते लगा कि यह सब ठीक है, लेकिन स्थाई सरकारी नौकरी लग जाती तो बड़ा अच्छा होता ।अब मैं प्रतियोगिता परीक्षाएं देने लगा और दो-चार प्रयास के बाद1992 में मेरी नियुक्ति बिहार सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग (वर्तमान में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) में सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में मेरी स्थाई नियुक्ति हो गई। आज की तारीख में मैं सेवा निवृत्त मार्केटिंग ऑफिसर हूं और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने के कारण कई संस्थानों जैसे सर्वजन कल्याण समिति, चित्रांश जन कल्याण समिति, 60 + केयर एंड फाउंडेशन आदि संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा के लिए प्रयासरत हूं। इस प्रकार यह कहावत बिल्कुल सही है कि "जहां चाह वहां राह"

दस्तक प्रभात
मिथिलेश कुमार सिन्हा

पद यात्रा

मन मोरे सति सरूप विचार

संत साहित्य का यदि हम अध्ययन करें तो हमें उसमें सत्य चिंतन का स्वरुप सबसे अधिक दिखाई देता है । वास्तव में सत्य एक ऐसा तत्व है जो सभी के पास होने के बाद भी उसे कोई-कोई ही समझ और स्वीकार कर पाया है । हर व्यक्ति का सत्य अपने जीवन और अनुभव के अनुरूप होता है । कोई धन सम्पत्ति को ही जीवन का सत्य मानता है तो कोई इससे पृथक जगत के संबंधों को ।

किसी की दृष्टि में रूप और पदवी प्राप्त करना ही जीवन का सबसे रहस्य और सत्य है तो कोई इसको जन्म देने वाला परमात्म भाव को तथा उससे जानने के भाव को ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानता है । इस प्रकार सभी के जीवन से उपजे सत्य अलग-अलग और अपनी प्रमाणिकता लिए हुए है । संत का मानना है कि हमारा अस्तित्व उस ईश्वर के कारण है तथा उसे जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है ।हमारा इस जगत में जन्म उस तत्व को जानने और उसे अनुभव करने के लिए ही हुआ है । संत रैदास भी अपने मन को चेताते हुए उस सत्य स्वरूप को जानने की ही बात कहते हैं क्योंकि ये मन परमात्मा की ओर बढ़ता हुआ भी अपनी चंचलतावश भटकाव की ओर भी चला जाता है । अतः वे मन को चेताते हुए कहते हैं कि झ मन मोरे सति सरूप विचार । आदि अंति अनंत परमपद, संसा सकल निवार ।। जस हरि कहिये तस हरि नाहिं, है अस जस कछु तैसा ।

जानत जानत जानि रह्यौ मन, मरम कहो निज कैसा ।। कहियत आन अनभव आन, रस मिल्यौ अवरु न होई । बाहरि भीतरि परगट गुपत, घट-घट प्रति बिगर न सोई ।। आदि हु ऐक अन्ता फुनि सोई, मधि उपाधि सु कैसे । अहै येक पै भ्रम सु दूजौ, कनक अलंक्रित जैसे ।। कहै रैदास परगास परम पद, का जप तप व्रत पूजा । ऐक अनेक, अनेक येक हरि, कहों कवन विधि दूजा ।। (पद- 71, रैदास ग्रंथावली) अर्थात इस पद के माध्यम से संत रैदास मन को चेताते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन तो बिना भ्रमित होए सत्य-स्वरुप ईश्वर को पहचान ।वह परमतत्व ऐसा है जिसका न आदि है न ही अंत वह तो मूलतः प्रत्येक सीमाओं से परे अनंत है । अतः ऐसे परंत्त्व का चिंतन करते हुए अपने में निहित सभी संशयों, भ्रमों को दूर करता चल । सामान्यतः हम ईश्वर को जैसा वर्णित करते हैं वैसा वह है ही नहीं और जैसा वह मूल रूप से उसे वैसा इस वाणी के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता । अर्थात ईश्वर की महिमा एवं उसके स्वरुप को पूर्णतः वर्णित नहीं किया जा सकता ।

ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करते-करते मन रुपी चेतन तत्व को जो भाव प्राप्त होता है उस भाव रूप मर्म रहस्य को इस गोचर जगत में विषयों से पूर्ण वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । ज्ञानी प्रबुद्ध जन उसे किसी दुसरे रूप में देखते हैं जबकि सामान्य जन अनुभव द्वारा उसे दुसरे रूप में प्राप्त करता है किंतु एक सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इस संसार में उसके बिना दूसरा कोई नहीं है । बाहर से लेकर भीतर तक तथा प्रगट से अप्रकट तक प्रत्येक जीव में बस वही विद्यमान है । उसके बिना कोई रिश्ता या संबंध पूर्ण नहीं होता । जब आदि से अंत तक व्ही विद्यमान है तो फिर मध्य में उसे अनेक मानने का विवाद कैसा ? जैसे स्वर्ण से ही आभूषण निर्मित होता है उसी प्रकार हम सभी उस परमात्मा से निर्मित हुए हैं । परमात्मा को अपने से पृथक मानना भ्रम मात्र है ।

संत रैदास कहते हैं कि समस्त संसार में परमात्मा का ही प्रकाश विद्यमान है । उसे प्राप्त करने के लिए जप-तप, व्रत-पूजा आदि व्यर्थ है । वह एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है फिर एक से भिन्न दूसरा वह कैसे हुआ । कहने का अभिप्राय ये है कि परमात्मा की सत्ता हम सब में है अतः हमें एक दुसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर परमात्मा को प्रसन्न रखना चाहिए । ईश्वर को पाने और जानने के अनेक मार्ग है हमें अपने मन पर काबू रख कर उस ईश्वर को मानवता द्वारा पाना चाहिए । यही जीवन का मूल सार और यही ईश्वर सच्चा स्वरुप है ।

दस्तक प्रभात/डॉ. कुलभूषण शर्मा

मौसम युद्ध हिट वेब सहित अनगिनत प्रकृति प्रकोप पृथ्वी को नष्ट करने का संकेत दे रही है

इंसान जहां अपना निवास स्थान बनाता है उसे बनाने के लिए पूरा जीवन भर का कमाई लगा देता है, ताकि वे अपने और अपना परिवार के साथ शेष जीवन सुरक्षित रूप से जी सकें।लेकिन यह कैसी विडंबना है की जिस पृथ्वी पर हमारा जीवन है उसे ही लगातार क्षति कर भविष्य में सुरक्षित जीवन का कामना कैसे कर सकते है। बार बार प्रकृति खतरनाक संकेत दे रही है फिर भी लोग इसके प्रति जागरूक नही हो रहे है। आज 22 अप्रैल के दिन दुनियाभर में पृथ्वी दिवस मनाया जा रह है। इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य लोगों के भीतर पर्यावरण के प्रति जागरुकता फैलाने और धरती को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन उत्सर्जन काफी बढ़ा है। इसका बुरा असर हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है। इस कारण पृथ्वी दिवस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वर्ष 2024 विश्व पृथ्वी दिवस की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक है । आज हमारे पर्यावरण, नदियों वातावरण यहां तक कि हमारे खाद्य पदार्थ में प्लास्टिक पूरी तरह से समा चुका है। यह थीम इसके निपटारे के लिए सामूहिक प्रयास को दशार्ती है। यह पृथ्वी दिवस प्लास्टिक का उपयोग बिलकुल खत्म करने और सामूहिक रूप से पृथ्वी के प्रति सजग होकर कार्य करने की अवश्यकता है।प्राकृतिक संसाधन हो या हरे भरे जंगल इसकी क्षति 21वीं सदी में जितनी नहीं हुई है उतना पिछले दो दशक में हो चुकी है। इस पर हर लोगो को चिंतन करना इसलिए भी आवश्यक हो गया है की वर्तमान में जिस प्रकार जिस प्रकार हिट वेब का सामना बिहार में करना पड़ रहा है उससे आम जनजीवन पूरी तरह हस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के वन विहीन क्षेत्र शेखपुरा जिला के लोगो को कल 44.1 डिग्री सेल्सियस का सामना करना पड़ा है और इसके साथ बांका और जमुई सहित 11 जिला भी लू के चपेट में रहा है। मौसम विभाग भी दोपहर 12 से 3 बजे बाहर नही निकलने का चेतावनी दी गई है। वो दिन भी दूर नही होगा जब यह समय अंतराल बढ़ता जायेगा।इसके विपरित की हम सोच लेते है की प्रकृति को अपने इशारे से चलाएंगे जिसका खतरनाक संकेत संयुक्त राज्य अमीरात (यूएई) में हाल के दिनों में हुई भारी बारिश ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यूएई में काफी कम बारिश होती है इसके लिए प्रकृति की छेड़छाड़ कर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया अपना कर बारिश करवाई जाती है पर इस बार कुछ ज्यादा प्रयोग होने से दुबई में भारी बारिश हो गई। उसने कई तरह की चिंताओं को जन्म दिया है। एक विश्व पर्यटक देश होने के बाबजूद कुछ ही घंटो में शहर तहस नहस कर दिया है। जिससे उभरने के लिए काफी समय लग सकता है। अब तो मौसम विज्ञानियों ने दुबई में बाढ़ के लिए 'क्लाउड सीडिंग' होने से भविष्य में मौसम युद्ध का रूप लेकर विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं का संकेत दिया है। पर्यावरण संरक्षण अभियान में अब तक लोगो की थी मंशा है की पर्यावरण संरक्षण कार्य मात्र सरकार का काम है या कोई एनजीओ ही मुहिम चला के ठीक कर देगा और जनमानस की जिम्मेदारी बिलकुल भी नहीं है इस मंशा से निकल कर हमे पृथ्वी को बचाने के लिए सामूहिक रूप से हर सफ्ताह श्रम दान देना आवश्यक हो गया है तभीअसल मायने में विश्व पृथ्वी दिवस को मानने का उद्देश्य पूरा होगा।

दस्तक प्रभात/विवेक कुमार

फुर्सत के फायदेमंद नुस्खे जगाएं

एक व्यक्ति के व्यस्त जीवन में फुर्सत का बहुत महत्व है, कुछ करने की चाहत में फुर्सत आवश्यक है । फुर्सत में कार्य समर्पित भाव से किये जा सकते है । दूसरे व्यक्ति के पास लगन की कमी, समय को फिजूल खर्च की बेहिसाब फुरसत ही फुरसत हमेशा रहती है । ऐसे में फुरसत का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों दिखते है । दो किस्म के विचार सामने आते । अक्सर दिनचर्या में कभी कभी कई लोग फुरसत का उपयोग इतने उपयोगी करते है कि वे समाज में एक उदाहरण बन जाते है । फुरसत में किये गए कार्य एक सन्देश बनते है समाज में बुद्धिजीवि सचमुच में फुर्सत के उपयोग व उसके मूल्यांकन को दशार्ते हैं । 24 घण्टे के समय में 24 व्यक्ति से व्यक्तिगत मुलाकात करने पर उनके फुर्सत का उपयोगी हिसाब उनके आंकड़े उपलब्ध हो सकते है । ये आंकड़े फुर्सत निकालकर संग्रह करने का एक शोधकार्य भी हो सकता है । अक्सर महान व्यक्तियों की सोच चिंता करने की लगन आदि में फुर्सत का उपयोगी साबित हुई । इसी का परिणाम है कि फुर्सत को कितनी अहमियत दिए । वे फुर्सत की सटीकता का पूर्ण ज्ञान समझे । अपने दिनचर्या के अन्य काम मे फुर्सत को बड़े ही चतुराई से आसान किये, यही वजह है की उनकी उपलब्धि में आसानी हुई । फुर्सत को एक दिन प्रतिदिन उपयोगी करने पर हमें मूल्यांकन करने में आसानी होती है । फुर्सत का समय यदि बीत गया तो लौट कर आता नहीं । आज के जीवन मे विज्ञान तकनीकी विकास में लोगों में समय की बचत हुई है । कम समय मे काम अधिक काम निबटाने में आसानी हुई है । हमें इसके अध्ययन में दिखेगा कि इसके सदुपयोग व दुरूपयोग में फुर्सत का गणित किस अवस्था में है । सीखने की करने की चाहत में तो अपनी दिनचर्या को सुखद आर्थिक उपार्जन कला कौशल आदि में फुर्सत से नाता जोड़ा विपरीत इसके दुरुपयोग में वर्तमान की युवापीढ़ी या अन्य न जाने कितने लोग दिनभर बेकार जुड़े रहने की फुर्सत में खूब व्यस्त दिखते है । युवाओं की इसकी वास्तविकता को भूलकर भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । फुर्सत है तो कोई अच्छा साहित्य लिखे, कोई अच्छी सेवाओ से समाज की भलाई करे, कलात्मकता को उभारे, प्रतिभाओं को उभारे ज्ञानोपयोगी विषय वस्तुओं को खुद पढ़े दुसरो को पढ़ाने में आगे बढ़े आदि ।उदाहरण में एक मजदूर दिनभर मजदूरी करके रात को अपने व्यस्त जीवन से कुछ फुर्सत में म्यूजिक सीखने की फुर्सत निकालता है । गीत गाने लगन सीखने की फुरसत स्वयं निर्धारित करता है वह फुर्सत निकालता है । अपनेआप को सन्तुष्ट रखने में फुर्सत का मोल फुर्सत से ही सम्भव करता है । ऐसे में व्यक्तिगत जीवन मे हर व्यक्ति की सोच में फुर्सत जैसी मूल्यवान वस्तु को खोकर आनद नहीं मिलेगा, इसमें फुर्सत को सीखने समझने उपयोगी करने के आनंद में समर्पित होना होगा ।बहुत से लोग फुर्सत की परिभाषा में इतने परिपक्क हो गए कि वे असीमित कार्य की फुर्सत व्यस्त जीवन मे रोज निकालते है। उदाहरण के तौर पर दर्जी खुद फटे कपड़े पहनते है । ग्राहक के कपड़े सिलते है । सर्दी में गर्म कपड़े सिलने पहनने की फुर्सत नही । संसार में किसी भी काम की बात पर फुर्सत कम रहने का बखेड़ा रहता है । यह शब्द जुबान पर त्वरित तैयार रहता है । फुर्सत मिलती नही फुर्सत निकाली जाती है । खुद को फुर्सत से संवारने में ज्यादा गम्भीरता चाहिए । पापों से बचने की तैयारी में फुर्सत निकालने में देर नहीं करे तो ही भलाई है । इंसान के पास समय का अभाव यानि फुर्सत नहीं की पट्टी लगी हुई है । पर क्या कभी सोचते है कि एक दिन जीवन की गाड़ी की सांस बंद हो जाएगी । जुबान बंद हो जाएगी । शरीर का कोई भी पुर्जा काम लायक नही रहेगा । बस एक स्थान वह भी शमशान का । क्या ऐसे में उसी जगह पर फुर्सत की आशा लगाये जीवन बीतेगा । संसार की चाकी दूसरे की निंदा में दुसरो को ज्ञानोपदेश में बीतने के सिवाय कुछ ही नहीं रह गया । इसीलिए फुर्सत की घड़ी को फायदेमंद करने की चिंताओं में एकाग्र होने की फिक्र करो ।

दस्तक प्रभात/ललित शर्मा

प्रचार के लिए स्वतंत्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अलीगढ़ में भाषण बांसवाड़ा का विस्तार है। ये दोनों भाषण एक दिन के अंतराल पर हैं। दोनों की थिम एक है। कांग्रेस पर हमले के बहाने, बहुसंख्यकों में उसके शासन का डर बैठाना। यह कहना कि 'उनकी गाढ़ी कमाई से अर्जित संपत्तियां, यहां तक कि 'स्त्रीधन कहे जाने वाले महिलाओं गहने-मंगलसूत्र-तक माओवादी की तरह छीन लिये जाएंगे। राष्ट्रीय संसाधन पर अल्पसंख्यकों, वे जो 'घुसपैठिए हैं, वे 'जिनके ज्यादा बच्चे हैं, का पहला हक होने की वकालत की याद दिला कर बहुसंख्यकों में उनके प्रति हिकारत पैदा कराना। प्रधानमंत्री अपने पक्ष में प्रचार के लिए स्वतंत्र हैं। पर वे कांग्रेसी मैनिफेस्टो या 2006 में तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के लिए नहीं। वे भूल जाते हैं कि ऐसे भाषण विभाजनकारी कोटि में आते हैं। चुनाव में होने के बावजूद एक प्रधानमंत्री के रूप में इसकी उन्हें इजाजत नहीं है। कांग्रेस चुनाव आयोग से मिल कर उनके एवं पार्टी के विरु द्ध 17 शिकायतें की हैं। प्रधानमंत्री के भाषण से लगता है, कांग्रेस जैसे सत्ता में आ रही है। ऐसा पहले चरण के मतदान में गिरावट से उन्हें लगा है। हालांकि कम वोट भाजपा का निरस्तीकरण नहीं है। पर यह आरएसएस कार्यकर्ताओं के अनुत्साह को दर्शाता है। दूसरी बात, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मोदी-राज में बढ़ी आर्थिक विषमताओं के आलोक में एक आयोग बैठाने की बात की है। सरप्लस भूमि-वितरण की बात की है। इसमें गलत क्या है? स्वयं प्रधानमंत्री एवं उनकी पार्टी और अन्य सारे दल इस तरह के कार्यक्रमों के साथ आने का वादा करते हैं। मनमोहन सिंह ने 'देश के आर्थिक संसाधनों को हाशिए पर पड़े तमाम समुदायों को देने की बात कही थी। यह प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि देश के मुसलमान 'घुसपैठिए नहीं हैं। वे भी अन्य के जैसे देश के नागरिक हैं, राष्ट्रवादी हैं। उनकी जनसांख्यिकी दर हिन्दू जितनी है। बेशक, लोगों के कल्याण और उनकी पहचान को जोड़ने पर राजनीतिक और चुनावी बहस हो सकती है, लेकिन मोदी के भाषण इस पर व्यापक संदेश भेजने के उनके स्वयं के प्रयासों के विरु द्ध हैं, जो लाभार्थियों में जाति-समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करता। वे खुद भारत की विविधता एक 'बहुरत्नधारी वसुंधरा मानते हैं, लेकिन पूरे समुदाय को एक विरोधी के रूप में पेश करके, प्रधानमंत्री उस बहस को व्यापक करने की संभावनाओं को सिकोड़ देते हैं।

हर फिक्र को धुएं में उड़ाता

साल 1961 की बहुचर्चित फिल्म 'हम दोनों का गाना 'हर फिक्र को धुएं में उड़ाता सबने सुना होगा। धूम्रपान करने वालों ने भी इसे अवश्य सुना होगा।फिल्म में गाने के बोल इस तरह दर्शाए गए कि फिल्म का हीरो अपने सभी फिक्र और चिंताओं को धुएं के कश में उड़ा देता है और चिंता मुक्त हो जाता है, परंतु क्या यह सही है कि मात्र सिगरेट के कश भरने और धुआं उड़ाने से आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी? इसका उत्तर है नहीं। बल्कि यदि आपको धूम्रपान की लत लग जाए तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ जरूर जाएंगी। आज जानते हैं कि ऐसा क्या है, इस चंद लम्हे की मामूली सी खुशी में, जो लाखों करोड़ों को इसकी लत लगा देती है। दरअसल, सिगरेट में मौजूद तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो कश लेते ही बड़ी तेजी से आपके फेफड़े में समा जाता है और कुछ ही क्षण में दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग में पहुंचते ही इसका संपर्क 'नर्व सेल से होता है और इसके असर से डोपामाइन नाम का रसायन बाहर आता है। यह रसायन आपके दिमाग को संकेत देता है कि कुछ अच्छा करने से आपको इनाम मिल सकता है। विशेषज्ञों की मानें तो, यह रसायन आपको ऐसा इशारा देता है कि आप एक बार दोबारा सिगरेट का कश भर लेते हैं। एक शोध के अनुसार सिगरेट की लत से प्रभावित लोगों, जिन्हें गले का कैंसर हुआ था, की गले की नली को काट कर अलग करना पड़ा। उपचार के बाद भी इस लत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वे दोबारा धूम्रपान करने को मजबूर थे। विशेषज्ञों के अनुसार दिमाग के जिस हिस्से को 'एनिमल पार्ट कहा जाता है, उससे ही निकोटीन की लत पर काबू पाया जा सकता है। नशीले पदार्थ हमारे दिमाग के 'एनिमल पार्ट को इस कदर उकसाते हैं कि वो ऐसे संदेश भेजता है कि हम ऐसा बार-बार करें। वहीं दिमाग का दूसरा हिस्सा हमें ऐसा करने से रोकता भी है। नशे की लत की गिरफ्त में लोग अक्सर इस संघर्ष से जूझते रहते हैं। इस लत का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि आप कितने समझदार हैं, बल्कि आपका दिमाग निकोटीन या अन्य नशीले पदाथरे पर किस तरह प्रतिक्रिया देता है। यदि समय रहते और सही संगति के चलते नशा या धूम्रपान रोक दिया जाए तो बेहतर हो परंतु ऐसा बहुत कम होता है। सिगरेट की लत के लिए केवल निकोटीन ही जिम्मेदार नहीं होती। इसके लिए एक प्रमुख भूमिका सिगरेट बनाने वाली कंपनियों और उनके द्वारा जारी किए भ्रामक विज्ञापन भी उतने ही जिम्मेदार हैं। पश्चिमी देशों में जैसे ही निकोटीन की लत को लेकर सवाल उठने लगे तो कुछ लोगों ने इसकी जड़ तक जाने की सोची।

भारत में धार्मिक पर्यटन छू रहा नित नई ऊंचाईयां

आरती कुमारी

हाल ही के समय में भारत के नागरिकों में "स्व" का भाव विकसित होने के चलते देश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ा है। अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में श्रीराम लला के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रत्येक दिन औसतन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह तो केवल अयोध्या की कहानी है इसके साथ ही तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। भारत में धार्मिक पर्यटन में आई जबरदस्त तेजी के बदौलत रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं। जेफरीज नामक एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज कम्पनी ने बताया है कि अयोध्या में निर्मित प्रभु श्रीराम के मंदिर से भारत की आर्थिक सम्पन्नता बढ़ने जा रही है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सम्पन्न हुए प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद स्थानीय कारोबारी अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बनाने जा रहा है तथा अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जेफरीज के अनुसार अयोध्या में प्रति वर्ष 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ सकते हैं। अभी अयोध्या में केवल 17 बड़े होटल हैं इनमें कुल मिलाकर 590 कमरे उपलब्ध हैं। लेकिन, अब 73 नए होटलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 40 होटलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है। अभी तक नए एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, टाउनशिप और रोड कनेक्टिविटी में सुधार जैसे कामों पर 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस निवेश का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर दिखाई देने जा रहा है। शीघ्र ही अयोध्या वैश्विक स्तर पर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। इससे होटल, एयरलाईन, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, सिमेंट जैसे क्षेत्रों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। भारत के विभिन्न शहरों से 1000 के आसपास नई रेल अयोध्या के लिए चलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश से दिनांक 23 जनवरी 2024 के बाद से प्रतिदिन भारी संख्या में धार्मिक पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि पहिले दिन ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीराम के दर्शन किये हैं। विश्व के कई अन्य देश भी धार्मिक पर्यटन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाएं सफलतापूर्वक मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब धार्मिक पर्यटन से प्रति वर्ष 22,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्जित करता है। सऊदी अरब इस आय को आगे आने वाले समय में 35,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक ले जाना चाहता है। मक्का में प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं, जबकि मक्का में गैर मुस्लिम के पहुंचने पर पाबंदी है। इसी प्रकार, वेटिकन सिटी में प्रतिवर्ष 90 लाख लोग पहुंचते हैं। इस धार्मिक पर्यटन से अकेले वेटिकन सिटी को प्रतिवर्ष लगभग 32 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आय होती है, और अकेले मक्का शहर को 12,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आमदनी होती है। अयोध्या में तो किसी भी धर्म, मत, पंथ मानने वाले श्रद्धालुओं पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। अतः अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 से 10 करोड़ तक प्रतिवर्ष जा सकती है। फिर अकेले अयोध्या नगर को होने वाली आय का अनुमान तो सहज रूप से लगाया जा सकता है। अभी अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अयोध्या में रुकते नहीं थे प्रातः अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर शाम तक वापिस चले जाते थे परंतु अब अयोध्या को इतना आकर्षक रूप से विकसित किया जा रहा है कि श्रद्धालु 3 से 4 दिन रुकने का प्रयास करेंगे। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक पर्यटक लगभग 6 लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। इस संख्या के हिसाब से तो लाखों नए रोजगार के अवसर अयोध्या में उत्पन्न होने जा रहे हैं। अयोध्या के आसपास विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब अयोध्या के रूप में वेटिकन एवं मक्का का जवाब भारत में खड़ा होने जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भी धरातल पर बहुत कार्य सम्पन्न किया है। साथ ही, अब इसके अंतर्गत एक रामायण सर्किट रूट को भी विकसित किया जा रहा है। इस रूट पर विशेष रेलगाड़ियां भी चलाए जाने की योजना बनाई गई है। यह विशेष रेलगाड़ी 18 दिनों में 8000 किलो मीटर की यात्रा सम्पन्न करेगी, इस विशेष रेलगाड़ी के इस रेलमार्ग पर 18 स्टॉप होंगे। यह विशेष रेलमार्ग प्रभु श्रीराम से जुड़े ऐतिहासिक नगरों अयोध्या, चित्रकूट एवं छतीसगढ़ को जोड़ेगा। अयोध्या में नवनिर्मित प्रभु श्रीराम मंदिर वैश्विक पटल पर इस रूट को भी रखेगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम भी अब दिखाई देने लगा है। "मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट" के अनुसार, भारत के नागरिक अब पहले के मुकाबले अधिक यात्रा कर रहे हैं। भारत के नागरिकों द्वारा विशेष रूप से अयोध्या, उज्जैन एवं बदरीनाथ जैसे आध्यात्मिक स्थलों के बारे में अधिक जानकारी हासिल की जा रही है। उक्त जानकारी "मेक माई ट्रिप" के प्लेटफार्म के 10 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामने आई है। वर्ष 2019 के बाद से भारत में एक वर्ष में तीन से अधिक यात्राएं करने वाले लोगों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आध्यात्मिक पर्यटन सम्बंधी जानकारी हासिल करने की गतिविधियों में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में 97 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से अयोध्या के सम्बंध में जानकारी हासिल करने सम्बंधी गतिविधियां में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 585 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज हुई है। इसी प्रकार, उज्जैन एवं बदरीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों के सम्बंध में भी जानकारी हासिल करने वाले नागरिकों की संख्या में क्रमशः 359 प्रतिशत और 343 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। भारत में अब पारिवारिक यात्रा की बुकिंग भी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इसमें वर्ष 2022 के तुलना में वर्ष 2023 में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि इसी अवधि में एकल यात्रा की बुकिंग में केवल 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उक्त जानकारी को भारत के नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा जारी एक जानकारी से भी बल मिलता है कि भारत में घरेलू हवाई यातायात अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। दिनांक 21 अप्रेल 2024 (रविवार) को रिकार्ड 471,751 यात्रियों ने 6,128 उड़ानों के माध्यम से, भारत में हवाई सफर किया है। इसके पूर्व हवाई यातायात करने वाले नागरिकों की औसत संख्या, कोरोना महामारी के पूर्व के खंडकाल में, 398,579 यात्रियों की थी। इसमें 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। देश में धार्मिक पर्यटन में हो रही भारी वृद्धि के चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में भी तेजी दिखाई देने लगी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है जबकि प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की रही थी। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही थी। जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। इसी प्रकार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा ने 6.5 प्रतिशत, एशिया विकास बैंक एवं बार्कलेस एवं प्राइस वॉटर कूपर्स ने 6.7 प्रतिशत, डेलाइट इंडिया ने 7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। परंतु, समस्त विदेशी संस्थानों के अनुमानों के झुठलाते हुए भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 8 प्रतिशत की रही है। यह सब देश में लगातार बढ़ते धार्मिक पर्यटन एवं विभिन त्यौहारों तथा शादी जैसे समारोहों पर भारतीय नागरिकों द्वारा दिल खोलकर पैसा खर्च करने के चलते सम्भव हो पा रहा है। इससे त्यौहारों एवं शादी के मौसम में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। जैसे दीपावली त्यौहार के समय भारत में नागरिकों के बीच विभिन्न नए उत्पादों की खरीद के लिए जैसे आपस में होड़ सी लग जाती है। भारत में लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दीपावली त्यौहार के समय में होता है। इसी प्रकार की स्थिति शादियों के मौसम में भी पाई जाती है। संभवतः विदेशी वित्तीय संस्थान भारत में हो रहे इस तरह के उक्त वर्णित परिवर्तनों को समझ नहीं पा रहे हैं एवं केवल पारंपरिक विधि से ही सकल घरेलू उत्पाद को आंकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारत की विकास दर के संबंध में विभिन्न विदेशी संस्थानों के अनुमान गलत साबित हो रहे हैं।

वन प्रबंधन के लिए सही योजनाएं नहीं बनाई गई तो हमें भविष्य में भयंकर परिणाम झेलने होंगे

अशोक भाटिया

गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं. एक नवंबर, 2023 से 22 अप्रैल 2024 तक वनाग्नि की 431 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं और इनसे 516.92 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। खास बात यह है कि 31 मार्च तक जंगलों में आग लगने की सिर्फ 34 घटनाएं हुई थीं और इनसे 35.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र ही प्रभावित हुआ था। लेकिन अप्रैल के 22 दिन में वनाग्नि और उससे होने वाला नुकसान करीब 13 गुना बढ़ गया। दरअसल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर इस साल की शुरुआत में ही दिखने लगा है। देश के बड़े हिस्से में तापमान औसत से अधिक दर्ज किया गया है और इस बार तीन मार्च से ही लू या हीटवेव का प्रकोप शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 19 अप्रैल, को जारी अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 18 अप्रैल, को भारत के 60 प्रतिशत से अधिक या 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। 2023 की तुलना में इस बार हीटवेव ने देश में 10 दिन पहले दस्तक दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 तक, तीन राज्यों में लू या हीटवेव का सितम रहा। तीन मार्च से 18 अप्रैल, 2024 तक अब यह संख्या बढ़ कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गई, जिन्हें गर्म हवाओं ने अपने आगोश में ले लिया था।भारत में लू या हीटवेव इस सप्ताह सुर्खियां बना रहा है, 16 अप्रैल को कथित तौर पर हीटस्ट्रोक से 13 लोगों की मौत हो गई। 20 अप्रैल को प्रकाशित, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने बताया कि देश के 90 प्रतिशत लोगों को गर्मी के कारण आजीविका क्षमता, खाद्यान्न उपज, वेक्टर जनित रोग फैलने और शहरी स्थिरता में नुकसान होने का खतरा है। यहां बताते चले कि, जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसे हीटवेव घोषित किया जाता है।कर्नाटक में साल का पहला लू का प्रकोप तीन मार्च को दर्ज किया गया था। नौ मार्च तक राज्य में चार दिन लू का कहर दर्ज किया गया था। गोवा में लू के चार दिन और गुजरात में दो दिन रहे। महीने की आखिरी लू 12 मार्च को दर्ज किया गया था।देश में 12 अप्रैल, को पश्चिम बंगाल में गंगा के अलग-अलग इलाकों में लू ने दस्तक दी। आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब और पश्चिम बंगाल में 12 से 18 अप्रैल तक लू का प्रकोप दर्ज किया गया।वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इससे निपटने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है, विशेष रूप से क्योंकि लू के सितम के जारी रहने के आसार हैं और यह लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।मौसम विभाग द्वारा 2 7 अप्रैल, 2024 तक लू या लू जैसी चरम स्थितियों पर कम से कम आठ राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में 30 अप्रैल, 2024 तक इन चरम स्थितियों के जारी रहने की आशंका जताई गई है।लोगों के स्वास्थ्य पर लू के प्रभाव को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली ऐसी चरम घटनाएं घातक भी हैं और इनसे निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की जरूरत है। देश के कई राज्यों में जंगल में आग लगने से हजारों हैक्टेयर का जंगल तबाह हो गया वहीं वन्य संपदा और वन्य जीवों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। जंगलों से उठी आग की लपटों ने जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड को आग की तपती भट्ठी बना दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल की स्थिति चीड़ की पत्तियों के कारण काफी विकराल है। 70 के दशक में ही पर्वतीय राज्यों में चीड़ उगाने के अभियान ने एक तरह का जंगल राज पैदा कर दिया। चीड़ उगाने की मुहिम में पर्वतीय राज्यों में न केवल चारागाहें छीन ली बल्कि मनुष्य को भी वनों से दूर कर दिया। वनाग्नि से हिमालीय राज्यों में कहर बरप रहा है, जहां तापमान सामान्य से दो से लेकर चार डिग्री तक बढ़ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बर्फ का सागर और एशिया की जलवायु के नियंत्रक हिमालय की क्या दशा होगी? तापमान बढ़ने से जंगलों में सूखे पत्ते और टहनियां ईंधन का काम करती हैं। एक छोटी सी चिंगारी हीट का काम करती है। ऐसे में अगर तेज हवायें चल रही हों तो यह आग पूरे जंगल को तबाह कर देती है। इंसानों की लापरवाही के चलते भी आगजनी की घटनायें बढ़ रही हैं। जम्मू के रियासी जिले के जंगल, हिमाचल के पार्वती घाटी में, राजस्थान के अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में बमराडी से लेकर सीमार के जंगलों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग से प्रकृति तबाह हो चुकी है। गर्मियों में तापमान के कहर ढाने के कारणों में ग्लोबल वामिर्जा तो है ही लेकिन भारत में बढ़ते तापमान का कारण वनों का क्षरण भी है। यही कारण है कि देहरादून, मंसूरी, पंतनगर, रुड़की का अधिकतम तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। पिछले दिनों मुक्तेश्वर और मसूरी जैसे ठंडे स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वनाग्नि की आंच उत्तराखंड हिमालय के लगभग 14 ग्लेशियरों तक पहुंच रही है। वन्य जीवन अपने आप में एक दुनिया होता है। वनों में जीवधारियों को पर्याप्त भोजन के साथ-साथ सुरक्षित आश्रय भी मिल जाता है इसलिए वन सभी तरह के जीवधारियों का प्राकृतिक आवास होते हैं। तमाम वनस्पतियां और वन्य जीव एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब हालात यह है कि जंगलों की आग वनस्पति और वन्य जीवों का अस्तित्व राख में बदल रही है। बाघ और हिरन जैसे वन्य जीवन तो जान बचाकर सुरक्षित क्षेत्र की ओर भाग सकते हैं। तभी तो बाघों और मनुष्य के लिए खतरनाक जीवों को शहरों की सड़कों पर घूमते देखा जाता है। मगर उन निरीह जीवों और कीट-पतंगों का क्या हाल होगा जो आग की गति से भाग भी नहीं सकते। जंगलों की आग मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन चुकी है। इस आग के धुएं में अलग-अलग तरह के कण होते हैं जिनमें कार्बन मोनोआक्साइड भी शामिल है। स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों को लगातार नुक्सान पहुंचा रहे हैं। ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो इस पर जमा ब्लैक कार्बन भी बहेगा इससे जल प्रदूषित हो जाएगा। यह विडम्बना ही है कि किसी पेड़ के कटने से वन विभाग आम आदमी का जीना हराम कर देता है। कौन नहीं जानता कि राज्यों में अवैध खनन माफिया की तरह वन माफिया भी सक्रिय हैं। हर बार जंगल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनाकर जंगल को बचाने का ढिंढोरा पीटा जाता है लेकिन आग से बचाने के लिए जंगल की प्रवृत्ति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। मानव और व्यवस्था सब तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। मौसम परिवर्तन के चक्र ने अपने पंजे भयंकर रूप से फैला दिए हैं। जंगल अपनी ही हवाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। पंजाब और हरियाणा जंगलों की आग से बचे हुए हैं क्योंकि पंजाब में 3.65 प्रतिशत और हरियाणा में 3.53 प्रतिशत जमीन पर ही जंगल है। अगर मनुष्य को भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से अपना बचाव करना है तो उसे प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करना होगा और जंगलों को आग से बचाने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। वन प्रबंधन के लिए सही योजनाएं नहीं बनाई गई तो हमें भयंकर परिणाम झेलने होंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मेष राशिः आज आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। आज आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिससे आपका मन...काम करने में लगा रहेगा। आज आपको व्यापारिक यात्रा से फायदा होगा। लोगों से मिलने और बात करने में खुशी महसूस करेंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में तालमेल रहेगा। आपके विचारों में सकारात्मकता रहेगी। किसी भी मामले पर बहस करने से बचें। ऑनलाइन बिजनेस कर रही महिलाओं की इनकम में इजाफा होगा।

वृष राशिः आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज सेहत के मामले में दिन अच्छा है। काफी समय पहले दिए इंटरव्यू का रिजल्ट आज आपके पक्ष में आयेगा। आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके करियर के लिए मददगार रहेंगे। आप परिवार की इच्छाएं पूरी करने में सफल होंगे। आज आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। आपको कुछ नये बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकते हैं।

मिथुन राशिः आज का दिन आपके लिए बेहद खास होगा। आप किसी जरूरी काम में व्यस्त रहेंगे। आपको इनकम के नए सोर्स प्राप्त होंगे। आपको व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ होगा। आपको अपने घरेलू काम में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। बड़े-बुजुर्ग की सेहत का ख्याल रखना, आपको उनका प्रिय बना देगा। माता-पिता का आशीर्वाद लें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा।

कर्क राशिः आज आपका दिन नई उमंगो के साथ शुरू होगा। किसी जरूरी काम में आपको भाई-बहन का सपोर्ट मिलेगा। आज आप परिवार के साथ कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठायेंगे। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आयेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

सिंह राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप कुछ नया प्लान बनायेंगे। बिजनेस में जो नए ऑफर मिलेंगे उन पर विचार करें, आपको फायदा हो सकता है। किसी बिगड़े रिश्ते को सुधारने में आज आप सफल हो सकते हैं। शाम को परिवार के साथ समय बितायेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा। मैनेजर पोस्ट के लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा।

कन्या राशिः आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आप पर ईश्वर की असीम कृपा है जिससे आपके बिगड़ते सभी काम बन जायेंगे। दोस्तों के साथ रिश्ते में सुधार आयेगा। आज आप अपने किसी मित्र की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले बड़े भाई से सलाह अवश्य लें। फिजूल खर्चों पर आज आप रोक लगाकर बचत करने के बारे में सोचेंगे।

तुला राशिः आज का दिन बेहद खास होने वाला है। ऑफिशियल मामलों में आपका कॉन्फिडेंस कुछ डगमगा सकता है, इसलिए अपने काम पर एकदम फोकस बनायें रखें। दोस्तों और परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे। कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आज कुछ नए काम भी अचानक सामने आ सकते हैं।

वृश्चिक राशिः आज आपका दिन शानदार रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों की अच्छी इनकम होगी। प्रॉपर्टी से जुडी समस्याओं के लिए भागदौड़ के उपरांत काम बन जायेगा। आज अपने विचारों को लेकर आप थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में आज आप एक्टिव रहेंगे। सगे सम्बन्धियों से अच्छे तालमेल बनेंगे। आज किसी जरूरतमंद की सहायता करने का मौका मिलेगा।

धनु राशिः आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशिया लाया है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज राह चलते किसी अनजान व्यक्ति से बेवजह न उलझें। अपनी स्थिति और योग्यता के हिसाब से ही काम करेंगे तो समाज में सम्मान मिलेगा। संयम रखने से रुकी योजनायें सफल होंगी। किसी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। आज आप कोई नई भाषा सीखने के बारे में विचार करेंगे।

मकर राशिः आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करेंगे। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। रोजगार के मामले में किसी से सलाह लेंगे। पार्टनरशिप में भी फायदा होने के योग बन रहे हैं। अपने स्वभाव को बैलेंस रखें आपके सभी काम बनेंगे। पुत्र पक्ष से सुख मिलेगा।

कुंभ राशिः आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान देंगे। जहां तक हो सके, सकारात्मक और कॉन्फिडेंट रहें। आपके जरूरी कामकाज आज निपट सकते हैं।रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज आस-पास के लोगों से कुछ नई बात सीखेंगे। आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाये रखने की जरूरत है।

मीन राशिः आज आपका दिन.. जोश से भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में लोगों से पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बच्चे माता-पिता के साथ मंदिर जायेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपकी अधूरी इच्छा पूरी हो सकती हैं। जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े है, उनके बिजनेस में आज तेजी आएगी।

हम तो डूबेंगे सनम तुम को भी ले डूबेंगे राहुल व पित्रोदा के बयानों से इंडी गठबंधन हैरान!

मनोज कुमार अग्रवाल

कहते हैं कि इंसान में आयु और अनुभव से समझ विकसित हो जाती है लेकिन कांग्रेस के नेता व कथित नेहरू गांधी परिवार के चश्मे चिराग राहुल गांधी पर यह बात लागू नही होती है हालांकि इस बार उन्होंने होमवर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन इसके बावजूद उनके जुबान से निकल रहे बयान कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर ही भारी पड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एक सलाहकार और मास्टर माइंड सैम पित्रोदा ने ऐसे समय में माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाने की बात कहकर सारे खेल को ही बिगाड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस को हाथों हाथ लिया है और कहा है कि कांग्रेस का मंत्र लूट है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। शहजादे और उनके सलाहकार देश के मध्यमवर्ग पर और अधिक टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं माता-पिता से मिलने वाली सम्पत्ति पर भी विरासत (इनहैरिटैंस) टैक्स लेने की कांग्रेस की योजना है कांग्रेस का पंजा आपके बच्चो का अधिकार छीनने के लिए व्याकुल है। चुनावी माहौल देखकर ऐसा लगता है मानो विपक्षी दलों का कुनबा इंडी गठबंधन सत्ताधारी दल से मुकाबला करने में जूझ रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए वे किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने तो गरीब महिलाओं के वोट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा भी कर डाली है। आरक्षण की सीमा तोड़कर 50 प्रतिशत से आगे ले जाने, देश को पुनः जात-पात की आग में जलाने के लिए जाति आधारित जनगणना जैसे वादे भी कांग्रेस कर रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने मानो हर बात को इस तरह पेश करने में महारत हासिल कर ली है कि कांग्रेस जो भी कह या कर रही है, वह देश के लिए अत्यंत खतरनाक है। वामपंथी सोच वाले सलाहकारों से घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अति- उत्साह में कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं, जिनसे भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल जाता है। एकाध बार हो जाए तो वह चूक या गलती मानी जा सकती है, किन्तु राहुल से बार-बार ऐसी गलतियां होती हैं, जिनका लाभ भाजपा उठाती है। अब चुनावी सभा में राहुल ने कह दिया कि सत्ता में आने पर अमीरों का धन लेकर गरीबों में बांट देंगे। 7 अप्रैल को हैदराबाद में राहुल ने कहा, 'हम पहले यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उसके बाद, धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे।' अब भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की नजर आम आदमी की कमाई पर है, वह उसे छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'ताला नगरी' अलीगढ़ में चुनावी जनसभा में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन (इंडिया) पर बेहद गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा, "मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे (पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी) का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, उसकी करेंगे। इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि यह जो संपत्ति है उसको अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। यह उनका चुनाव घोषणा हा है। वह सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा कर्मचारी हैं श्री सम्पत्ति है। यह सर्वे कराकर कांग्रेस सरकार के नाम पर को छीन कर बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक गर आपके पास दो घर हैं तो एक घर छीन लेगी। यह है, यह कम्युनिस्टों की सोच है, ऐसा ही करके कितने ही बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति कांग्रेस पार्टी और इंडी में लागू करना चाहते हैं।" भाजपा ने यह भी कहना शुरू कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अब कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनको बांटने की तैयारी कर रही। कल्पना कीजिए कि यदि महिला वर्ग में यह धारणा घर कर गई कि कांग्रेस की नजर वास्तव में उनके गहनों पर है तो क्या कोई महिला कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देगी? केवल महिलाएं ही क्यों, यदि उच्च मध्यम वर्ग एवं अभिजात्य वर्ग में भी यह विचार आ गया तो वे भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यह तो असल में अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया।बची कसर उनके तकनीकी गुरु सैम पित्रोदा ने करदी है जो इन दिनों अमेरिका में हैं उनके बयान भी पैतृक सम्पत्ति पर कर लगाने की बात कर रहे हैं। पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की फजीहत और बढ़ा दी है एक और कांग्रेस अपने नेता के बयान पर सफाई देने में जचटी थी इस बीच पित्रोदा भी फूट पड़े और सारा रायता दोबारा बिखर गया है। राहुल को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करने की जरूरत है। उन्होंने धन के बंटवारे का जो शिगूफा छोड़ा है, वह न व्यावहारिक है और न ही उचित। यदि परिश्रम कर कमाने वालों का धन छीनकर निठल्लों को देने लगे तो देश में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना मात्र डराने वाली है। ऐसी अराजकता पैदा करने वाली योजनाओं के बारे में सार्वजनिक दावे कोई भी राजनीतिक तौर पर परिपक्व नेता तो नहीं करेगा। अब भाजपा इसे मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस सफाई देती रह जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के मंजे खिलाड़ी हैं उनका मुकाबला कर पाना राहुल जैसे नौसिखिए और समय की नजाकत से बेख़बर उनके कांवेंट शिक्षित सलाहकारों के वश की बात नही है। ऐसे कमजोर रणनीतिक माहौल में उन क्षेत्रीय दलों का भी नुकसान हो सकता है जो अपने बूते पर मतदाता के बीच वजूद रखते हैं लेकिन अपने गठबंधन के नेता के ऐसे बयान उनके वोटर्स को भी भ्रमित कर सकते हैं ऐसे गठबंधन को कौन वोट देगा जिसके नेता माता पिता की सौंपी विरासत पर टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस की सोच सही समय पर सामने आ गई है अब इंडी और कांग्रेस दोनों की लुटिया डूबनी तय है।

दिल्ली में कचरे के पहाड़, सरकार गंभीर नहीं

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने कचरे के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया है। देश की राजधानी और व्यवस्था के स्तर पर अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होने के दावे के बावजूद अगर दिल्ली में कई जगह कचरे के पहाड़ खड़े दिखते हैं, तो यह अपने आप में एक अफसोसनाक तस्वीर है। विडंबना है कि लंबे समय से इस समस्या के उत्तरोत्तर गंभीर होते जाने और कई बार बड़ा मुद्दा बनने के बाद भी अब तक इसका हल निकालने की कोई गंभीर पहल नहीं दिखती। यह बेवजह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर हैरानी जताई है कि दिल्ली में हर रोज ग्यारह हजार टन ठोस शहरी अपशिष्ट पैदा होता है, जिसमें से तीन हजार टन कचरे का उचित निपटान नहीं किया जाता। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि यह स्तब्ध करने वाली बात है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को लागू हुए आठ साल गुजर चुके हैं, मगर अब तक दिल्ली में इस पर ठीक से अमल नहीं हुआ है। दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार के बीच जिस तरह की खींचतान चलती रहती है, उसमें इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा! सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया है। क्या इन इकाइयों को अपने दायित्व का अहसास नहीं है? यह समझना मुश्किल नहीं है कि दिल्ली में अगर रोजाना ग्यारह हजार टन अपशिष्ट निकलता है और उसमें से तीन हजार टन कचरे का उचित निपटान नहीं हो पाता, तो आखिर उसका क्या होता है और आसपास के इलाकों की आबोहवा पर उसका क्या असर पड़ता होगा। गौरतलब है कि दिल्ली में भलस्वा, गाजीपुर और ओखला स्थित कचरा पट्टियों पर जितने बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जमा होता गया है, उससे आसपास के इलाकों में कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। सोमवार को गाजीपुर कचरा पट्टी में आग लग गई थी, जिसे बुझाने में अठारह घंटे लग गए। कचरे के निपटान की जिम्मेदारी सरकार के संबंधित नागरिक निकाय की है। मगर सवाल है कि उसकी निगरानी करने और पूरे कचरे के निपटान या प्रबंधन को सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है?

शतरंज की बिसात पर उभरा नन्हा सितारा

(मनोज चतुर्वेदी)

भारतीय शतरंज आजकल ऊंची उड़ान पर है। यह साबित हुआ केंडीडेट्स चेस टूर्नामेंट में। इसमें तीन भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया और जीते 17 साल के डी गुकेश। विश्वनाथन आनंद के बाद इस टूर्नामेंट को जीतने वाले गुकेश दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने सबसे कम उम्र में यह गौरव हासिल किया है। उनसे पहले यह रेकॉर्ड गैरी कासप्रोव के नाम था। उन्होंने 1984 में 22 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। गुकेश ने अब भारत में आनंद के बाद दूसरा विश्व चैंपियन बनने की उम्मीद बंधाई है। वह विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को चुनौती देंगे।

नंबर 1 की लड़ाई – भारतीय शतरंज में आए बदलाव को इस तरह समझा जा सकता है कि आनंद लगातार 36 बरसों तक देश के नंबर एक खिलाड़ी रहे थे। लेकिन, इस साल के पहले चार महीनों में देश के नंबर एक खिलाड़ी की दौड़ में आनंद के अलावा गुकेश, प्रज्ञाननंदा, विदित गुजराती और अर्जुन इरिगेसी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी लाइव रेटिंग में एक-दूसरे को पीछे छोड़ते दिखे हैं। अजरबैजान के ग्रैंडमास्टर टीमौर रेडजाबोव के इस साल किए ट्वीट से भारत की प्रगति को समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा था कि भारत में नंबर एक स्थान पाना कितना संघर्षपूर्ण हो गया है। गुकेश ने भी आनंद को पिछले साल अगस्त में फीडे ईएलओ रेटिंग में पीछे छोड़ा था।

ग्रैंडमास्टर का देश – भारत में पहले ग्रैंडमास्टर बनना कितना मुश्किल था इसे इस बात से समझा जा सकता है कि देश को 1988 में पहली बार आनंद के रूप में पहला ग्रैंडमास्टर मिला। इसके 12 साल बाद तक देश को पांच ही और ग्रैंडमास्टर मिल सके थे। लेकिन, मौजूदा समय में देश में 84 ग्रैंडमास्टर हैं। गुकेश के प्रदर्शन के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत ने संख्या बढ़ाने में ही तरक्की नहीं की, गुणवत्ता के मामले में भी आगे बढ़ा है।

कार्लसन को जवाब – गुकेश ने अपने खेल से पूर्व विश्व चैंपियन मैगनस कार्लसन की सोच को गलत साबित कर दिया। कार्लसन ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों से उन्हें कोई उम्मीद नहीं और गुकेश को तो भारी हार का सामना करना पड़ेगा। सातवें राउंड में गुकेश जब फिरोजा अलीरजा से हारे, तो एक बार को लगा कि कहीं कार्लसन की बात सच तो नहीं होने जा रही। लेकिन, इसके बाद गुकेश के खेल में जबरदस्त सुधार दिखा और उन्होंने चैंपियन बनकर ही दम लिया। कार्लसन ने भी गुकेश की ताकत को मान लिया।

लॉकडाउन का फायदा – गुकेश मानते हैं कि कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उनके करियर ने उड़ान पकड़ी। साल 2018 में प्रज्ञाननंदा सहित आठ ग्रैंडमास्टर बने थे। गुकेश इसके एक साल बाद ग्रैंडमास्टर बने। लॉकडाउन के समय उनकी ईएलओ रेटिंग 2550 के करीब थी। लेकिन, उन्होंने लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया और अपने समकालीन ग्रैंडमास्टर्स को पीछे छोड़ने में सफल हो गए। असल में गुकेश का चेस इंजन (कंप्यूटर प्रोग्राम) पर शुरुआती करियर में ध्यान नहीं देना ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करता है। आजकल युवा खिलाड़ी चेस इंजन का सहारा लेते हैं। गुकेश के कोच विष्णु प्रसन्ना कहते हैं कि चेस इंजन का उपयोग नहीं करने का मकसद त्रुटिहीन गणनाएं करने और स्थितियों को जल्द समझने की क्षमता विकसित करना था।

सबसे छोटे ग्रैंडमास्टर – गुकेश अपनी तैयारी के ढंग की वजह से ही 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में ग्रैंडमास्टर बन गए थे। भारत में तो यह रेकॉर्ड है, लेकिन दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर कारजेकिन की उपलब्धि को गुकेश पीछे नहीं छोड़ पाए। अगर वह अंडर-12 विश्व चैंपियन बनने के दौरान आधा अंक और पा जाते तो कारजेकिन का भी रेकॉर्ड तोड़ देते।

पिता की मेहनत – गुकेश अगर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो इसमें उनके पिता डॉक्टर रजनीकांत के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। पेशे से ईएनटी विशेषज्ञ रजनीकांत ने बेटे का करियर बनाने के लिए अपने करियर पर ब्रेक लगा दिया। पांच बरसों तक वह बेटे को लेकर विभिन्न टूर्नामेंटों में देश-विदेश जाते रहे। कई बार विदेश में ठहरने का पैसा बचाने के लिए दोनों हवाई अड्डे पर ही सो जाते थे। गुकेश जब ग्रैंडमास्टर नॉर्म पाने के लिए विभिन्न टूर्नामेंट में खेल रहे थे, तब छह महीने में उनके पिता ने 50 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए। जब पिता अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे थे, तब घर पर कमाने वाली इकलौती शख्स थीं गुकेश की मां पद्मा, जो बायोलॉजिस्ट हैं।

टॉप पर भारतीय – भारत ने शतरंज में पिछले एक-डेढ़ दशक में जबरदस्त तरक्की की है। दुनिया के टॉप 25 खिलाड़ियों में पांच भारतीय शामिल हैं। वहीं, महिला वर्ग में टॉप 15 में तीन महिला खिलाड़ी हैं। यह भारत की प्रगति को दर्शाता है। गुकेश यदि डिंग लिरेन को हराकर विश्व चैंपियन बन जाते हैं, तो इसका देश में शतरंज को जरूर लाभ मिलेगा।

देश को संदेश देने में नाकाम रही विपक्ष की रांची रैली

विपक्षी दलों की झारखंड की राजधानी रांची में हुई महारैली देश को कोई स्पष्ट संदेश नहीं दे सकी। हांलाकि इससे बड़ी उम्मीद थी। उम्मीद थीं कि राजनैतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र अब तक प्रस्तुत कर चुके हैं। इस रैली में वे कॉमन मिनीमम कार्यक्रम जारी कर सकतें हैं किंतु ऐसा कुछ नही हुआ। हर बार की तरह सिर्फ भाषण तक ही सीमित रही रैली। झारखंड की राजधानी रांची में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने 'उलगुलान न्याय महारैली' का नाम दिया गया है। इस दौरान मंच में बड़े-बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही मंच पर दो खाली कुर्सियां रखी गईं। एक जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए और दूसरी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। उनकी जगह केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंच साझा किया। भारी संख्या में लोग रैली में पहुंचे।

(अशोक मधुप)

सात चरणों में पूरे होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। मतदाताओं ने प्रत्याशियों निर्णय इवीएम को सौंप दिया। दूसर चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इतना सब होने पर भी विपक्षी 28 दलों का गठबंधन अब तक न कोई अपना कॉमन प्रोग्राम प्रस्तुत कर सका।

विपक्षी दलों की झारखंड की राजधानी रांची में हुई महारैली देश को कोई स्पष्ट संदेश नहीं दे सकी। हांलाकि इससे बड़ी उम्मीद थी। उम्मीद थीं कि राजनैतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र अब तक प्रस्तुत कर चुके हैं। इस रैली में वे कॉमन मिनीमम कार्यक्रम जारी कर सकतें हैं किंतु ऐसा कुछ नही हुआ। हर बार की तरह सिर्फ भाषण तक ही सीमित रही रैली।

झारखंड की राजधानी रांची में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने 'उलगुलान न्याय महारैली' का नाम दिया गया है। इस दौरान मंच में बड़े-बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही मंच पर दो खाली कुर्सियां रखी गईं। एक जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए और दूसरी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। उनकी जगह केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंच साझा किया। भारी संख्या में लोग रैली में पहुंचे

रैली के दौरान भीड़ ने 'जेल का ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे' और 'झारखंड झुकेगा नहीं' जैसे नारे लगाए। झारखंड की राजधानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने के बावजूद भारी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। चिलचिलाती गर्मी के बीच सभी रैली के समर्थन जुटे रहे। 'उलगुलान' शब्द, जिसका अर्थ क्रांति है। इसे आदिवासियों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा की लड़ाई के दौरान गढ़ा गया था।

हेमंत सोरेन को कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। इसी केंद्रीय एजेंसी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और आप सुप्रीमो के लिए कुर्सियां खाली रखी गई थीं, लेकिन उनकी पत्नियां कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल मंच पर बैठी थीं। कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल का भाषण मुख्यतः अपने पतियों की गिरफ्तारी के विरोध में था। दोनों का दावा था कि उनके पतियों को केंद्र की मोदी सरकार ने गलत ढंग से गिरफ्तार कराया हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबा देना चाहती है। इसके लिए सबको एकजुट होना होगा। रैली में नेताओं का यह भी आरोप था कि केंद्र में भाजपा फिर लौटी तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। रैली में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार झूठ बोलने, गारंटी के नाम पर लोगों को ठगने, लोकतंत्र को कमज़ोर करने और जुमलों के

सहारे राजनीति करने के आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि देश में बेरोज़गारी चरम पर है और प्रधानमंत्री मोदी का हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा हवा में घूम रहा है।

देश में पहले चरण के मतदान के ठीक अगले दिन आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि वे 400 पार की बात करते हैं लेकिन 180-190 सीटों से आगे नहीं जाने वाले। इसलिए, वोट देना ज़रूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, पहले चरण में ही उत्तर प्रदेश में इनकी हालत ख़राब हो गई है और जब यूपी इन्हें हटा सकता है, तो आप क्यों नहीं। यह देश मोदी की नहीं, संविधान की गारंटी चाहता है। जबकि झारखंड में मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस रैली को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया है।

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा, इनके मंच पर भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं का जमावड़ा हुआ और ये भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं. यह हास्यास्पद है। प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा, इनका दावा था कि रैली में पांच लाख लोग शामिल होंगे लेकिन आए बमुश्किल 10-15 हज़ार लोग। उनमें आपस में मारपीट हुई। ये लोग सिर्फ़ सत्ता में आने के लिए एक मंच पर आए थे। रैली में सिर्फ़ परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों की भागीदारी थी, इसलिए इसे सुपर फ़्लॉप कहा जाना चाहिए। हालांकि उलगुलान न्याय महारैली में लोगों की खासी भागीदारी देखी गई। झारखंड के सुदूर इलाक़ों से लोग बसों, गाड़ियों और ट्रेनों से रांची पहुंचे। ऐसे लोगों को लाने के विशेष इंतज़ाम किए गए थे। रैली स्थल पर लोगों की भीड़ देर शाम तक जमी रही।

उलगुलान रैली में शामिल होने आई कार्यकर्ताओं की भीड़ में दो गुटों के बीच झड़प हो गयी। कुर्सियां भी तोड़ी गई। ये मारपीट, ये हुडदंग कोई अच्छा संदेश नही दे सकें। उलगुलान रैली में शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। रैली में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। इस वजह से वे रैली में शामिल नहीं हुए।

सात चरणों में पूरे होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। मतदाताओं ने प्रत्याशियों निर्णय इवीएम को सौंप दिया। दूसर चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इतना सब होने पर भी विपक्षी 28 दलों का गठबंधन अब तक न कोई अपना कॉमन प्रोग्राम प्रस्तुत कर सका। न नहीं सभी दलों द्वारा सर्व सम्मत नेता ही चुना गया।

दरअसल विपक्षी दलों का यह गठबंधन, उन दलों का भी गठबंधन कहां जा सकता है, जो दल भाजपा के साथ नहीं जा सके। अवसर नहीं मिला। इस विपक्षी दलों के आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन को खड़ा करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा। ये सब उन्ही की मेहनत से खड़ा हुआ। किंतु मौके की तलाश में बैठे नीतीश कुमार अवसर मिलते ही इस गठबंधन से किनारा करके बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। भाजपा के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने किया। भाजपा से बात पक्की होने तक वे सपा के अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के साथ थे। बात पक्की होते ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। 28 दलों वाले इस एलायंस में प्रायः वह ही दल हैं जिनकी अपने प्रदेश में सरकार है। प्रदेश में सरकार होने के कारण वह भाजपा से गठबधंन नही कर पा रही।

चुनाव का एक चरण बीत गया। दूसरा 26 को है। इसके बाद पांच चरण शेष हैं। लगता है कि ये भी जल्द ही हो जांएगे, विपक्ष के 28 दलों के एलाइंस इंडिया का मिनिमम कार्यक्रम तय हुआ। ये बैठकर कोई ऐसा एजेंडा भी नही बना पाए कि बहुमत में आने पर किस कार्यक्रम पर वे सरकार चलांएगे। दूसरा उनका संयुक्त प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या कुछ प्रदेशों की तरह तीन या छह-छह माह में अब प्रधानमंत्री भी बदले जांएगे। जो भी हो विपक्षी गठबंधन इंडिया का जैसे अच्छा नाम मिली था, वैसा कुछ आगे नही हुआ। उसने निराश ही किया। देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 दलों के गठबंधन से उम्मीद काफी ज्यादा थीं, किंतु वह एक पर भी खरा नही उतर सका। ये सारे दल अलग?अलग विचार और सिद्धांतों के मानने वाले हैं। ऐसे में एकजुट होने के लिए इनका कॉमन एजेंडा भी होना चाहिए। ऐसा न होने पर इनकी एकजुटता छलावा है। धोखा है। अब तो इनका का उददेश्य केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करना रह गया। आलोचनाएं भी सकारात्मक नही। नकारात्मक। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत में धार्मिक पर्यटन छू रहा नित नई ऊंचाइयां

(प्रह्लाद सबनानी)

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भी धरातल पर बहुत कार्य सम्पन्न किया है। साथ ही, अब इसके अंतर्गत एक रामायण सर्किट रूट को भी विकसित किया जा रहा है। इस रूट पर विशेष रेलगाड़ियां भी चलाए जाने की योजना बनाई गई है।

हाल ही के समय में भारत के नागरिकों में 'स्व' का भाव विकसित होने के चलते देश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ा है। अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में श्रीराम लला के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रत्येक दिन औसतन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह तो केवल अयोध्या की कहानी है इसके साथ ही तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। भारत में धार्मिक पर्यटन में आई जबरदस्त तेजी के बदौलत रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं।

जेफरीज नामक एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज कम्पनी ने बताया है कि अयोध्या में निर्मित प्रभु श्रीराम के मंदिर से भारत की आर्थिक सम्पन्नता बढ़ने जा रही है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सम्पन्न हुए प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद स्थानीय कारोबारी अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बनाने जा रहा है तथा अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जेफरीज के अनुसार अयोध्या में प्रति वर्ष 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ सकते हैं। अभी अयोध्या में केवल 17 बड़े होटल हैं इनमें कुल मिलाकर 590 कमरे उपलब्ध हैं। लेकिन, अब 73 नए होटलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 40 होटलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है। अभी तक नए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टाउनशिप और रोड कनेक्टिविटी में सुधार जैसे कामों पर 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस निवेश का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर दिखाई देने जा रहा है। शीघ्र ही अयोध्या वैश्विक स्तर पर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। इससे होटल, एयरलाईन, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, सिमेंट जैसे क्षेत्रों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। भारत के विभिन्न शहरों से 1000 के आसपास नई रेल अयोध्या के लिए चलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश से दिनांक 23 जनवरी 2024 के बाद से प्रतिदिन भारी संख्या में धार्मिक पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि पहिले दिन ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीराम के दर्शन किये हैं।

विश्व के कई अन्य देश भी धार्मिक पर्यटन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाएं सफलतापूर्वक मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब धार्मिक पर्यटन से प्रति वर्ष 22,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्जित करता है। सऊदी अरब इस आय को आगे आने वाले समय में 35,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक ले जाना चाहता है। मक्का में प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं, जबकि मक्का में गैर मुस्लिम के पहुंचने पर पाबंदी है। इसी प्रकार, वेटिकन सिटी में प्रतिवर्ष 90 लाख लोग पहुंचते हैं। इस धार्मिक पर्यटन से अकेले वेटेकन सिटी को प्रतिवर्ष लगभग 32 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आय होती है, और अकेले मक्का शहर को 12,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आमदनी होती है। अयोध्या में तो किसी भी धर्म, मत, पंथ मानने वाले नागरिकों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। अतः अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 से 10 करोड़ तक प्रतिवर्ष जा सकती है। फिर अकेले अयोध्या नगर को होने वाली आय का अनुमान तो सहज रूप से लगाया जा सकता है। अभी अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अयोध्या में रूकते नहीं थे प्रातः अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर शाम तक वापिस चले जाते थे परंतु अब अयोध्या को इतना आकर्षक रूप से विकसित किया गया है कि श्रद्धालु 3 से 4 दिन रुकने का प्रयास करेंगे। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक पर्यटक लगभग 6 लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। इस संख्या के हिसाब से तो लाखों नए रोजगार के अवसर अयोध्या में उत्पन्न होने जा रहे हैं। अयोध्या के आसपास विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब अयोध्या के रूप में वेटिकन एवं मक्का का जवाब भारत में खड़ा होने जा रहा है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भी धरातल पर बहुत कार्य सम्पन्न किया है। साथ ही, अब इसके अंतर्गत एक रामायण सर्किट रूट को भी विकसित किया जा रहा है। इस रूट पर विशेष रेलगाड़ियां भी चलाए जाने की योजना बनाई गई है। यह विशेष रेलगाड़ी 18 दिनों में 8000 किलो मीटर की यात्रा सम्पन्न करेगी, इस विशेष रेलगाड़ी के इस रेलमार्ग पर 18 स्टॉप होंगे। यह विशेष रेलमार्ग प्रभु श्रीराम से जुड़े ऐतिहासिक नगरों अयोध्या, चित्रकूट एवं छत्तीसगढ़ को जोड़ेगा। अयोध्या में नवनिर्मित प्रभु श्रीराम मंदिर वैश्विक पटल पर इस रूट को भी रखेगा।

केंद्र सरकार द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम भी अब दिखाई देने लगा है। 'मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट' के अनुसार, भारत के नागरिक अब पहले के मुकाबले अधिक यात्रा कर रहे हैं। भारत के नागरिकों द्वारा विशेष रूप से अयोध्या, उज्जैन एवं बदरीनाथ जैसे आध्यात्मिक स्थलों के बारे में अधिक जानकारी हासिल की जा रही है। उक्त जानकारी 'मेक माई ट्रिप' के प्लेटफार्म के 10 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामने आई है। वर्ष 2019 के बाद से भारत में एक वर्ष में तीन से अधिक यात्राएं करने वाले लोगों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आध्यात्मिक पर्यटन सम्बंधी जानकारी हासिल करने की गतिविधियों में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में 97 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से अयोध्या के सम्बंध में जानकारी हासिल करने सम्बंधी गतिविधियों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 585 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज हुई है। इसी प्रकार, उज्जैन एवं बदरीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों के सम्बंध में भी जानकारी हासिल करने वाले नागरिकों की संख्या में क्रमशः 359 प्रतिशत और 343 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। भारत में अब पारिवारिक यात्रा की बुकिंग भी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इसमें वर्ष 2022 के तुलना में वर्ष 2023 में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि इसी अवधि में एकल यात्रा की बुकिंग में केवल 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

उक्त जानकारी को भारत के नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा जारी एक जानकारी से भी बल मिलता है कि भारत में घरेलू हवाई यातायात अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। दिनांक 21 अप्रेल 2024 (रविवार) को रिकार्ड 471,751 यात्रियों ने 6,128 उड़ानों के माध्यम से, भारत में हवाई सफर किया है। इसके पूर्व हवाई यातायात करने वाले नागरिकों की औसत संख्या, कोरोना महामारी के पूर्व के खंडकाल में, 398,579 यात्रियों की थी। इसमें 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

देश में धार्मिक पर्यटन में हो रही भारी वृद्धि के चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में भी तेजी दिखाई देने लगी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ने भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है जबकि प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की रही थी। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही थी। जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। इसी प्रकार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा ने 6.5 प्रतिशत, एशिया विकास बैंक एवं बार्कलेस एवं प्राइस वॉटर कूपर्स ने 6.7 प्रतिशत, डेलाईट इंडिया ने 7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। परंतु, समस्त विदेशी संस्थानों के अनुमानों के झुठलाते हुए भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 8 प्रतिशत की रही है। यह सब देश में लगातार बढ़ते धार्मिक पर्यटन एवं विभिन त्यौहारों तथा शादी जैसे समारोहों पर भारतीय नागरिकों द्वारा दिल खोलकर पैसा खर्च करने के चलते सम्भव हो पा रहा है। इससे त्यौहारों एवं शादी के मौसम में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। जैसे दीपावली त्यौहार के समय भारत में नागरिकों के बीच विभिन्न नए उत्पादों की खरीद के लिए जैसे आपस में होड़ सी लग जाती है। भारत में लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दीपावली त्यौहार के समय में होता है। इसी प्रकार की स्थिति शादियों के मौसम में भी पाई जाती है। संभवतः विदेशी वित्तीय संस्थान भारत में हो रहे इस तरह के उक्त वर्णित परिवर्तनों को समझ नहीं पा रहे हैं एवं केवल पारंपरिक विधि से ही सकल घरेलू उत्पाद को आंकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारत की विकास दर के संबंच में विभिन्न विदेशी संस्थानों के अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। (लेखक सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)

विरासत कर
विमर्श जारी

विरासत कर पर भारत में भले ही विमर्श जारी हो, पर इसे लागू करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस द्वारा अनौपचारिक रूप से 'विरासत कर' के प्रस्ताव ने पूरे भारत में जिज्ञासा पैदा कर लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि, पार्टी ने कांग्रेस के विदेश अध्यक्ष सैम पित्रोदा की टिप्पणियों से स्वयं को अलग कर लिया है, पर उनके बयान ने भाजपा को कांग्रेस पर हमले का एक और मौका दे दिया है। जहां तक अमेरिका जैसी इस टैक्स व्यवस्था को लागू करने का सवाल है, इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न आयामों का समग्र परीक्षण होना चाहिए जिसमें आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक आयाम शामिल हैं। अमेरिका में लंबे समय से विरासत पर कर लगाने की अवधारणा रही है, हालांकि इसकी अपनी जटिलतायें और विवाद हैं। ऐसे टैक्स को उचित ठहराने के अनेक तर्क हैं। पहला, संग्रहीत धन को लगातार पीढ़ियों तक बिना सार्वजनिक कल्याण के हस्तांतरित करने पर लगाम लगा कर यह संपत्ति-असमानता को संबोधित करता है। दूसरा, यह सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत है जिससे सार्वजनिक सेवाओं और पहलों की फंडिंग में आसानी होती है। लेकिन भारत में विरासत कर के क्रियान्वयन की अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं। एक प्रमुख चिन्ता संभवत: टैक्स बचाने के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं तथा 'बेनामी संपदा' का वर्चस्व है। इसके साथ ही भारत के सांस्कृतिक व सामाजिक ढांचे में 'पारिवारिक संबंधों' तथा 'विरासत व्यवहारों' पर काफी जोर दिया जाता है। इसके साथ ही भारतीय कर व्यवस्था में अनेक प्रकार की लेवी हैं जिनमें आय कर, पूंजीगत लाभ कर तथा 2015 में समाप्त किया गया संपत्ति कर शामिल हैं। इसमें एक 'विरासत कर' और जोड़ने से जटिलता पैदा हो सकती है। ऐसा टैक्स लगाने की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि यहां संपत्तियों के अनेक प्रकार तथा अनेक विरासती ढांचे हैं।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत में लोकसभा चुनाव के समय 'विरासत कर' पर विमर्श कांग्रेस ने क्यों शुरू किया है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसके पूर्व रूप 'स्टेट ड्यूटी' को अपने पहले कैबिनेट फैसले से समाप्त कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया है कि उनके इस निर्णय से गांधी-नेहरू परिवार ने अपनी करोड़ों की संपत्ति पर टैक्स बचा लिया था, पर अब वह उसे आम मध्यवर्गीय लोगों पर थोपना चाहती है। कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है क्योंकि वे राजीव गांधी के प्रमुख सलाहकार रहे हैं तथा राहुल गांधी के 'मेंटर' हैं। कांग्रेस को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अपनी 'खैरात बांटने' वाली योजनायें पूरी करने के लिए मध्य वर्ग पर फिर से टैक्स का भारी बोझ लादना चाहती है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान में भले ही थोड़ी अतिरंजना हो, पर इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि अपने 138 साल के जीवन में 'मध्यमार्गी' तथा 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' की पैरोकार रही कांग्रेस आज 'अति-वामपंथी' व 'जातिवादी' शक्तियों के चंगुल में फंस गई है। कांग्रेस ने 'विरासत कर' का सवाल उठा कर यह आशंका पैदा कर दी है कि कहीं वह 'लाइसेंस-परमिट राज' फिर बहाल तो नहीं करना चाहती है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बड़े साहस के साथ इस सड़ी-गली विरासत से मुक्ति पाई थी। देश की युवा पीढ़ी, खासकर विदेशों में पढ़ने और रोजगार करने वाले युवा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते सम्मान व आर्थिक शक्ति से अभिभूत हैं और उनको सरकार की आर्थिक नीतियों में पूर्ण विश्वास है। ऐसे में कांग्रेस निरर्थक मुद्दे उठा कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती है।

पंजाब से उद्योगों का पलायन

पंजाब सरकार में न केवल लंबे समय से कोई उद्योग नीति नहीं है, बल्कि वहां उद्योगों के लिए आवश्यक ढांचागत संरचना में लगातार गिरावट आई है।

अश्विनी महाजन
(लेखक, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

स्वतंत्रता के बाद वर्ष 2011-12 तक पंजाब को भारत का एक अमीर व फलता-फूलता राज्य माना जाता था। वर्ष 2000-01 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय न केवल देश में सबसे अधिक थी, बल्कि यह भारत के दूसरे सबसे अमीर प्रदेश हरियाणा से 9 प्रतिशत अधिक थी। लेकिन वर्ष 2012-13 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय गिर कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई और आज पंजाब प्रति व्यक्ति आय के विचार से एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में 19वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही वह अब देश के राज्यों में सबसे धीमी प्रगति करने वाला दूसरा राज्य है।

वर्ष 2011-12 में जब पंजाब प्रति व्यक्ति आय के विचार से देश में सर्वोच्च स्थान पर था, तब इसमें कृषि का हिस्सा 24 प्रतिशत, उद्योगों का 28.4 प्रतिशत तथा सेवाओं का 47.6 प्रतिशत था। लेकिन 2022-23 तक कृषि का हिस्सा बढ़ कर 28.94 प्रतिशत हो गया, जबकि उद्योगों और सेवाओं का हिस्सा गिर कर क्रमश: 25.51 प्रतिशत तथा 45.91 प्रतिशत हो गया। अनुमान लगाया जा सकता है कि पंजाब में उद्योग व सेवा क्षेत्र घटा। इसके उलट पड़ोसी राज्य हरियाणा की जीडीपी में उद्योगों का हिस्सा बढ़ कर 2011-12 और 2021-22 के बीच 25.90 प्रतिशत से बढ़ कर 28 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार गुजरात में उद्योगों का हिस्सा इसी कालखंड में 36 प्रतिशत से बढ़ कर 43 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 27.9 प्रतिशत से बढ़ कर 33 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार इस कालखंड में पंजाब में वि-औद्योगीकरण हो रहा था। हालांकि, पंजाब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी जनसंख्या के विस्थापन के कारण स्वतंत्रता के बाद से ही लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में पंजाबी अमेरिका, कनाडा, यूरोप व अनेक अन्य देशों में गए हैं। पंजाब को इन प्रवासी पंजाबियों से काफी लाभ भी प्राप्त हुआ है। प्रवासी पंजाबियों द्वारा विदेशों से भेजी धनराशि ने पंजाब में कृषि एवं उद्योगों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके कारण पंजाब में लंबे समय तक औद्योगिक विकास की लहर दिखाई पड़ी।

लेकिन पिछले काफी समय से पंजाब में औद्योगिक विकास न केवल ठहर गया, बल्कि बड़ी संख्या में उद्योगों ने पंजाब से बाहर पलायन शुरू कर दिया। पंजाब के उद्योग अब पड़ोसी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आदि में जाने लगे हैं। इसके साथ ही वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व गुजरात, आदि सुदूर प्रदेशों में भी जा रहे हैं। पंजाब को खासकर इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए जाना जाता था, पर अनेक इंजीनियरिंग उद्योग अब अपने उत्पादों के उपयोगकर्ता राज्यों में चले गए हैं। दूसरी ओर, खेल उत्पादों का बड़ा केन्द्र माने जाने वाले जालंधर के अनेक खेल उद्योग अब उत्तर प्रदेश के मेरठ चले गए हैं। यह भी देखने में आया है कि टेक्सटाइल व गारमेंट उद्योग अब मध्य प्रदेश, साइकिल उद्योग चेन्ने और चीन तथा निटवियर उद्योग अफ्रीका, दक्षिणपूर्व एशिया और मध्य प्रदेश चले गए हैं।

पंजाब सरकार की नीतियां उद्योग-विरोधी हैं। पंजाब में आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन उल्लेखनीय है कि पंजाब की जीडीपी का केवल 28.94 प्रतिशत ही कृषि से आता है, जबकि राज्य की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। भारतीय लोकतंत्र का एक दु:खद हिस्सा उसकी 'लोकरंजक नीतियां' हैं। पंजाब में इन लोकरंजक नीतियों ने पंजाब के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। पांच नदियों का क्षेत्र पंजाब जल के मामले में बहुत समृद्ध रहा है। लेकिन पंजाब में आसानी से भूमिगत जल दोहन के कारण बड़ी संख्या में ट्यूबवेल लगाए गए। किसानों को खुश करने के लिए पंजाब सरकार ने कृषि के लिए 'मुफ्त बिजली योजना' शुरू की। इसके परिणामस्वरूप जल का अत्यधिक दोहन शुरू हुआ। इस कारण अब पंजाब के अनेक जिले 'डार्क जोन' में बदल गए हैं। इसका अर्थ है कि वहां भूमिगत जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी आई है। पंजाब सरकार द्वारा कृषि को मुफ्त बिजली देने की नीति ने न केवल भूमिगत जल की उपलब्धता को प्रभावित किया है, बल्कि इसका प्रभाव उद्योगों पर भी पड़ा है। पंजाब सरकार ने कृषि को दी जाने वाली मुफ्त बिजली का अधिकांश बोझ अब उद्योगों और बिजनेसों पर डाल दिया है। इसके कारण उद्योगों के लिए बिजली बहुत महंगी हो गई है। इससे अन्य प्रदेशों की तुलना में पंजाब के उद्योगों को घाटा उठाना पड़ता है। इससे उद्योगों की जीवन्तता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनके पास पंजाब छोड़ कर दूसरे प्रदेशों और यहां तक कि विदेशों में जाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचा है। पंजाब के पर्यावरण कानून इतने कठोर हैं कि उनका पालन लगभग असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में उद्योगों के पास अपनी इकाइयां बंद करने या दूसरे राज्यों में जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। केवल इतना ही नहीं, पंजाब में उद्योगों और बिजनेसों को पानी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है जिसके कारण उद्योगों को घाटा होता है।

गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आदि राज्यों में तेजी से औद्योगीकरण और आर्थिक विकास का कारण ढांचागत विकास तथा अन्य सुविधायें हैं जिससे लाजिस्टिक खर्च घटता है। सभी जानते हैं कि पंजाबी अच्छे उद्यमी होते हैं और इसी कारण औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास में पंजाब ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। लेकिन आज पंजाब उन राज्यों से प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पा रहा है जहां लाजिस्टिक पर खर्च कम है तथा ढांचागत विकास में काफी प्रगति हुई है। उल्लेखनीय है कि हालिया वर्षों में पंजाब में ढांचागत संरचना की स्थिति बहुत खराब हुई है।

केवल इतना ही नहीं, जीएसटी व्यवस्था के क्रियान्वयन ने पंजाब के उद्योगों पर प्रभाव डाला है। पहले पंजाब सरकार परोक्ष करों की दरें कम रखती थी, लेकिन जीएसटी व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद राज्य-विशिष्ट राजकोषीय प्रोत्साहनों का दायरा बहुत कम हुआ है। इसके कारण पंजाब में उद्योगों की प्रतियोगी शक्ति अब अन्य राज्यों की तुलना में बहुत घट गई है। यदि कोई पंजाब में नया उद्योग लगाना चाहे तो उसे न केवल पर्यावरणीय, बल्कि अनेक अन्य प्रकार की अनुमतियों की आवश्यकता होती है जो बहुत कठिन काम है। इसके साथ ही उद्योगों के लिए भूमि का आबंटन बहुत कठिन है तथा इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके अलावा पंजाब का वित्तीय क्षेत्र भी गंभीर समस्याओं का शिकार है। पंजाब का अधिकांश कृषि कर्ज डूब गया है और इसके कारण पंजाब में एनपीए बहुत अधिक है। केवल इतना ही नहीं, पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति में तेजी से गिरावट आ रही है। इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव पंजाब में उद्योगों पर पड़ रहा है।

पंजाब की समुद्र से बहत अधिक दूरी तथा लाजिस्टिक का भारी खर्च निर्यात की लागत बढ़ाता है। इसके कारण पंजाब के उद्योगों को बहुत लंबे रास्ते से अपना सामान भेजना पड़ता है। पहले वस्तुओं को पाकिस्तान से हो कर भेजा जा सकता था, पर अब यह रास्ता बंद होने के कारण वस्तुओं को समुद्रपार भेजने के लए मुंबई बंदरगाह का रास्ता अपनाना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए अमृतसर में 'एयर कार्गो' सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन इसके लिए सहायक प्रयासों की भारी कमी है। एयर कार्गो का उद्योगों के साथ बैक-लिंकेज न होने के कारण वर्तमान समय में एयर कार्गो सुविधा के केवल 20 प्रतिशत का ही उपयोग हो पा रहा है। जहां अन्य राज्य सरकारों ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए हैं, वहीं पंजाब सरकार के पास न केवल लंबे समय से कोई उद्योग नीति नहीं है, बल्कि उद्योगों के लिए आवश्यक ढांचागत संरचना में लगातार गिरावट आ रही है।

इसके साथ ही पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं विकास गतिविधियों की भारी कमी है। औद्योगिक विकास की कमी के कारण पंजाब लगातार आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। लेकिन अब सबसे अधिक चिन्ता की बात यह है कि पंजाब प्रशासन के पास इस विषय पर कोई विचार या नीतिगत पहल नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि राज्य से उद्योगों के पलायन तथा उद्योग नीति की अनदेखी की यह प्रवृत्ति न रोकी गई तो पंजाब आर्थिक विकास में बहुत पीछे हो जाएगा। यह स्थिति पंजाब और पूरे देश के लिए अच्छी नहीं होगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिहार में शैक्षणिक सुधार

कीयूर पाठक
(लेखक, प्रयागराज विवि में सह प्रोफसर हैं)

पिछले कुछ दशकों में अनगिनत मोर्चों पर बिहार सरकार की विफलता को खारिज नहीं किया जा सकता है, और विफलता का एक विशिष्ट उदाहरण शराब के खिलाफ बिना किसी उचित तैयारी और अध्ययन के बनाए गए कानून में देखा जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे कई मुद्दे हैं जहां सरकार ने अपनी पर्याप्त कमजोरी का प्रदर्शन किया है जैसे कि ग्रामीण प्रवास, कृषि वगैरह। हालाँकि, सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जिनकी बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के सराहना की जानी चाहिए, यह राज्य में शिक्षा के विषय पर पहल है। आज जब लगभग पूरे भारत में बाजार शिक्षा पर पूरी तरह कब्ज़ा करने पर तुला हुआ है(

ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा को संरक्षण देने का राज्य का प्रयास एक बहुत ही साहसिक कदम माना जा सकता है। एक तरह से, यह राज्य द्वारा वैश्विक पूंजी का जवाब है। जब शैक्षणिक संस्थान सरकार के हाथ से निकलकर कॉरपोरेट के हाथों में जा रहे हैं, तब बिहार सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था पर किया जा रहा काम एक तरह से कल्याणकारी राज्य की वापसी जैसा है. स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ऐसे प्रयास होने चाहिए। हालांकि, हाल के वर्षों में इसकी बड़ी शुरुआत दिल्ली में देखी जा सकती है जहां यह दावा किया गया कि सरकारी स्कूली शिक्षा को प्रतिष्ठित स्तर पर ले जाया गया है, और इस दावे से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन बिहार में शिक्षा सुधारों के माध्यम से राज्य फिर से अपनी जन-सरोकारी भूमिका में, आंशिक रूप से ही सही, कुछ ही विषयों में दिखाई दे रहा है। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहां सामाजिक और आर्थिक असमानता भी चरम पर है. तब ऐसी स्थिति में शिक्षा को खुले बाज़ार में उतारने का आर्थिक विकास का मॉडल हाशिये पर पड़े लोगों को और भी हाशिये पर धकेल देगा।

यह हमेशा से एक ज्वलंत प्रश्न रहा है कि हाशिये पर पड़े वर्गों के शिक्षा के अधिकारों के लिए कितनी जगह बचेगी, जबकि अधिकांश निजी स्कूल पैसा कमाने वाले उद्योगों की तरह काम कर रहे हैं। और यह बात समझ लेनी चाहिए कि निजी स्कूल अपनी गुणवत्ता के कारण नहीं फलते-फूलते, बल्कि सरकारी स्कूलों की नाकामी उन्हें पैर पसारने का मौका देती है। दुर्भाग्य से, दशकों से राज्य द्वारा सरकारी स्कूलों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। और यह सब अनायास नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे वैश्विक पूंजी की सुनियोजित साजिश थी कि पहले सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया जाए और फिर निजी स्कूलों को स्वत: वैधता मिल जाएगी। एक तरह से समाज ने सरकारी स्कूलों से सारी उम्मीदें ही छोड़ दी है, मान लिया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। परिणामस्वरूप, सामाजिक मनोविज्ञान का विकास हुआ जिसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता को एक गंभीर प्रश्न के रूप में नहीं लिया। यदि ऐसा किया गया होता तो सरकारों पर दबाव पड़ता और वे सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काम करतीं, लेकिन ऐसा कम ही हुआ। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों को फिर से राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बना दिया है। हमने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछ कार्यों को देखा। उदाहरण के लिए, काफी समय से स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी, जिसे पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की गई। एक लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति सरकार की शिक्षा के प्रति सोच की गंभीरता को बताने के लिए काफी है. निस्संदेह इस पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हुआ होगा. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिहार के स्कूल खंडहर में तब्दील हो गये थे. कौन सी इमारत कब गिर जाएगी, यह कहना मुश्किल था। बच्चों को अक्सर खुले मैदान या बरामदे में बैठने के लिए मजबूर किया जाता था।

लेकिन इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए सरकार ने बड़ी रकम आवंटित की. बच्चों के लिए किताबें, ड्रेस और बैग तथा पानी की बोतलों के साथ-साथ अन्य सामग्री का आवंटन न केवल उन्हें स्कूलों की ओर आकर्षित करता है, बल्कि माता-पिता के लिए वित्तीय बोझ भी कम करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो खेत में मजदूरी करके मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। शहरी संभ्रांत लोगों के लिए ये चीजें निरर्थक हो सकती हैं लेकिन ग्रामीण लोगों के लिए यह उनकी अपनी आय से वहनीय नहीं है।

हम सभी ने बच्चों को हाथ में धूल भरी पॉलिथीन में या फटे कपड़े (झोला) में किताबें ले जाते देखा था, लेकिन अब उनके हाथों में सुंदर बैग थे और उनके शरीर पर फटे अधनंगे कपड़ों की जगह वर्दी चमक रही थी। यह सर्वविदित तथ्य है कि वे बच्चों पर कितना कम ध्यान देते थे।

सरकार ने शिक्षकों को सख्ती से बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होने के लिए बाध्य किया है, जो आसान काम नहीं था, वर्षों की सरकारी लापरवाही ने उन्हें अकर्मण्य बना दिया था। शिक्षा व्यवस्था में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए कुछ अन्य छोटे-बड़े प्रयास भी वहां देखे जा सकते हैं। एक प्रासंगिक पहलू जिस पर शायद अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है वह है मध्याह्न भोजन।

इसे सुचारू तरीके से और स्थानीय स्तर पर ही जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, किसी भी बाहरी एजेंसी के हस्तक्षेप से कई अन्य जटिलताएं पैदा होने की संभावना है। इन सभी उपलब्धियों के बीच सबसे बड़ी समस्या यह दिख रही है कि भविष्य में इस सुधार को कैसे जारी रखा जाए, क्योंकि इसके लिए अभी भी उचित तंत्र का अभाव नजर आ रहा है; और तंत्र के अभाव में सभी प्रयास और उपलब्धि निरर्थक साबित हो सकते हैं।

आप की बात

बंगाल में भ्रष्टाचार

ममता बनर्जी की निहित स्वार्थी राजनीति ने पश्चिम बंगाल में लाखों होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नेतागीरी के बल पर अपनों की नियुक्ति कुछ दलों के लिए एक राजनीतिक परंपरा बन गई है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला एक कलंक के रूप में सामने आया है। लोगों ने में लाखों रुपए देकर शिक्षकों की नौकरियां खरीदी थीं, लेकिन अब उनको प्राप्त किये वेतन की सरकारी वसूली का डर सता रहा है। हाईकोर्ट ने 26,000 शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके द्वारा प्राप्त वेतन की वसूली का आदेश कमिश्नरों को दिया है। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली की तरह बंगाल भी भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। राज्य के कई मंत्रियों का विभिन्न मामाले में जेल की हवा खाना यह साबित करता है कि वहां चयन प्रणाली किस सीमा तक भ्रष्टाचार की जद में है। कोर्ट द्वारा शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद अब चयन मंडल और अन्य संबंधित विभागों पर भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि, ममता बनर्जी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, पर इस फैसले से उनको चुनावों के बीच तगड़ा धक्का लगा है। संदेशखाली प्रकरण से भी स्पष्ट है कि बंगाल टीएमसी के चौतरफा गुंडाराज से त्रस्त है और इसका नतीजा चुनावी नतीजों में दिख सकता है।

– **अमृतलाल मारू,** इन्दौर

पित्रोदा का बयान

सैम पित्रोदा के विरासत में मिली संपत्ति में 55 परसेंट सरकार द्वारा ले लिए जाने के कानून का समर्थन करने के बाबत सुप्रीमकोर्ट में भी ऐसे एक मामले में बहस जरी है। हालांकि, कांग्रेस ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है, पर उसका इरादा नेक नहीं लगता है। वैसे सरकार को जीएसटी से भारी राजस्व मिल रहा है। विडंबना है कि पेट्रोलियम पदार्थों और शराब पर भारी टैक्स वसूलने के बाद भी अब कांग्रेस की नजर जनता के धन पर लगी है। एक ओर तो कांग्रेस किसी प्रकार सत्ता तक पहुंचने के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने या सरकारी खजाना खोल देने जैसी बातें कर रही है, वहीं वह विरासत कर थोपने का विचार कर रही है। पित्रोदा का बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है और सत्ता में आने के लिए तड़प रही है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने कांग्रेस की गारंटियों पर व्यंग करते हुए कहा है कि ऐसी गारंटियां वही कर सकता है जिसे अपने सत्ता में आने का कोई विश्वास न हो। विरासती कर, संपत्ति के पुनर्वितरण तथा मुसलमानों को आरक्षण जैसी बातें कर कांग्रेस अपने वर्तमान और भविष्य, दोनों को संकट में डाल रही है। पित्रोदा जैसों को जमीनी हालात की जरा भी जानकारी नहीं है।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

गुकेश की उपलब्धि

भारत के 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर एक इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले वे दुनिया के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं उन्होंने गैरी कासपोरोव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया । अब वे वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज देंगे। इस जीत के बाद वे वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिगं लिरेन से भिड़ेंगे। यह मुकाबला साल के आखिर में होगा। कासपोरोव ने 1984 में 22 साल की उम्र में रूस के ही अनातोली कारपोव को विश्व चैंपियनशिप के खिताब के लिए चुनौती दी थी। गुकेश यह टूर्नामेंट जीतने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं। पांच बार के चैंपियन विश्वनाथ ने 2014 में यह विश्व कप खिताब जीता था। गुकेश ने 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। विश्वनाथ आनंद ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि डी. गुकेश को सबसे युवा चैलेंजर बनने पर मुझे निजी तौर पर बहुत गर्व है। तुमने एक कठिन हालात में विजय प्राप्त की है। आज हमारा देश विश्व में सर्वाधिक युवाओं का देश है। ऐसे में गुकेश की उपलब्धि देश के युवाओं को न केवल शतरंज, बल्कि अन्य खेलों तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की निश्चित रूप से प्रेरणा देगी।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

खैरात की लत

अब तो देश में अधिकांश जनता को खैरात की आदत पड़ चुकी है या दूसरे शब्दों में कहें तो लत लग गई है। हमारे देश के लोगों में यह खूबी है कि जो चीज एक बार मुफ्त मिलना शुरू हो फिर उसे घटाना या बंद करना मुमकिन नहीं होता। आरक्षण इसका एक उदाहरण है। आजादी के बाद से आरक्षण से लाभान्वित तबका इसे घटाने को तैयार नहीं है। आरक्षण बढ़ाते जाइए तो किसी को आपत्ति नहीं होगी और घटाने की बात करेंगे तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। यदि 2024 का चुनाव जीतने के बाद आर्थिक कारणों या जनता के जीवनस्तर में पर्याप्त सुधार के कारण मुफ्त आवंटन योजनायें लंबे समय तक चलाना उचित न हो तो भी इनको बंद करना संभव नहीं होगा। सच हो या झूठ, अब लगभग सभी राजनीतिक दलों के लिए मुफ्तखोरी या खैरातों का अपने घोषणा पत्र में आश्वासन देना आवश्यक हो गया है। खैरात की यह लत सभी लतों से अधिक घातक है। इससे लोग अपना विकास करने और आत्मनिर्भर बनने के बजाय परजीवी बनने की आदत पाल लेते हैं। इसे जल्दी खत्म करना राष्ट्रहित में कारगर होगा।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

अभिमत

तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और तेल के भंडार खत्म होने की कगार पर हैं। अगर हम साइकिलों का उपयोग करें तो हमें मोटरवाहनों में प्रयोग होने वाला पेट्रोल व डीजल को आयात नहीं करना पड़ेगा या कम से कम करना पड़ेगा। अच्छी सेहत के लिए साइकिल चलाना जरूरी है। साइकिल चलाने वालों को अलग से शारीरिक कसरत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे मांसपेशियों की अच्छी कसरत हो जाती है। मोटरसाइकिल की अपेक्षा साइकिल काफी हल्की होती हैं, इसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी चला सकते हैं।

अच्छी सेहत के लिए साइकिल जरूरी

नवाचार

■ बाबा मायाराम

इन दिनों गांवों से लेकर शहरों तक मोटरसाइकिल का तेजी से चलन बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी साइकिलों का अपना विशेष स्थान है, बल्कि अब इसे आत्मनिर्भरता के साथ अच्छी सेहत के लिए जरूरी माने जाने लगा है।

वैश्विक महामारी के बाद से मैंने भी साइकिल चलाना शुरू किया है, जिससे न केवल मुझे स्वस्थ रहने में मदद मिली है, बल्कि प्रकृति और परिवेश से जुड़ने का मौका भी मिला है। जनसाधारण लोगों से मिलने और बात करने का अवसर मिला है।

मध्यप्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ की तलहटी में स्थित कस्बे में मेरा निवास है। मैं रोज सुबह साइकिल की सैर करता हूं। कस्बे से पांच किलोमीटर दूर एक पहाड़ी नदी तक जाता हूं और वहां से लौटकर आता हूं।

इस पहाड़ी नदी का नाम मछवासा है। पहले यह नदी बारहमासी हुआ करती थी, पूरे साल भर बहती थी, अब बरसाती हो गई है। लेकिन बारिश के दिनों में इस नदी का सौंदर्य देखते ही बनता है। विशेषकर, कस्बे के ऊपर के गांवों में इसे देखना मनमोहक होता है।

चारों तरफ हरियाली, कल-कल बहती नदी, घास की सरसराहट और हवा की खुशबू होती है। एक ओर चिड़ियों का गीत सुनाई देता है, दूसरी ओर पेड़ों की चमकीली पत्तियां, कीट-पतंगों की भिनभिनाहट और पानी की झिलमिलाहट खींचती है।

बारिश से धुली साफ-सुथरी सड़क, पेड़ों से लटकते पक्षियों के घोंसले, आकाश में बादलों के सफेद गोले और मोतियों सी ओंस की बूंदें लुभाती हैं, तो खेतों में घूमते सियार, रास्ता भटके हिरण, खेतों में दाना चुगते मोर, बंदरों की उछल-कूद और लोमड़ियां दौड़ते दिख जाती हैं।

जो जंगल गर्मी में उदास और बेजान से दिखते हैं, वे बारिश के आते ही हरे-भरे और सजीव हो उठते हैं। मौसम में नई बहार आ जाती है। हाल ही में बेमौसम बारिश में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। हालांकि बेमौसम बारिश के नुकसान भी हैं।

इसके अलावा, खेतों में काम करते किसान, सब्जी वाले, दूध वाले, बकरी चराने वाले, चरवाहे, स्कूली बच्चे, नर्मदा की परकम्मा (परिक्रमा) पर निकले श्रद्धालुओं से साक्षात्कार होता रहता है। नर्मदा नदी पवित्र मानी जाती है, इसकी लोग पैदल परकम्मा करते हैं। नर्मदा इस इलाके के उत्तर से गुजरती है। जबकि दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं।

बहुत लम्बा अरसा नहीं हुआ, जब साइकिल प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पहचान हुआ करती थी। हालांकि उस समय साइकिलें कम होती थीं और दुकानों से किराये से मिलती थीं। पर साइकिलों का बोलबाला था। उनका सफर सपना होता था।

लेकिन दो दशक पहले से साइकिलों के चलन में बड़ी कमी आई है। और मोटर कार, मोटरसाइकिल. स्कूटर व अन्य वाहनों की बाढ़ आ गई है। साइकिल पीछे हो गई हैं और कारें आगे हो गई हैं। यह एक तरह से वैश्वीकरण का नतीजा भी है।

साइकिल से मोटरसाइकिल या कारों की ओर रूझान बढ़ना अचानक व स्वाभाविक नहीं है बल्कि इसके पीछे सरकारी नीतियां भी हैं। वेतनमानों में वृद्धि है। नई-नई चिकनी चौड़ी सड़कों व राजमार्गों, फ्लाईओवरों का बनना है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं।

कोविड-19 के बाद से साइकिलों के प्रति लोगों का रूझान फिर से बढ़ा है। अच्छी सेहत व फिटनेस के प्रति सजगता आई है। इसके बाद से लोगों ने सुबह-शाम घूमना, साइकिल से सैर करना और प्रकृति के साथ समय गुजारना शुरू किया है। साइकिल मरम्मत करने वाले कहते हैं कि पहले की अपेक्षा अब साइकिलों की मांग बढ़ गई है।

महामारी के दौरान जब तालाबंदी हुई थी, तब शहरों से पैदल चलकर या साइकिल यात्रा करके लोग उनके घरों तक पहुंचे थे। सड़कों पर पैदल यात्रियों व साइकिल सवारों का तांता लग गया था। इससे साइकिल जैसे वाहनों का महत्व और स्पष्ट रूप से समझ आया है।

साइकिल एक बहु उपयोगी वाहन है। इसकी उपयोगिता कई रचनात्मक कामों में भी सामने आती रही है। हमारे गांव के पास एक स्वयंसेवी संस्था थी, यह 80 के दशक की बात है। इस संस्था की एक गतिविधि सचल पुस्तकालय (मोबाइल लाइब्रेरी) हुआ करती थी। संस्था के कार्यकर्ता साइकिल से गांवों में जाते थे, और लोगों को पढ़ने के लिए किताबें देते थे। इन किताबों में अच्छा साहित्य होता था। दूरदराज के गांवों में किताबें उपलब्ध कराने की यह अनूठी पहल थी।

साइकिल एक बहु उपयोगी वाहन है। इसकी उपयोगिता कई रचनात्मक कामों में भी सामने आती रही है। हमारे गांव के पास एक स्वयंसेवी संस्था थी, यह 80 के दशक की बात है। इस संस्था की एक गतिविधि सचल पुस्तकालय (मोबाइल लाइब्रेरी) हुआ करती थी। संस्था के कार्यकर्ता साइकिल से गांवों में जाते थे, और लोगों को पढ़ने के लिए किताबें देते थे। इन किताबों में अच्छा साहित्य होता था। दूरदराज के गांवों में किताबें उपलब्ध कराने की यह अनूठी पहल थी।

इसी तरह, संस्था की एक और गतिविधि थी, गांवों में दवाई सुविधा का संचालन करना। हर सप्ताह गांव में एक दिन संस्था की डॉक्टर आती थीं और लोगों की छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करती थीं। वह महिला डॉक्टर साइकिल से आना-जाना करती थीं, जो उन दिनों कौतूहल का विषय हुआ करता था। डाकिया तो साइकिल से डाक लाता ही था। शहर से स्कूल शिक्षक भी साइकिल से आते थे।

इसी प्रकार, देश में साक्षरता अभियान में भी साइकिलों का प्रयोग किया गया। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी स्वतंत्रता की तो साइकिल प्रतीक है। जो महिलाएं आमतौर से घर से नहीं निकल पाती थीं, साइकिल ने उनकी दुनिया को बड़ा बनाया। कई महिलाएं साइकिलों से शहर में काम करने करने जाती हैं, दफ्तर जाती हैं। स्कूली लड़कियों के लिए तो कई प्रदेश सरकारों ने योजनाएं शुरू की हैं।

औद्योगिक शहरों में मजदूरों के लिए साइकिल की सवारी आम बात थी। सुबह-शाम मजदूरों की साइकिलें सड़कों पर दौड़ती थीं। एक अलग ही नज़ारा हुआ करता था। मध्यप्रदेश के इंदौर, जबलपुर और छत्तीसगढ़ के भिलाई के आसपास ऐसे दृश्य आम थे। साइकिल ही ऐसे शहरों की पहचान हुआ करती थी।

आजादी के शुरूआती दशक में भारतीय सिनेमाओं में भी साइकिल दिखती थीं। कई गानों में साइकिल के दृश्य होते थे। गांव, पेड़, खेत-खलिहान, पशु-पक्षी सब दिखते थे। लेकिन अब कम दिखाई देते हैं।

शहरों व छोटे कस्बों के सिनेमाघरों में भी बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ती थी, जिनमें से अधिकांश साइकिल सवार होते थे। दूरदराज़ के गांवों से लोग लम्बी यात्राएं करते थे। साइकिल, एक सुलभ व सस्ता वाहन था, और आज भी है।

पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो साइकिलें बेहतर वाहन हैं। पर्यावरण की मित्र हैं। यह हाथ-पैर की ताकत से चलती हैं। इसे चलाने के लिए किसी प्रकार के ईंधन की जरूरत नहीं है। इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। प्रकृति को इससे कोई खतरा नहीं है। जबकि मोटर-कारों का जलवायु परिवर्तन में बड़ा योगदान है।

तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और तेल के भंडार खत्म होने की कगार पर हैं। अगर हम साइकिलों का उपयोग करें तो हमें मोटरवाहनों में प्रयोग होने वाला पेट्रोल व डीजल को आयात नहीं करना पड़ेगा या कम से कम करना पड़ेगा।

अच्छी सेहत के लिए साइकिल चलाना जरूरी है। साइकिल चलाने वालों को अलग से शारीरिक कसरत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे मांसपेशियों की अच्छी कसरत हो जाती है। मोटरसाइकिल की अपेक्षा साइकिल काफी हल्की होती हैं, इसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी चला सकते हैं। सड़क हादसों का जोखिम भी नहीं रहता। अगर साइकिल से गिर भी जाएं तो ज्यादा चोट नहीं आती। इसके रखरखाव व मरम्मत में भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते।

साइकिल के लिए पार्किंग की समस्या नहीं है। न तो खड़ी करने के लिए और न ही सड़क पर चलाने के लिए इसे ज्यादा जगह चाहिए। इसे घर में रखा जा सकता है। जबकि कारों के लिए सड़क पर, पार्किंग में सभी के लिए जगह चाहिए, जो एक बड़ी समस्या है।

साइकिल से सड़क जाम होने की समस्या नहीं है। इसे संकरे रास्तों व गलियों में चलाया जा सकता है। अगर इसके लिए अलग से लेन हो तो, न तो यह दूसरे वाहनों की गति में रूकावट होगी और न ही साइकिल चलाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। साइकिल उनके लिए भी अच्छी है, जो भीड़ से बचना चाहते हैं।

इससे बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलती है। साइकिल निर्माण, मरम्मत और खरीद-बिक्री के धंधे में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। साइकिल मरम्मत की दुकान बहुत ही सस्ते में शुरू की जा सकती है, ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती।

सड़कों पर वाहनों का बोझ बढ़ता जा रहा है। सड़क जाम, दुर्घटनाएं, प्रदूषण की खबरें आती रहती हैं। साइकिल के चलन इन सभी में कमी आ सकती है। छोटे व कस्बों में इन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है।

साइकिल गरीबों की ही नहीं, सबकी पसंद बनती जा रही है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस भी मनाया जाने लगा है। इसलिए हमें भी साइकिलों को बढ़ावा देना चाहिए। साइकिल का प्रचार करना चाहिए। सड़कों पर पैदल व साइकिलों के लिए अलग से लेन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

कुल मिलाकर, हमें सादगीपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ जीवनशैली की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से साइकिल एक आदर्श वाहन है, विशेषकर, कम दूरी के लिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए। यह एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का वाहन है। लेकिन क्या हम प्रदूषणमुक्त शहर बनाने और अच्छी सेहत के लिए इसे अपनाएंगे?

बीता सप्ताह

20 अप्रैल

- लोकसभा के 21 राज्यों की 102 सीटों पर 2024 का प्रथम चरण का चुनाव बस्तर छत्तीसगढ़ में 63 फीसदी वोट पड़े।
- छग के रायगढ़ जिले से लगे ओड़ीशा में रेंगाली सारधा महानदी घाट में नाव पलटने से सात लोगों की मृत्यु हो गई।
- लाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के अगले नौ सेना प्रमुख बनाए गए।
- केन्या के हेलीकाप्टर दुर्घटना में सैन्य प्रमुख जनरल ओगोला सहित सेना के नौ अधिकारियों की मृत्यु हो गई।

21 अप्रैल

- भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलम्पिक का कोटा प्राप्त कर भारत को दिलाया ओलंपिक कोटा।
- भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आंध्रप्रदेश कैडर के वरिष्ठ अधिकारी नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक बनाया गया।
- संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस थीम गीत का एमवी जारी किया गया।
- टोक्यो में भारती पैरा-केनोइस्ट तपदीप ने एशियाई कैनोइंग / पैरा कैनोइंग स्प्रिट चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।

22 अप्रैल

- मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीआरए) में नाव डूबने से 58 लोगों की मौत हो गई।
- वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रियेक्टरों में कार्बन-14 आइसोटोप का किया गया उत्पादन।
- मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों में लोकसभा का दोबारा मतदान हुआ।
- विश्वविद्यालयीन अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए पंजीकरण प्रारंभ किया गया।

23 अप्रैल

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई गणमान्य जन को पद्म पुरुस्कार से सम्मानित किया।
- पहली बार भाजपा के लोकसभा चुनाव का प्रत्यक्ष अवलोकन सात देशों के प्रतिनिधियों ने किया।
- अमेरिका में पढ़ रहे तेलंगाना के दो छात्रों की मौत एटीजोना में सड़क दुर्घटना में मौत गई।
- कुवैत में हिंदी दूतावास ने की हिंदी रेडियो प्रसारण की सराहना।

24 अप्रैल

- सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु और पतंजलि औषधि प्रमुख रामदेव बाबा के विज्ञापन संबंधी प्रकरण पर कहा कि माफीनामा विज्ञापन जितना बड़ा क्यों नहीं है।
- गुंटूर लोकसभा सीट से टीडीपी प्रत्याशी चंद्रशेखर लोकसभा 2024 के चुनावी हलफनामे अनुसार 5785 करोड़ के मालिक हैं।
- रक्षा मंत्रालय ने मध्यम दूरी की वैलेस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया।
- भारत की गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजीडेंट समन्वयक बनाई गईं।

25 अप्रैल

- वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा।
- जगदलपुर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए।
- भाजपा सांसद राजवीर सिंह दिलेर की हार्टअटैक से मौत हो गई।
- रूसी उपप्रधानमंत्री तिमूर इवानोव को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

26 अप्रैल

- लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में कांकेर, महासमुंद, और राजनांदगांव में मतदान हुआ।
- उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई।
- अम्मान के स्वतंत्र चुनाव आयोग ने घोषणा की कि जार्डन में 10 सितंबर को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे।
- चीन के तीरंदाजी विश्वकप में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम के धीरज बोलदेवरा, तरुणदीप राय, प्रवीण रमेश जाधव फाइनल में पहुंचे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कितनी दूर हैं गांधी ?

■ रमाकांत नाथ

गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसा को लोग भूल गये हैं। ऐसे दो हथियारों से गांधीजी ने भारत में उस साम्राज्यवादी शक्ति को हराया, जिसे पराजित न कर पाने की घोषणा की गई थी। जिस स्थापित साम्राज्य का 'अंत नहीं' कहा गया था, उस अजेय शक्ति की हार हुई, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। क्या यह बिना रक्तपात, बिना युद्ध के संभव था?

आज के लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। जो लोग यह मानते हैं कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति था और उसने अपने आदर्शों से दुनिया में अहिंसा की बयार बहाई थी, वे यह जानते हैं, लेकिन इस धारणा को हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

गांधी की हत्या को एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की जा रही है। गांधी के स्मारकों को मिटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। जब सरकारी षड़यंत्र, भ्रष्ट व्यवस्था, गांधीवादी बयानबाजी, आत्मप्रचार, वोट और सत्ता की रक्षा के लिए गांधी का उपयोग हो तो असली गांधी का पता कैसे चलेगा? वे गांधीवादी भावना को कैसे महसूस कर सकते हैं? गांधी दर्शन के सिद्धांतों और अनुप्रयोग से कैसे अवगत हो सकते हैं? क्या वे गांधी दर्शन का प्रचार करेंगे?

गांधी इसे एक रास्ता, एक रोशनी, एक विकल्प, एक आशा कहते थे। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी गांधी प्रासंगिक हैं और उनका दर्शन लागू है, लेकिन भारत में गांधी और उनके विचार विस्थापित हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के महान सेनानी नेल्सन मंडेला ने जीवन में गांधी को कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने गांधी के आदर्शों को इस तरह क्रियान्वित किया कि एक निरंकुश सरकार गिर गई।

परोक्ष रूप से इस देश से गांधी और उनके प्रतीकों को मिटाने की योजना चलाई जा रही है। ऐसी योजना को छद्म गांधीवादियों का समर्थन प्राप्त है, जो अपराध में शामिल हैं। बलात्कार, चोरी, दलाली, माफिया से लेकर अन्य घोटालों तक में लगे लोगों को गांधी कहा जाने लगा है। इस मूर्ति को देखकर लोगों का असली गांधी को भूल जाना स्वाभाविक है। कई लोग खुद को गांधी भक्त गांधीवादी कहते हैं, लेकिन गांधी उनसे कोसों दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गांधी आज कितने आगे हैं?

गांधी इसे एक रास्ता, एक रोशनी, एक विकल्प, एक आशा कहते थे। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी गांधी प्रासंगिक हैं और उनका दर्शन लागू है, लेकिन भारत में गांधी और उनके विचार विस्थापित हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के महान सेनानी नेल्सन मंडेला ने जीवन में गांधी को कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने गांधी के आदर्शों को इस तरह क्रियान्वित किया कि एक निरंकुश सरकार गिर गई। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर मंडेला का राजनीतिक अभियान जारी रहा और दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के साथ ही ब्रिटिश शासन का अंत हो गया।

इसी तरह काले अधिकारों के क्रांतिकारी अमेरिकी वकील मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधीजी को अपने जीवन में ऐसा सम्मान दिया जिससे वे अमेरिका के सबसे महान व्यक्ति के रूप में जाने गये। मार्टिन लूथर ने एक बार कहा था, यीशु ने हमें हमारा लक्ष्य बताया है, लेकिन महात्मा गांधी ने हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है।

परमाणु वैज्ञानिक और सापेक्षता के सिद्धांत के आविष्कारक और गांधीजी के प्रशंसक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने कई पत्रों में गांधीजी को अहिंसा का सच्चा उपासक बताया है। द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत पहले, आइंस्टीन के साथ गांधीजी के संबंध पत्रों के माध्यम से विकसित हुए थे। उन्होंने महात्मा को अपने समय के महानतम दूरदर्शी लोगों में से एक बताया।

कुछ साल पहले, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 2009 में एक स्कूली कार्यक्रम में ओबामा एक लड़की का अजीब सवाल सुनकर हैरान रह गए थे। बराक ओबामा ने उस सवाल का माकूल जवाब देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। लड़की ने राष्ट्रपति ओबामा से पूछा, 'अगर आपको जीवित या मृत किसी व्यक्ति के साथ डिनर करना हो तो आप किसे चुनेंगे?' राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, गांधी। इससे पता चलता है कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी, विकसित देश के शासकों के लिए गांधी कितने महान हैं।

ओबामा के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिकी इतिहास बदल गया। वे राष्ट्रपति बनने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने। ओबामा ने अपने सीनेट कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई और उनकी स्मृति को जीवित रखने का प्रयास किया। कई जगहों पर ओबामा ने गांधी की प्रशंसा की है और गांधी से प्रभावित होने की बात स्वीकार की है, यहां तक कि उन्होंने अपनी एक किताब 'ए प्रॉमिस्ड लैंड' में भी गांधी की प्रशंसा की है।

ओबामा की तरह दुनिया के कई राजनेता गांधी से प्रभावित रहे हैं और उनके सत्य-अहिंसा के दर्शन की प्रशंसा की है। दुनिया के अनेक दार्शनिक, कवि, लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता अपने लेखन के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से गांधी की प्रशंसा करते हैं। ओबामा के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे अल गोर भी गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित थे। उनका हृदय सत्य-आधारित जीवन के लिए था, जिसे वे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मानते थे।

दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि गांधी की अहिंसा और धार्मिक भाईचारे ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। ये दो चीजें भारत का मूल दर्शन हैं, जिसे गांधी ने दुनिया के सामने व्यक्त किया, जबकि भारत दुनिया का गुलाम बन गया था। इसके कारण दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और गांधी के विचारों के करीब हो सके।

भारत में भी गांधीवादी आदर्शों के बहुत से अनुयायी थे और अब भी हैं। इनमें आचार्य विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महादेव भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, सरोजिनी नायडू, सी.राजगोपालाचारी, शंकर राव देव, गोविंद बल्लभ पंत, सुशीला नायर, जमुना लाल बजाज, आचार्य राममूर्ति, दादा धर्माधिकारी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित गोपबंधु दास आदि। ये गांधी के आदर्शों के अनुयायी हैं, लेकिन अगर उन्होंने कभी खुद को गांधीवादी या गांधीजी के रूप में प्रचारित नहीं किया।

गांधी और उनके अनुयायियों के बाद जब दुनिया के हर कोने में गांधी की पूजा की जा रही है, उनके दर्शन को लागू किया जा रहा है, लेकिन भारत में गांधी दर्शन की हत्या हो रही है। इस दुर्भावनापूर्ण गतिविधि में छद्म गांधीवादी मुख्य भागीदार हैं। पाठ्यपुस्तकों से बाहर कर जहां गांधी को एक असामाजिक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जा रहा हो वहां गांधी दर्शन पर ये दो तरह के हमले परोक्ष रूप से भारत को गांधी विचार से मुक्त करने की कोशिश ही कर रहे हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।)

भाजपा के लिए कठिन है '400 पार' की डगर

40 दिनों और सात चरणों में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्र के मूड को पढ़ना कभी आसान या सुरक्षित नहीं होता। इस प्रतिवाद के बावजूद यह अभी भी कहा जाना चाहिए कि भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनने की शुरुआत है जो आकार में हल्के से मध्यम शक्ति का हो सकता है; और इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव विश्लेषण कौन कर रहा है। हालांकि, चुनाव के पहले चरण की समाप्ति के बाद इस स्तर पर यह कहना मुश्किल है कि यह भावना क्यों और कैसे पैदा हो सकती है या क्या यह नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल देने के खिलाफ एक तगड़ा माहौल बनाने में सफल हो सकती है। अगर यह माहौल बनाना है तो भाजपा के भारी धन बल और चुनाव अभियान की पहुंच व प्रभाव के खिलाफ खड़ा होना होगा। चुनावी बॉन्ड योजना से भाजपा को मिले 8,250 करोड़ रुपये से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा भारी खर्च स्पष्ट रूप से अभद्रता की सीमा पर है। चुनावी बॉन्ड योजना अब अवैध घोषित हो चुकी है।

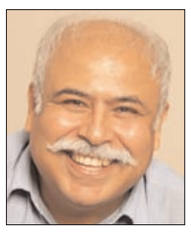

इसके बाजूद एकतरफा मिली यह धन शक्ति नुकसान भी पहुंचा सकती है क्योंकि यह एक ओर अद्वितीय पहुंच को सक्षम बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर यह भाजपा की भारी नकारात्मकताओं को उजागर करने का काम करती है। यह धन शक्ति एक दमदार, दबंग व अहंकारी व्यक्तित्व को वोट मांगने के समय मदद नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री की यात्रा को छोड़ दें तो भाजपा ने अपने नेताओं के लिए सबसे अधिक निजी हेलीकॉप्टर बुक किए हैं। रायटर के अनुसार गूगल सर्च विज्ञापनों पर भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले चार-एक और फेसबुक विज्ञापनों पर तीन के मुकाबले एक खर्च किया है। वे इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर इस्तेमाल कर मतदाताओं को अपनी सतही कहानी का प्रचार करने के लिए कहती है कि 2019 की तुलना में भाजपा 303 सीटों के अपने आंकड़े में सुधार करेगी।

जगदीश रत्तनानी

महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुए जबरन विभाजन ने महाराष्ट्रीयन गौरव को चोट पहुंचाई है। इसने भाजपा के खिलाफ गुस्से का एक मजबूत अंतर्प्रवाह बनाया है कि पार्टी ने महाराष्ट्र में एक निर्वाचित सरकार को प्रभावित करने के लिए गुजरात का इस्तेमाल किया है। असंतुष्ट और बागी विधायकों को भगाने के लिए भाजपा नेतृत्व ने पहले गुजरात के सूरत (और बाद में गुवाहाटी) का इस्तेमाल एक सुरक्षित शहर के रूप में किया।

यह समझना मुश्किल है कि ऐसा कैसे संभव है जब तक कि सत्तारूढ़ गठबंधन पिछली बार मिली सीटों को बचाए रखते हुए नई सीटों पर जीत हासिल नहीं करता है, तब तक वह 400 पार के लक्ष्य को कैसे पा सकता है। उदाहरण के तौर पर पिछली बार पूरे दक्षिणी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सत्तारुढ़ गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। 2019 में दक्षिण भारत में नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) गठबंधन ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के पांच राज्यों में 130 सीटों में से 30 सीटें जीतीं लेकिन उनमें से 25 कर्नाटक से आई थीं। कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार है जो अपने प्रगतिशील कामों के लिए विख्यात है। कर्नाटक सरकार अपने चुनाव अभियान की ताकत को बढ़ाती है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि भाजपा 2019 में कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से 25 के अपने आंकड़े तक पहुंच पाएगी।

तमिलनाडु में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहां पिछली बार पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी लेकिन अब वह शहरी इलाकों में कड़ी टक्कर दे रही है। फिर भी वहां भाजपा के अभियान को द्रविड़ आंदोलन की वैचारिक चुनौती को देखते हुए राज्य में प्रतिसाद मिलने की संभावना नहीं है। वहां सभी क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति और विचारधारा का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेरियार के द्रविड़ आंदोलन से है। डीएमके विशेष रूप से बार-बार प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने का आरोप लगाते हुए एक मजबूत अभियान चलाने में सक्षम रही है। संभावना है कि भाजपा को वहां एक भी सीट न मिले।

इसी प्रकार, उत्तरी क्षेत्र में 2019 में भाजपा को अधिकतम सीटें मिलीं थीं। वहां बढ़ने की कोई गुंजाइश न होने तथा कहीं और से कोई नया आधार न होने के कारण भाजपा के लिए अपनी समग्र टैली में सुधार करना लगभग असंभव हो जाता है। वास्तव में बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नई वास्तविकताओं को देखते हुए पार्टी अपने स्व-घोषित बेंचमार्क से काफी नीचे आ सकती है।

भाजपा के आगे-पीछे चलने के कारण बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग 'पलटू राम' कहने लगे हैं। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि एनडीए की जेडीयू-बीजेपी-एलजेपी तिकड़ी 2019 के लोकसभा चुनावों में जीती गई 40 सीटों में से 39 कैसे जीत पाती है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव एक जबरदस्त चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वे नीतीश कुमार को अपना निशाना बनाए हुए हैं और व्यंग्यात्मक लहजे में 'माननीय' मुख्यमंत्री कहते हैं लेकिन राजद के अंदरूनी लोगों का कहना है कि राजद ने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल अपने संकीर्ण हितों के लिए किया है। यह सोच अपने आप में कहती है कि नीतीश कुमार एक मोहरा बन गए हैं, वे सत्ता पर नियंत्रण खो चुके हैं और भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। बिहार को 'विशेष दर्जा' दिलाने की मांग को पूरा करवाने में नीतीश कुमार विफल रहे, जिसके लिए वे केंद्र से लगातार मांग और अनुरोध करते रहे हैं। भाजपा के साथ वापस जुड़ने के बाद से नीतीश कुमार की शब्दावली से बिहार के लिए 'विशेष दर्जा' शब्द गायब हो गया है।

महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुए जबरन विभाजन ने महाराष्ट्रीयन गौरव को चोट पहुंचाई है। इसने भाजपा के खिलाफ गुस्से का एक मजबूत अंतर्प्रवाह बनाया है कि पार्टी ने महाराष्ट्र में एक निर्वाचित सरकार को प्रभावित करने के लिए गुजरात का इस्तेमाल किया है। असंतुष्ट और बागी विधायकों को भगाने के लिए भाजपा नेतृत्व ने पहले गुजरात के सूरत (और बाद में गुवाहाटी) का इस्तेमाल एक सुरक्षित शहर के रूप में किया। एक आंदोलन के बाद मुंबई के महाराष्ट्र की राजधानी बनने तक महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य थे। मुंबई में एक 'हुतात्मा चौक' उन शहीदों का स्मारक है जो अलग मराठी भाषी महाराष्ट्र राज्य के लिए संघर्ष में मारे गए थे। उस समय मोरारजी देसाई तत्कालीन संयुक्त बॉम्बे-गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। उसे तब 'बॉम्बे स्टेट' कहा जाता था। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 पर जीत हासिल की थी। संभावना है कि कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट वाले एकजुट विपक्ष के खिलाफ यहां भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरावती लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सांसद नवनीत राणा ने एक जनसभा में खुलकर कहा कि इस बार 'मोदी लहर' नहीं है।

कई अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को उत्साहजनक प्रतिसाद मिलने की खबरें हैं लेकिन वायनाड को लेकर सीपीआई-कांग्रेस के झगड़े का नकारात्मक प्रभाव और अमेठी सीट को लेकर अनिश्चितता है। रॉबर्ट वाड्रा ने स्पष्ट रूप से अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है।

दूसरी तरफ, भाजपा का प्रमुख चेहरा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थके हुए और निस्तेज दिखते हैं। वे एक भंवर में फंसे हुए प्रतीत होते हैं जिससे निकलने के लिए और अधिक समय की जरूरत होती है। उन्होंने अपने भाषणों में धर्म का अति प्रयोग करना शुरू कर दिया है (भाजपा मानकों के मुताबिक यह अति की सीमा तक पहुंच गया है!) जो हास्यास्पद होने की सीमा तक पहुंच गया है। एक सभा में उन्होंने श्रोताओं से कहा कि जब अयोध्या के मंदिर में भगवान राम के 'जन्मदिन' पर भगवान राम की मूर्ति पर सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हों तब वे रोशनी भेजने के लिए अपने मोबाइल टॉर्च पर प्रकाश भेजें। उसी बैठक में उन्होंने कहा- 'मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी'।

लेकिन हम इसे यूं ही नजरअंदाज कर सकते हैं- इसे तनाव कहें, थकान कहें या लोकतंत्र के त्यौहार के बीच बेतुकी नाटकबाजी कहें। इसके बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि भारत भविष्य में भी लोकतंत्र का जश्न मनाता रहेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंडिकेट द बिलियन प्रेस)

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

देशप्राण
स्वतंत्र हिन्दी दैनिक

बंद हो आंदोलनों में रेल रोकना

पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू रेलवे स्टेशन में जारी किसानों के आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को बिना किसी अपराध के सजा भुगतनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर रेलवे को भी भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से रोज 40 से 50 ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। यात्रियों को ज्यादा समय व पैसा लगाकर अपने गंतव्य स्थानों तक जाना पड़ रहा है। रेलवे के पार्सल बुकिंग केंद्र में भी पचास फीसदी की कमी आने की बात बतायी जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि किसानों की न्यायसंगत मांगों को पूरा किया ही जाना चाहिए। वे लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं। ऐसे में सत्ताधीशों का भी नैतिक दायित्व बनता था कि वे किसानों से बातचीत की टेबल पर बैठकर बात करते। जिससे सड़क व रेल यातायात बाधित भी नहीं होता। वैसे किसानों को भी आंदोलन करने से पहले देशकाल-परिस्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए था। देश इस समय चुनावी मूड में है। कोई भी सरकार किसानों से जुड़े किसी मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने में सक्षम नहीं है। किसानों को नये जनादेश का इंतजार करके किसान आंदोलन को दिशा देनी चाहिए थी। किसानों को देश व समाज के अहसासों का भी ध्यान रखना चाहिए। कल्पना कीजिए कि रेल यात्रा करने वाले लोगों को जब अचानक सूचना मिलती है कि उनकी ट्रेन रद्द हो गई है तो उन पर क्या बीतती होगी? लोग घंटों रेलवे टिकट बुकिंग केंद्रों पर खड़े होकर अपने लिये टिकट आरक्षित करवाते हैं। कई महीने पहले एडवांस में रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। फिर एक दिन यात्रा से ठीक पहले पता चलता है कि उनकी ट्रेन रद्द हो गई है। आंदोलनकारियों को सोचना चाहिए कि उस ट्रेन से कोई मरीज कहीं दूर उपचार हेतु जा रहा होगा। कहीं कोई बेरोजगार नौकरी के लिये साक्षात्कार देने जा रहा होगा। हो सकता है कि सही समय पर न पहुंच पाने के कारण कई छात्र परीक्षा या नौकरी पाने से वंचित हो गए होंगे। समय-समय पर देश की शीर्ष अदालत के मार्गदर्शक फैसले आते रहे हैं कि हमें किसी आंदोलन के नाम पर नागरिक जीवन को बंधक नहीं बनाना चाहिए। यदि आंदोलनकारियों के अधिकार हैं तो आम नागरिकों के भी अपने अधिकार हैं। एक पुरानी कहावत है कि जहां से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है, वहां पर पहले व्यक्ति की आजादी खत्म हो जाती है। यानी हमारी किसी भी तरह की आजादी का मतलब किसी की आजादी का अतिक्रमण करना नहीं हो सकता। वैसे भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी हमें सोचना चाहिए कि यातायात के साधनों, वह चाहे बस हो या ट्रेन, के परिचालन में बाधा डालना एक अपराध जैसा है। ट्रेन को थामना देश के विकास के पहिये थामने जैसा ही है। हमारे कारोबार, जीवन व्यवहार, तीर्थाटन तथा सेना के आवागमन को गति देने वाली ट्रेनों को रोकना निस्संदेह, दुर्भाग्यपूर्ण ही है। निश्चित रूप से इसमें हमारे देश के नीति-नियंताओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों किसानों को अपनी मांगें मनवाने के लिये रेल रोकने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं।

चुनावों में चुनौती बन रहा चीन

प्रशांत माली

हाल के वर्षों में, प्रौद्योगिकी और राजनीति का जुड़ाव तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संभावित हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन भारत के लोकसभा चुनाव सहित कई अन्य चुनावों को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का दुरुपोयोग कर सकता है। यह लेख इस मुद्दे के बहुआयामी आयामों को रेखांकित करता है और तकनीकी, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक निहितार्थों की खोज करता है। ताइवान के

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चीन सोशल मीडिया के जरिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा बनाई गई राजनीतिक सामग्री वितरित करेगा, जो 'इन हाई-प्रोफाइल चुनावों में उसके हितों को लाभ पहुंचा सकता है', क्योंकि एआई से तेजी से मीम्स, वीडियो और ऑडियो सामग्रियां बन रही हैं। कंपनी ने जून, 2023 से चीन और उत्तर कोरिया में ह्यकुछ उल्लेखनीय साइबर रुझान देखे हैं, जो न केवल अपने परिचित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक जटिल प्रभावी तकनीकों का उपयोग करने का भी प्रयास करते हैं।' माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि चीनी साइबर हमलावरों ने तीन लक्ष्य क्षेत्रों को चुना है- दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के देश, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके क्षेत्रीय विरोधी और अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार।

अनुभवों के जरिये इसकी भी पड़ताल की गई है कि इनसे निपटने में सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चीन सोशल मीडिया के जरिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा बनाई गई राजनीतिक सामग्री वितरित करेगा, जो 'इन हाई-प्रोफाइल चुनावों में उसके हितों को लाभ पहुंचा सकता है', क्योंकि एआई से तेजी से मीम्स, वीडियो और ऑडियो सामग्रियां बन रही हैं। कंपनी ने जून, 2023 से चीन और उत्तर कोरिया में ह्यकुछ उल्लेखनीय साइबर रुझान देखे हैं, जो न केवल अपने परिचित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक जटिल प्रभावी तकनीकों का उपयोग करने का भी प्रयास करते हैं।' माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि चीनी साइबर हमलावरों ने तीन लक्ष्य क्षेत्रों को चुना है- दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के देश, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके क्षेत्रीय विरोधी और अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार। चीनी अभियान एआई-जेनरेटेड या एआई-समर्थित सामग्री को परिष्कृत करना जारी रखते हैं। इन अभियानों के पीछे के खिलाड़ियों ने एआई-जनरेटेड मीडिया को बढ़ाने की इच्छा दर्शाई है, जो उनके रणनीतिक आख्यानों को लाभ पहुंचाता है, साथ ही वे वीडियो, मीम्स और ऑडियो सामग्री भी बनाते हैं।

चीन, मतदाताओं को सबसे ज्यादा किस चीज से विभाजित किया जा सकता है, इस पर मतदान कराने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मतभेद पैदा हो सकें। वह संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को भी अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है। उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य लक्ष्यों और गुप्तचर जानकारी संग्रह को वित्तपोषित करने और आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्टोकरंसी लूट और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने वाले हमलों को बढ़ा दिया है। इसने अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए एआई का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है।

सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने चीन द्वारा एआई का इस्तेमाल कर भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में चुनावों को बाधित करने की आशंका से संबंधित जो चेतावनी जारी की है, वह चिंताजनक है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के अनुसार, चीन आगामी प्रमुख चुनावों में विशेष रूप से अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एआई द्वारा बनाई गई सामग्री का इस्तेमाल कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एनालिसिस सेंटर (एमटीएसी) की रिपोर्ट इस आसन्न खतरे को रेखांकित करती है कि 'इस साल दुनिया भर में होने वाले प्रमुख चुनावों को देखते हुए, खासकर भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में, चीन अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए एआई जनरेटर सामग्री बनाएगा और उसका प्रचार करेगा।'

माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चीन के कथित ट्रायल रन की खबरों के बाद आई है, जहां उसने जनवरी में एआई द्वारा बनाई सामग्री के जरिये दुष्प्रचार का प्रयास किया था। रिपोर्ट में स्टॉर्म 1376 नामक एक बीजिंग समर्थित समूह का उल्लेख है, जिसे स्पैमोफ्लाज या ड्रैगन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो ताइवानी चुनाव के दौरान अत्यधिक सक्रिय था। यह राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए चीन द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामले का अध्ययन करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तकनीकी हस्तक्षेप की क्षमता को रेखांकित करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाई गई सामग्री जनमत को प्रभावित करने के लिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठा सकती है। माइक्रो टार्गेटिंग और भावनात्मक संदेश जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर, एआई एल्गोरिदम इको चेंबर बना सकता है, जो मौजूदा विश्वासों को मजबूत करता है और समाज को ध्रुवीकृत करता है। इसके अलावा, 'डीपफेक' तकनीक का उदय सूचना के पारंपरिक स्रोतों में विश्वास को कम करते हुए, तथ्य और कल्पना के बीच की बारीक रेखा को धुंधला कर एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है।

सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एआई सामग्री के दुरुपयोग को रोकने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, इंटरनेट की सीमाहीन प्रकृति क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों को जटिल बनाती है, जिससे दुर्भावनापूर्ण लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार बिना किसी दंड के काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी नवाचार की तीव्र गति विनियामक प्रयासों से आगे निकल जाती है, जिससे नीति निमार्ताओं के लिए उभरते खतरों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, एआई सामग्री निर्माण और प्रसार का विकेन्द्रीकृत स्वरूप पारंपरिक प्रवर्तन रणनीतियों में बाधा डालता है, जिसके लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। डिजिटल युग में लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए चीन द्वारा एआई-जनरेटर सामग्री के संभावित उपयोग से प्रौद्योगिकी और राजनीति के बीच जटिलता स्पष्ट होती है। ताइवान जैसे अन्य देशों के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि तकनीकी हस्तक्षेप दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को मजबूत विनियामक ढांचा विकसित करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और चुनावों की सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसा करने में विफलता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करेगी और नागरिकों का अपने राजनीतिक संस्थानों पर भरोसा कम हो सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

विरासत टैक्स व निजी सम्पत्ति सर्वे मामलाः संकट में कांग्रेस

ललित गर्ग

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच जिस तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं, उनमें देश विकास से अधिक मुक्त की रेवड़िया बांटने या अतिश्योक्तिपूर्ण सुविधा देने की बातें हैं तो विरासत टैक्स के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई को हड़पने के सुझाव है। ऐसी विरोधीभासी सोच एवं योजनाएं कांग्रेस की अपरिपक्व एवं स्वार्थप्रेरित राजनीति को ही उजागर करती है। इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राहुल गांधी के विश्वस्त सलाहकार सैम पित्रोदा ने चुनावी समर में अपने ताजा बयान में विरासत टैक्स की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका में लागू इस टैक्स की पैरवी करते हुए भारत के लिये उपयोगी बताया। सैम ने अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख सफाई दी है, तो कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन राजनीति की इन कुचालों एवं ऐसे बयानों में कांग्रेस का इरादा जनता की मेहनत की कमाई की संगठित लूट और वैध लूट ही नजर आता है। सैम पित्रोदा के बयान में कांग्रेस की सोच एवं संकल्प ही नहीं दिखा बल्कि कांग्रेस की भावी योजनाओं की परतें भी खुली है। भले ही इस बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हो, लेकिन जनता को मूर्ख समझ हर बार हंगामा खड़ा करना कांग्रेस की नीति एवं नियत रही है। सैम ऐसे ही विवादास्पद बयानों से पूर्व में भी चर्चा में रहे हैं।

अमेरिका में विरासत टैक्स जैसी अनेक स्थितियां एवं कानून हैं जो भारत में नहीं है क्योंकि हर देश की अपनी स्थितियां होती है। सैम के इस बयान ने इसलिए तूल पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के सर्वे का वादा किया है। इसकी व्याख्या भाजपा पहले से ही इस रूप में कर रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का आकलन करके संपन्न-सक्षम लोगों की संपदा का एक हिस्सा लेने का इरादा रखती है। चूंकि सैम पित्रोदा का कथन कुछ इसी ओर संकेत करता दिख रहा था, इसलिए भाजपा ने नए सिरे से उनके बयान को मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो कहा जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे, तब आप पर विरासत का बोझ लाद देगी। कांग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी कह कर मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कह दिया कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने का नहीं सोच रही है, जैसा सैम पित्रोदा कह रहे हैं तो वह अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वेक्षण वाली बात हटाए। निश्चित ही कांग्रेस की संपत्ति के सर्वेक्षण की बात में गहरे अर्थ, संदेह एवं शंकाएं निहित हैं। राजननेताओं के बयानों पर राजनीति होना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन जनता के हितों पर आघात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतन्त्र में सतत रूप से अमीर-गरीब का विमर्श चलता रहता है, गरीबों के हित की बात करके अधिसंख्य मतदाताओं को लुभाना राजनीतिक चतुराई है, लेकिन जनता को बांटना एवं अलग-अलग खेमों में खड़ा करना, लोकतंत्र को कमजोर करता है। मगर भारत का मतदाता अब इतना सुविज्ञ एवं समझदार हैं कि वे राजनेताओं की मंशा को समझकर उस समय आगे बढ़कर नेतृत्व खुद संभाल लेते हैं जब नेतागण अपना पथ भूल जाते हैं।

भारत के चुनावों का इतिहास इसका गवाह रहा है। इसलिए राजनैतिक विमर्श चाहे जितना गर्त में चला जाये मगर मतदाता की सूझबूझ, जागरूकता एवं विवेक कभी मंद नहीं पड़ती।भले ही सैम पित्रोदा अमेरिका का उदाहरण देकर उस पर भारत में बहस की जरूरत जता रहे थे, लेकिन उन्हें गलत समय ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए था, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह भारत की परिस्थितियों के लिये सही न हो और जिसके विवाद का विषय बनने की भरी-पूरी संभावनाएं हो। यह तो कांग्रेस ही जाने कि वह संपत्ति के सर्वे के जरिये क्या हासिल करना चाहती है, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि देश में आर्थिक असमानता कम करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी इस आवश्यकता की पूर्ति न तो वामपंथी सोच वाले तौर-तरीकों से की जा सकती है और न ही उन उपायों से, जो समाज में विभाजन पैदा करें। जो भी निर्धन-वंचित हैं या सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछडे. हैं, उनके उत्थान की अतिरिक्त चिंता की जानी चाहिए, लेकिन बिना उनका जाति, मजहब देखे, बिना विभाजन की राजनीति को किये।

सैम पित्रोदा, राजनीति की दुनिया में यह नाम कोई नया नहीं है, कांग्रेस के शासन में तकनीकी एवं आधुनिक विकास के वे पुरोध रहे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके पित्रोदा इस समय राहुल के खास लोगों में से एक हैं। पित्रोदा अपने काम से कम अपने बयानों के चलते ज्यादा चर्चे में रहते हैं। उनके बयान अक्सर कांग्रेस के लिए भी सरदर्द बनते रहे हैं। पित्रोदा के अनेक बयान पहले भी विवाद एवं कांग्रेस के सिरदर्द की वजह बन चुके हैं। साल 2019 में ही उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मध्यमवर्गीय परिवार को रोजगार और अधिक अवसर मिलेंगे। इस बयान ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थीं और पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था। पित्रोदा यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2019 के ही पुलवामा हमले पर कहा था कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था। निश्चित ही कांग्रेस के शासन में ऐसे हमले एवं साम्प्रदायिक दंगे होते ही रहते थे। उन्होंने बालाकोट एयरस्ट्राइक ऑपरेशन पर सबूत मांगे थे। सैम पित्रोदा के बयान एवं कांग्रेस के घोषणा पत्र के निजी सम्पत्ति सर्वे की बात में अवश्य ही

अमेरिका में विरासत टैक्स जैसी अनेक स्थितियां एवं कानून हैं जो भारत में नहीं है क्योंकि हर देश की अपनी स्थितियां होती है। सैम के इस बयान ने इसलिए तूल पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के सर्वे का वादा किया है। इसकी व्याख्या भाजपा पहले से ही इस रूप में कर रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का आकलन करके संपन्न-सक्षम लोगों की संपदा का एक हिस्सा लेने का इरादा रखती है। चूंकि सैम पित्रोदा का कथन कुछ इसी ओर संकेत करता दिख रहा था, इसलिए भाजपा ने नए सिरे से उनके बयान को मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो कहा जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे, तब आप पर विरासत का बोझ लाद देगी। कांग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी कह कर मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कह दिया कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने का नहीं सोच रही है, जैसा सैम पित्रोदा कह रहे हैं तो वह अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वेक्षण वाली बात हटाए। निश्चित ही कांग्रेस की संपत्ति के सर्वेक्षण की बात में गहरे अर्थ, संदेह एवं शंकाएं निहित हैं।

रिश्ता है, जिसने पूरे देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है कि निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर वह इस धन को अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। ऐसी योजना यूपीए सरकार में तय भी हुई थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और उसमें भी सबसे अधिक मुस्लिमों का है, उस प्रकार से कांग्रेस की यह मुसलमानों को लुभाने एवं उन्हें लाभ पहुंचाने की अघोषित चुनावी घोषणा है, इस तरह की घोषणाएं लोकतंत्र में सुशासन एवं राजनीति मूल्यों को धुंधलाने की कुचेष्टा ही कही जायेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता बादशाह नहीं होता बल्कि साधारण मतदाता बादशाह होता है क्योंकि उसके ही एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मतदाता को जो मूर्ख समझते हैं उनसे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं होता। ऐसे तथाकथित बयानों से भारत में संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र कभी भी प्रभावित नहीं होगा, वह सफल रहा है और रहेगा क्योंकि भारत के लोग अनपढ़ व गरीब हो सकते हैं मगर वे अज्ञानी या मूर्ख नहीं है। उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत मजबूत होता है और वे राजनीतिक दलों के भ्रम में नहीं आने वाले, गुमराह नहीं होने वाले। यह सच है कि जब से भारत में जातिवादी, क्षेत्रवादी, भाषावादी, वर्गवादी व सम्प्रदायवादी राजनीति का बोलबाला हुआ है तभी से राजनीति के विमर्श में गिरावट आनी शुरू हुई है, लेकिन इस गिरावट को संभालने के लिये मतदाता को अधिक परिवक्व एवं समझदार होने की अपेक्षा है।

लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी कह कर मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कह दिया कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने का नहीं सोच रही है, जैसा सैम पित्रोदा कह रहे हैं तो वह अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वेक्षण वाली बात हटाए। निश्चित ही कांग्रेस की संपत्ति के सर्वेक्षण की बात में गहरे अर्थ, संदेह एवं शंकाएं निहित हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 61

उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा

बीते कुछ दशकों की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चमकदार पहलू रहा है सेवा निर्यात की गति। इसने न केवल कारोबारी अंतर को थामे रखने में मदद की है बल्कि यह देश में रोजगार निर्माण का स्रोत भी रहा है। इनमें उच्च कौशल वाले रोजगार शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में देश की सफलता को देखते हुए इस बात का परीक्षण करना सही होगा कि वैश्विक स्तर पर हम कहां हैं और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा मासिक बुलेटिन में प्रकाशित एक शोध आलेख कहता है कि पिछले तीन दशकों में यानी 1993 से 2022 के बीच डॉलर के संदर्भ में भारत का सेवा निर्यात 14 फीसदी से अधिक की समेकित सालाना वृद्धि दर से बढ़ा। यह 6.8 फीसदी की वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि की तुलना में काफी अच्छा है। इसके परिणामस्वरूप समान अवधि में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.5 फीसदी से बढ़कर 4.3 फीसदी जा पहुंची। इसकी बदौलत भारत दुनिया में सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया। 2001 में भारत 24वें स्थान पर था।

फिलहाल दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे और सांस्कृतिक तथा मनोरंजक सेवा निर्यात में छठे स्थान पर है। भारत को तकनीकी प्रगति और उसे अपनाने से फायदा हुआ है। भारत के कामकाजियों में अंग्रेजी बोलने वाले लोग अच्छी खासी तादाद में हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अनेक प्रतिभाएं हैं। इसके अलावा घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और नीतिगत ध्यान ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी और उससे संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में अहम वैश्विक हिस्सेदारी हासिल करने में मदद की है। यह बात बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की स्थापना के कारण भी महसूस की जा सकती है। 2015-16 से 2022-23 तक भारत में जीसीसी की संख्या 60 फीसदी बढ़कर 1,600 से अधिक हो चुकी है। दुनिया भर में डिजिटल तकनीक को अपनाने का सिलसिला बढ़ा है और भारत भी साफ तौर पर इससे लाभान्वित हुआ है। डिजिटल आपूर्ति वाली सेवाओं के निर्यात में 2019 से 2022 के बीच 37 फीसदी का इजाफा हुआ और यह भारत के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। तकनीकी क्षेत्र से इतर भारत का यात्रा निर्यात भी मजबूत रहा है, हालांकि वह अभी भी महामारी के असर से जूझ रहा है और इसमें आंशिक हिस्सेदारी पर्यटन की भी है। भारत ने परिवहन सेवा निर्यात में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और आय के मामले में इसकी रैंक 2005 के 19वें से सुधरकर 2022 में 10वीं हो गई है।

भारत ने वैश्विक सेवा व्यापार में प्रतिस्पर्धी क्षमता भी प्रदर्शित की है, खासतौर पर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में। परंतु सवाल यह है कि क्या मध्यम से दीर्घ अवधि के दौरान यह मजबूती बरकरार रहेगी? भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के शोध ने दिखाया है कि बाहरी मांग और मूल्य प्रतिस्पर्धा सेवा निर्यात को बहुत अधिक प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में एक फीसदी का इजाफा देश के सेवा निर्यात में 2.5 फीसदी बढ़ोतरी लाता है। इसके अलावा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में एक फीसदी इजाफा वास्तविक सेवा निर्यात में 0.8 फीसदी की गिरावट ला सकता है। चूंकि वैश्विक आर्थिक वृद्धि के आने वाले वर्षों में अपेक्षाकृत कमजोर रहने की आशंका है ऐसे में सेवा निर्यात को भी प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ सकता है। हालिया विश्लेषण बताता है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं। ऐसा भूराजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण हुआ है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए भी चुनौती बन सकता है। इतना ही नहीं भारत के लिए आर्टिफिशल इंटेलीजेंस खतरा भी है और अवसर भी। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह मध्यम अवधि में सेवा व्यापार को कैसे प्रभावित करेगी। भारत को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है लेकिन उसे अपने निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

बिनय सिन्हा

रोजगार और साझी समृद्धि की दिशा में काम जरूरी

एक तरफ देश लगातार आर्थिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ देश में असमानता का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। विस्तार से बता रहे हैं अजय छिब्बर

प्रतिष्ठित उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने एक दफा कई लोगों को चौंकाते हुए कहा था, 'मैं नहीं चाहता कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने, मैं चाहता हूं कि यह एक खुशहाल मुल्क बने।' भारत को 'विश्व खुशहाली रिपोर्ट' 2024 में 143 देशों में 126वां स्थान दिया गया है- यानी इसे बहुत खुशहाल देश नहीं माना गया है। विडंबना यह है कि भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की बहुत संभावना है। इस दशक के समाप्त होने तक अगर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सात फीसदी सालाना की दर से बढ़ता रहा तो हम जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इतना ही नहीं अगर 2021 की कीमतों पर हमारी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 14,000 डॉलर तक पहुंच गई (उच्च आय वाला देश बनने के लिए विश्व बैंक द्वारा तय सीमा) तो 2047 तक हमारा देश 21 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मौजूदा आकार है यानी हम यकीनी तौर पर एक आर्थिक महाशक्ति होंगे।

परंतु केवल आय लोगों को खुशहाल नहीं बनाती। दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, अमेरिका जिसका मंत्र है, 'जीवन, आज़ादी और खुशी की तलाश', वह खुशहाली सूचकांक में 23वें स्थान तक गिर गया है। प्रसन्न होने के लिए भारत को न केवल जीडीपी में इजाफा करने की आवश्यकता है बल्कि उसे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, असमानता में कमी तथा सामाजिक एकता की भी जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) आय, स्वास्थ्य (जीवन संभाव्यता) और शिक्षा (साक्षरता और विद्यालयीन शिक्षा) का आकलन करता है और उसमें भारत 190 देशों में 132वें स्थान पर है जो काफी कम है। महामारी के झटके के बाद भी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जीडीपी के 1.3 फीसदी के बराबर के मामूली स्तर पर है। शिक्षा पर होने वाला सरकारी व्यय बढ़कर जीडीपी के करीब 5 फीसदी के बराबर हुआ है और बच्चियों समेत ज्यादा लोग स्कूल जा रहे हैं। परंतु सीखने का स्तर कमजोर बना हुआ है और अधिकांश युवा कौशल विहीन हैं तथा बुनियादी काम करना भी नहीं जानते।

ऐसे में खतरा यह है कि कहीं भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक त्रासदी में न बदल जाए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ताजातरीन रोजगार रिपोर्ट देश में रोजगार की निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। खासतौर पर युवाओं के लिए। माध्यमिक और हाईस्कूल तक की शिक्षा पाने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या 2000 के 35.2 फीसदी से बढ़कर 2022 में 65.7 फीसदी हो गई। विश्व बैंक कहता है कि रोजगार के अनुपात में गिरावट आ रही है। कृषि रोजगार में कमी आनी चाहिए थी लेकिन उसमें इजाफा हो रहा है। बीते पांच वर्ष में इसमें छह करोड़ का इजाफा हुआ है। जिन लोगों को खेतों के बाहर काम मिला उन्हें मोटे तौर पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में दिहाड़ी पर काम करने का ही मौका मिला। परंतु यहां भी लैंगिक स्तर पर काफी भेदभाव दिखता है। अरब क्रांति ने हमें दिखाया था कि शिक्षा और बेरोजगारी का मिश्रण बहुत उथलपुथल ला सकता है। सरकार की प्रतिक्रिया यही है कि रोजगार तैयार करना उसका काम नहीं है। निजी क्षेत्र को रोजगार तैयार करने चाहिए लेकिन जटिल श्रम कानूनों और पुराने पड़ चुके नियमन की वजह से जमीन लगातार महंगी होते जाने के कारण तथा कारोबारी सुगमता की अन्य लागत के महंगा होने के कारण निजी क्षेत्र उच्च तकनीक और पूंजी के इस्तेमाल वाले क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है न कि कम कौशल वाले विनिर्माण क्षेत्र में जहां ढेर सारे कम पढ़े-लिखे लोग नौकरी तलाश करते हैं। कई कंपनियां अपना काम छोटी कंपनियों को सौंप देती हैं जो कम कुशल दैनिक श्रमिकों से काम कराती हैं। तकनीकी क्षेत्र के रोजगार बढ़ रहे हैं लेकिन वे हर वर्ष श्रम योग्य आबादी में शामिल हो रहे एक करोड़ युवाओं की रोजगार की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। सरकार की औद्योगिक नीति की पीएलआई सब्सिडी कम श्रम गहन क्षेत्रों पर केंद्रित है। ऐसे में रोजगार की कमी चौंकाती नहीं है।

गरीबी में तो कमी आई है लेकिन असमानता की स्थिति अस्पष्ट है। परिवार खपत सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़े दिखाते हैं कि खपत असमानता में 2011-12 के सर्वे की तुलना में कम हुई है। एक बार पूरे आंकड़े सामने आने के बाद यह पुष्टि होगी कि उनकी तुलना हो सकती है या नहीं। चाहे जो भी हो खपत की कम रिपोर्टिंग उच्च स्तर पर स्पष्ट रूप से असमानता को कम दर्शाती है। वर्ल्ड इनेक्विलिटी लैब का 'द बिलियनेयर राज' नामक एक नया अध्ययन बताता है कि भारतीयों की आय और संपत्ति की असमानता दुनिया में सर्वाधिक असमानताओं में शामिल है और आबादी के एक फीसदी हिस्से के पास 22.6 फीसदी आय और 40.1 फीसदी संपत्ति है। भारत में असमानता का स्तर चीन और अमेरिका से अधिक तथा दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समकक्ष है। अगर आरोपों के मुताबिक यह मान भी लिया जाए कि वर्ल्ड इनेक्विलिटी लैब के आंकड़े बढ़ाचढ़ाकर पेश किए गए हैं तो भी इस बात में संदेह नहीं है कि भारत में असमानता का स्तर काफी अधिक है। यूएनडीपी दिखाता है कि एचडीआई, जहां भारत पहले ही काफी पीछे है, उसमें जब असमानता को शामिल किया जाता है तो भारत के लिए इसमें 31 फीसदी की और गिरावट आती है। हुरुंस की वैश्विक अमीरों की सूची के मुताबिक भारत में 271 अरबपति हैं। अगर तुलना करें तो जर्मनी में 140 और जापान में 44 अरबपति हैं। इन सभी देशों का जीडीपी भारत से अधिक है।

कुछ लोगों की दलील है कि अधिक अरबपतियों का होना इस बात का संकेत है कि भारत बड़े पैमाने पर ऐसी कंपनियां तैयार कर रहा है जिनमें कोरिया और जापान की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की क्षमता है। वे एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला तैयार करती हैं जहां छोटी कंपनियां समृद्ध होती हैं। परंतु हमने लैटिन अमेरिका में देखा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाकर रखी गई ऐसी बड़ी कंपनियां तब बड़ी बाधा बनकर सामने आती हैं जब वे राजनीति और इस प्रकार नियमन को प्रभावित करने में सक्षम हो जाती हैं। नवाचार की कमी और नियमन को यूं प्रभावित करने वाली कंपनियों के कारण लैटिन अमेरिका मध्य आय के जाल में फंस गया। अब भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियों के साथ कोरिया और जापान की राह पर जाएगा या संरक्षित बाजारों के साथ लैटिन अमेरिका की राह पर यह देखना होगा। संरक्षित बाजारों में उपभोक्ताओं को उच्च मार्जिन चुकाना होता है और देश मध्य आय के जाल में उलझ सकता है।

महंगी और विलासितापूर्ण शादियों तथा 'नव धनाढ्यों' द्वारा संपत्ति के अशोभनीय प्रदर्शन के साथ भारत की बढ़ती असमानता साफ नजर आ रही है। कुछ लोग इसे अच्छा संकेत मानते हैं और उनके मुताबिक यह इस बात का प्रतीक है कि धन अब तिरस्कृत नहीं बल्कि सम्मानित है। अगर इनके साथ बेहतर और अधिक रोजगार हों तथा समृद्धि साझा की जाए तो हम सभी इस नए उभरते भारत का जश्न मना सकते हैं। नई 'कल्याणकारी' व्यवस्था जहां गरीबों को निःशुल्क अनाज, गैस सिलिंडर, निःशुल्क बिजली और पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, वे कुछ चुनाव जीतने में मदद कर सकते हैं लेकिन बिना अधिक रोजगार तैयार किए हम 'विकसित' भारत नहीं बना सकते। भारत के विकास मॉडल में गंभीर सुधार की जरूरत है क्योंकि अगर असमानता एक बार पैबस्त हो गई तो उसे दूर करना मुश्किल होगा। हम समृद्ध भारत के साथ-साथ समावेशी भारत चाहते हैं ताकि भारत वैसा खुशहाल देश बन सके जैसा जे.आर.डी. चाहते थे।

ओडिशा, आंध्र के चुनाव राजनीति के लिए खास

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बीजू जनता दल (बीजद) के अगले संभावित प्रमुख एवं पूर्व अधिकारी वी के पांडियन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि 'गठबंधन को लेकर होने वाली बातचीत राजनीतिक सूझबूझ' पर आधारित होती हैं। पांडियन का यह वक्तव्य बीजद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों में गठबंधन पर बातचीत अटकने और बाद में असफल रहने से ठीक पहले आया था। ओडिशा में 13 मई को विधान सभा और लोक सभा चुनाव होने हैं। मगर गठबंधन पर बातचीत टूटने का असर बीजद और भाजपा के शीर्ष नेताओं की राजनीतिक समझ-बूझ पर पड़ता नहीं दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दोनों में किसी ने भी सार्वजनिक सभाओं में एक दूसरे की आलोचना नहीं की है। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है तो पटनायक ने अपने काम के आधार पर लोगों से बीजद के पक्ष में वोट देने का अनुरोध किया है।

हालांकि, राज्य भाजपा का प्रचार अभियान आक्रामक रहा है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने पांडियन पर हमला करने से गुरेज नहीं किया है और उन्हें 'भ्रष्टाचार का चेहरा' तक करार दिया है। मगर दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं ने चुनाव बाद साथ आने के द्वार पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। हालांकि, पांडियन को लेकर भाजपा असहज दिख रही है। यह अटपटा लगता है न? मगर ओडिशा के मतदाताओं से पूछें तो उनका नजरिया शीशे की तरह साफ है। राज्य के मतदाताओं ने विधान सभा और लोक सभा चुनाव में अलग-अलग अंदाज में मतदान किए हैं। ओडिशा में लोक सभा की 21 सीटें हैं। 2014 के चुनाव में बीजद ने 20 सीटें जीती थी और भाजपा को झोली में केवल 1 सीट आई थी। वर्ष 2009 में बीजद को 12 और भाजपा को 9 सीटें मिलीं।

मगर 2019 में भाजपा लोक सभा में मिले समर्थन को विधान सभा चुनाव में सीटों में नहीं बदल पाई। बीजद को कुल 147 सीटों में 112 पर सफलता मिली। भाजपा को केवल 23 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। बीजद को भाजपा से 12 प्रतिशत अधिक मत प्रतिशत मिले। नतीजे मन माफिक नहीं रहे लेकिन भाजपा ने इस तटवर्ती राज्य में एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली। चुनाव आंकड़ों का गहन अध्ययन करें तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। उदाहरण के लिए भुवनेश्वर लोक सभा सीट पर विचार करते हैं। इस सीट पर भाजपा की अपराजिता सारंगी ने बीजद के अरूप पटनायक को 30,000 वोट से पराजित कर दिया। इसके बाद भी भाजपा एक भी विधान सभा क्षेत्र में जीत नहीं दर्ज कर पाई और एक सीट पर तो कांग्रेस बाजी मार गई। जयदेव विधान सभा क्षेत्र में यह तीसरे स्थान पर रही और बीजद और इसके बीच 40,000 मतों का अंतर रहा! विधान सभा चुनाव में इतना बड़ा अंतर साधारण तो नहीं होता। भुवनेश्वर-उत्तर में बीजद का उम्मीदवार 25,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत गया। एकामरा भुवनेश्वर सीट पर बीजद ने लगभग 50,000 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। भुवनेश्वर-मध्य, खोर्धा और बेगुनिया विधान सभा सीटों पर भी बीजद ने प्रभावी जीत दर्क की। भाजपा इनमें कहीं भी टक्कर देने की स्थिति में नहीं थी।

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

बारगढ़ जैसे दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में भी यही स्थिति रही। यहां एक बड़ी बात साफ झलक रही है कि ओडिशा के मतदाताओं का नजरिया विधान सभा और लोक सभा चुनावों को लेकर साफ रहा है और दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं दिखी है। विधान सभा में यहां के मतदाता बीजद को वोट देते हैं और लोक सभा में भाजपा को समर्थन देते हैं और पूरी तरह समझते हैं कि किन चुनाव में किसे जीत का ताज पहनाना चाहिए। इसे लेकर उनके मन में कोई उलझन नहीं है।

मगर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में ऐसी बात नहीं दिखती है। यहां भी 2029 की तरह विधान सभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ होंगे। 2019 में जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य विधान सभा चुनाव में कुल 175 सीटों में 151 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। लोक सभा चुनाव में पार्टी को 25 में 22 सीटें मिलीं। उस समय मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) को केवल 3 सीटें मिलीं। वहां के मतदाताओं के बीच विकल्प एक ही था। आंध्र प्रदेश के लोग जगन को ही दोनों चुनावों में जीत का ताज पहनाना चाहते थे।

यहां एक बात तो जरूर मन में उठती है। आखिर, मतदाताओं के इस सोच के पीछे क्या वजह हो सकती है। कल्याणकारी योजनाओं के मोर्चे पर जगनमोहन रेड्डी एवं वाईएसआर कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है, यह अलग बात है कि राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। उनके सांसद लगातार आंध्र प्रदेश से जुड़े विषय उठाते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा सेला चावल नहीं खरीदने के निर्णय ने राज्य में भारी उथल-पुथल मचाई है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। इसके उलट बीजद के सांसद शालीन रहे हैं और राज्य में भाजपा के प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद केंद्र में सरकार के साथ खड़े हैं।

नवीन पटनायक लोगों में काफी लोकप्रिय हैं, खासकर महिला मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। यह भी माना जा रहा है कि यह पटनायक का अंतिम चुनाव हो सकता है, इसलिए लोग उन्हें राज्य के हक में समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मगर इस बार लोक सभा में भाजपा बीजद को पीछे छोड़ सकती है।

आंध्र प्रदेश में जिस टीम-उनकी माता, बहन वाईएस शर्मिला- ने जगन को जीत दिलाई वह बिखर चुकी है। शर्मिला कडप्पा लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। जगन को यह स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि उनकी बहन को क्यों उनका साथ छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा बनने की चाहत रखने वाली तेदेपा ने भाजपा और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी (जेएसपी) के साथ गठबंधन तैयार किया है। तेदेपा राज्य में 17 लोक सभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जबकि भाजपा और जेएसपी दोनों ही 2-2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी। विधान सभा में तेदेपा 144, भाजपा 10 और जन सेना 21 विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

क्या आंध्र प्रदेश ओडिशा का अनुसरण करेगा और लोक सभा और विधान सभा में अलग-अलग दलों को समर्थन देगा? या फिर ओडिशा आंध्र प्रदेश की राह पर चलेगा और विधान सभा और लोक सभा में इस बार कुछ नया कर दिखाएगा? परिणाम जो भी हो, वे भारतीय राजनीति के लिए उसके बड़े मायने होंगे।

आपका पक्ष

चुनावी चंदा जरूरी, मगर पूर्ण पारदर्शिता के साथ

चुनावी बॉन्ड के जरिये दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण अभी तक सामने आया है, उससे दो चिंताजनक पहलू उजागर हुए हैं। एक तो यह कि जो कंपनियां प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग की जांच का सामना कर रही थीं, उन्होंने भी चंदा दिया। दूसरा यह कि कुछ ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया जो घाटे में चल रही थीं। ये दोनों पहलू संदेह पैदा करते हैं। इस संदेह का निवारण होना चाहिए कि कहीं व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए तो चंदा नहीं दिया गया। अतः यह आवश्यक है कि चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी हो और जनता को यह जानकारी मिल सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि चंदे की प्रक्रिया साफ-सुथरी होगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब आवश्यक यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे ऐसे सवाल न उठने पाएं जैसे चुनावी बॉन्ड को लेकर उठे। चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा देने की व्यवस्था को खत्म करने के साथ ही कोई नई पारदर्शी व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इसका अंदेशा हो गया है कि कहीं चंदा देने का पुराना तौर-तरीका ही फिर से न चलन में आ जाए जिसमें किसी को इस बात का कुछ पता ही नहीं चलता था कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। राजनीति को काले धन से परे रखने के हरसंभव जतन किए जाने चाहिए। चुनावी चंदे की नई व्यवस्था में यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी दल या सरकार किसी कारोबारी पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल कर सके। इसी के साथ कारोबारियों को स्वेच्छा से और अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को चंदा देने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। चुनावी चंदे को पारदर्शी व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपारदर्शी तरीके से चंदे के लेन-देन से राजनीतिक दलों की तो बदनामी होती ही है, भारतीय लोकतंत्र की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

लोक सभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को मेरठ में पहली बार मतदान करने के बाद उत्साहित युवा

एआई में पिछड़ने का जोखिम नहीं ले सकता भारत

आर्टिफिशल इंटेलीजेंस (एआई) में निरंतर अग्रणी रहने के लिए बड़े शोधों और संसाधनों की आवश्यकता के लिए सरकार को पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में तो आगे-पीछे रहना चल सकता है। चीन जैसे देश एआई का सर्वाधिक उपयोग रक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं और संभावना है कि एआई के जरिये चीन अंतरिक्ष में भी युद्ध की संभावनाएं खोज रहा है। भारत के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन हमारी प्रतिभा का सर्वाधिक उपयोग विकसित देश कर रहे हैं। एआई के शोध में भी कई देशों में भारतीय वैज्ञानिक ही सहयोग कर रहे हैं। भविष्य की प्रगति का सबसे प्रमुख कारक आर्टिफिशल इंटेलीजेंस के उपयोग से अधिकाधिक क्षेत्र में न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के शोध करने होंगे और एआई में पिछड़ने का मतलब है आर्थिक, सामरिक, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में पीछे रह जाना।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पहले दीक्षांत समारोह में शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (दाएं) को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 27 अप्रैल 2024

स्त्री धन पर दो टूक

सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किए अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा है कि स्त्री धन पूरी तरह महिला की संपत्ति होती है, जिस पर पति का कोई हक नहीं होता। हालांकि हिंदू लॉ की यह पोजिशन पहले से स्पष्ट है और इस लिहाज से फैसले को नया नहीं बताया जा सकता, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज की तारीख में न केवल कानूनी हलकों में बल्कि सामाजिक संदर्भों में भी काफी अहमियत रखता है।

संयुक्त संपत्ति नहीं | सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह बात और स्पष्ट हो गई है कि स्त्री धन को पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। स्त्री धन का मतलब उस धन, संपत्ति, गहने-जेवर या रकम से है, जो शादी के समय लड़की को या लड़के और लड़की को दिया जाता है। आम तौर पर परिवार इसे अपनी संपत्ति के रूप में देखता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना महत्वपूर्ण है कि अगर किसी संकट के दौरान पति इस धन का इस्तेमाल करता है तो यह उसका नैतिक दायित्व है कि वह धन या उसके बराबर रकम पत्नी को वापस करे।

AI image

न बढ़े प्रतिक्रियावादी रुझान

फैसले की टाइमिंग | यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब कई अन्य फैसलों की बदौलत और महिलाओं की बढ़ती जागरूकता के कारण भी, समाज में स्त्री-पुरुष संबंधों का सदियों से चला आ रहा समीकरण बदल रहा है। महिलाएं घर से निकल कर हर क्षेत्र में अपना दखल बढ़ा रही हैं। परिवार के अंदर भी पैतृक संपत्ति में अपना जायज हिस्सा मांग रही हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में फैसले लेने की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदारी कर रही हैं।

टकराव के आसार | इन सबका एक साइड इफेक्ट यह है कि पुरुषों के एक हिस्से में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बेचैनी का अहसास बढ़ा है। कहीं यह उनमें बढ़ते असुरक्षा बोध के रूप में सामने आता है तो कहीं महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने की प्रवृत्ति के रूप में।

सीमित न हों अधिकार | ऐसे में यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज का बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस रूप में देखता है। चूंकि स्त्री धन और उस पर मालिकाना पारंपरिक तौर पर ही स्त्रियों का माना जाता रहा है, इसलिए समाज में प्रचलित पारंपरिक सोच का एक रिएक्शन यह भी हो सकता है कि इस फैसले का स्वागत करते हुए लड़कियों के अधिकारों को वहीं तक सीमित करने की कोशिश की जाने लगे।

बदलते रुझान पर हो नजर | कानूनी तौर पर तो लड़कियों के सारे अधिकार सुरक्षित हैं। अदालतें इस मामले में सतर्क भी हैं। लेकिन समाज में इस फैसले की आड़ में प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी सोच हावी न हो, इसे लेकर सावधानी बरतने की खास जरूरत है।

'47 का ट्रॉमा निर्मल में हमेशा रहा

Trauma

हिंदी के प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा का पाठक वर्ग उनकी मृत्यु के 18 साल बाद भी लगातार बढ़ता ही रहा है। कोई इसका कारण आधुनिक एकांत से जूझती उनकी कहानियों में तलाशता है तो कोई मानवीय संबंधों की पड़ताल करते उनके उपन्यासों में। हाल ही में राजकमल प्रकाशन ने 'थिगलियां' शीर्षक से उनकी असंकलित कृतियों की एक नई किताब प्रकाशित की है। इस किताब के साथ-साथ निर्मल वर्मा के सृजन संसार के अन्य पक्षों पर ***प्रियंका दुबे*** *ने उनकी पत्नी और सुपरिचित कवि-गद्यकार गगन गिल से बात की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश :*

सप्ताह का इंटरव्यू

गगन गिल

■ तकरीबन 24 वर्ष बाद निर्मल वर्मा का नया फिक्शन 'थिगलियां' संग्रह के जरिए पाठकों के बीच आया है। इसके बारे में थोड़ा बताएं।

इस संग्रह में प्रकाशित कुछ कहानियां मुझे खुद मिलीं, जबकि कुछ के लिए मित्रों ने सहयोग किया। मसलन, कुछ कहानियां बहुत पुरानी थीं और उन्हें मैगजीन के पुराने अंकों को फाड़कर मित्रों ने उपलब्ध कराया। हर लेखक अपने करियर के शुरुआती दौर में इतनी सावधानी तो रखता ही है कि उसका सबसे सशक्त काम ही सामने आए। इसलिए जिन कृतियों के बारे में वह मानता है कि वे उसके काम का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं या जो कमजोर हैं, उन्हें वह प्रकाशित नहीं कराता। शायद इसलिए निर्मल जी ने इन कहानियों को अपने पहले संग्रह में नहीं रखा होगा। लेकिन जब मेरी निगाह में वो चार पुरानी कहानियां आईं, तब मुझे वो सारी एक से बढ़कर एक लगीं। खासतौर पर 'थिगलियां' को लेकर मुझे यह समझ नहीं आया कि इतनी संतप्त कहानी उन्होंने तब अपने संग्रहों में रखी क्यों नहीं! मेरा ख्याल है कि शायद यह उनका कलात्मक आग्रह होगा क्योंकि हमें तो इस कहानी में कोई कमजोरी नजर नहीं आई।

■ आपने इसकी भूमिका लिखी है, इसमें मौजूद सामग्री को संकलित भी किया है और साथ ही किताब के अंत में कुछ नोट्स भी लिखे हैं..

यह भूमिका और नोट्स लिखने में मुझे संकोच था, क्योंकि निर्मल जी के साथ मैं स्वयं को बहुत अजीब स्थिति में पाती हूं। वह मेरे पति थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनके लेखन पर बात करने की अधिकारी नहीं हूं। हालांकि इस बार उनकी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे इतना जरूर लगा कि मैंने इसके लेखक के जीवन को घटते हुए देखा था। तो शायद मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात कर सकती हूं कि जीवन कैसे घट रहा होता है और कहानियां कैसे बनती हैं। बस इसी चीज को मैंने अपने नोट्स और भूमिका में समेटने की कोशिश की है। शायद इससे कोई क्लैरिटी मिले कि साहित्य में कोई भी चीज व्योम में नहीं घटित होती। जो कुछ जीवन में चल रहा होता है, उसी के कुछ अंश छनकर हमारे साहित्य में भी आते हैं। मगर यह कब आते हैं, कैसे आते हैं, यह तो मिस्ट्री है।

■ 'थिगलियां' कहानी में उर्दू और पंजाबी भाषा का गहरा प्रभाव है जो विभाजन के ठीक बाद की दिल्ली की तस्वीर जिंदा कर देती है। इस दृष्टि से यह कहानी उनकी बाकी सभी रचनाओं से एकदम अलग भी दिखाई देती है। क्या उन्होंने एक प्रयोग की तरह इस कहानी के लिए विशेष तौर पर इस भाषा को गढ़ा था?

मुझे लगता है कि इस कहानी का भाषाई वातावरण ही उनके लेखक का असली भाषाई वातावरण था। उनके पिता पटियाला से आए थे, दादा भी लंबे समय तक जीवित रहे तो उनके घर में पंजाबी-हिंदी मिक्स बोली जाती थी। वैसे, निर्मल रचनाओं में अपनी भाषा बहुत बदलते थे। आप देखें कि किसी विदेशी कहानी में उनकी भाषा अलग है और फिर 'अंतिम अरण्य' तक आते-आते उनकी भाषा पहाड़ी हो जाती है। यह एक लेखक के तौर पर उनकी बहुत बड़ी ताकत थी कि वह जिस माहौल, समय और परिस्थिति को अपनी कृति में ऐड्रेस कर रहे होते थे, उसी के अनुसार भाषा और संसार भी गढ़ लेते थे।

■ निर्मल वर्मा ने अपने बाकी सारे फिक्शन में हिंसा का परीक्षण उसकी आंतरिकता में किया है जबकि विभाजन की हिंसा बहुत ही ठोस, प्रत्यक्ष और मूर्त थी। क्या आपको लगता है कि उन्होंने 'थिगलियां' को इसलिए अपने संग्रहों से दूर रखा क्योंकि यह कहानी आंतरिकता के उनके विजन से मेल नहीं खाती?

मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और मैंने भी इस मामले को ऐसे ही समझा है। निर्मल बाहर की पीड़ा को लेकर हमेशा संकोच में रहते थे। वह अपने रचना संसार में शायद भीतर की पीड़ा को ही केंद्र में रखना चाहते थे।

> जब 1984 के दंगे हुए थे, तब टेलिफोन भी इतने सुलभ नहीं थे और हिंसा में डूबी दिल्ली की बुरी हालत थी। तब निर्मल मुझसे भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उस समय उन्होंने एक शांति की अपील नवभारत टाइम्स में निकाली, जो उनका अपना बयान था। उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि उनके दिमाग में पार्टिशन का ट्रॉमा लगातार बना ही रहा है, और लगातार उनकी कहानियों में आता रहा

■ वह 'एक चिथड़ा सुख' से लेकर 'रात का रिपोर्टर' तक दिल्ली को जैसे दर्ज करते हैं, उसमें भी उनका इंटरनल सेल्फ हमेशा एक्सटर्नल के साथ साथ चलता है...

एक लेखक तो अपने भीतर के इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्फ को साथ लेकर चलता ही है। मुझे याद आता है कि जब 1984 के दंगे हुए थे, तब टेलिफोन भी इतने सुलभ नहीं थे और हिंसा में डूबी दिल्ली की बुरी हालत थी। तब निर्मल मुझसे भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उस समय उन्होंने एक शांति की अपील नवभारत टाइम्स में निकाली, जो उनका अपना बयान था। उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि उनके दिमाग में पार्टिशन का ट्रॉमा लगातार बना ही रहा है। वह ट्रॉमा उनके भीतर जीवन भर रहा और उनकी कहानियों में बार-बार आता रहा। वह 'थिगलियां' 1955 में आ रहा है और 'इशारे' में 2000 में आ रहा है। यह बड़ा विचित्र है कि कैसे एक ही चीज आपको बार-बार परेशान करती है।

■ 'इशारे' तो विभाजन पर उनकी बहुत हॉन्टेड कहानी है..

उसमें 'छोड़ने' की तकलीफ कितनी गहरी है! और यह बड़ा दिलचस्प है कि यह कहानी सन 2000 में छपी थी। तब भारतीय राजनीति बदल रही थी और निर्मल पर इस या उस विचारधारा में चले जाने के तमाम आक्षेप लग रहे थे। तब दिए उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स भी सामने हैं लेकिन मुझे उन बयानों के बारे में आज कुछ नहीं कहना। एक तरफ तो उनका यह सेल्फ है जो वह बयान दे रहा था और दूसरी तरफ उसका यह 'इशारे' कहानी में आने वाला सेल्फ है। यह बताता है कि भारत की राजनीति में जब दो खेमों के बीच अलगाव हो रहा था, ठीक उसी वक्त इस लेखक की रचना में एक कसक आती है। कसक जो कहती है कि आम लोगों के बीच यह अलगाव नहीं होना चाहिए।

www.nbt.in

जिसके सपने में आता है भारत

सिंगापुर में एक दिन अपनी नातिन टीया के साथ कैब से भ्रमण पर निकला। हालांकि साथ में पूरा परिवार ही था। घूम-टहल कर जब लौटना हुआ तो फिर कैब बुक की। इस कैब का सिंगापोरियन ड्राइवर नोवेंडी बहुत ही हंसमुख और हाजिरजवाब था। उसने जोरदार ढंग से हम लोगों का स्वागत ब्यूटीफुल फैमिली के रूप में किया, और टीया को राजकुमारी कहते हुए उसे सिंगापुर का भविष्य बताया। जब उसे पता चला कि टीया का जन्मदिन 16 सितंबर को है, जिस दिन आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक Lee Kuan Yew का जन्म हुआ था, तो उसने टीया को भविष्य में सिंगापुर का प्रेसिडेंट बताया।

अचानक नोवेंडी हिंदी बोलने लगा। हम सब हैरान। वह बोला- मेरा भारत महान। मैं आप जैसे लोगों से हिंदी सीखता हूं और 'सपने में भारत भ्रमण' करता हूं। अभी तक सपने में मैं बिहार, मणिपुर, लेह, लद्दाख, आगरा, गोवा वगैरह घूम चुका हूं। मैं कई तरह के टूरिज्म जानता हूं, लेकिन नोवेंडी का ड्रीम टूरिज्म मेरे लिए एकदम नया था। उसने कहा, मेरा जन्म नवंबर में हुआ है, इसलिए मेरा नाम नोवेंडी पड़ा है। फिर हंसते हुए बोला- मेरी एक पत्नी, दो बच्चे हैं और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी एक्स-गर्लफ्रेंड ही मेरी पत्नी है।

लगभग चार वर्षों से टैक्सी चला रहे नोवेंडी ने कोविड-19 के दौरान जान पर खेलकर लोगों की मदद की थी। बताने लगा, मेरे एक लखपति रिश्तेदार को पैसे का घमंड था। उनको लगता था कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होनी को कौन टाल सकता है। उन्हें कोरोना हुआ और छह दिन बाद एंबुलेंस में ही उनकी मृत्यु हो गई। आप सिर्फ एक बार ही जीते हैं। उसने कहा, कोरोना से हमें यही सीख मिली और इसलिए मैंने बेफिक्र होकर लोगों की सेवा की।

खुद अपनी आंख से

राजीव कुमार वर्मा

मुझे लगा, नोवेंडी से जरूर मेरा कोई नाता है। मैंने नवंबर में उसके जन्म का दिन पूछा, उसने 21 तारीख बताई। मैंने कहा, मेरे भी जन्म का दिन 21वां ही है। चलो, कम से कम मूलांक का नाता तो मिला। उसने बिहार और महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा। वह अहिंसा, मध्यम मार्ग और नालंदा विश्वविद्यालय भी जानता था। बताने लगा, मैं महीने में तीन दिन गणपति, मुरुगन, शक्ति और बजरंगबली की पूजा करता हूं। भगवान शिव और देवी दुर्गा पर भी उससे चर्चा हुई। मैंने उसे वृहत्तर भारत के बारे में बताया और पूरे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में राम पूजा के बारे में बताया। उसे पहले से ही रामायण के बारे में काफी जानकारी थी। मैंने उससे उसके गुरु के बारे में पूछा तो उसका जवाब था कि आप जैसे ही गुरुओं से सीखा है। फिर बोला, आप लोगों का चेहरा प्रफेसर जैसा है। हमने उसे धन्यवाद कहा और उसे दिल्ली विश्वविद्यालय और नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बारे में बताया। बेटी आरुषि भी उसकी हिंदी से बहुत प्रभावित हो रही थी। पिछले सात वर्षों से आरुषि-अनुपम सिंगापुर में रह रहे हैं। इन दोनों ने भी उससे सिंगापुर के बारे में काफी बातें की।

जब मैंने एक आधुनिक देश के रूप में सिंगापुर की तारीफ की तो नोवेंडी बहुत खुश हुआ। उसने Lee Kuan Yew के बारे में विस्तार से बताया, और उन्हें आधुनिक सिंगापुर का निर्माता कहा। पहले हम लोग उसकी हिंदी से हैरान थे, अब इतिहास और भारतीय धर्म के बारे में उसकी जानकारी से। उसने हमें बार-बार बेटी और दामाद के पास आने को कहा। और जब उसने हमें घर छोड़ा, तो विदा भी 'नमस्ते' कहकर ही ली।

चलते-चलते...

जीवन के लिए जरूरी प्रोटीन और DNA में फेर-बदल कर वैज्ञानिकों ने ऐसी कोशिकाओं का निर्माण किया है, जो शरीर की कोशिकाओं की तरह ही दिखती हैं, और उसी तरह काम भी कर सकती हैं। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि इस क्षेत्र में यह पहली उपलब्धि है, जो मेडिकल साइंस में एक नया बदलाव लाएगी और उपचार में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। यह शोध नेचर केमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ है।

चीन की बड़ी समस्या

दुनिया का ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले चीन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। आर्थिक विकास धीमा हो रहा है और असर दिख रहा है रोजगार पर। क्या है चीन में नौकरियों की हालत, कितना बड़ा है संकट?

रेकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी

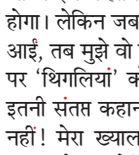

चीन में बेरोजगारी रेकॉर्ड स्तर पर है। पिछले साल जून का डेटा बताता है कि शहरों में 16 से 24 साल के युवाओं में यह 21.3% थी। अपनी नाक बचाने के लिए चीन ने अगले सर्वे में उन युवाओं को शामिल नहीं किया, जो पढ़ाई करते हुए नौकरी तलाश कर रहे हैं। इसके बाद भी इस साल मार्च में बेरोजगारी दर 15.3% थी।

ग्रैजुएट पर ज्यादा मार

यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों और ग्रैजुएट युवाओं का संकट ज्यादा गहरा है। हालात छुपाने के लिए चीन इनकी बेरोजगारी का डेटा जारी नहीं करता। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले 25.2% युवा बेरोजगार थे। उसी आधार पर आज अनुमान लगाएं, तो करीब एक तिहाई चीनी ग्रैजुएट बेरोजगार हैं।

AI image

नौकरी क्यों नहीं मिलती

क्योंकि यूनिवर्सिटी और वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज से हर साल बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स पढ़कर निकल रहे हैं। इनकी संख्या की तुलना में नौकरी के अवसर पैदा नहीं हो रहे। इस साल ही लगभग सवा करोड़ ग्रैजुएट तैयार होंगे, साल 2000 की तुलना में करीब 10 गुना। दो दशक पहले बेरोजगारों में ऐसे युवाओं का प्रतिशत केवल 9 था, जो अब 70% से ज्यादा हो चुका है।

क्या नीति जिम्मेदार

Asian financial crisis से निपटने के लिए चीन ने शिक्षा पर खर्च की नीति अपनाई। इसके मुताबिक बच्चे नौकरियों के बजाय पढ़ाई पर जोर दें, जिससे मार्केट में पैसा आए। वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते अभिभावकों के पास पैसा था, तो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया। लेकिन, इससे एडमिशन बेहिसाब बढ़ गए और खूब कॉलेज-विश्वविद्यालय खोले गए।

किस काम की पढ़ाई

चीन में प्राइवेट इंस्टिट्यूट खुले, जिनमें एडमिशन आसान था लेकिन इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ा। चीनी कंपनियों की शिकायत है कि युवाओं में जरूरी स्किल की कमी है। ऐसे विषयों में ज्यादा एडमिशन हो रहे जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड कम है। युवा अब overqualified हो रहे। रही-सही कसर चीन की घटती आर्थिक रफ्तार ने पूरी कर दी है।

प्रस्तुति : शैलेंद्र पांडेय

https://t.me/AllNewspapers

यहां क्यों होती थी दुर्योधन की पूजा

हर की दून में पुरातन और आधुनिकता का अनुपम संगम मिलता है

चंदन सिंह घुघत्याल

'हर की दून' हिमालय के खूबसूरत परिवेश के बीच समुद्र तल से लगभग 11700 फुट की ऊंचाई पर बसा एक महत्वपूर्ण पौराणिक क्षेत्र है। हर की दून का शाब्दिक अर्थ है 'ईश्वर की घाटी'। यहां की दो प्रथाओं - दुर्योधन की पूजा और बहु पति प्रथा- के बारे में काफी सुन रखा था। सच जानने की इच्छा और यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखने की ललक हमें अपने साथी विशाल मोहला और ओबेरॉय सदन की नौवीं कक्षा के 20 छात्रों (ट्यूटीज) के साथ मिड टर्म के दौरान 'हर की दून ट्रेक' पर ले आई।

ओसला गांव के नीचे सुपिन नदी में बने पुल को पार कर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए अपने बेस कैंप कलकत्तिधार पहुंचे। अगले दिन करीब 5 घंटे में 14 किलोमीटर चलकर हम हर की दून पहुंचे। चारों ओर हिमाच्छादित चोटियां और ग्लेशियर देखकर व अपने को बर्फ के बीच पाकर मन प्रफुल्लित हुआ। बच्चे बर्फ में जी भर खेले। करीब एक-डेढ़ घंटा वहां रुकने के बाद हमने वापसी का ट्रेक शुरू किया। वापसी में बर्फबारी भी शुरू हो गई। खैर अपने-अपने रेनकोट में सभी सुरक्षित बेस कैंप पहुंचे।

कहते हैं, अज्ञातवास के दिनों में पांडवों की शरण स्थली लाखामंडल भी इस क्षेत्र से काफी नजदीक है। युधिष्ठिर जिस स्वर्ग रोहिणी से स्वर्ग गए बताए जाते हैं, वह पर्वतमाला भी हर की दून से बिल्कुल सामने दिख जाती है। अभी तक मन का यह सवाल जस का तस था कि क्या वाकई यहां दुर्योधन को पूजा जाता है। हमने इसकी सचाई जानने की कोशिश की। नैटवाड़ में महान योद्धा कर्ण का मंदिर भी बना है। लोग कर्ण मंदिर में पूजा-अर्चना आज भी करते हैं। दुर्योधन को देवता मानने वाले भी यहां अच्छी-खासी संख्या में हैं।

जब मैंने इस ट्रेक के अंतिम गांव ओसला के बुजुर्गों से वहां स्थित मंदिर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव में स्थित मंदिर सोमेश्वर भगवान का है और वे सभी शिव की पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि 22 गांवों में सोमेश्वर भगवान की डोली जाती है, और वही उनके आराध्य हैं। जब मैंने पूछा कि दुर्योधन मंदिर कहां है, तो उन्होंने दबी जुबान से बताया कि दुर्योधन का मंदिर भी सोमेश्वर मंदिर के पास ही था। अब वह इसी में समाहित हो गया है। दुर्योधन की अब कोई मूर्ति नहीं है।

जब यही प्रश्न नवयुवकों से पूछा तो उन्होंने दुर्योधन की पूजा और उसके मंदिर वाली बात को नकार दिया। उनका कहना था कि ट्रेकर्स ने यहां के इतिहास को गलत ढंग से पेश किया है।

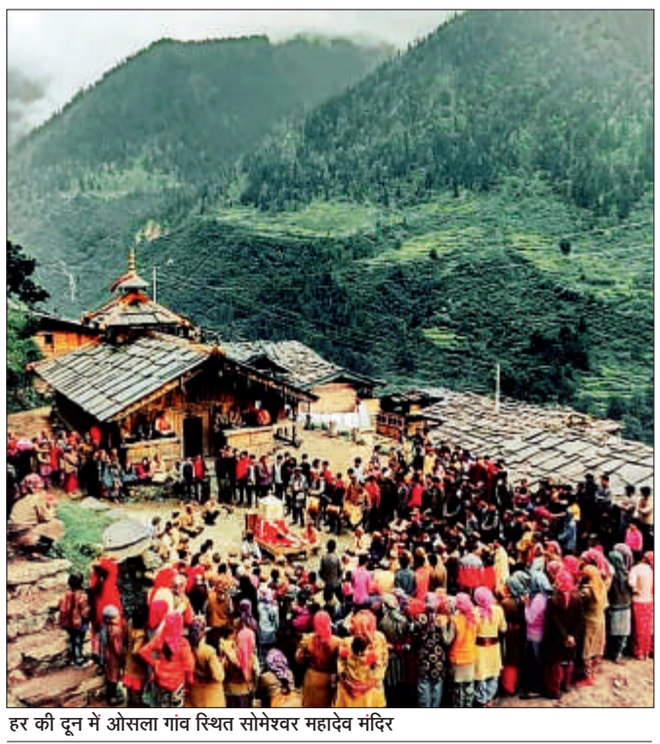

हर की दून में ओसला गांव स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर

क्यों अद्भुत है हर की दून

- प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखती है
- महाभारत प्रसंगों से जुड़े स्थल हैं यहां
- दुर्योधन की पूजा के मिलते हैं साक्ष्य

लेकिन हर की दून में ट्रेक गाइड जसपाल सिंह राणा ने बताया कि दुर्योधन को उनके बुजुर्ग सुयोधन कहते और उसकी वीरता का बखान भी करते थे। राणा कहते हैं, 'दुर्योधन की पूजा अवश्य होती थी, भले ही आज की पीढ़ी इस बात को नकार रही है।' चाय की दुकान चलाने वाले कालू जुवांठा ने बताया कि सुयोधन को देवता का रूप अवश्य मिला हुआ था, लेकिन समय के साथ यह मान्यता कम हो गई है।

जब हम ओसला गांव में स्थित सोमेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए गए तो लोगों ने बताया कि आजकल भगवान सोमेश्वर भगवन जखोल गांव में विराजमान हैं। मुख्य मंदिर के पास दो और मंदिर थे, जिन्हें लोगों ने स्टोर रूम बताया। हो सकता है वे दो स्टोर रूम सुयोधन के मंदिर हों। गांव के ही बुजुर्ग राजू पंवार से जब यही प्रश्न बच्चों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि राजाओं की पूजा तो सभी करते थे, राजा में ईश्वरीय अंश होता है। दुर्योधन भी तो राजा ही थे।

सूचना क्रांति के इस युग में महाभारत के किरदारों में दुर्योधन की भूमिका अत्यधिक नकारात्मक देखने को मिली। शायद इसीलिए नई पीढ़ी के लोगों ने बुजुर्गों की मान्यता को तिलांजलि दे दी हो।

अब बारी थी दूसरे प्रश्न का उत्तर खोजने की। क्या आज भी यहां बहु पति प्रथा है? हमने गंगगवाड़ से ओसला को जा रहे ग्रामवासी चतुर सिंह रावत से यह प्रश्न पूछा। उन्होंने बताया कि यदि दो या तीन भाइयों में उम्र का अंतर कम हो तो एक भाई द्वारा ब्याही गई दुल्हन सभी भाइयों की पत्नी होती है। इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया कि इससे जानवरों और खेती-बाड़ी में बंटवारा नहीं होता है। गाइड जसपाल सिंह राणा ने भी हमें उनके गांव के खच्चर पालक दो भाइयों से मिलवाया। दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। हमने गांव की ही एक बुजुर्ग महिला से पूछा तो उन्होंने बताया कि गृहशांति का यह अचूक बाण था।

बकरी चरा रहे रोशन ने बताया कि करीब 20-30 साल पहले तक शादी के लिए वर पक्ष को बहुत पैसा देना पड़ता था। आमदनी कम थी। जोड़-तोड़कर एक दुल्हन के लायक पैसे लड़के के परिवार वाले जुटा लेते थे, बाकी बेटों की दुल्हन के लिए पैसा नहीं जुटा पाते थे। इसलिए बहु पति प्रथा थी। महिला सशक्तीकरण और शिक्षा क्रांति के इस युग में बहु पति प्रथा का चलन हर सुनने वाले को गलत लगता है। इस क्षेत्र के लोग भी इस प्रथा को नकार रहे हैं।

इस तरह तीन दिन में हमने कुल 46 किलोमीटर का ट्रेक किया। हरे-भरे पहाड़ों, पीले सरसों के फूलों से रंगमयी घाटी, कलकल बहती सुपिन, मोनाल की चहचहाहट, हिमनद, बकरियों का मिमियाना, खच्चरों की घंटिका- ये सब और दर्जनों अन्य अनुभव जहन में इस तरह से दर्ज हुए हैं कि शायद ही कभी मिटें या धुंधले पड़ें।

(लेखक दी दून स्कूल में टीचर हैं)

ऑफ दि ट्रैक

इंतजार में है संकट

दिलीप लाल

दुनिया ने 2008 के वित्तीय संकट और 2020 की कोविड महामारी के विनाशकारी प्रभावों को झेला है। पर क्या हम अगले बड़े वित्तीय संकट के लिए तैयार हैं? शोधकर्ताओं का मानना है कि पर्यावरण का विनाश धीमे जहर की तरह दुनिया को आर्थिक रूप से कमजोर बना रहा है। 2030 तक यह कोविड से भी बड़ा आर्थिक संकट ला सकता है। ग्रीन फाइनेंस इंस्टिट्यूट की हालिया रिपोर्ट में ब्रिटेन को चेतावनी दी गई है कि लगातार बिगड़ते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण उसके GDP में 12% तक की कमी आ सकती है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पर्यावरण के क्षरण से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जोखिम बढ़ रहे हैं, जिसका असर इंटरनैशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ रहा है। प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री पार्थ दासगुप्ता ने अपनी समीक्षा 'जैव विविधता का अर्थशास्त्र' में बताया है कि प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से नुकसान ने दुनिया को आर्थिक रूप से बड़े खतरे में डाल दिया है। यह स्पष्ट है कि प्रकृति के विनाश की अनदेखी करने की आर्थिक कीमत बहुत अधिक होगी। इस संकट से निपटने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। ग्रीन फाइनांस में निरंतर नवाचार और निवेश के माध्यम से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं- रेन्यूएबल एनर्जी में निवेश, जैसे सौर, पवन, जल विद्युत और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना। हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाकर हम न इस संकट से बच सकते हैं, बल्कि समृद्ध भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं।

गैलरी

कीमती हैं रंग

इसी हफ्ते विएना में हुई एक नीलामी में एक स्त्री के अधूरे पोट्रेट की कीमत 266 करोड़ रुपये आंकी गई है। युवा महिला का यह पोट्रेट ऑस्ट्रियाई चित्रकार गुस्तावे क्लिम्ट ने 1917 में बनाया था। माना जा रहा था कि वह खो चुका है। वहीं पिछले कुछ महीनों में भारत से भी कुछ पेंटिंग्स ने खासी इज्जत और कीमत कमाई है। देखते हैं, देश-दुनिया में पिछले दिनों नाम और दाम कमाने वाली कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स :

पोट्रेट ऑफ मिस लीसर : मिस लीसर का पोट्रेट गुस्तावे इसलिए पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि इसे पूरा कर पाने से पहले ही 1918 में उनकी मौत हो गई थी।

पायसेज एग्रेस्टे : भारतीय परंपरा, अध्यात्म और आधुनिकता के चितेरे एसएच रजा की दो पेंटिंगें पिछले दिनों 86 करोड़ में बिकीं। पायसेज एग्रेस्टे उनमें से एक है।

द स्टोरी टेलर : मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल की बनाई यह पेंटिंग उनकी मौत के 82 साल बाद सितंबर, 2023 में 61.8 करोड़ रुपये में बिकी। यह एक रेकॉर्ड है।

रीडर्स मेल

संपत्ति का अधिकार

26 अप्रैल का संपादकीय 'राज्य के दखल का रूप' पढ़ा। व्यक्ति की निजी संपत्ति के अधिकार का संरक्षण और समाज के व्यापक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना एक जटिल चुनौती है। जस्टिस कृष्ण अय्यर के विचार इस बहस को गहराई देते हैं, जहां व्यक्ति और समुदाय के बीच अटूट संबंध पर जोर दिया गया है। महात्मा गांधी की संपत्ति के प्रति नैतिक दृष्टिकोण की अवधारणा भी इस संदर्भ में प्रासंगिक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है, वह जर्जर इमारतों और उनकी जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा है। यह न केवल निजी संपत्ति के अधिकार, बल्कि शहरी विकास, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भी छूता है। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस जटिल विषय पर स्पष्टता लाएगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्व के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। यह फैसला भविष्य में नीति निर्माण और शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश साबित हो सकता है। संपत्ति का अधिकार केवल एक व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक दायित्व भी है। इसे निभाते हुए हम एक न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।

मोहित श्रीवास्तव, ईमेल से

अमेरिका समझे अहमियत

यह पत्र 24 अप्रैल के संपादकीय 'ग्रीन कार्ड का इंतजार' से संबंधित है। ग्रीन कार्ड के जरिए अमेरिका की सबसे ज्यादा नागरिकता प्राप्त करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। इसके बावजूद नौ लाख से अधिक प्रवासी भारतीय वहां की नागरिकता के लिए लाइन में हैं। भारत सरकार को कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से बातचीत करके भारतीय नागरिकों को शीघ्र नागरिकता देने के प्रयास करने चाहिए, ताकि उनके जीवन की दुविधा खत्म हो, और वे परिवार समेत निश्चिंत हो सकें। खाड़ी सहित विदेशों से भारतीय बड़ी मात्रा में भारत में पैसा भेजते हैं, जो कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी करता है। फिर अमेरिका को भी प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि वहां पर कार्यरत भारतीय अमेरिका के लिए सभी पहलुओं पर उपयोगी हैं। नागरिकता प्रदान करने के साथ ही वहां पर भारतीयों पर हो रही हिंसा पर भी अमेरिकी प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

आर.एन.आई. नं. 510/57@ सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • शनिवार • 27 अप्रैल • 2024

www.rashtriyasahara.com

भाषण पर सवाल जवाब

निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा में दिए भाषण पर भाजपा से जवाब मांगा है। कांग्रेस और वामदलों ने नरेन्द्र मोदी के भाषण को विभाजनकारी और महाहानिकर बताते हुए आयोग से शिकायत की थी। इसी पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नोटिस दिया है। किसी पदेन प्रधानमंत्री के विरुद्ध आदर्श संहिता उल्लंघन मामले में यह पहली कार्रवाई है। आयोग का अपनी याददाश्त के आधार पर ऐसा दावा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा की शिकायतों पर जवाब मांगा गया है। ये जवाब 29 अप्रैल तक दिए जाने हैं। इस तरह से आयोग ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का एक कठिन पड़ाव पार कर लिया है। उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उसने संहिता उल्लंघन पर प्रधानमंत्री तक को नहीं

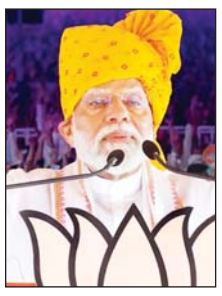

बख्शा। यह आरोप भी कमजोर हुआ है कि आयोग विपक्ष और कमजोर दलों के नेता को ही निर्देशित करने में आगे रहता है। पर उसका निर्णायक इम्तिहान दोनों दलों के जवाब पर की जाने वाली कार्रवाई में होगा जो आयोग की शक्ति और क्षेत्र को परिभाषित करने वाला होगा। सार्वजनिक जीवन में गरिमा-मर्यादा और नियम-कायदे का आग्रही तबके ही नहीं, पूरे देश ने देखा-सुना कि बांसवाड़ा में और फिर अलीगढ़ तक में खास समुदाय और धर्म के लोगों के बारे में क्या-क्या न कहा गया। माना कि चुनाव बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में आप समुदाय-धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते पर यही भाव चुनावी सभाओं में भी रहना बुरा नहीं होता। यह सामान्य जन अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री को तमाम विभाजनों और दोष-रेखाओं से ऊपर होना चाहिए। तब आयोग को भी रिकार्ड बनाने का मौका नहीं मिलता। चुनाव की घोषणा करते हुए आयोग ने भाषणों में सभ्यता के निर्वाह का अनुरोध दलों से किया था, जिसका पालन किसी ने नहीं किया। विपक्ष में स्थितिजन्य आक्रामकता स्वाभाविक ही होती है। सत्ता अपने व्यवहार से उसको परिमार्जित करती है। खरगे और राहुल सरकार की नीतियों की आलोचना के अधिकार के प्रयोग में सभ्यता भूलते रहे हैं। वे न केवल प्रधानमंत्री को निजी स्तर चोट पहुंचाने वाली भाषा का धड़ल्ले से प्रयोग करते सुने-देखे गए हैं, बल्कि तू-तड़ाक पर भी उतर आए हैं। यह भी रिकार्ड है कि नरेन्द्र मोदी देश के सर्वाधिक आलोच्य प्रधानमंत्री हैं। अगर यही एक परिपक्व लोकतंत्र की भाषा है तो यह वाकई बेहद पीड़ादायक परिदृश्य है।

सुविधाजनक संचार

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अब व्हाट्सऐप संदेशों द्वारा जानकारी साझा करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी के पिच्छत्तरवें वर्ष में यह छोटी सी योजना की शुरुआत की है। व्हाट्सऐप के रोजाना की जिंदगी में शामिल होने और इसके शक्तिशाली संचार सुविधा होने की बात भी उन्होंने की। इस पहल के अंतर्गत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तथा शीर्ष अदालत के समक्ष निजी तौर पेश होने वाले वादियों को मुकदमा ऑनलाइन दाखिल करने, वाद सूची, आदेशों तथा निर्णयों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए इसकी सराहना की। प्रधान न्यायाधीश ने व्हाट्सऐप नम्बर साझा करते हुए स्पष्ट किया कि इस पर कॉल या संदेश प्राप्त नहीं होंगे। निःसंदेह यह सबसे बड़ी

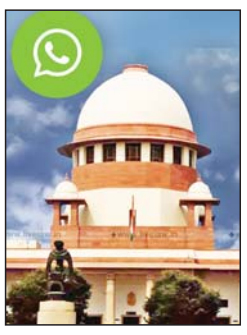

अदालत को पेपरलेस बनाने की तरफ उठा बड़ा कदम है। तकनीक संबंधी सुविधाओं को जितनी जल्दी हो सके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेना उचित होता है। प्रधान न्यायाधीश निरंतर अदालती काम को लेकर ऐसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जजों में सबसे ज्यादा फैसले लिखने का रुतबा प्राप्त है। छह वर्ष के भीतर 513 फैसले लिख चुके हैं। न्याय व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर उन्होंने बड़े कदम उठाए हैं। विभिन्न फैसलों को उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में अनुदित करवाने की व्यवस्था करके तथा हिन्दी, तमिल, उड़िया और गुजराती में फैसलों का अनुवाद करने के लिए समिति का गठन भी किया। देश में 48 करोड़ से अधिक व्हाट्सऐप प्रयोगकर्ता हैं, जो 2025 तक 80 करोड़ तक पहुंचने का अंदाजा है। हालांकि व्हाट्सऐप मेटा टेक्नॉलाजी कंपनी की सुविधा है, जिसके सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं। किसी भारतीय संचार संस्थान को इस जरूरत को समझते हुए आगे कदम बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सरकार, देश के अन्य बड़े संस्थान और गोपनीय दस्तावेज के लिए देसी तकनीक का प्रयोग किया जाना उचित है। तकनीक के मामले में हम दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके तकनीक का इस्तेमाल सुविधाओं के लिए करना वक्त की मांग है, इसके बिना काम नहीं चल सकता।

कटाक्ष/ कबीरदास

सूरत मॉडल पे ही जा!

भई मोदी जी की ये बात हमारी समझ में तो नहीं आई। बताइए, कामयाब सूरत मॉडल आने के बाद भी, बहनों और माताओं के मंगलसूत्र में ही अटके हुए हैं। नहीं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें इसका ख्याल करके इस चक्कर से बचना चाहिए था कि सारी वफादारी के बावजूद बेचारे चुनाव आयोग को कोई नोटिस-वोटिस न देना पड़ जाए। इसका ख्याल करके तो हर्गिज नहीं कि देश तो देश, दुनिया भर में कैसा डंका बजेगा। वह सब नहीं। पर जब सूरत मॉडल खोज लिया है, फिर उसी पर ध्यान लगाते, मंगलसूत्र के लिए माथाफोड़ी करने की क्या जरूरत थी। बताइए, सूरत मॉडल को कामयाब होते सबने देखा है कि नहीं। एकदम अचूक।

सिंदूर कर लो, हिन्दू-मुस्लिम कर लो, गारंटी कर लो, 2047 वाला विकास कर लो, सब में आखिरकार पब्लिक बीच में आती ही आती है। और पब्लिक को गोदी मीडिया के बल पर चाहे कितना सिखा-पढ़ा लो, चाहे अपने उद्धारकर्ता होने का उसे कितना ही भरोसा दिला लो, चाहे उसका माथा कितना ही घुमा लो, गर्म करा लो, उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। कब गर्व-वर्व सब भूल कर, पब्लिक अपने पेट की आवाज सुनने लग जाए, कह नहीं सकते। देखा नहीं कैसे सब कुछ करने-कराने के बाद भी, कैसे नासपीटी ने पहले चरण की वोटिंग से नागपुर वालों का ही दम फुला दिया। फिर जब सूरत से एकदम अचूक मॉडल हाथ आ गया है, पब्लिक-वब्लिक के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्या है? और सच पूछिए तो सूरत मॉडल सिर्फ अचूक ही नहीं है, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ भी है। खरीद-वरीद के जीतने से तो सस्ता और टिकाऊ है ही, पब्लिक को बहला-फुसला कर बटन दबवाने के मुकाबले भी, काफी सस्ता और टिकाऊ है।

मुकेश दलाल की बिना चुनाव की सांसदी, चुनाव वाली सांसदी से तो बहुत सस्ती पड़ी ही होगी। और कामयाबी की गारंटी ऊपर से। हम तो कहते हैं कि मोदी की असली गारंटी तो यही है। बिना चुनाव के जीत की गारंटी। बॉन्ड का पैसा, पुलिस, ईडी, सीबीआई सलामत रहें, विरोधी उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिलेगा। जो फिर भी ना माने, शौक से जेल से चुनाव लड़ सकता है। तब हिचक क्या है; हिम्मत करके एक बार देश भर में सूरत मॉडल आजमाएं, और बेशक, पांच सौ पार का झंडा फहराएं।

अनमोल वचन

किसी विज्ञान को समझने के लिए उसका इतिहास जानना आवश्यक है।

-ऑगस्टे कॉम्टे

संपादकीय

editpagesahara@gmail.com

भारत विरोध पर मुहर

मालदीव

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

हिन्द महासागर में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बीजिंग और नई दिल्ली, दोनों मालदीव को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखने के लिए कृतसंकल्पित रहे हैं। इसका असर मालदीव की घरेलू राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस द्वीपीय देश में मुइज्जू के राजनीतिक उभार से भारत की समस्याएं बढ़ रही हैं। दरअसल, मुइज्जू भारत की मालदीव में उपस्थिति को अनियंत्रित बता कर देश की सत्ता के शीर्ष पर आए हैं, और भारत विरोध की नीति के सहारे देश की संसद में पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब मुइज्जू ने जिस प्रकार देश की संसद में भी बंपर बहुमत हासिल किया है, उससे लगता है कि उनके भारत विरोध और चीन परस्त नीतियों को जनता ने पसंद किया है। ऐसे में यह विचार लाजिमी है कि आखिर, मालदीव की जनता भारत जैसे विश्वसनीय मित्र के खिलाफ जाकर चीन की कुटिल कर्जनीति में क्यों उलझना चाहती है, और इसके दूरगामी परिणाम भारत के लिए कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जनसंख्या की लिहाज से बहुत छोटे इस इस्लाम बाहुल्य देश में पिछले कुछ वर्षों में परंपरावाद को उभारने की कोशिशें राजनीतिक फायदा देने वाली साबित हुई हैं।

खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाने वाले मालदीव के हजारों नागरिकों की कथित धार्मिक अभिव्यक्ति को मुइज्जू ने वोट में बदलने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने भारत से ऐतिहासिक जुड़ाव को नजरअंदाज कर बदलती परिस्थितियों में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की ओर रुख किया। फिलिस्तीन जैसे भावनात्मक मुद्दे को धार्मिक आधार पर उठाया तथा इस्लामिक आदर्शवाद पर आधारित नये मालदीव की परिकल्पना को राजनीतिक आधार पर जनता के सामने रखा। मुइज्जू ने संसद में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है। अर्थ यह कि वे राजनीतिक संस्थागत दृष्टिकोण से, सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं खासकर न्यायपालिका की शक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। मालदीव में राजनीतिक उथल-पुथल का इतिहास रहा है।

भारत को हिन्द महासागर के अहम साझेदार मालदीव के साथ राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की कोशिशें करते रहना होगा। आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता देनी होगी। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे प्रमुख सुरक्षा भागीदारों के साथ भी रक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा जिससे चीन को इस क्षेत्र में निर्णायक रणनीतिक बढ़त लेने से रोका जा सके

के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने के लिए एक सैन्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और अमेरिका ने पहले मालदीव की सेना को प्रशिक्षित किया था। भारत मालदीव को हिन्द महासागर क्षेत्र में प्रमुख समुद्री भागीदार के रूप में मान्यता देता है।

यह द्वीपीय राष्ट्र भौगोलिक दृष्टि से भारत और कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों पर नजर रखता है। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मालदीव व्यापार, पर्यटन और शिपिंग के लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। मालदीव रणनीतिक रूप से लक्षद्वीप द्वीप समूह से केवल सात सौ किलोमीटर और भारत की मुख्य भूमि से बारह सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत से इसकी निकटता को देखते हुए महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है। हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन ने तेजी से सैन्य आधुनिकीकरण किया है, इससे भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं।

हिन्द महासागर में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव और उसकी महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल में मुइज्जू की दिलचस्पी कम नहीं है। 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर मोहम्मद मुइज्जू के चुने जाने के बाद से क्षेत्र में देश के रिश्ते बदल गए हैं। मालदीव ने चीन के साथ रक्षा समझौतों और बुनियादी ढांचे के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के समुद्री अनुसंधान जहाज जियांग यांग होंग को मालदीव के बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देने से चीन का प्रभाव और भी पुष्ट होता है। जनवरी में जब मुइज्जू ने चीन का दौरा किया था, इसके चौबीस घंटे के बाद चीन के इस जहाज ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी।

संभवतः मुइज्जू इसके जरिए भारत को यह संदेश भी दे देना चाहते थे कि वे चीन से रिश्तों को लेकर कोई समझौतावादी रुख नहीं अपनाएंगे। बारह सौ द्वीपों की श्रृंखला से बने मालदीव के अधिकांश द्वीप निर्जन हैं। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहा है। वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखने से दिल्ली को हिन्द महासागर के एक प्रमुख हिस्से पर नजर रखने की क्षमता मिलती है।

मुइज्जू को देश में चीन के हितों के समर्थक के रूप में देखा जाता है। भारत और चीन, दोनों रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यस्त पूर्व पश्चिम शिपिंग लेन में फैले हुए हैं। चीन, अपनी तेजी से बढ़ती नौसेना के साथ, रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान तक पहुंच तथा भारत को रोकना चाहता है। दिल्ली और बीजिंग, दोनों ने मालदीव को बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान के रूप में करोड़ों डॉलर दिए हैं। मुइज्जू अब चीन पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं, और यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण बन रहा है।

भारत को हिन्द महासागर के अहम साझेदार मालदीव के साथ राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की कोशिशें करते रहना होगा। आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता देनी होगी। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे प्रमुख सुरक्षा भागीदारों के साथ भी रक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा जिससे चीन को इस क्षेत्र में निर्णायक रणनीतिक बढ़त लेने से रोका जा सके। चीन मालदीव जैसे छोटे से देश की भारत पर सैन्य निर्भरता कम करने के लिए उसकी सैन्य क्षमताओं का विकास कर रहा है, इससे मालदीव की सेना मजबूत होगी और इसके राजनीतिक दुरुपयोग की आशंकाएं भी बढ़ सकती हैं। मुइज्जू चीन के उस सामरिक चक्रव्यूह को रचने में मददगार बन रहे हैं, जिसके अनुसार चीन मालदीव में नौसैनिक अड्डा बना कर समुद्री सीमा पर भारत को रणनीतिक रूप से घेर ले जिससे हिमालय की सीमा पर भारत पर सैन्य दबाव बढ़ सके।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में 8.1 फीसद की वृद्धि

- देश के मीडिया और मनोरंजन (एमएंडई) क्षेत्र में 2023 में 8.1 फीसद की वृद्धि हुई और यह 2.32 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया
- उद्योग मंडल फिक्की और ईवाई की एक संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक, इसके 2024 में 2.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने और 2026 तक तीन लाख करोड़ रुपये को पार करने की संभावना है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं। पर समाज व राजनीति के बारे में हमारे कुछ विचार जरूर हैं। आज सुबह एक विचार आपके सामने रख रहा हूं: ऐसे लोगों/दलों को हरगिज वोट मत दीजिये जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ऐसे लोग धर्म के 'धंधेबाज' होते हैं, ये देश और समाज का भला नहीं करते! जय हिंद!

उर्मिलेश, पत्रकार

@UrmileshJ

हथियारों की होड़ चिंताजनक

मुद्दा | ललित गर्ग

शांति के तमाम उपायों के बीच दुनिया भर में सैन्य खर्च, शस्त्रीकरण एवं घातक हथियारों की होड़ खतरे की घंटी हैं। शस्त्रीकरण के भयावह दुष्परिणामों से समूचा विश्व भयाक्रांत है। हर पल आणविक हथियारों के प्रयोग को लेकर दुनिया डर के साये में जी रही है। इसीलिए आज अयुद्ध, निशस्त्रीकरण एवं शांति की आवाज चारों ओर से उठ रही हैं। शक्ति संतुलन के लिए शस्त्र-निर्माण एवं शस्त्र संग्रह की बात से किसी भी परिस्थिति में सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि इससे अपव्यय तो होता ही है, साथ ही गलत हथियारों के हाथों में पड़कर दुरुपयोग की आशंकाएं बढ़ जाती हैं।

ताजा घटनाक्रम को देखें तो एक ओर रूस और यूक्रेन आमने-सामने हैं, दूसरी तरफ इस्राइल और ईरान के बीच तल्खी भी चरम पर है। चीन और ताइवान के बीच भी रह-रह कर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे माहौल में सवाल स्वाभाविक है कि क्या सचमुच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए घातक हथियारों की प्रयोगभूमि बन रही है? सवाल और भी हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हथियारों पर ताजा रिपोर्ट ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। दुनिया सीधे-सीधे दो खेमों में बंट गई है। स्टॉकहोम की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं, डराने वाले भी हैं। शांति के तमाम उपायों के बीच दुनिया भर में सैन्य खर्च का बढ़ना एवं नये-नये हथियारों का बाजार गरम होना, चिंताजनक है। रिपोर्ट में खास बात यह है कि दुनिया में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर बरकरार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। भारत ने बीते पांच साल में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप का हथियार आयात 2014-18 की तुलना में 2019-23 में लगभग दोगुना बढ़ा है, जिसके पीछे रूस-यूक्रेन युद्ध बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देशों ने खरीदे। इस लिस्ट में रूस-यूक्रेन युद्ध ने देश के रक्षा निर्यात को काफी

प्रभावित किया है। इस कारण पहली बार रूस हथियार निर्यात में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है तो अमेरिका पहले और फ्रांस दूसरे नम्बर पर है। पिछले 25 सालों में पहली बार अमेरिका एशिया और ओशिनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा।

अमेरिका की हथियारों की होड़ एवं तकनीकीकरण की दौड़ पूरी मानव जाति को ऐसे कोने में धकेल रही है, जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। अब तो दुनिया के साथ-साथ अमेरिका स्वयं ही हथियारों एवं हिंसक मानसिकता का शिकार है। अमेरिका ने दुनिया पर आधिपत्य स्थापित करने एवं अपने शस्त्र कारोबार को पनपाने के लिए जिस अपसंस्कृति को दुनिया में फैलाया है, उससे पूरी मानवता पीड़ित है। अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था (न्यू वर्ल्ड ऑर्डर) की बात की है, खुलेपन की बात की है। लगता है कि 'विश्व मानव' का दम घुट रहा है, और घुटन से बाहर आना चाहता है। विडंबना देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित देश है, लेकिन उसके नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित और भयभीत नागरिक हैं। वहां की जेलों में आज जितने कैदी हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं हैं। कई वाकये हो चुके हैं कि किसी रेस्तरां, होटल या फिर जमावड़े पर अचानक किसी सिरफिरे ने गोलीबारी शुरू कर दी और बड़ी तादाद में लोगों को मार डाला। 2014 में अमेरिका में हत्या के दर्ज सवा चौदह हजार मामलों में अड़सठ फीसद मामलों में बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था।

दरअसल, मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध एवं हथियारों की विभीषिका से मुक्ति दिलाना जरूरी है। युद्धरत देशों में शांति स्थापित कर, युद्ध-विराम करके विश्व को निर्भय बनाना चाहिए। निश्चय ही यह किसी एक या दूसरे देश की जीत नहीं, बल्कि समूची मानव-जाति की जीत होगी। यथार्थ यह है कि अंधकार प्रकाश की ओर चलता है, पर अंधापन मृत्यु-विनाश की ओर। रूस ने अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का अहसास गलत समय पर गलत उद्देश्य के लिए कराया है। युद्ध से तबाही रूस-यूक्रेन की नहीं, बल्कि समूची दुनिया की तबाही होगी, क्योंकि रूस परमाणु विस्फोट करने को विवश होगा जो दुनिया की बड़ी चिंता का सबब है। बड़े शक्तिसंपन्न देशों को युद्ध विराम के प्रयास करने चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि जो देश हथियारों के निर्माता हैं, वे क्यों चाहेंगे कि युद्ध विराम हो। जब तक शक्तिसंपन्न देशों की शस्त्रों के निर्माण एवं निर्यात की भूख शांत नहीं होती तब तक युद्ध की आशंकाएं मैदान में, समुद्र में, आकाश में तैरती रहेंगी।

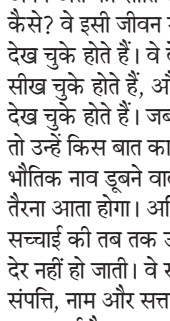

अध्यात्म | संत राजिन्दर

हम अपना जीवन भौतिक और बौद्धिक लक्ष्यों को पाने में लगा देते हैं, पर हम अध्यात्म से अनजान ही रहते हैं। जब भौतिक मृत्यु की उफनती

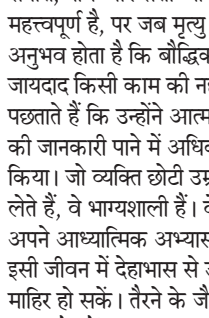

लहरें हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो हम में कोई आध्यात्मिक क्षमता नहीं होती कि हम अपने जीवन के अंत में से आसानी से निकल सकें। जब हमें खबर मिलती है कि हमें एक जानलेवा बीमारी है, या अचानक हमें अपनी मृत्यु दिखाई देती है, तो हम भयभीत हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। हमने अपना समय जीवन और मृत्यु का सच्चा अर्थ समझने में नहीं लगाया होता है, और हम अपने अंत से डर जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने ध्यान-अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक धारा में तैरना सीखने में अपना जीवन गुजारा है, उन्हें कोई डर नहीं होता। वे अपने अंत का शांति और निडरता से सामना करते हैं। कैसे? वे इसी जीवन में परलोक के जीवन की शान देख चुके होते हैं। वे देहाभास से ऊपर उठने की कला सीख चुके होते हैं, और स्वयं परलोक के क्षेत्रों को देख चुके होते हैं। जब उनका भौतिक अंत आता है, तो उन्हें किस बात का डर होगा? जब उनके शरीर की भौतिक नाव डूबने वाली होगी तो उन्हें परलोक में तैरना आता होगा। अधिकतर इंसान भौतिक मृत्यु की सच्चाई की तब तक उपेक्षा करते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। वे समझते हैं कि बौद्धिक ज्ञान, धन-संपत्ति, नाम और सत्ता अर्जित करना ही अधिक महत्त्वपूर्ण है, पर जब मृत्यु पास आती है तो उन्हें अनुभव होता है कि बौद्धिक ज्ञान और सांसारिक जायदाद किसी काम की नहीं हैं। उस अवसर पर वे पछताते हैं कि उन्होंने आत्मा, परमात्मा और परलोक की जानकारी पाने में अधिक समय क्यों नहीं व्यतीत किया। जो व्यक्ति छोटी उम्र में अध्यात्म की शिक्षा पा लेते हैं, वे भाग्यशाली हैं। वे प्रति दिन कुछ समय अपने आध्यात्मिक अभ्यास में लगा सकते हैं ताकि इसी जीवन में देहाभास से ऊपर उठने की कला में माहिर हो सकें। तैरने के जैसे, इसका अभ्यास करना पड़ता है। दैनिक ध्यान-अभ्यास से हमारी आध्यात्मिक कुशलता तो विकसित होगी ही जिससे हम वहां पर पहुंच सकें, जहां पर हम अंतर के रूहानी मंडलों का अनुभव पा जाएं।

रीडर्स मेल

सोच-समझ कर वोट करें

चुनाव के इस असंतुलित वातावरण में चारों ओर नई सरकार के चुने जाने का उत्साह दिखाई देता है। एक पक्ष को अनजाने में या फिर उसकी प्रासंगिकता का क्षीण हो जाने के कारण कोई देख नहीं रहा। इस चुनाव से कहीं महत्त्वपूर्ण है जीवन के अनेक पड़ावों में से सही या गलत का चुनाव, सुख को प्राप्त करने की चाहत में अनचाहे दुखों का चुनाव, जीवन के हर पड़ाव पर स्वयं की अस्मिता को व्यक्त करने का चुनाव और उससे भी महत्त्वपूर्ण है अपने अस्तित्व का चुनाव। यह सुनकर आपको शायद अटपटा लग रहा होगा लेकिन आधुनिक युग में हम अपने अस्तित्व का चुनाव स्वयं नहीं करते हैं। कभी स्थिति के चलते तो कभी आर्थिक रूप से कमजोर होना हमसे उस भविष्य का चुनाव करवा देता है, जो हम नहीं करना चाहते। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र में किसका चुनाव किया जाए। किसको चुना जाए। ऐसा चुनाव कैसे किया जाए। सोचना जरूरी है।

प्रिया कुशवाह, ई मेल से

नियमों की अनुपालना जरूरी

पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाई जा रही है, हिमालय की चोटियों से लगा कर सागर की तलहटी तक प्लास्टिक, पोलिथिन और ई-वेस्ट कचरे से भर चुकी हैं, और जैव-विविधता तथा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, नदियों में कूड़ा-करकट फेंक कर उन्हें गंदा किया जा रहा है, तापमान बढ़ने से हिमाच्छादित ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है जिससे कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। अमानक पोलिथिन पर बेन के बावजूद इसका उत्पादन, विक्रय और उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे संभव होगा, इस पर रोकथाम के लिए सख्त नियमों की दरकार है। सिर्फ सख्त नियमन ही नहीं, उनकी अनुपालना भी जरूरी है।

संजय डागा, इंदौर

क्यों लगे विरासत कर?

हाल ही में सैम पित्रोदा के संपत्ति में 55 परसेंट सरकार द्वारा ले लिए जाने के कानून का समर्थन करने की बाबत सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे इसी प्रकार के मामले में बहस जारी है। सरकार को तरह-तरह के टैक्स लगाकर, जीएसटी में बड़ी भारी आमदनी प्राप्त हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थों पर, शराब पर शत-प्रतिशत से अधिक टैक्स वसूलने के बाद भी सरकारों की नजर जनता के धन पर लगी रहती है। सभी तरह के टैक्स चुका कर कठोर परिश्रम से एकत्र किए गए धन पर फिर से कुंडली मारने की मंशा स्वीकार करने योग्य नहीं है, और ऐसी स्थिति में तो और भी जब सरकारी संसाधनों को वोट कबाड़ने के लिए कर्ज लेकर दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। महिलाओं को, किसानों को अरबों रुपये नकद दिए जा रहे हैं। अस्सी करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मुफ्त अनाज बांटने की घोषणा हो चुकी है। दिन-रात एक कर के सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद भी हर कार्य के लिए रिश्वत देकर अपने परिवार का पेट पालने के बाद संतानों के भविष्य के लिए संग्रहित किए जाने वाले धन को भी छीनने की मंशा निंदनीय है, और इसका देश भर में जोरदार विरोध होगा।

सुभाष बुडावन वाला, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750

वर्ष-33, अंक 255

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी

संपादकीय

संस्थापक: शहीद लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चंद्र जी एवं करम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

कूड़े में फैंको अमेरिकी रिपोर्ट

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चल रहे चुनाव उत्सव पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। अमेरिका, चीन और अन्य देश पैनी नजरें रखे हुए हैं। यद्यपि अमेरिका ने इन चुनावों को लेकर अपना कोई पर्यवेक्षक या कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है लेकिन वह समय-समय पर ऐसा कुछ करता रहता है, जिससे भारत विचलित हो जाता है। अमेरिका का मानवाधिकारों को लेकर भारत को ज्ञान देना उसका पुराना हथकंडा रहा है, जबकि भारत ने हमेशा ही उसकी बोलती बंद की है। अमेरिका खुद अपने भीतर कभी झांककर नहीं देखता कि उसके यहां खुद क्या हो रहा है। मानवाधिकारों के मामले पर अमेरिका खुद कटघरे में खड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा मानवाधिकारों का पैरोकार होने का दावा करने वाला अमेरिका दोहरे मानदंड अपनाता है और वह पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी मानवाधिकार रिपोर्ट को भारत ने बेहद पक्षपातपूर्ण बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। भारत ने अमेरिका की बोलती यह कहकर बंद कर दी कि उस रिपोर्ट को हम कोई महत्व ही नहीं देते हैं। यह रिपोर्ट भारत की छवि खराब करने के लिए ही गढ़ी हुई है।

अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और दूसरे अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से भेदभाव जारी रखा। बीजेपी का समर्थन करने वालों ने निश्चित समूहों के लोगों पर हिंसक हमले किए। रिपोर्ट के अनुसार, सिविल सोसायटी से जुड़े लोगों को चुप कराने और सरकार की आलोचना करने वालों पर चरमपंथ समेत राजनीति से प्रेरित अन्य आरोप लगाकर स्वतंत्र पत्रकारों को चुप कराने या उन्हें जेल भेजने की कोशिशें हुई हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी के हनन और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है।

2023 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में 80 पन्ने भारत के बारे में हैं। रिपोर्ट के सारांश में सबसे पहले मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बीते साल मई में हुई नस्लीय हिंसा का ज़िक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान मानवाधिकरों के हनन के मामले देखे गए। बलात्कार, दुकानें और घर जलाने, पूजास्थलों को नष्ट करने के मामले नज़र आए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मई की तीन तारीख से लेकर नवंबर 15 के बीच इस हिंसा में 175 लोगों की मौत हुई और 60 हज़ार से अधिक लोग विस्थापित हुए।

पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने युद्ध अनुमाद में अफगानिस्तान और इराक में क्या किया। आतंकवाद विरोध के नाम पर चलाए गए अभियान में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। अमेरिका की जेलें कैदियों से भरी पड़ी हैं और जेल के भीतर की स्थितियां आधुनिक गुलामी की जगह बन गई है। धार्मिक असहिष्णुता और घृणा अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सिख और मुस्लिम विरोधी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। राजनीतिक रिश्वतखोरी ने भी अमेरिकी व्यवस्था को कलंकित कर दिया है। अरबों का काला धन अमेरिकी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं।

रिपोर्ट में गोवंश की तस्करी के आरोप में कुछ लोगों को पीट-पीट कर मार डालने, पुलिस हिरासत में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या किए जाने का उल्लेख है। रिपोर्ट में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि राज्य एजैंटों द्वारा न्याय से इत्तर कार्रवाइयों के पैटर्न का संकेत है। अमेरिका को हत्याएं करने वाले बाहुबली और आतंकवादी क्यों प्यारे लगते हैं यह समझ से बाहर है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में उसकी दादागिरी चलती रहे। इससे पहले भी अमेरिका सीएए और भारत के चुनावों को लेकर टिप्पणी कर चुका है, जिसका मुंहतोड़ जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर दे चुके हैं। मानवाधिकारों के मामले में अमेरिका का रिकार्ड खुद बहुत ज्यादा कलंकित है। नस्लीय भेदभाव, बंदूक और पुलिस हिंसा जैसी बीमारियों से वैश्विक शक्ति ग्रस्त है। बंदूक की हिंसा से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नस्लवाद बढ़ रहा है और जातीय अल्पसंख्यकों को लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की ज्यादतियों से अश्वेतों का मारा जाना किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अमेरिका की दादागिरि और एक तरफा प्रतिबंधों ने मानवीय आपदाएं ही पैदा की हैं।

पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने युद्ध अनुमाद में अफगानिस्तान और इराक में क्या किया। आतंकवाद विरोध के नाम पर चलाए गए अभियान में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। अमेरिका की जेलें कैदियों से भरी पड़ी हैं और जेल के भीतर की स्थितियां आधुनिक गुलामी की जगह बन गई है। धार्मिक असहिष्णुता और घृणा अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सिख और मुस्लिम विरोधी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। राजनीतिक रिश्वतखोरी ने भी अमेरिकी व्यवस्था को कलंकित कर दिया है। अरबों का काला धन अमेरिकी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी गम्भीर नस्लीय असमानता देखने को मिल जाती है। अगर अमेरिका मानवाधिकारों का इतना ही बड़ा पैरोकार है तो गाजापट्टी में इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार पर अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करता। अमेरिका गाजीपट्टी में फलीस्तीनियों के नरसंहार के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार क्यों कर रहा है। ग्वांतामानो की जेल में बंदी बनाकर रखे गए लोगों से क्रूर और अमानवीय व्यवहार के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। अमेरिका ने पर्दे के पीछे रहकर युद्ध भड़काने का ही काम किया है। जब युद्धों में लोग मरते हैं। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं तब अमेरिका मानवाधिकारों के बारे में क्यों नहीं सोचता। शांति-शांति का राग अलापने वाला अमेरिका वैश्विक शांति का विध्वंसक बना हुआ है, इसलिए भारत को अमेरिका के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। अमेरिकी रिपोर्ट को रद्दी में फैंकना ही अच्छा कदम है।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

NewsPaperPaid

क्या कारगर रहेगी अखिलेश की रणनीति ?

ताक-झांक

आर.आर. जैरथ

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपनी पुरानी रणनीति के विपरीत इस बार कम यादवों और मुसलमानों को मैदान में उतारा है और ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को अधिक टिकट दिए हैं। जिन 62 सीटों पर वह इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ रही है,

उनमें से सपा ने केवल 6 यादव और 4 मुसलमानों को चुना है। दूसरी ओर, इसने गैर-यादव ओबीसी समूहों से 25 और उच्च जातियों से 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वह निश्चित रूप से 14 आरक्षित सीटों से दलितों को मैदान में उतारेगी। लेकिन अपने मतदाता आधार का विस्तार करने के एक प्रयोग के तहत, सामान्य वर्ग की 2 सीटों पर दलित उम्मीदवारों को नामांकित करने की संभावना है।

सपा के पारंपरिक यादव-मुस्लिम आधार से दूर जाने की अखिलेश यादव की कोशिश यूपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है क्योंकि यह ओबीसी मतदाता समूहों पर भाजपा के आधिपत्य को सीधी चुनौती है। ये समूह 2014 के बाद से यूपी में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा की लगातार प्रचंड जीत की रीढ़ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों की सूची का जाति विभाजन दिलचस्प है क्योंकि यह सपा सूची के ओबीसी वर्चस्व के बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी ने 29 ओबीसी को उम्मीदवार बनाया है लेकिन 32 टिकट ऊंची जातियों के खाते में गए हैं। ब्राह्मणों और ठाकुरों का वर्चस्व ओबीसी समूहों को सशक्त बनाने में विश्वास रखने वाली पार्टी होने के उसके दावे पर संशय पैदा करता है। ऐसा लगता है कि यूपी एक दिलचस्प लड़ाई के लिए तैयार है। 2014 से भाजपा को भारी जीत दिलाने और जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ने वाली मोदी लहर का प्रभाव अगर कम रहा तो समीकरण दिलचस्प होंगे।

इस बार बेंगलुरू से महिला सांसद जा सकती है संसद

कर्नाटक जैसे प्रबुद्ध दक्षिणी राज्य में यह आश्चर्य की बात है कि इसकी राजधानी बेंगलुरु ने कभी भी किसी महिला सांसद को लोकसभा में नहीं भेजा है। इस बार उम्मीद है कि ये पुरुष वर्चस्व बदल सकता है। पहली बार शहर से दो महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने

बेंगलुरु दक्षिण सीट से सौम्या रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने बेंगलुरु उत्तर सीट के लिए शोभा करंदलाजे को चुना है। रेड्डी भाजपा के फायरब्रांड और मौजूदा सांसद तेजस्वी सूर्या से टक्कर लेंगी और यह एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है।

रेड्डी 2023 में बेंगलुरु दक्षिण के जयनगर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 16 वोटों से हार गई थी और एक मजबूत उम्मीदवार हैं। निस्संदेह, सूर्या एक ओजस्वी वक्ता और प्रखर हिंदुत्ववादी हैं।करंदलाजे केंद्रीय मंत्री हैं और बेंगलुरु में एक जानी-मानी हस्ती हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के राजीव गौड़ा हैं। हालांकि बेंगलुरु उत्तर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2004 में यह भाजपा के हाथ में चला गया और तब से पार्टी के पास है। राजनीतिक हलकों का कहना है कि दोनों चुनावों का नतीजा कर्नाटक की राजधानी में मोदी लहर की ताकत पर निर्भर करता है।

कन्हैया को कांग्रेस से नहीं मिल रहा समर्थन

पूर्वोत्तर दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की प्रसिद्ध भाषण कला उनकी उम्मीदवारी के प्रति उनकी पार्टी की खुली उदासीनता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। ऐसा लगता है कि कुमार को स्थानीय दिल्ली कांग्रेस नेताओं, विशेषकर दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली

से बहुत कम मदद मिल रही है, और प्रचार के लिए उन्हें अद्वितीय लालू यादव शैली में दिए गए अपने उग्र भाषणों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लवली ने पूर्वोत्तर दिल्ली से कांग्रेस के टिकट के लिए कड़ी मेहनत की थी लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल रहे। जाहिर तौर पर, क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिहारी प्रवासी आबादी के कारण पार्टी ने कुमार पर फैसला किया। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता बिहार के बेगुसराय के रहने वाले हैं।

दरअसल, लड़ाई यूपी प्रवासी बनाम बिहारी प्रवासी में बदल सकती है क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी भी बिहार से हैं। तिवारी लोकप्रिय भोजपुरी फिल्म अभिनेता हैं और एकमात्र मौजूदा भाजपा सांसद हैं जिन्हें चुनाव में दोहराया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुमार को दिल्ली के पूर्व कद्दावर नेता अजय माकन का पुरजोर समर्थन प्राप्त था। माकन के गांधी परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं और वह कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को प्रभावित करने में सक्षम थे। लालू यादव ने कुमार को बिहार से टिकट देने का विरोध किया था क्योंकि उन्हें डर था कि यह कुशल वक्ता भविष्य में बेटे तेजस्वी के लिए प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकते हैं।

अवनी डायस का मामला?

विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की संवाददाता अवनी डायस के भारत से जल्दबाजी में बाहर निकलने की परिस्थितियों को समझाने के लिए नई दिल्ली स्थित विदेशी पत्रकारों को आमंत्रित किया।

यह निमंत्रण विदेशी पत्रकारों द्वारा भारत सरकार को कड़ा पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगने के बाद आया है। यह विदेशी मीडिया का एक असामान्य कदम था और इससे जाहिर तौर पर सरकार को परेशानी हुई। जैसा कि बाद में पता चला, बैठक में कोई खास नतीजा नहीं निकला। यह उत्सुकता की बात थी कि अधिकांश विदेशी मीडिया संगठनों ने अपने स्थानीय कर्मचारियों को भेजा, न कि विदेश से भारत में तैनात लोगों को। स्वाभाविक रूप से, अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए। सरकारी हलकों को आश्चर्य हो रहा है कि विदेशी मीडिया संगठनों ने अपने भारतीय स्टाफ सदस्यों को भेजने का फैसला क्यों किया, अगर वे एबीसी संवाददाता के बाहर निकलने से चिंतित थे तो विदेश से तैनात पत्रकारों को क्यों नहीं भेजा गया।

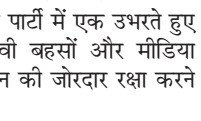

जाति जनगणना पर राहुल का जोर

राहिल नोरा चोपड़ा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारत के दलितों, ओबीसी, गरीबों की स्थिति का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग करके ओबीसी, एससी और

एसटी के प्रश्न को राष्ट्रीय चर्चा की प्राथमिकता पर रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि समाज का एक्सरे (हाशिए पर मौजूद वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय गणना) अब मेरे जीवन का मिशन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनिंदा 22 लोगों को दिए गए 16 लाख करोड़ में से देश के 90 प्रतिशत लोगों को थोड़ी-थोड़ी रकम वापस करने का वादा किया गया है। दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने यह नहीं कहा कि हम पूरे 16 लाख करोड़ रुपए लौटाएंगे। हमने गणना की है और कहा है कि केवल थोड़ी सी रकम वापस की जाएगी।

रायबरेली में गांधी वर्सेज गांधी की अटकलें

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना के बीच, भगवा गलियारे इन व्यापक अटकलों से भरे हुए हैं कि वरुण गांधी, जिन्हें भाजपा ने उनके पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से टिकट देने से इनकार कर दिया था, को रायबरेली से उतारा जा सकता है। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों ने भी खुलासा किया है कि शीर्ष भाजपा नेतृत्व अब रायबरेली में "गांधी बनाम गांधी" लड़ाई बनाने पर विचार कर रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट पर अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ संभावित चुनावी मुकाबले से इनकार कर दिया है। इस बीच, यह याद किया जा सकता है कि हाल ही में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और

रायबरेली कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था कि पार्टी को "प्रियंका या गांधी परिवार के किसी अन्य सदस्य" को रायबरेली से मैदान में उतारना चाहिए। प्रियंका लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही हैं और अब अगर पार्टी उन्हें अनुमति देती है तो वह रायबरेली सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही वह नेहरू-गांधी परिवार से रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली तीसरी पीढ़ी होंगी।

'नकली' शिवसेना दिखाएगी असली ताकत

शिव सेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने अपने विश्वास पर भरोसा करते हुए दावा किया है कि इंडिया गंठबंधन 543 सदस्यीय लोकसभा में 300 से अधिक सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शिवसेना (यूबीटी) के

उम्मीदवार नरेंद्र खेडेकर के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को 'नकली' कहने के लिए लोग जल्द ही भाजपा को सबक सिखाएंगे। आप मेरी पार्टी को 'नकली' शिवसेना कहते हैं, लेकिन यही सेना आपको अपनी असली ताकत दिखाएगी। उन्होंने हमला जारी रखते हुए कहा, क्या मेरी शिव सेना आपकी डिग्री की तरह है जिसे आप नकली कहते हैं? लोग आपको आपकी जगह दिखाएंगे। गौरतलब है कि मोदी ने ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को "नकली" शिवसेना कहा है।

दूरदर्शन मामले में भगवा दल पर निशाना

मौजूदा आम चुनावों के बीच अपने प्रतिष्ठित लोगो का रंग लाल से भगवा करने के लिए प्रसार भारती के पूर्व सीईओ और तृणमूल कांग्रेस सांसद, जवाहर सरकार ने स्वायत्त राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक, दूरदर्शन की आलोचना की है। हालांकि अपने कदम का बचाव करते हुए दूरदर्शन (डीडी) ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि इसका प्रारंभिक लोगो, जो 1959 में लांच किया गया था, वह भी भगवा रंग का था। दूरदर्शन के इस कदम को लेकर जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर सात चरणों के लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने और जीतने के लिए राष्ट्रीय संपत्तियों और प्रतीक चिह्नों का रंग भगवा करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, जब लोग चुनावी मोड में हैं तो भारत का चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के इस भद्दे, भगवा समर्थक उल्लंघन की अनुमति कैसे दे सकता है? वहीं, 2012 से 2014 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी लोगो के रंग को लेकर आरोप लगाया कि इसे बदलना सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने की सरकार की कोशिश है।

पीएम का शुक्रिया, लोग पढ़ रहे हमारे मेनिफेस्टो

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा अब पार्टी में एक उभरते हुए सितारे हैं, क्योंकि टीवी बहसों और मीडिया इंटरेक्शन में पार्टी लाइन की जोरदार रक्षा करने का श्रेय उन्हें जाता है।

हालांकि पवन खेड़ा, जो पिछले कुछ समय से पर्दे के पीछे से काम करने के लिए जाने जाते हैं, ने पार्टी की मीडिया रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं और उचित समय पर मीडिया को तुरंत जानकारी उपलब्ध कराई है। घोषणापत्र पर मोदी की टिप्पणी को आम चुनाव के बीच मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का प्रधानमंत्री का एक और प्रयास बताते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में कभी भी हिंदू या मुस्लिम जैसे शब्दों के बारे में बात नहीं की गई या उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। हमने न्याय के बारे में बात की-युवाओं, आदिवासियों, श्रमिकों, महिलाओं के लिए न्याय। प्रधानमंत्री को धन्यवाद कि लोग आज हमारे घोषणापत्र को पढ़ रहे हैं यह जानने के लिए कि क्या हमने ऐसे किसी विभाजनकारी शब्द का इस्तेमाल किया है... वे महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।

उन्होंने आगे कहा, न तो हमारे घोषणापत्र में, न ही हमारे दिमाग में, संविधान में, न ही समाज में ऐसे शब्दों के लिए जगह है।

दुबई की बेतहाशा बारिश इंसान के बस की बात नहीं

कुछ साल पहले, मैं दक्षिण अफ्रीका-मोज़ाम्बिक सीमा के पास एक सुनसान हवाई अड्डे के उमस भरे रनवे पर लियरजेट की संकरी सीढ़ियां चढ़ रहा था। वहां हवा में नमी इस कदर ज्यादा थी कि जुबान पर उसका स्वाद महसूस हो रहा था। मौसम का हाल बताने वाला राडार तेजी से विकसित होने वाले गरज वाले बादल दिखा रहा था। हमारा मिशन तूफान के सबसे सक्रिय हिस्से से होकर गुजरना, उसे मापना, सूखी बर्फ गिराना, तेजी से वापस मुड़ना और अंतिम माप लेना था।

लियरजेट का अंदरूनी हिस्सा एक ब्लेंडर जैसा था, जिसमें बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट थी। हजारों मीटर नीचे, एक छोटा विमान बारिश को मापते हुए तूफान के बहाव के बीच से गुजर रहा होगा। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप हर दिन करते हैं, हालांकि लियरजेट के पंखों पर तश्तरी के आकार के ओलों के निशान इसके इसी तरह के कई पूर्व कार्यों की गवाही दे रहे थे। लियरजेट में तूफान के बीच से उड़ान भरने के मजे के अलावा, हाल तक मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे उस परियोजना का हिस्सा बनने का मौका मिला, जब मैंने दुबई में हाल ही में आए भयंकर तूफान के बारे में नहीं सुना तो मुझे ऐसा ही लगा। जिस परियोजना का मैं हिस्सा था, उसे रेन (नेल्सप्रूट में रेन ऑग्मेंटेशन) नाम दिया गया था, वह एक क्लाउड सीडिंग प्रयोग था जो कई वर्षों से चल रहा था। क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को बादल में जोड़ा जाता है ताकि नमी को कुछ आधार मिल सके और बूंदें बन सकें। धीरे-धीरे वे बूंदें आपस में जुड़ जाती हैं और इतनी भारी हो जाती हैं कि बारिश के रूप में गिर सकती हैं। सिद्धांत रूप में, ''बीजयुक्त'' बादलों में बारिश के लिए उपयुक्त अधिक बूंदें उगेंगी। कोई भी उड़ान बीजारोपण के प्रभावी होने का प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई समान बादल नहीं है जिसके साथ किसी विशेष बादल को बोने के परिणाम की तुलना की जा सके। इसलिए बहुत सारे मिशनों को उड़ाना और उनमें से आधे बीज के लिए नहीं, मापने के लिए होते हैं, मापना आवश्यक है, जिससे स्वयं प्रयोग (बीज वाले

बादल) और नियंत्रण (बिना बीज वाले बादल) के लिए एक डेटा सेट तैयार हो सके। रेन के परिणामों के सांख्यिकीय विश्लेषण में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कई वर्षों की कोशिश के बाद, कुछ तूफानों से बारिश की दरों में संशोधन सफल रहा, हालांकि यह साबित करना कभी संभव नहीं होगा कि किसी एक तूफान में बदलाव किया गया था।

एकदम सही तूफान

मंगलवार की सुबह, 16 अप्रैल को, मेरे स्कूल की कक्षा का चैट नेटवर्क, जो 40 वर्षों के विस्तार के बाद वैश्विक अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण है, बहरीन में ब्रेंडन और दुबई में अभूतपूर्व बारिश की रिपोर्टों से जगमगा उठा। एंट एक पायलट है और उस सुबह दुबई से उड़ान भर रहा था। उन्होंने संतृप्त रेगिस्तान के ऊपर अपनी उड़ान की तस्वीरें विधिवत प्रसारित कीं। अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में उस मंगलवार को 24 घंटों में इतनी बारिश हुई, जितनी अमूमन 18 महीने में होती है। हवाई अड्डा एक बंदरगाह जैसा लग रहा था। चैट समूह में मौसम-विज्ञानी होने के नाते, मैंने उपग्रह और पूर्वानुमान मॉडल डेटा को देखा। मैंने जो देखा वह एक आदर्श तूफान के अवयव थे।

पुराने रेगिस्तानों, जैसे कि अरब प्रायद्वीप, को आम तौर पर बहुत शुष्क बनाए रखने वाली चीज़ हवा का लगातार और तीव्र रूप से डूबना है - जो बारिश के लिए आवश्यक चीज़ों के बिल्कुल विपरीत है। डूबती हुई हवा हड्डी की तरह सूखी होती है, जो वायुमंडल के शीर्ष से ठंड से आती है, और नीचे आते ही संपीड़ित और गर्म हो जाती है। यह हेअर ड्रायर की तरह सतह के करीब आता है। इस परत के नीचे, विशेषकर गर्म महासागरों के निकट के रेगिस्तानों में, वाष्पीकरण प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन उस नमी को ऊपर डूबती हवा ने कैद कर रखा होता है। यह एक कड़ाही की तरह होता है जिसका ढक्कन मजबूती से लगा हुआ है। 16 अप्रैल को कड़ाही से जिस चीज़ ने ढक्कन हटाया वह असामान्य रूप से दूर दक्षिण में एक बहुत ऊंचाई वाली जेट स्ट्रीम थी। वास्तव में दो जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय जेट और ध्रुवीय जेट, जो एकजुट हो गए थे और अपने पीछे आयातित, ठंडी हवा छोड़ गए थे। कड़ाही के ढक्कन के साथ-साथ डूबती हुई हवा भी ख़त्म हो गई थी। इस बीच उत्तरी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर से नमी भरी हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा था और रेगिस्तान में एकत्रित हो रहा था। संयुक्त अरब अमीरात में ओस बिंदु तापमान सामान्य रूप से कांगो बेसिन के वर्षावनों में पाए जाने वाले तापमान के समान था। इन परिस्थितियों में, तूफान बहुत तेजी से विकसित होते हैं और इस मामले में एक विशेष प्रकार का तूफान, एक मेसोस्केल संवहन प्रणाली, कई घंटों तक बनी और कायम रहती है। इन्फ्रारेड उपग्रह डेटा से पता चला कि इसका आकार फ्रांस के बराबर था।

क्लाउड सीडिंग दोषी नहीं

इस तरह के तूफान की शक्ति, तीव्रता और संगठन को समझना कठिन है। हालाँकि, जिस बात ने मुझे आश्चर्यचकित किया, वह प्रकृति की महिमा नहीं थी, बल्कि आने वाली बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराने वाली खबरें थीं। एक ब्रॉडशीट में यह भी कहा गया कि इसके लिए रीडिंग यूनिवर्सिटी, जो कि मौसम संबंधी विशेषज्ञता का एक केंद्र है, जिम्मेदार है। यह पता चला है कि यूएई कई वर्षों से क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट, यूएई रिसर्च प्रोग्राम फॉर रेन एनहांसमेंट साइंस चला रहा है। उनका दृष्टिकोण विमान से हाइग्रोस्कोपिक (पानी को आकर्षित करने वाली) नमक की फ्लेयर्स को गर्म संचयी बादलों में डालना है। यह विचार, उस वर्षा परियोजना के समान है जिस पर मैंने एक बार काम किया था, बादल की बूंदों की वृद्धि और इस प्रकार वर्षा को बढ़ावा देना है। बड़ी बूंदें अधिक आसानी से गिरती हैं।

अपनी-अपनी निष्ठा...

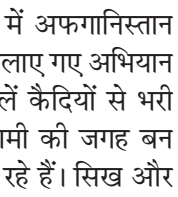

गीता पाढा

"अभिनयकार, पत्रकार, गीतकार भांति-भांति के
लोग राजनीति में आ रहे हैं,
और अपने-अपने दल के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं,,
निष्ठा इस कदर कि इतिहास को ही झूठला रहे हैं,
हद तो तब हुई जब भारत को आजाद भी वो
2014 के बाद बता रहे हैं...।।"

मोदी के लिए प्रचार करना चाहते हैं दुनियाभर में रह रहे गुजराती

तैयार किया मास्टर प्लान

अहमदाबाद, (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच दुनियाभर में रह रहे गुजराती प्रवासी भारत पहुंच रहे हैं ।यूएस, यूके, लंदन सहित अन्य यूरोपीय देशों में रह रहे प्रवासी गुजराती बड़ी संख्या में भारत पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए कमर कस चुके हैं। प्रवासी गुजरातियों ने पीएम मोदी के पक्ष में प्रचार करने के लिए सूरत से लेकर अहमदाबाद तक रैली करने का भी फैसला किया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल होंगे। रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें हालांकि, इसे लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम काफी पहले छेड़ी जा चुकी है, जिसमें लोगों से पीएम मोदी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर चुकी है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

और बढ़े मतदान

देश में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही करीब 35 प्रतिशत लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। कुल मिलाकर, मतदान इस बार बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है और मतदान प्रतिशत भी ऐसा नहीं है कि जिसे देख बहुत चिंता हो। कुल मिलाकर, दूसरे चरण में 88 निर्वाचन क्षेत्रों के 1,202 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। खास बात यह है कि इस चरण में कुल 15.88 करोड़ मतदाताओं में से 3.28 करोड़ युवा मतदाता हैं और उनमें भी 34 लाख युवाओं को तो पहली बार वोट डालने का मौका मिला। कितने युवाओं ने आगे बढ़कर मतदान किया है, इसका आंकड़ा तो आगामी दिनों में आएगा, पर इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को युवाओं से बड़ी उम्मीदें हैं। इस चरण में जिन 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान हुआ है, उनमें से सर्वाधिक महत्व केरल का है, जहां शाम तीन बजे तक लगभग 52 प्रतिशत वोट डल चुके थे। इसके बाद कर्नाटक की आधी सीटों, मतलब 14 सीट और राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान हुआ है। ये दोनों ऐसे राज्य हैं, जहां भाजपा मजबूत है और कांग्रेस को एक नई शुरुआत की आस है।

उत्तर प्रदेश की आठ और बिहार की पांच सीटों पर भी मतदान हुआ है। इस चरण के चर्चित प्रत्याशियों में राहुल गांधी भी हैं और शशि थरूर भी, तो अभिनेत्री हेमा मालिनी को भी तीसरी बार जीत का भरोसा है। कुल मिलाकर, इन सभी 88 सीटों पर कांटे की टक्कर वाली स्थिति है।

अठारहवीं लोकसभा के गठन के लिए दूसरे चरण के मतदान में पहले चरण के मतदान की तुलना में ज्यादा उत्साह का दिखना सुखद और स्वागतयोग्य है।

दोपहर तीन बजे तक हुए मतदान से ही यह बात साफ हो गई थी कि प्रथम चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में मतदान ज्यादा होने जा रहा है। छोटे राज्यों में ज्यादा तेजी से और ज्यादा मतदान हुआ है। त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ में भी तेज मतदान प्रशंसनीय है। यहां तक कि जम्मू-कश्मीर में भी दिन में तीन बजे तक लगभग 58 प्रतिशत मतदान हो चुका था। वैसे, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर कम मतदान हो रहा है, तो चुनाव के प्रति जिम्मेदारी और जन-जागरूकता पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहले चरण में कम मतदान की चर्चा खूब हुई है और इसके आधार पर हार-जीत के आकलन की भी कोशिश दिखी है। हालांकि, कम या ज्यादा मतदान के कभी निश्चित नतीजे नहीं होते। अतः चुनाव विशेषज्ञों का जोर हार-जीत की चर्चा के बजाय मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर ज्यादा होना चाहिए। मतदान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ही लोकतंत्र को मजबूत करती है और नेताओं को भी सतर्क करती है कि वे केवल अपने सुरक्षित दायरे में ही प्रचार न करें, अधिकतम, बल्कि सभी मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करें।

ध्यान रहे, अब अगले या तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। चुनाव आयोग ने तिथियों का फैसला करते हुए पूरे दस दिन का अंतर रखा है और यह मतदान के चरणों के बीच सर्वाधिक अंतर है। इतने अंतर का लाभ तभी है, जब कम से कम 70 प्रतिशत के करीब मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जा सके। ज्यादा समय लेकर चुनाव कराने का आकलन करना होगा, अगर ज्यादा समय लेकर चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ता है, तो फिर चुनाव आयोग के अगले फैसलों पर इसका असर पड़ना चाहिए। बहरहाल, तीसरे चरण में कुल 94 सीटों पर मतदान संपन्न होगा और उसके साथ ही आधे से ज्यादा चुनाव पूरा हो जाएगा। खैर, लोकतंत्र में संयम सबसे जरूरी है। जिन लोगों ने मतदान कर दिया है या जिनके भाग्य का फैसला हो चुका है, उन्हें नतीजों के लिए अभी लंबा इंतजार करना है।

अमीर-गरीब में अंतर फिर चर्चा में है। अमीरों से ज्यादा धन लेने या विरासत कर की भी चर्चा है। ऐसे में, गौर कीजिए कि आज से चालीस साल पहले तक देश में संपदा शुल्क की वसूली होती थी। उस पर 26 जुलाई, 1984 को लोकसभा में हुई बहस आज भी प्रासंगिक लगती है।

ऐसा कानून बनाइए जो विषमता मिटा दे

दिगंबर सिंह | वरिष्ठ नेता और सांसद

- हमारी जो नीति चल रही है, अमीर-गरीब के बीच भेद बढ़ता चला जाएगा।
- हमारी सरकार और अफसर किसानों को संपन्न नहीं बनने देना चाहते।
- बाप के मरने के बाद उसकी औलाद पुश्त-दर-पुश्त क्यों खाती रहे?

उपाध्यक्ष महोदय, खुशी की बात है कि इस विधेयक के जरिये एस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, 1953 में संशोधन करने के लिए मंत्री महोदय प्रस्ताव लाए हैं। अच्छा होता, यदि इसमें कुछ और भी संशोधन किए जाते, क्योंकि हमारी सरकार की नीति समाजवाद को देश में लाने की है। समाजवाद का अभिप्राय गरीब और अमीर के बीच के भेद कम करना है, पर हम देख रहे हैं, जैसी हमारी नीति आज चल रही है, उससे यह भेद कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है।...

लाभ सिर्फ पूंजीपतियों और बड़े अधिकारियों को हो रहा है। मैं लोकसभा में भी लंबे अरसे से देख रहा हूं कि अधिकतर बिलों का उद्देश्य एक ही होता है कि पूंजीपतियों को पूंजीपति कैसे रहने दिया जाए तथा सरकारी नौकरियों में अधिकारियों की बात कैसे चलती रहे। मेरा अनुभव यह भी है कि आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में भी पूंजीपतियों की चलती थी और बड़े-बड़े अफसरों की चलती थी और आजादी मिलने के बाद भी मैं यही देख रहा हूं...। यद्यपि हम समाजवाद को लाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन आप देखिए कि उसका नतीजा हमारे सामने क्या आ रहा है? वर्ष 1976-77 में 15 करोड़, 56 लाख रुपये एस्टेट ड्यूटी (संपदा शुल्क) के वसूल करने के लिए बकाया रहते थे, पर उसके बाद हमारी नीतियों के परिणामस्वरूप यह राशि 1977-78 में बढ़कर 17 करोड़ रुपये हो गई और 1980-81 में बढ़कर 27 करोड़, 65 लाख रुपये हो गई।...

एक संशोधन यह भी होना चाहिए कि यदि कोई आदमी मरता है, तो एक सीमा से अधिक उसकी संपत्ति जनता की होनी चाहिए।... आप इनसे आगे बढ़कर भी देखें। वर्ष 1979-80 में राजा-महाराजाओं पर 21 करोड़, 15 लाख रुपये बकाये थे, जिनमें से सिर्फ 4 करोड़, 64 लाख रुपये वसूल हुए। इसी तरह, 1981-82 में बकाया बढ़कर 18 करोड़ हो गया।

मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी नीति चल रही है, किसानों की स्थिति सब लोगों को पता है, वे गरीब होते चले जा रहे हैं, उनके साथ इस तरह से भेद किया जा रहा है। यदि यही स्थिति चलती रही, तो मैं समझता हूं कि उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे लिए एक जटिल समस्या पैदा हो जाएगी। मेरा अनुभव यह है कि हमारी सरकार और अफसर किसानों को संपन्न नहीं बनने देना चाहते।...

अगर संशोधन लाना है, तो ऐसा करना चाहिए, जिससे पूंजीपति न बढ़ें और उस पूंजी का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को मिले। सन् 1952 में यहां पांचतारा होटल अधिक नहीं थे, पर अब उनकी भरमार है और उनमें जगह नहीं मिलती है। पूंजीपतियों के पास पैसा बढ़ रहा है, अतः एक सीमा बना दीजिए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इस सीमा से अगर अधिक संपत्ति छोड़कर कोई मरता है, तो बाकी की उसकी संपत्ति राष्ट्र को जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी। यह कौन सा तरीका है कि बाप के मरने के बाद उसकी औलाद पुश्त-दर-पुश्त खाए? अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आर्थिक विषमता की वजह से जो लूट-मार चल रही है, बेकार लोग घूम रहे हैं, यह अव्यवस्था चलती रहेगी।...

लोग कहते हैं, यह भगवान की कृपा नहीं है। भगवान तो आदमी को मां के पेट से पैदा करता है, सबकी मां का दूध एक-सा होता है, लेकिन गरीब चिथड़ों में रहता है, धनवान का बच्चा मखमली गद्दों में रहता है। यह कैसी व्यवस्था है? अतः जैसा मैंने कहा है, वैसा आप प्रतिबंध लगा दीजिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो चोरी, लूटपाट चलती रहेगी, बंद नहीं होने वाली है। अगर आप ऐसा संशोधन नहीं ला रहे हैं, तो दूसरा विधेयक लाइए और क्रांतिकारी कदम उठाइए, जैसा महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल चाहते थे और सरकार की भी नीति रही है कि आर्थिक विषमता को मिटाया जाए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

आमने-सामने

हम कोशिश कर रहे कि समानता आए

एस एम कृष्णा | तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री

- हम यह कह नहीं सकते, कर वसूली तंत्र एक-एक पाई वसूल रहा है।
- संपदा शुल्क की प्रवृत्ति ऐसी है कि मुकदमेबाजी की बहुत गुंजाइश है।
- अगर अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत काला धन है, तो प्रमाणित नहीं है।

श्रीमान, वाद-विवाद में अनेक विषयों की चर्चा की गई, लेकिन इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है।...हम संपदा शुल्क अधिनियम में सीमित रूप से संशोधन इसलिए कर रहे हैं कि इसकी जटिल प्रक्रिया से बचा जा सके। अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत उपयोगी सुझाव दिए हैं, इस सरकार समेत, कोई भी सरकार यह तसल्ली करके नहीं बैठ सकती कि कर वसूली तंत्र द्वारा एक-एक पाई वसूल की जा रही है। सरकार का प्रयास रहना चाहिए कि त्रुटियों को दूर कर कानून कड़ा बनाए और उसके बाद कर वसूल करने वाले सरकारी तंत्र को चुस्त बनाए। इस सरकार का हमेशा यही प्रयास रहा है...।

संपदा शुल्क 1953 में लागू किया गया था। इसे लागू करने के पीछे हमारा उद्देश्य समतावादी समाज स्थापित करना और अमीर-गरीब के बीच अंतर को कम करना है। ...ये विचार इस अर्थ में बिल्कुल श्रेष्ठ हैं कि इनसे सभी सहमत हैं। हमने इस दिशा में संभवतः सभी कदम न उठाए हों, परंतु निस्संदेह इस ओर कुछ अग्रसर हुए हैं।... हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने के बजाय यदि बिहार सरकार (या कोई राज्य सरकार) कानून बनाना चाहे, तो वह कानून बना सके।... मैं केवल कानूनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं न कि राजनीतिक इच्छा। पार्टियों की ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा है या नहीं, यह बिल्कुल एक अलग प्रश्न है।...

हम प्रतिदिन अधिकारों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। संघीय सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्यों को करों का सीमित क्षेत्र दिया गया है। अब यह एक ऐसा मामला है, जिसमें संघीय सरकार स्वयं इस क्षेत्र से हट रही है और राज्य सरकारों को इच्छानुसार हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर रही है।

...वास्तव में, इस संशोधन को पारित करने से हम संशोधन के अगले चरण में पहुंच जाएंगे, जिसमें संभवतः इन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकेगा।

...संपदा शुल्क की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि इसमें मुकदमेबाजी की बहुत अधिक गुंजाइश है। इस प्रकार की मुकदमेबाजी के कई चरण हैं और संपदा शुल्क की वसूली के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए समय अंतर अत्यधिक है, परंतु इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायालय में जाने के मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 75 करोड़ की आबादी वाले इतने विशाल देश में लगभग 45 लाख लोग आयकर के दायरे में हैं, यह धनराशि बकाया होने का कारण है। अतः कर निर्धारण के बारे में और कर वसूली के बारे में बात करते समय हमें इस समस्या की ओर सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। लगभग 4,23,000 धन कर दाता हैं। लगभग 1,13,000 उपहार कर दाता हैं। लगभग 74,000 संपदा शुल्क के मामले हैं। अब धन कर की कुल राशि लगभग 93 करोड़ रुपये, उपहार कर लगभग 8.5 करोड़ रुपये, संपदा शुल्क की राशि लगभग 21.48 करोड़ रुपये है। यह संभावना है कि इस कर की वसूली के समय कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, परंतु हम सबका प्रयास रहा है कि व्यवस्था को दोषरहित बनाएं, ताकि सरकारी खजाने में जो कर की राशि देय है, वह अदा की जाए, वसूल हो और लेखा-जोखा रखा जाए।...

आरोप यह है कि इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर करों की चोरी हो रही है। सरकार ने यह कभी नहीं कहा है कि करों की चोरी नहीं हो रही है। ...हम यह चाहते हैं कि हमें यह जानकारी मिले कि कर-अपवंचन किस मात्रा में हो रहा है। ...एक पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत काला धन है, परंतु यह प्रमाणित नहीं हो सका है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हमने स्वयं एक समिति के अध्ययन हेतु यह काम एक संस्था को सौंपा है। वे कुछ अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे पता चल सकेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन कितनी मात्रा में है।...

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

साइबर संसार में अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे हम

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अपराजिता भारती | जन-नीति सलाहकार

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की गुत्थी सुलझाने के क्रम में नए उपकरण से हमारे सामने कुछ नई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, इसीलिए हमें समग्रता में सोचना होगा।

हाल ही में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक ऐसे एप 'सेफनेट' पर काम कर रहा है, जो माता-पिता के फोन को उनके बच्चों के फोन से जोड़ेगा, ताकि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकें। अमूमन इस तरह की निगरानी में किसी एप या वेबसाइट को खोलने की अनुमति देने और बच्चे कितनी देर तक ऑनलाइन रहेंगे, यह तय करने के प्रावधान होते हैं, पर कहा जा रहा है कि सेफनेट में यू-ट्यूब जैसे मंचों पर देखी गई सामग्रियों की जानकारी देने सहित फोन कॉल डिटेल व एसएमएस भी साझा किए जा सकेंगे। 'इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोशिएशन ऑफ इंडिया' ने सुझाव दिया है कि यह एप सभी उपभोक्ताओं के फोन में डिफॉल्ट के रूप में होना चाहिए। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक गंभीर मसला है और यह बहस लाजिमी है कि इंटरनेट के इस्तेमाल से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि, बच्चा किस संदर्भ में इंटरनेट देख रहा है, उसके आधार पर इस प्रभाव का आकलन होना चाहिए, लेकिन नीति-निर्माताओं का मानना है कि वास्तविक दुनिया की तरह आभासी दुनिया में भी 'निगरानी का कर्तव्य' मूलतः माता-पिता को ही निभाना चाहिए। हालांकि, यहां कुछ बातों पर ध्यान देना भी आवश्यक है।

पहली, वास्तविक दुनिया में भी माता-पिता बच्चों तक पहुंचने वाली सभी सूचनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। वे आमतौर पर यह जानकर चौंक जाते हैं कि उनके बच्चों को कोई बात कैसे पता चली? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे उन बातों से अमूमन दूर रहते हैं, जो बच्चे अपने दोस्तों के बीच करते हैं। ऐसे में, यदि ऑनलाइन दुनिया में माता-पिता अपने बच्चों की बातचीत पर पूर्ण नियंत्रण लगाना शुरू कर देंगे, तो बच्चे टकराव मोल ले सकते हैं, जैसा कि बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है। यानी, माता-पिता की निगरानी और बच्चों की स्वायत्तता के बीच एक नाजुक डोर है, जिसको समझना लाजिमी है।

दूसरी बात, निजता पर हमले के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों के दुरुपयोग की आशंका अधिक होती है। यह विशेषकर उन बच्चों के लिए अधिक चिंताजनक है, जो अपने ही परिवार में दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत में एक तिहाई महिलाएं अपने जीवनसाथी के हाथों हिंसा का शिकार होती हैं। ऐसे लोग पत्नी पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए भी इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यही नहीं, लड़कों की तुलना में लड़कियों की गतिविधियां अधिक नियंत्रित की जाएंगी, जैसा हम अपनी भौतिक दुनिया में भी लगातार देखते हैं।

जाहिर है, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की गुत्थी सुलझाने के क्रम में हमारे सामने नई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, इसीलिए हमें समग्रता में सोचना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कानून में सुधार करना होगा। मसलन, आईटी अधिनियम 2000 की जगह लेने वाले नए भारतीय कानून में ब्रिटेन के 'एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड' (जिसे बच्चों की संहिता कहा जाता है) और 'द ओटेरोवा न्यूजीलैंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन सेफ्टी ऐंड हार्म्स' जैसे कानूनों के प्रावधान शामिल करने चाहिए। दूसरी, पहले से उपलब्ध नियंत्रक उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवहार तय करने होंगे। तीसरी, हमें शिक्षण संस्थानों को भी इस विमर्श में शामिल करना होगा। माता-पिता मुख्य रूप से बच्चों के 'स्क्रीन-टाइम' को लेकर चिंतित रहते हैं, जो महामारी के बाद बढ़ गई है। इस पर पुनर्विचार लाजिमी है।

चौथी बात, सभी शिक्षक और माता-पिता यह जानते हैं कि किसी भी समाधान को बच्चे खुले दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। वे रचनात्मक होते हैं और इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर अधिक कुशल हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चे खुद अपनी सुरक्षा को लेकर उत्सुक हों। और अंत में, 'यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप' के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 80 फीसदी माता-पिता इंटरनेट की दुनिया खंगालने के लिए अपने बच्चों से समय-समय पर मदद मांगते रहते हैं। लिहाजा, हमें पूरे परिवार पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आज के किशोर घर पर सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के प्रशिक्षक बन सकें। वैसे भी, आजकल के माता-पिता स्वयं रील में डूबे हुए हैं और उन्हें भी मदद की जरूरत पड़ती रहती है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 27 अप्रैल, 1949

श्यामाप्रसाद मुखर्जी का सुझाव

महाराष्ट्र व्यापार-उद्योग मण्डल में भाषण करते हुए भारत के उद्योग मंत्री डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भारतीय उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि (१) सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जहां उद्योगपति सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, वहां उनसे प्रतियोगिता करके उन्हें बाजार से निकाल दे, अथवा (२) देश के भावी औद्योगिक प्रसार में भारतीय उद्योगपतियों को उनके वाजिब योगदान से वंचित रखे। यही नहीं, यह भी आश्वासन उन्होंने दिया है कि विदेशों से माल मंगाने में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि देशी उद्योगों पर उसका विपरीत परिणाम न हो। और, ''अगर कोई भारतीय उद्योग ऐसा महसूस करे कि सरकार द्वारा ग्रहण की गई नीति का उस पर विपरीत परिणाम पड़ने की संभावना है, या उस उद्योग को लगे कि उसे विशेष संरक्षण मिलना चाहिए तो,'' उद्योग मन्त्री कहते हैं, ''हमने (सरकार ने) जो सामान्य नीति बनाई है वह यह है कि उस उद्योग को सरकार से इसके लिए जांच करने की मांग करनी चाहिए।'' विशेष संरक्षण दिया जाये या नहीं इसका निर्णय तो जांच के बाद तटकर बोर्ड करेगा, परन्तु डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का कहना है कि विशेष हालत में उनका महकमा जांच के समय भी अस्थायी संरक्षण की सिफारिश करेगा।

देश-हित की दृष्टि से उपर्युक्त आश्वासन सर्वथा उपयुक्त है और दिया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस पर अमल भी होना चाहिए। परन्तु सामान्य व्यक्ति देश-हित की ऊंची भावना से प्रेरणा लेते हुए भी यह देखे बगैर नहीं रहता कि हम जो माल ले रहे हैं वह अपेक्षाकृत सस्ता और अच्छा है या नहीं। स्वदेशी के साथ यह शर्त यदि पूरी न हो तो स्वदेशी का उत्साह स्थायी नहीं रहता, बल्कि उसे बनाने वाले देशी उद्योगों एवं उद्योगपतियों के बारे में भी एक हलकी भावना मन में बैठ जाती है। हमें मानना होगा कि हमारे देश में भी कुछ-कुछ यही हो रहा है। आम शिकायत यह है कि विदेशों से आया हुआ माल जहां सस्ता और अच्छा होता है वहीं देशी माल अपेक्षाकृत महंगा और घटिया किस्म का रहता है।... इसलिए उद्योग मंत्री ने उद्योपतियों को ठीक सलाह दी है कि वे अपने माल की किस्म अच्छी और कीमत कम करने का प्रयत्न करें।

मनसा वाचा कर्मणा

शराबी शिष्य

एक जेन गुरु के सैकड़ों शिष्य थे। सभी शिष्य अपने गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासन का पूरा-पूरा पालन करते और वक्त पर प्रार्थना किया करते, मगर उनमें से एक शिष्य ऐसा था, जो कभी सही समय पर प्रार्थना नहीं करता था, वह हमेशा शराब के नशे में रहता। जैसे-जैसे गुरु बूढ़ा होने लगा, वैसे-वैसे कुछ अधिक गुणी शिष्यों की यह उत्कंठा बढ़ती गई कि आखिर हमारे समूह का नया नेता कौन होगा? किस भाग्यशाली भिक्षुक को हमारी परंपरा के रहस्यमय मर्म को जानने का अवसर मिलेगा? कौन उत्तराधिकारी चुना जाएगा?

वक्त गुजरता गया। आखिरकार अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर मरणासन्न गुरुने शराबी शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे पंथ की परंपरा के गोपनीय रहस्यों का ज्ञान दिया। जब मठ में यह खबर फैली, तो दूसरे तमाम शिष्य बगावत पर उतर आए। सड़क पर उतरकर वे चिल्लाने लगे, हमारे लिए यह सचमुच शर्मनाक बात है! हमने एक ऐसे गुरु के पीछे अपना पूरा जीवन खपा दिया, जो हमारे गुणों को देख ही नहीं सकता था? हमने एक गलत गुरु का चुनाव किया था।

बाहर हो रहे शोर को सुनकर गुरु ने बस इतनी ही टिप्पणी की, 'मुझे वह रहस्यमय ज्ञान एक ऐसे शिष्य को देना था, जिसे मैं अच्छी तरह से जान सका। इसमें कोई दोराय नहीं कि मेरे सभी शिष्य बहुत गुणी हैं, मगर वे केवल अपने गुण ही दिखाते हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि सदाचार अक्सर घमंड, अभिमान और असहिष्णुता को छिपाने का काम करता है। इसीलिए मैंने एकमात्र उस शिष्य को चुना, जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं उसका दोष देख सकता हूं : शराबीपन!'

पाउलो कोएल्हो

मसीह अलीनेजाद | ईरानी-अमेरिकी पत्रकार

इजरायल, अमेरिका, जॉर्डन और सऊदी अरब ने मिलकर ईरान की 99 प्रतिशत मिसाइलें रोक दीं। क्या किसी के पास इस बर्बर शासन पर अपनी ही औरतों के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाने का कोई तरीका है?

चुनावी आश्वासन भी एक भ्रामक विज्ञापन

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने में समर्थ हैं, किंतु चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से अतार्किक बयानबाजी की जा रही हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रकार से चुनावी वायदे किए जा रहे हैं, वे स्वयं राजनीतिक दलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। सवाल यह है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए जो घोषणापत्र जारी किए गए हैं, उनमें दिए गए आश्वासन कितने प्रासंगिक हैं? क्या सभी आश्वासन लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, न्याय, निरपेक्षता की परिधि में आते हैं? क्या किसी दल को भ्रामक आश्वासन देने का अधिकार है? जनता को भ्रमित करने वाले आश्वासनों को क्या भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी में रखकर दंडनीय अपराध घोषित नहीं कर देना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को तमाम घोषणापत्रों का परीक्षण करके समाज को बांटने वाले राजनीतिक दलों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?

विचारणीय बिंदु यह है कि कुछ राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में ऐसे-ऐसे आश्वासन हैं, जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता व मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि प्रेम और जंग में सब कुछ जायज होता है। मगर चुनावी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार करके मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल मात्र अफवाहें व जातीय विद्वेष फैलाकर चुनावी आदर्शों को ठेंगा दिखा रहे हैं, उनको देखकर तो यही लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से देश के अधिकांश राजनीतिक दलों का कोई सरोकार नहीं रह गया है। ताज्जुब तो तब होता है, जब खुलेआम जाति कार्ड खेलकर राजनीतिक दल समाज के बंटवारे की भूमिका तैयार करने से बाज नहीं आते।

स्पष्ट है, आरोप-प्रत्यारोप की इस जंग में सत्य और असत्य का निर्धारण करने वाला भी कोई नहीं है। कोई भ्रामक विज्ञापन होता, तो शिकायत भी की जाती। शिकायत होती, तो झूठे आश्वासन देने वाले को दंडित कराया जा सकता था। मगर ऐसा नहीं हो सका है। ऐसे में, सवाल यही है कि यदि भ्रामक विज्ञापन दंडनीय अपराध हैं, तो चुनावी घोषणापत्र में दिए गए आश्वासन भी भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में क्यों नहीं रखे जा सकते? आवश्यकता यही है कि राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए गए घोषणापत्रों का शब्दशः परीक्षण किया जाए तथा जो आश्वासन मानक पर खड़े नहीं उतर सकें, उन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

घोषणापत्र व विज्ञापन

घोषणापत्र और विज्ञापन का अंतर समझें

घोषणापत्र को विज्ञापन समझने की भूल न करें। दोनों दो तरह के दस्तावेज हैं। दोनों का चरित्र अलग है और दोनों का संदर्भ भी अलग है। घोषणापत्र वास्तव में किसी पार्टी के इरादों का एक रोडमैप होता है। इसमें बताया जाता है कि यदि वह सत्ता में आती है, तो अमुक-अमुक काम करेगी। इसमें वस्तुस्थिति का जिक्र ज्यादा होता है, यानी हकीकत अधिक बयां की जाती है, कशीदाकारी नाममात्र की होती है। इसके विपरीत, विज्ञापन किसी उत्पाद का प्रचार है। इसमें उत्पाद की अच्छाई बताई जाती है, ताकि उपभोक्ताओं के दिलों को वह छू सके और वे उसे खरीद सकें। इसमें अफसाना अधिक होता है, हकीकत कम। इसीलिए, कोई भी राजनीतिक दल शायद ही अव्यावहारिक आश्वासन की बात अपने घोषणापत्र में करता है। सभी उन्हीं वायदों का जिक्र करते हैं, जो वे पूरा कर सकते हैं या पूरा करने के करीब होते हैं।

यह सही है कि आज के सोशल मीडिया के युग में सच और झूठ को बांट पाना बहुत मुश्किल होता है। विशेषकर डीप फेक ने तो ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि कोई विशेषज्ञ ही श्वेत-श्याम के बीच के महीन चक्रव्यूह को तोड़ पाता है। ऐसे में, यह अतिशयोक्ति नहीं कि ऐसे-ऐसे आश्वसान भी नेताओं के मुंह से कहलवा दिए जाएं, जो उन्होंने कहे ही न हों। यह सही है कि अव्यावहारिक आश्वासन की निगरानी होनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो वादे किसी कारण से पूरे न हो सके, उनको भ्रामक बताकर घोषणापत्र को ही खारिज कर दिया जाए।

हमें यह समझना होगा कि घोषणापत्र आखिर जरूरी क्यों है? चुनाव में हरेक दल को लड़ने का समान आधार मिलना चाहिए। यह आधार उनको घोषणापत्र ही मुहैया कराता है। यदि कोई राजनीतिक दल घोषणापत्र जारी नहीं करेगा, तो वह कैसे मतदाताओं तक पहुंच सकेगा और उनको अपने पक्ष में कर सकेगा? चूंकि मतदाताओं को आशान्वित करने में घोषणापत्र अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए कुछ राजनीतिक दल ऐसे-ऐसे आश्वासन भी दे देते हैं, जो असंभव जान पड़ सकते हैं। बेशक, ऐसे आश्वासन देने वाले दलों पर कुछ हद तक कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन भारतीय मतदाता अब इतना जागरूक हो गया है कि वह पकड़ लेता है कि कौन राजनीतिक दल कितने पानी में है। लोकतंत्र की ताकत भी यही है कि मतदाता इतने सशक्त हो जाएं कि वे चुनाव-प्रक्रिया को अपने मुताबिक ढाल सकें और अच्छे-बुरे की समझ खुद में विकसित कर सकें। हमें चुनावी घोषणापत्रों को परखने का अधिकार भी मतदाताओं को ही देना चाहिए, किसी और को नहीं।

दिव्यांशु, टिप्पणीकार

सत्य ही तथ्य की ढाल है

ईवीएम पर भरोसा

यह अच्छा हुआ कि बेतुकी दलीलों और कुछ फर्जी खबरों के सहारे ईवीएम का बटन दबाते समय दिखने वाली पर्ची यानी वीवीपैट के सौ प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईवीएम से प्राप्त नतीजों का सभी वीवीपैट से मिलान करने की मांग एक तरह से पिछले दरवाजे से मतपत्र से चुनाव कराने की पैरवी ही थी। यह पैरवी इससे भली तरह अवगत होने के बाद भी की जा रही थी कि मतपत्रों से चुनाव के समय किस तरह धांधली होती थी और मतपेटियां लूटने के साथ नतीजे आने में समय लगता था। बंगाल में तो पंचायत चुनावों में अभी भी मतपेटियां लूटने का काम होता है। ईवीएम के खिलाफ पहले भी सवाल उठते रहे हैं और उनका समाधान भी किया गया है। पहले वोटर को यह नहीं दिखता था कि उसका वोट वांछित प्रत्याशी को गया या नहीं? यह दिखाने के लिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई। फिर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा के एक बूथ की ईवीएम से मिले नतीजों का मिलान वीवीपैट से किया जाने लगा। इसके बाद यह मिलान पांच बूथों पर होने लगा। इसके बाद भी कुछ लोग संतुष्ट होने को तैयार नहीं। इनमें याचिकाबाज वकीलों के साथ कुछ राजनीतिक दल भी हैं। इनमें वे दल भी हैं, जो ईवीएम से हुए चुनावों में जीत हासिल कर सत्ता तक पहुंचे हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता और उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे रह-रहकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उच्चतर न्यायपालिका को ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा वे कोई न कोई बहाना लेकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने को अपना धंधा बना लिया है। ऐसे तत्व विदेशी मीडिया के उस हिस्से को भी खाद-पानी देने का काम करते हैं, जिसे न तो भारत की प्रगति रास आ रही है और न ईवीएम की सफलता पच रही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील प्रशांत भूषण ने यह दलील दी कि वह यह दावा तो नहीं करते कि इस मशीन से छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ईवीएम विरोधी यह भी दलील दे रहे थे कि मतदान की गोपनीयता भंग होने की चिंता नहीं की जानी चाहिए। यदि ईवीएम विरोधियों की यह मांग मान ली जाती कि सभी वीवीपैट की गिनती की जाए तो उससे नतीजे मिलने में कम से कम 12-15 दिन का समय तो लगता ही, खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाता। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर भरोसा जताया और सभी याचिकाएं खारिज कर दीं, लेकिन बेहतर होता कि वह इस मशीन को बदनाम करने के अभियान पर लगाम भी लगाता।

मूंछ की लड़ाई

मूंछ की लड़ाइयों के किस्से राजे रजवाड़े के दिनों के सुनते रहे हैं। इस लड़ाई में लोग जान तक गंवा देते थे। लोकतंत्र के चलन में आने के बाद भी यह लड़ाई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। प्रतीक के रूप में अब भी जारी है। इस समय बिहार में शिक्षा विभाग और कुलाधिपति के कार्यालय के बीच ऐसी ही प्रतीकात्मक मूंछ की लड़ाई चल रही है। संयोग है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक और कुलाधिपति डा. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर-दोनों मूंछ रखते हैं। समानता यह है कि इनकी मूंछें सामान्य स्टाइल की हैं, जिन्हें देखने से डर नहीं लगता है। लड़ाई का रोचक पक्ष यह है कि इसमें अपर मुख्य सचिव और कुलाधिपति का नहीं, तीसरे पक्ष को नुकसान हो रहा है। तीसरे पक्ष में आप विश्वविद्यालयों-कालेजों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र-छात्राओं को रख सकते हैं। पीड़ित पक्ष अब अदालत की शरण में जा रहा है। मगध विवि की ओर से पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि उसके बैंक खाते को चालू करने की अनुमति दी जाए। खाता बंद रहने से शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बंद है। छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। परीक्षाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। बैंक खाता बंद रहने के संकट से राज्य के सभी विश्वविद्यालय जूझ रहे हैं। राज्य में कुलाधिपति की दो व्यवस्था है। कुछ विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति का पद मुख्यमंत्री के पास है। अधिसंख्य विश्वविद्यालयों में यह पद राज्यपाल संभाल रहे हैं। मूंछ की लड़ाई उन्हीं विश्वविद्यालयों में चल रही है, जिनके कुलाधिपति राज्यपाल हैं। लड़ाई का मुद्दा क्या है? शिक्षा विभाग कह रहा है कि हम जो राज्य के खजाने से धन दे रहे हैं, उसके खर्च की आडिट कराएंगे। इधर विवि कह रहा है कि हम स्वायत्त संस्थान हैं। हमारे खर्च का हिसाब सरकार क्यों लेगी। निश्चित रूप से इस विवाद के निबटारे के लिए कोई न कोई प्रविधान शिक्षा विभाग और विवि के नियम-परिनियम में होगा। कानून के जानकारों से सलाह लेकर इसका निष्पादन किया जा सकता है। जल्द समाधान नहीं हुआ तो शैक्षिक जगत में असंतोष बढ़ सकता है। कह सकते हैं कि मूंछ की लड़ाई घातक मोड़ पर पहुंच चुकी है।

> मूंछ की लड़ाई उन्हीं विश्वविद्यालयों में चल रही है, जिनके कुलाधिपति राज्यपाल हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

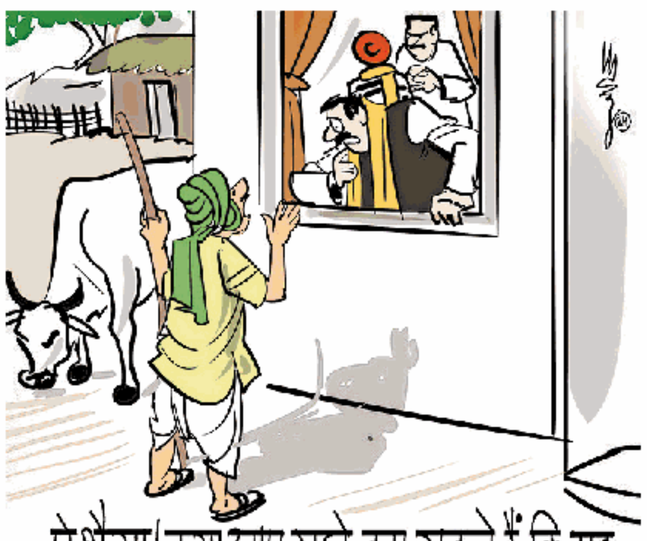

क्या कन्नौज से चुनाव लड़ने उतरे अखिलेश यादव की तरह राहुल गांधी को भी अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए?

आज का सवाल

क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम पर बेवजह सवाल उठाने वाले शांत होंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

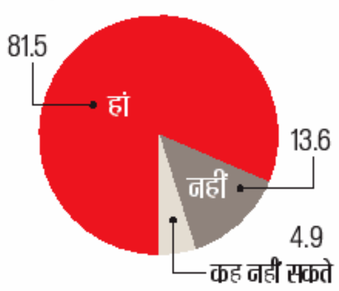

चुनावी चंदे की नई व्यवस्था का सवाल

उमेश चतुर्वेदी

यह प्रश्न अनुत्तरित है कि चुनावी बांड योजना के खारिज होने के बाद राजनीतिक फंडिंग की नई व्यवस्था क्या होगी?

राजनीतिक भ्रष्टाचार की चर्चा का एक सिरा चुनाव सुधार पर ही जाकर खत्म होता है। चुनावी फंडिंग भी इसका एक अहम पहलू है। इसी कड़ी में राजनीतिक फंडिंग को सुधारने की दिशा में 2018 में चुनावी बांड को एक बेहतर कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को खत्म कर दिया। चुनावों के ठीक पहले आए सरकार विरोधी फैसले पर विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी बांड की व्यवस्था को खारिज किए जाने के बाद राजनीतिक फंडिंग कैसे होगी? सवाल सिर्फ फंडिंग का नहीं है, बल्कि उसकी पारदर्शी व्यवस्था का भी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनावी बांड को न्यायिक चुनौती देने वाले भी किसी कारगर सुझाव को लेकर सामने नहीं आए हैं। अक्सर ऐसे लोगों की याचिका की पैरवी करने वालों के वकील प्रशांत भूषण भी इसे लेकर स्पष्ट नहीं हैं। हरसंभव मंच पर चुनावी बांड को खत्म किए जाने को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे विपक्षी दलों के पास भी कोई ठोस वैकल्पिक सुझाव नहीं है।

पारदर्शी फंडिंग व्यवस्था और चुनावी बांड की जरूरत का जवाब बनकर सामने आई है चुनाव आयोग की कार्रवाई से जब्त मोटी रकम। सिर्फ प्रथम चरण के मतदान से पहले यानी 13 अप्रैल तक ही रिकार्ड मात्रा में नकदी, ड्रग्स, शराब और गहने आदि जब्त किए जा चुके हैं। इस दौरान करीब 4,650 करोड़ की नकदी, ड्रग्स, शराब और गहने आदि जब्त होने की सूचना है। 2019 की पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब्ती से यह रकम बहुत ज्यादा है। वर्ष 2019 में करीब 844 करोड़ की नकदी जब्त की गई थी, जबकि इस बार पहले दौर के मतदान के पूर्व तक ही 395 करोड़ की नकदी जब्त की गई है। इसी तरह 2019 में 304 करोड़ मूल्य की शराब की जब्ती हुई थी, जबकि इस बार 13 अप्रैल तक ही 490 करोड़ की शराब जब्त की जा चुकी है। चुनावों में बांटने और रकम आदि जुटाने के लिए ड्रग्स का भी इस्तेमाल इन दिनों बढ़ा है। चुनाव आयोग ने पिछले आम चुनाव में जहां 1,280 करोड़ की ड्रग्स जब्त की थी, वहीं इस बार अभी तक ही यह आंकड़ा 2,068 करोड़ रुपये तक चला गया है। इसी तरह उपहार आदि के रूप में पिछली बार जहां महज 60.15 करोड़ मूल्य के सामान जब्त हुए थे, तो इस बार 1,142 करोड़ के सामान जब्त किए जा चुके हैं। स्पष्ट है कि चुनाव दर चुनाव किस कदर आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ने पर है।

अमेरिका में चुनावी फंडिंग सरकारी और निजी दोनों तरह से जुटाई जा सकती है। हालांकि सरकारी फंडिंग से जुड़े नियम बेहद सख्त और पेचीदा हैं। इसलिए

अवधेश राजपूत

करीब सभी उम्मीदवार निजी फंडिंग का सहारा लेते हैं। वहां निजी फंडिंग की कोई सीमा भी नहीं है। उम्मीदवार अपनी पार्टी के सदस्यों, समर्थकों और कारपोरेट कंपनियों एवं संस्थानों से रकम जुटाते हैं। निजी फंडिंग लेने वाला व्यक्ति कानूनन सरकारी फंडिंग का दावा नहीं कर सकता। अमेरिका में चुनावी खर्च इतना अधिक हो चुका है कि उसकी पूर्ति के लिए सरकारी फंडिंग ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसीलिए उम्मीदवार निजी फंडिंग का सहारा लेते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव के दोनों प्रत्याशी राष्ट्रपति बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप करीब-करीब 600-600 करोड़ डालर की फंडिंग जुटा चुके हैं।

अमेरिका की तरह भारत में भी चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी है, मगर हकीकत में इतने में कोई प्रत्याशी ठीक से विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव में खर्च होने वाली मोटी रकम की कहानी सभी दल जानते हैं। इसलिए अपने हिसाब से नियम की काट खोजते हुए पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लिहाजा सबको भारी फंडिंग की जरूरत होती है। सवाल यह है कि चुनावी बांड को खत्म करने के बाद सरकार पर हमलावर दल क्या यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें मिलने वाला फंड पवित्र और जायज है? चुनावी बांड में बेशक भाजपा को सबसे ज्यादा रकम मिली और उसके सत्तारूढ़ होने के कारण यह बहुत स्वाभाविक भी है, किंतु सवाल उठाने वाले दलों को मिली रकम भी कम नहीं है।

उदारीकरण के बाद से राजनीति में शुचिता का सवाल जितनी तेजी से उठा, सियासी फंडिंग का चलन भी उसी अनुपात में बढ़ा है। चुनावी बांड की व्यवस्था से पहले नियम था कि कंपनियां अपने तीन साल के लाभ का सिर्फ सात प्रतिशत ही दलों को दान कर सकती थीं। चुनावी बांड को खारिज करने का मुख्य आधार गोपनीयता का नियम रहा, जिसके तहत बांड खरीदने वाले की जानकारी हासिल नहीं की जा सकती थी। चुनावी बांड के पहले तक तो यह भी पता नहीं होता था कि किसने, किस दल को, कितनी रकम दी? ज्यादातर रकम नकदी होती थी, जिसका ठोस हिसाब भी नहीं होता था। 1996 के आम चुनावों के ठीक पहले हवाला कांड में जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव पर एक लाख रुपये लेने का आरोप था। तब उन्होंने स्वीकार किया था कि दल चलाने के लिए कब और कहां से पैसे आते हैं, इसका हिसाब नहीं रखा जा सकता। नकदी से मिली बेहिसाब रकम की जब चोरी आदि हो जाती थी, तब भी नेता पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से बचते थे, क्योंकि चोरी में रकम की जानकारी देते तो उसका स्रोत भी बताना पड़ता। कई दल अपने सैकड़ों करोड़ की नकदी को कार्यकर्ताओं और अपने सदस्यों से दान रूप में हासिल करने का झूठा दावा भी इसी वजह से करते रहे।

अब जब चुनावी बांड की व्यवस्था समाप्त हो गई है तो राजनीतिक दल अपने खर्च के लिए येन-केन प्रकारेण पैसे जुटाएंगे। कानूनी प्रविधानों के छिद्रों का इस्तेमाल भी होगा। इस लिहाज से देखें तो चुनावी बांड एक सीमा तक बेहिसाब फंडिंग को हिसाबी दायरे में ही ला रहा था। पारदर्शिता के लिहाज से उसमें सुधार किया जा सकता था। राजनीतिक शुचिता का हिमायती होने का दावा करने वालों को चाहिए कि वे फंडिंग की ऐसी पारदर्शी वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करें, जिसमें संदेह की गुंजाइश न हो। अन्यथा चुनाव सुधार और पारदर्शी फंडिंग का समर्थन भी खोखला ही माना जाएगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक टिप्पणीकार हैं)

response@jagran.com

महिला हितैषी कानूनों का दुरुपयोग

क्षमा शर्मा

जो महिलाएं दहेज प्रताड़ना झेलती हैं, कानून उनकी मदद करे, वहीं इसके साथ ही निर्दोषों को फंसाने पर रोक भी लगे

चिंताजनक है कानूनों का एकतरफा झुकाव ● फाइल

दहेज अधिनियम और अन्य महिला कानूनों के दुरुपयोग की खबरें लगातार आती रहती हैं। उच्चतम न्यायालय ने ही इसे एक बार 'कानूनी आतंकवाद' कहा था, लेकिन इसके बावजूद इस मोर्चे पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक महिला ने अपने पति से परिवार अदालत में तलाक ले लिया, लेकिन इसके छह महीने बाद उसने दहेज निरोधी अधिनियम के तहत पूर्व पति और उसके घर वालों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर पति को चार्जशीट किया। इस पर उसने उच्च न्यायालय की शरण ली और अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाई समाप्त करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने उसकी अपील निरस्त कर दी। इसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उसके वकील ने उच्चतम न्यायालय में यह भी कहा कि महिला ने पहले भी जब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपील की तो अदालत ने इसे नहीं माना था और महिला ने भी इस मामले को नहीं बढ़ाया था। वकील ने यह तर्क भी दिया कि जब परिवार अदालत द्वारा शादी समाप्त की जा चुकी है तो इस तरह की शिकायत साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनु. 142 के तहत मिले विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए मामले को खारिज कर दिया। उसने यह भी कहा कि तलाक के बाद लोगों को उत्पीड़न से बचाना जरूरी है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति को दस साल तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। इन वर्षों में उसने और उसके परिवार ने कितनी मुसीबत झेली होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सोचिए कि जिनके पास साधन-संसाधन न हों, वे क्या करें?

अदालतें दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के झूठे मामलों में स्त्रियों को फटकार तो लगाती रहती हैं, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग इसलिए नहीं थम रहा, क्योंकि उन्हें झूठा मामला बनाने पर कोई सजा नहीं मिलती। बदले की भावना, पति के परिवार वालों के साथ न रहना, जमीन-जायदाद के मसले, कई बार पुरुष मित्र के साथ जाने की चाहत आदि को लेकर 498-ए का खूब दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे मामलों में आदमी की पहचान भी बार-बार उजागर की जाती है। कई बार उसके फोटो भी छपते हैं। नौकरी चली जाती है। जेल भी जाना पड़ता है। कुछ के तो सारे पैसे और पूरी बचत तक खर्च हो जाती है। यह अफसोस की बात है कि कानूनों ने पुरुषों और उनके परिवार को ऐसे दानवों के रूप में बदल दिया है, जो किसी स्त्री के आरोप लगाते ही अपराधी मान लिए जाते हैं। आरोपित को अपराधी बनाने का चलन हमारे यहां बेहद आम है। मीडिया का एक हिस्सा इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेता है। आखिर यह कैसे मान लिया गया है कि कानून का काम सिर्फ एक पक्ष को न्याय देना है। स्त्री या पुरुष, जो भी अपराधी हो उसे सजा मिले, लेकिन किसी के आरोपित बनते ही उसे अपराधी सिद्ध कर देना कहां का न्याय है?

कायदे से जिस पर आरोप लगा है, वह जब तक अपराधी साबित न हो जाए, तब तक उसकी पहचान उजागर न की जाए। ऐसा करने से बहुत से निरपराधों को बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे नीति-नियंता इन बातों को नहीं जानते, लेकिन नारी हित के नाम पर क्रूर कानून बदलने की कोई कोशिश नहीं की जाती। क्या इसलिए कि उन्हें महिलाओं के वोट चाहिए और जरा सा भी परिवर्तन करेंगे तो महिला हितों के नाम पर दुकानदारी करने वाले शोर मचाएंगे? विकसित देशों में शायद ही कहीं ऐसे कानून हों, जहां एक पक्ष को सत्यवादी मान लिया जाए और दूसरे को बिना प्रमाण अपराधी। आखिर पुरुषों के मानवाधिकारों के बारे में कब सोचा जाएगा या पुरुष होने का मतलब मनुष्य होना नहीं है?

हाल में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी दहेज निरोधी अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की। उसने एक मामले में फैसला दिया कि बहुत बार महिलाएं पति के रिश्तेदारों तक को इस एक्ट में आरोपित बना देती हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं होता। वे अलग भी रहते हैं। जो घटनाएं हुई ही नहीं होतीं, उनका उल्लेख किया जाता है, जिससे 498-ए का केस बनाया जा सके। उक्त मामले में पति के आठ रिश्तेदारों को आरोपित बनाया गया था। न्यायालय ने पति और उसकी मां के खिलाफ मामले को जारी रखा, मगर रिश्तेदारों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।

बीते कुछ समय में तो ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं कि पति के परिवार से भारी-भरकम रकम लेकर मामले को खत्म किया गया। अब जिनके पास पैसे हैं, वे तो ऐसे समझौते कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं, वे क्या करें? कहां जाएं? आखिर उच्चतम न्यायालय तक कितने लोग पहुंच सकते हैं? निःसंदेह महिलाएं और उनके परिवार दहेज से परेशान रहते हैं। जिन महिलाओं को दहेज के चलते तंग किया जाए, कानून उनकी पूरी मदद करे, लेकिन इसके साथ ही निरपराधियों को फंसाने की कोशिश पर रोक लगाई जाए। हरियाणा के एक परिचित ने बताया कि वहां ऐसे गिरोह बन गए हैं, जो महिला कानूनों की आड़ में ब्लैकमेल करके वसूली करते हैं। सरकारों और महिलाओं के लिए काम करने वाले लोगों को इस ओर जरूर सोचना चाहिए। कानूनों का दुरुपयोग उनकी विश्वसनीयता कम करता है। वक्त की मांग यह है कि महिला कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। कानून किसी एक पक्ष को डराने के लिए नहीं, सभी पक्षों को न्याय देने के लिए होते हैं। राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि उनके वोटर पुरुष भी हैं। कहीं यह तो नहीं मान लिया गया कि आखिर वे जाएंगे कहां, इसे या उसे वोट तो देंगे ही? आखिर नेता पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए क्यों कुछ करना नहीं चाहते? राजनीतिक विमर्श में उनसे जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

योग्यता और सम्मान

सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य की होती है। विज्ञानियों के अनुसार जब किसी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है तो उसे प्रसन्नता एवं संतुष्टि की अनुभूति होती है, जिसका सकारात्मक असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, तब उसके भीतर हीनभावना उत्पन्न होती है। वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन की शांति और उत्साह को पूर्णतः खो देता है। अपने अनादर की वजह से जो गहरी चोट उसके दिल पर लगती है, उससे वह असंतोष, घृणा, शत्रुता और प्रतिशोध की नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है।

संसार को व्यवस्थित रखने के लिए प्रकृति ने विनिमय की व्यवस्था बनाई है। इसके अनुसार यदि आप कुछ देते हैं, तभी कुछ प्राप्त कर पाते हैं। स्पष्ट है कि उचित मूल्य चुकाए बिना इस संसार में किसी को भी कुछ नहीं मिलता। इस नियम के हिसाब से सीधा उपाय तो यही है कि जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें वैसी योग्यता भी प्राप्त करनी चाहिए। योग्यता अपने आप ही हमें अभीष्ट तक पहुंचा देती है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य सम्मान और प्रशंसा का आकांक्षी हो तो उसके लिए उसे उसी अनुरूप अर्हता भी अर्जित करनी होगी।

कोई धूर्त व्यक्ति अपनी चालाकियों से अस्थायी रूप से सम्मान प्राप्त कर ले तो भी उसे उससे स्थायी संतुष्टि नहीं मिलेगी। उलटे जब उसकी वास्तविकता उजागर होगी तो वह उपहास का पात्र बनेगा। याद रहे कि कागज की नाव बहुत ज्यादा समय तक नहीं तैर सकती और अंततः डूब जाती है। इसीलिए कपट से कुछ प्राप्त करने के बजाय योग्यता और गुणवान बनने पर अपना समय एवं शक्तियां केंद्रित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्थायी सम्मान के पात्र बनेंगे। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। वास्तविकता को सराहते हैं, कृत्रिमता को नहीं। पलाश का फूल आकर्षक दिखता है, किंतु लोग गुलाब की सुगंध के कारण ही कांटों के बावजूद उसे पसंद करते हैं।

राजयोगी ब्रह्माकुमार निकुंज जी

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

भाजपा की संभावनाओं की पड़ताल

'दक्षिण में भाजपा की संभावनाएं' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. एके वर्मा ने दक्षिण भारतीय राज्यों के चुनावी परिदृश्य का गहन विश्लेषण किया है। इसकी शुरुआत उन्होंने कर्नाटक से की है। इस बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दक्षिण के सभी राज्यों में सधी हुई रणनीति अपनाई है। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी से गठबंधन कर जहां सामाजिक आधार का विस्तार किया गया, वहीं आंध्र में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टियों के साथ गठजोड़ को प्राथमिकता दी। तमिलनाडु में वह अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता की विरासत पर दावा ठोकने के प्रयास में है। ऐसे में पूरी संभावना है कि भाजपा इस बार दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। इसके बूते अगर पार्टी को 370 से अधिक सीटें हासिल हो जाएं तब आसानी से राजग 400 का आंकड़ा छू लेगा। दूसरी ओर, विपक्षी दल अपने बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के फेर में वे मजहबी आरक्षण का जो राग अलाप रहे हैं, इसका दुष्परिणाम उन्हें चुनाव परिणाम में देखने को जरूर मिलेगा।

मुकेश कुमार मनन, पटना

चुनाव में दक्षिण भारत की भूमिका

'दक्षिण में भाजपा की संभावनाएं' शीर्षक आलेख में डा. एके वर्मा ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सही लिखा है कि इस बार लोकसभा चुनावों में भाजपा को लक्ष्य की प्राप्ति कराने में दक्षिण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बेशक गत दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी मेहनत की है। एशिया नेट न्यूज नेटवर्क को एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर दक्षिणी भारत में बढ़ेगा। इस चुनाव में भाजपा ने लोकसभा सीटों के लिहाज से पांचवें सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में अभूतपूर्व प्रयास किया। तेलंगाना में भाजपा का वोट शेयर दोगुना हो गया है। केरल में पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों के प्रति ईसाइयों के बीच असंतोष को उजागर किया। यह राज्य में ईसाई समुदाय से अपील करने के भाजपा के प्रयासों को रेखांकित करता है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

आरक्षण में कटौती की आशंका

अवधेश कुमार द्वारा लिखित आलेख 'अपने ही बुने जाल में फंसी कांग्रेस' पढ़ा। प्रारंभ से ही मुस्लिम समाज कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में मुस्लिम वोट कांग्रेस से अलग होकर क्षेत्रीय दलों के खाते में जा चुका है। तेलंगाना एवं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की मदद से कांग्रेस सत्ता में आई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम समाज को हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की है। पूर्व से आरक्षण की सीमा निर्धारित की जा चुकी है। अब यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि ओबीसी, एससी एवं एसटी के आरक्षण में कटौती कर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण प्रदान कर सकती है। कांग्रेस को इन आशंकाओं का सही जवाब देना चाहिए, अन्यथा उसे इसका नुकसान चुनावी मैदान में भुगतना पड़ सकता है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

इम्पैक्ट प्लेयर का विरोध

आजकल आइपीएल के मैचों में दर्शकों को बड़ा मजा आ रहा है। गत वर्ष से इम्पैक्ट प्लेयर नियम लागू होने से रोमांच और बढ़ गया है। बैटर्स की पूछ बढ़ गई है। आलराउंडर्स का महत्व कम हो गया है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के अनुसार टास के बाद प्रत्येक टीम को अपने प्लेइंग इलेवन के अलावा पांच खिलाड़ियों के नाम देने होते हैं, जिनमें से एक का वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर प्रयोग करते हैं। यह खिलाड़ी मैच में किसी भी समय प्लेइंग 11 में किसी अन्य खिलाड़ी की जगह शामिल हो सकता है। इसके बारे में टीम को पहले से आधिकारिक जानकारी देनी होती है। रिप्लेस किया गया खिलाड़ी प्लेइंग 11 में वापस नहीं आता। इस नियम के कारण कप्तान को एक ही मैच में 12 खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिल जाता है। टीम की बैटिंग लाइन लंबी हो जाती है। ऊपर के सभी बैटर खुल के खेलते हैं। फिर फील्डिंग की बारी आने पर किसी बैटर के स्थान पर विशेषज्ञ गेंदबाज को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह टीम में ले लिया जाता है। ऐसे में आलराउंडर खिलाड़ियों की पूछ घट गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, बाएं हाथ के स्पिनर होने के साथ बढ़िया बल्लेबाज अक्षर पटेल, पुराने फास्ट बालर जहीर अहमद आदि ने इस नए नियम के विरुद्ध विचार व्यक्त किए हैं। आगामी विश्व कप में यह नियम नहीं होगा। फिर इस नियम के अनुसार टीम को चुनने का कोई औचित्य नहीं है। क्रिकेट के मूल सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

X पोस्ट

लोकतंत्र खतरे में तब होता है जब आपके पास वोट देने का अधिकार हो और आप वोट देने ही न जाएं।

अरविंद चोटिया@arvindchotia

विरासत टैक्स की बात करने वाले राजनीति में भी इसी प्रकार के प्रविधान का सुझाव क्यों नहीं देते?

राहुल पंडिता@rahulpandita

कुछ लोग विरासत टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से राजनीतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शत-प्रतिशत हस्तांतरित होनी चाहिए।

निस्तुला हेबार@nistula

सैम पित्रोदा करीब 60 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें यह नहीं मालूम कि वहां पूरे देश में कोई एकसमान विरासत टैक्स नहीं। ऐसे व्यक्ति दशकों से कांग्रेस पार्टी के नीति-निर्धारकों में से एक रहे हैं।

हार्दिक राजगोर@Hardism

कुछ दिग्गज कंपनियों ने चेतावनी जारी की है कि चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश तकनीक के दुरुपयोग से भारत में चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये देश आखिर केंद्र की सत्ता में किसे देखना चाहते हैं?

आकाश चोपड़ा@cricketaakash

जनपथ

मनमोहन जी कह गए 'पहले हक' की बात,
आगे निकले 'सैम जी' उनसे भी दो हाथ!
उनसे भी दो हाथ आपकी कर्म-कमाई,
बंटी सभी के बीच समझिए अब तो भाई।
बहुसंख्यक हैं गाय कीजिए इनका दोहन,
बात यही स्पष्ट कह गए हैं मनमोहन!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 16

****

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

अदालत का फैसला करेगा महिलाओं को सशक्त

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही स्त्रीधन की समुचित व्याख्या करते हुए जो फैसला दिया है, वह कानूनी दृष्टि से तो लोगों को स्त्री के अधिकारों को छीनने से रोकेगा ही। साथ ही सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी पत्नियों के हक को पुख्ता करेगा। बेहतर तो यह है कि पारिवारिक विवाद परिवार या समाज के स्तर पर ही सुलझा लिए जाएं। इसमें पुलिस-कोर्ट-कचहरी को हस्तक्षेप न करना पड़े। यदि ऐसा हो जाए तो हालात बदल सकते हैं। जब तक ऐसा संभव नहीं होता, तब लोगों को कोर्ट की शरण लेनी ही पड़ेगी और तब कोर्ट ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। स्त्रीधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर पक्ष को आईना दिखाने के साथ आगाह भी करने वाला है कि वह स्त्रीधन को अपनी बपौती समझने की भूल न करे। कोई ऐसा करता है तो यह उसके लिए भूल हो सकती है, लेकिन कानून की नजर में यह अपराध है। इसमें संबंधित व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत मुकदमे की कार्रवाई का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप में रेखांकित कर दिया है कि स्त्रीधन पर केवल और केवल स्त्री का ही हक है। उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह कड़वी सच्चाई है कि देश का जो सामाजिक परिवेश है, उसमें स्त्री धन पर ससुराल पक्ष अपना हक मानता है। जाने-अनजाने यह भूल व्यापक स्तर पर होती आ रही है। विवाह के समय महिला को मिलने वाले धन, कपड़े, आभूषण, उपहार और कालांतर में नौकरी से लड़की को होने वाली आमदनी सब पर पूरा हक मानने की सामान्य प्रवृत्ति बड़ी संख्या में आम भारतीय परिवारों में घर की हुई है। यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ससुराल पक्ष इस पर सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार समझता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें ऐसा करने से रोकेगा। इस फैसले के बाद समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। महिलाओं को दहेज की समस्या से बचाने के लिए दहेज निरोधक कानून बनाया गया। इसके बावजूद दहेज का व्यापक प्रचलन है या कह सकते हैं कि खुले आम लिया और दिया जा रहा है। साथ ही इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून बनने के बाद इसके क्रियान्वयन में सख्ती होती है, तो इसका असर समाज में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। किसी भी समस्या को दूर करने के लिए कानून का सख्ती से क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है।

ताजा फैसला विश्वास जगाने वाला है। यह समस्या पर चोट करने वाला साबित होगा। फैसला इस पहलू से भी उपयोगी है कि इससे समाज में जागरूकता के प्रसार भी होगा। जागरूकता और कानून का भय, ये दोनों पहलू मिलकर ही व्यवस्था को पटरी से उतरने से रोकते हैं। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनको उत्पीड़न से बचाने के लिए जांच एजेंसियों को शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई करने पर ध्यान देना चाहिए।

पुरुष शरीर भूताग्नि प्रधान है। स्त्री शरीर भूत सोम प्रधान है। पुरुष के आग्नेय शरीर की प्रतिष्ठा सोम-शुक्र है। सौम्य स्त्री तत्त्व शुक्र रूप से पुरुष की प्रतिष्ठा है। अतः पुरुष भी स्त्री है। स्त्री के सौम्य शरीर की प्रतिष्ठा आग्नेय शोणित है। अतः आग्नेय पुरुष तत्त्व शोणित रूप से स्त्री की प्रतिष्ठा है।

बीजी की पूर्णता

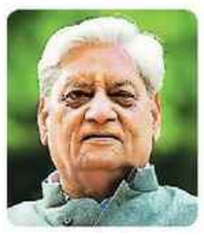

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

शुक्र में स्थित पूंभ्रूण ही 21 मात्रा (ऋणाग्नि) से पुत्र रूप परिणत होता है। पिता से ही आत्मधेय रूप सात कलाएं (धनाग्नि) प्राप्त करता है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पुरुष में ऊपर की 6 पीढ़ियों से ऋणरूप 56 सहोमात्रा प्रतिष्ठित रहती है तथा 28 स्वयं अपनी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करता है।

चन्द्रमा को स्व-सृष्टि प्रक्रिया के लिए ऋतु का आश्रय लेना पड़ता है। ऋतुकाल में ही चन्द्रमा स्व-सौम्य रेत का आधान करता है। चन्द्रमा के तीन मनोता हैं-श्रद्धा, रेत, यश। चन्द्रमा का सौम्य प्राण पितर हैं। सोमरस ही रेत में परिणत होता हुआ पुरुष सृष्टि का प्रवर्तक बनता है। पन्द्रह कलायुक्त कृष्णपक्ष का पितृप्राण युक्त चान्द्रसोम ही ऋतुकाल में अन्न में प्रविष्ट होकर, रेत रूप बनता है। यही पुरुष प्रसूति का कारण बनता है।

यह चान्द्ररेत रेतप्रदाता पिता में प्रतिष्ठित होता है। यही रेत शोणित में आहृत होता है। चन्द्रमा का संवत्सर 13 माह का होता है। इसी काल में गर्भ पूर्णावयव बनता है। यह पुरुष चन्द्रमा से युक्त होने से पितृप्राण है, ऋतुकाल से ऋतु रूप है, शोणित दृष्टि से आर्तव रूप है। चन्द्रमा द्वारा पितृप्राण का शुक्र में समावेश हुआ, वहां सहोरूप चान्द्रभाग ऋण-धन द्वारा प्रजा के विस्तार में परिणत हुआ। पं. मोतीलाल जी ने श्राद्ध विज्ञान में विस्तृत व्याख्या की है, इस सिद्धान्त की। ऋग्वेद संहिता का उदाहरण देते हैं, महर्षि दीर्घतमा के मंत्रों द्वारा-

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्त्ति।
भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुपगात् प्रष्टुमेतत्।।
(ऋग्वेद 1.164.4)

भारतीय विवाह-बन्धन का लक्ष्य है पुत्र प्राप्ति कर पितृ ऋण से उऋण हो जाना। कैसे? बीजी-पिता शुक्राहुति के साथ शुक्रस्थ ऋण कलाओं का भी आधान कर देता है। प्रत्येक पुरुष की उत्पत्ति उसके पिता के 21 सहभागों के ऋण से हुई है। पुरुष के आत्मा-शरीर दो विभाग हैं। आत्मा से शुक्रमय महानात्मा का अर्थ है, जो जीवात्मा की आधार भूमि है। पंचभौतिक शरीर इस आत्मा का आश्रय है। जब तक शरीर का स्वरूप रक्षक प्राणाग्नि हैं, तब तक शरीर सुरक्षित है। प्राणाग्नि की रक्षा रक्त पर टिकी होती है। रक्त की स्वरूप रक्षा (संचरण क्रिया) आत्मा-चेतना पर आश्रित रहती है। भूमि और रक्त स्थूल हैं। प्राण और आत्मा सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म ही स्थूल की प्रतिष्ठा बनता है। प्राणात्मक महानात्मा शरीर की प्रतिष्ठा है।

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानामेना निहिता पदानि।
वत्से बष्कयेऽधि सप्ततन्तून् वितत्निरे कवय ओतवा उ ॥
(ऋग्वेद 1.164.5)

प्रजातन्तु विस्तार महानात्मा का कर्म है। देवता आग्नेय-सौम्य दो प्रकार के हैं। महानात्मा के आरंभक शुक्र-शोणित कहे गए हैं। महानात्मा सौम्य शुक्र में प्रतिष्ठित रहता है, अतः इसमें सोम की प्रधानता रहती है। किन्तु इसमें गर्भ में अग्नि भी विद्यमान रहता है। यह सोम सौम्य चान्द्रप्राण से युक्त होने से पितृसहः (28 कलायुक्त) कहा गया है। इन 28 कलाओं का विस्तार पुत्र-पौत्रादि सात पीढ़ियों में होता है। पिता अपने पुत्र में सात तन्तुओं का वितान (विस्तार) करता है। मूल में तो सौम्य प्राण ही (कवि) वितान करते हैं, पिता नहीं। ये 28 प्राण हैं। इन्हीं के द्वारा बीजी पुरुष सात पीढ़ी तक पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि में 21-15-10 आदि क्रम से वितान करता है।

अचिकित्त्वाञ्चिकितुषश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्मने न विद्वान्।
वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम् ॥
(ऋग्वेद 1.164.6)

बीजी (मूलपुरुष) इस तनन प्रक्रिया से सात स्थानों में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। इस क्रम में एक मूल प्रतिष्ठ होती है (विज्ञानात्मा), जिसने छह रजों (लोकों) को अपने में बांध रखा है। अर्थात् महानात्मा को आधार बनाकर पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र-वृद्ध, अतिवृद्ध, वृद्धातिवृद्ध प्रपौत्र ये 6 लोक विस्तारित होते हैं। ये रजांसि कहलाते हैं। बीजी को स्थिर धन तथा रजांसि को अस्थिर, रजो मर्यादा से बाहर मान लिया गया है।

माता पितरमृत आबभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे।
सा बीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥
(ऋग्वेद 1.164.8)

माता-पिता के ऋत भाग को उसके शरीर से च्युत करके उसे अपने गर्भाशय में प्रतिष्ठित कर गर्भरूप देने में समर्थ होती है। पुरुष कर्म का आधार है-'प्रजोत्पादनमहं करिष्ये' अर्थात् मैं प्रजा को उत्पन्न करूंगा। स्त्री अर्द्धांगिनी बनती है। इसका प्रारंभिक संकल्प ही दाम्पत्य भाव है, मानस संयोग है। तब भौतिक संयोग होता है। मातृगत शोणिताग्नि के आकर्षण से पुरुष में विद्युत संचार होता है। शुक्र में क्षोभ उत्पन्न होता है। अग्नि के आकर्षण से शुक्र पुरुष शरीर से च्युत होता है। अप् तत्त्व ऋत है-आपः, वायु, सोम। शुक्र-शोणित में पूंभ्रूण-स्त्रीभ्रूण की बहुलता से गर्भ का स्वरूप बन जाता है। यही अपत्य (सन्तान) महानात्मा की प्रतिष्ठा बनता है। इसी में सपिण्डता प्रवर्तक 28 कलात्मक पितृसहः पिण्ड सुरक्षित रहते हैं।

स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्नविचेतदन्धः।
कविर्यः पुत्रः स ईमाचिकेत यस्ता विजानात् स पितुष्पितासत्॥
(ऋग्वेद 1.164.16)

अग्नि वृषा है, पुरुष है। सोम योषा है, स्त्री है। पुरुष शरीर भूताग्नि प्रधान है। स्त्री शरीर भूत सोम प्रधान है। पुरुष के आग्नेय शरीर की प्रतिष्ठा सोम-शुक्र है। सौम्य स्त्री तत्त्व शुक्र रूप से पुरुष की प्रतिष्ठा है। अतः पुरुष भी स्त्री है। स्त्री के सौम्य शरीर की प्रतिष्ठा आग्नेय शोणित है। अतः आग्नेय पुरुष तत्त्व शोणित रूप से स्त्री की प्रतिष्ठा है। अतः स्त्री भी पुरुष कहलाती है। पुरुष-स्त्री शरीरों के मिथुन भाव से सृष्टि नहीं होती। पुरुष के सौम्य शुक्र तथा स्त्री के आग्नेय शोणित के समन्वय से सृष्टि होती है। 'स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस आहुः'। वस्तुतः इस द्वितीय युग्म (शुक्र-शोणित भाव) से भी गर्भ स्थिति नहीं होती। योषा-वृषा का तीसरा युग्म इस प्रक्रिया को सम्पन्न करता है। यह क्रिया 'कविपुत्र' कही जाती है। शुक्र सौम्य है किन्तु इसके गर्भ में रहने वाला पुंभ्रूण आग्नेय है। वृषा-प्राण प्रधान है। शोणित के गर्भ में रहने वाला स्त्रीभ्रूण-सौम्य-योषा प्रधान है। यही शोणित की प्रतिष्ठा है। जब तक इन पूंभ्रूण (सौम्य शुक्र में स्थित आग्नेय वृषा प्राण) तथा स्त्रीभ्रूण (आग्नेय शोणित में स्थित सौम्य योषा प्राण) का दाम्पत्य भाव नहीं हो जाता, तब तक शुक्र शोणित का मिथुन भाव व्यर्थ है। अतः यह तीसरा मिथुन भाव ही गर्भ स्थिति का कारण है। तथ्य यह है कि शुक्र-शोणित का मिथुन भाव में ऋण मोचन की गुप्त क्रिया सुरक्षित है। बन्धन मुक्ति इसी से होती है। यही हमारे विवाह-सूत्र के बन्धन का कारण बनता है।

शुक्र में स्थित पूंभ्रूण ही 21 मात्रा (ऋणाग्नि) से पुत्र रूप परिणत होता है। पिता से ही आत्मधेय रूप सात कलाएं (धनाग्नि) प्राप्त करता है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पुरुष में ऊपर की 6 पीढ़ियों से ऋणरूप 56 सहोमात्रा प्रतिष्ठित रहती है तथा 28 स्वयं अपनी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करता है। ये 56 मात्रा ऋण हैं, तथा 28 मात्रा धन हैं। इन 28 धनात्मक मात्राओं में 21 पुत्र में चली जाती हैं, सात स्वयं के पास रहती हैं। इस प्रकार 56 मात्रा का ऋण इसे चुकाना है। इनमें से 35 मात्रा की चुकती तो पुत्र उत्पन्न होने पर हो जाती है। ये भी ऋण भाग से पुत्र में चले जाते हैं। अब पुरुष में सात धन भाग तथा 21 ऋण भाग शेष रहते हैं। ये 28 भाग जीवनभर पुरुष के पास रहते हैं। इसकी बन्धनमुक्ति तभी संभव है जब कि यह 21 ऋणभागों का शोधन कर ले और सात भागों को पूर्ण कर ले। इसी पितृऋण मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। इससे चन्द्रलोक में स्थित पिता के अपूर्ण स्वरूप को पूर्णता मिलती है।

क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

https://t.me/AllNewsPaperPdf

आर्ट एंड कल्चर

राजनीति और फिल्मी सितारे

सिनेमा उस समय भी था, लेकिन न तो महात्मा गांधी के साथ और न ही भगत सिंह के साथ आजादी की लड़ाई में अभिनेताओं की कोई सीधी भूमिका देखी जा सकी थी। हां, यह जरूर है कि दादा साहब फाल्के, बाबू राव पेंटर, विजय भट्ट, वी. शांताराम जैसे फिल्मकारों ने राजनीतिक रूप से सचेत फिल्मों का निर्माण किया और अपनी विधा से स्वाधीनता आंदोलन को भरसक सहयोग पहुंचाने की कोशिश की। इसी राजनीतिक चेतना का विस्तार आजादी के बाद भी देखा जा सकता है। फिल्मकारों ने उस समय काफी अच्छी और महत्त्वपूर्ण फिल्में दीं, पूरे सकारात्मक सोच के साथ। एक ओर 'नया दौर', 'लीडर' तथा दूसरी ओर 'आवारा', 'जिस देश में गंगा बहती है' जैसी फिल्में बन रही थीं। गुरुदत्त 'प्यासा' जैसी फिल्में बनाकर उस पीढ़ी को निराशा के प्रति भी सचेत कर रहे थे। उस समय भी दलगत राजनीति में अभिनेताओं की सक्रियता न के बराबर थी।

विनोद अनुपम
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कला समीक्षक
@patrika.com

आज सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए अभिनेताओं-अभिनेत्रियों की कतार लगी है और राजनीतिक पार्टियां पलक पांवड़े बिछाए हुए हैं। ऐसे में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि अचानक कौन सा परिवर्तन आ गया? एक अद्भुत विरोधाभास यह भी है कि आज जब अधिकांश फिल्में समय, समाज और सोद्देश्यता से एक दम विपरीत बन रही हैं। सिनेमा का एकमात्र उद्देश्य संस्कृति एवं समाज का विखंडन दिखाना ही हो गया है। ऐसे में संसदीय राजनीति के प्रति उनका अतिरिक्त झुकाव ढेर सारे निहितार्थों की ओर इशारा करते लगता है। वास्तव में सिनेमा और राजनीतिक पार्टियों में कोई सीधा सरोकार नहीं रहने के बावजूद दोनों के स्वभाव में आश्चर्यजनक समानता देखी जा सकती है। आजादी के बाद शुरुआती दौर में जब राजनीतिक पार्टियां अपनी जनता के प्रति जवाबदेह थीं, तो सिनेमा भी उसी तेवर के साथ सामने आ रहा था। दोनों के समानुपातिक तेवर पर गौर इसी से किया जा सकता है कि बाद के दिनों में जैसे-जैसे पार्टियों ने जन सरोकारों से अपना मुंह फेरना शुरू किया, सिनेमा भी आम जनता से दूर होती चली गई।

सियासत : सबसे पुरानी पार्टी, सबसे कम सीटों पर मुकाबले में

370 पार vs 340 का वार

नई दिल्ली
अनंत मिश्रा

आजादी के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बोलबाला था। पार्टी 500 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर दो तिहाई बहुमत हासिल करती थी। उस दौर में कांग्रेस के मुकाबले चुनाव लड़ने वाले दल सीमित सीटों पर चुनाव लड़ते थे। समय चक्र बदला तो धीरे-धीरे देश में राजनीति का मिजाज भी बदलता गया। नब्बे के दशक में आते-आते कांग्रेस अनेक राज्यों में कमजोर होने लगी। चुनाव दर चुनाव लोकसभा चुनाव में सीटें घटती गईं। ऐसे में कांग्रेस की चुनाव लड़ने वाली सीटों की संख्या भी घटती गई। वर्तमान दौर में भाजपा जहां अबकी बार 370 पार का दावा कर रही है, वहीं पहली बार कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार पार्टी 340 प्रत्याशी उतारने जा रही है। यह संख्या कांग्रेस के चुनावी इतिहास का सबसे कम आंकड़ा है।

कहीं पास, कहीं दूर

कांग्रेस रणनीति भाजपा को रोकने की है, इसलिए पार्टी ने अनेक राज्यों में गठबंधन धर्म निभाने के लिए कम सीटों पर लड़ना भी मंजूर किया। लेकिन, कांग्रेस विपक्ष को पूरी तरह अपने साथ लाने में कामयाब नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने दिल्ली और गुजरात में तो हाथ मिला लिया, लेकिन पंजाब में दोनों दल आमने-सामने ताल ठोक रहे हैं। केरल की भी यही कहानी है। वामपंथी दलों से अनेक राज्यों में हुए समझौते के बावजूद केरल में दोनों दल दो-दो हाथ कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 'इंडिया' गठबंधन में शामिल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से समझौता नहीं है।

कांग्रेस की बदलती स्थिति

वर्ष	लड़ी	जीतीं	जीती सीटों का प्रतिशत
1951	479	364	76
1957	490	311	76
1962	488	361	84
1967	516	283	55
1971	441	352	80
1977	492	154	31
1980	492	353	72
1984	517	414	80
1989	510	197	39
1991	500	244	49
1996	529	140	26
1998	477	141	30
1999	453	114	25
2004	417	145	35
2009	440	206	47
2014	464	44	09
2019	421	52	12

जीती सीटों का गणित प्रतिशत में

लोकसभा में कुल सीटें: 543

- कांग्रेस अब तक सर्वाधिक सीटें लड़ी 529-(1996 में)
- इस बार कांग्रेस लड़ रही सिर्फ 340 सीटों पर (सबसे कम)
- अब तक घोषित प्रत्याशी 310

बड़े राज्यों में इस बार इन सीटों पर लड़ रही

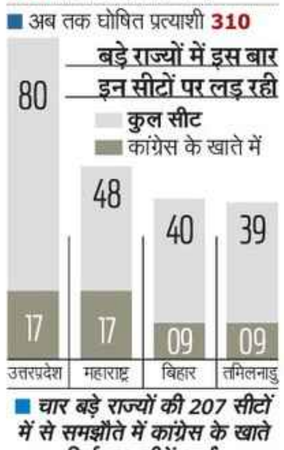

चार बड़े राज्यों की 207 सीटों में से समझौते में कांग्रेस के खाते सिर्फ 52 सीटें आईं।

इन दलों के साथ समझौता

- उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी
- बिहार में राष्ट्रीय जनता दल
- महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव और एनसीपी-शरद
- तमिलनाडु में दुमुक गठबंधन के साथ
- जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस के साथ
- झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ

20 साल में घटीं 100 सीटें

- 1984 में लड़ी थीं 517 सीटों पर
- 20 साल बाद यानी 2004 में 417 पर आजमाया भाग्य
- पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 81 सीटें कम

बड़ा खतरा : मतदान और प्रचार के दौरान राहत के उपाय करना आवश्यक

चुनावों की गर्मी में करें ताप की परवाह

इस वर्ष का गर्मी का मौसम आम चुनाव के कारण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। सात चरणों के चुनाव में मतदान दिनों में पात्र मतदाता भाग ले रहे हैं। गर्मियों से राहत के लिए सामुदायिक स्तर की तैयारियों के अलावा, बाहरी कार्यक्रमों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और सामुदायिक ढ़ांचे की मजबूती और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। सामुदायिक जागरूकता, गर्मी स्वास्थ्य संचार रणनीति, कुशल प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, समुदाय के नेतृत्व वाली तैयारी, सुनियोजित लक्षित जागरूकता आबादी में गर्मी से संबंधित बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है।

2024 के भारतीय आम चुनाव वर्तमान अल नीनो चरण से संक्रमण के साथ मेल खाते हैं, जो प्रशांत महासागर के गर्म होने के कारण देश में गर्मी और शुष्कता का कारण बनता है। पूर्वानुमानित ला नीना चरण हीटवेव का एक बड़ा खतरा पैदा करता है। चुनाव के दिनों में अधिक भीड़ और आश्रय स्थलों की कमी गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। पिछले साल की गर्मी के मौसम की कठिनाई को देखते हुए, जहां कई लोगों की मौतें न केवल दिन के उच्च तापमान के कारण हुईं, बल्कि अत्यधिक आर्द्रता के स्तर के कारण भी हुईं। इसलिए सावधानी भी आवश्यक हैं। अप्रेल 2023 में नवी मुंबई में खुली हवा में एक सभा में 14 व्यक्तियों की गर्मी के कारण हुई मौतें एक भयानक चेतावनी थी। चुनाव के दौरान यदि सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। गर्मी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव संबंधी गतिविधियों जैसे-प्रचार और रैलियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

गर्मी के प्रति जागरूकता, सामुदायिक स्तर की तैयारियों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देकर हीटवेव से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को कम करना संभव है। आइएमडी के मौसमी अनुमानों के आधार पर, भारत के चुनाव आयोग (इसीआइ) ने चुनावों से पहले ही हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, ईसीआइ ने गर्मी से संबंधित 'क्या करें और क्या न करें' की सूची दी है। चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुरक्षा के लिए गर्मी से सुरक्षा के बारे में व्यापक सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता होगी।

डॉ. महावीर गोलेच्छा
एम्स, दिल्ली एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रशिक्षित स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ
@patrika.com

> आयोजकों के साथ आम आदमी को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। चुनाव सभाओं में भाग लेते समय, पर्याप्त मात्रा में पानी और छाता रखना महत्त्वपूर्ण है। साथ ही लंबे समय तक बाहर रहने से बचना चाहिए।

आयोजकों के साथ आम आदमी को भी प्रतिभागियों के रूप में जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसी सभाओं में भाग लेते समय, पर्याप्त मात्रा में पानी और छाता रखना महत्त्वपूर्ण है और लंबे समय तक बाहर रहने से बचना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक प्रचार सभाओं के आयोजन और नियंत्रण के संबंध में अतिरिक्त नियम जारी किए हैं। विशिष्ट निवारक उपायों को अपनाना महत्त्वपूर्ण है जो चुनाव अभियानों, रैलियों और चुनावों के दौरान व्यक्ति को फिट और स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। प्रतिदिन सादा, हल्का भोजन करना आवश्यक है। ये खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ शरीर को उसके आदर्श ऊर्जा स्तर पर रखने और निर्जलीकरण से बचाने में सहायता करते हैं। जंक फूड और तले हुए खाद्य पदार्थों से दूर रहें क्योंकि इन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इन्हें पचने में काफी समय लगता है। मसालेदार खाना खाने से भी आपको गर्मी लग सकती है।

बड़ी सभाओं, राजनीतिक रैलियों और चुनावी प्रक्रिया के दौरान भाग लेते समय, लोगों को हल्के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने चाहिए और चौड़ी किनारी वाली टोपी या टोपी और धूप का चश्मा भी पहनना चाहिए। यदि लोगों को चक्कर आना, कमजोरी, चिंता, तीव्र प्यास या सिरदर्द जैसे लक्षण हैं, तो नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा में सहायता लेने की सलाह दी जाती है। तुरंत ठंडे वातावरण में जाना और अपने शरीर के तापमान को मापना महत्वपूर्ण है।भारी पसीना, चक्कर आना या मतली जैसे निर्जलीकरण या गर्मी की थकावट के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

समुदाय आधारित गैर सरकारी संगठनों को लोगों, विशेष रूप से बुजुर्गों, युवाओं, गर्भवती महिलाओं और बाहरी श्रमिकों को गर्मी से संबंधित बीमारियों की पहचान करने, रोकथाम के सुझाव और प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूक करना चाहिए।

आगामी चुनावी मौसम में, जब लाखों भारतीयों को मतदान करने के लिए खतरनाक तापमान सहना होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता अभियान और सक्रिय सामुदायिक तैयारी आवश्यक है। जनसंख्या पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने का संकल्प लें। हमें याद रखना चाहिए कि गर्मी से बचाव के लिए किया गया हमारा हर कार्य मायने रखता है।

चुनाव आयोग की जिम्मेदारी

चुनाव के दौरान नेता कई बार भड़काऊ भाषण देते हैं और बयानबाजी करते हैं। असल में अधिक से अधिक संख्या में वोट पाने के लिए वे ऐसा करते हैं। जनता पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। बयानबाजी की पुष्टि होने पर चुनाव आयोग को उस नेता को आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए।

-शंकर गिरि, रावतसर, हनुमानगढ़

आपकी बात

जनता करे बहिष्कार

कई नेता अपने भाषणों के जरिए समाज में नफरत फैलाते हैं। चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसका असर यह होगा कि भविष्य में कोई भी नेता भड़काऊ बयान देने पर दस बार सोचेगा। जनता को भी ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए।

-रानिया सेन, जयपुर

आज का सवाल

नोटा का चुनाव पर क्या असर होता है?

कल का सवाल था: नेताओं को भड़काऊ बयानबाजी से कैसे रोका जा सकता है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

पद की गरिमा बनी रहे

भड़काऊ बयान देकर जनता को बरगलाने का प्रयास किया जाता है। नेता को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जनता को भी इस तरह के नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। नेता लोकतंत्र का सम्मान करें और देश के विकास पर ध्यान दें। साथ ही जनता की समस्याओं को हल करें। ऐसे नेताओं का जनता साथ देती है।

-संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

कड़ी कार्रवाई की जरूरत

यदि किसी दल का नेता भड़काऊ भाषण देता है तो उस दल को अपने नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को ऐसे नेता को चुनाव लड़ने के अपात्र घोषित कर देना चाहिए और उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसी बयानबाजी के बाद यदि हिंसा होती है, तो संबंधित नेता को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए।

-भगवती प्रसाद गेहलोत, मंदसौर, मप्र

दैनिक जागरण

सत्य ही तथ्य की ढाल है

ईवीएम पर भरोसा

यह अच्छा हुआ कि बेतुकी दलीलों और कुछ फर्जी खबरों के सहारे ईवीएम का बटन दबाते समय दिखने वाली पर्ची यानी वीवीपैट के सौ प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईवीएम से प्राप्त नतीजों का सभी वीवीपैट से मिलान करने की मांग एक तरह से पिछले दरवाजे से मतपत्र से चुनाव कराने की पैरवी ही थी। यह पैरवी इससे भली तरह अवगत होने के बाद भी की जा रही थी कि मतपत्रों से चुनाव के समय किस तरह धांधली होती थी और मतपेटियां लूटने के साथ नतीजे आने में समय लगता था। बंगाल में तो पंचायत चुनावों में अभी भी मतपेटियां लूटने का काम होता है। ईवीएम के खिलाफ पहले भी सवाल उठते रहे हैं और उनका समाधान भी किया गया है। पहले वोटर को यह नहीं दिखता था कि उसका वोट वांछित प्रत्याशी को गया या नहीं? यह दिखाने के लिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई। फिर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा के एक बूथ की ईवीएम से मिले नतीजों का मिलान वीवीपैट से किया जाने लगा। इसके बाद यह मिलान पांच बूथों पर होने लगा। इसके बाद भी कुछ लोग संतुष्ट होने को तैयार नहीं। इनमें याचिकाबाज वकीलों के साथ कुछ राजनीतिक दल भी हैं। इनमें वे दल भी हैं, जो ईवीएम से हुए चुनावों में जीत हासिल कर सत्ता तक पहुंचे हैं।

ईवीएम की विश्वसनीयता और उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे रह-रहकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उच्चतर न्यायपालिका को ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा वे कोई न कोई बहाना लेकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने को अपना धंधा बना लिया है। ऐसे तत्व विदेशी मीडिया के उस हिस्से को भी खाद-पानी देने का काम करते हैं, जिसे न तो भारत की प्रगति रास आ रही है और न ईवीएम की सफलता पच रही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील प्रशांत भूषण ने यह दलील दी कि वह यह दावा तो नहीं करते कि इस मशीन से छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ईवीएम विरोधी यह भी दलील दे रहे थे कि मतदान की गोपनीयता भंग होने की चिंता नहीं की जानी चाहिए। यदि ईवीएम विरोधियों की यह मांग मान ली जाती कि सभी वीवीपैट की गिनती की जाए तो उससे नतीजे मिलने में कम से कम 12-15 दिन का समय तो लगता ही, खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाता। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर भरोसा जताया और सभी याचिकाएं खारिज कर दीं, लेकिन बेहतर होता कि वह इस मशीन को बदनाम करने के अभियान पर लगाम भी लगाता।

नदियों का प्रदूषण

यमुना में प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम को जिम्मेदार मानते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उस पर एक बार फिर बड़ा जुर्माना लगाकर यह संदेश दिया है कि नदियों के प्रदूषण के प्रति गंभीरता बरती जानी चाहिए। एनजीटी ने माना है कि केवल आगरा नगर निगम ही नहीं, मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने भी इस मामले में उदासीनता और लापरवाही बरती है, इसलिए क्रमशः 58.39 करोड़ और 7.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह चिंता की बात है कि एनजीटी पूर्व में भी कई नगर निगमों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर चुका है, फिर भी अपेक्षित सुधार होता नजर नहीं आता। यह प्रवृत्ति बन गई है कि कोई विवाद न्यायाधिकरण या कोर्ट में पहुंचने पर अधिकारी समस्या समाधान का हलफनामा दे आते हैं और फिर चुप बैठ जाते हैं। बात यमुना की ही करें तो आगरा में 61 नालों से अशोधित पानी यमुना में पहुंच रहा था और अधिकारी न तो उन्हें टैप कर पा रहे थे और न ही ऐसा पानी एसटीपी तक पहुंचा पा रहे थे। नदियों के साथ हमारे जीवन का सामाजिक ही नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध भी है, इन्हें पूर्णतया प्रदूषणमुक्त किया जाना चाहिए। बात केवल यमुना की ही नहीं, गंगा व अन्य नदियों में भी प्रदूषण पर अंकुश नहीं लग पा रहा, जो जलीय जीव-जंतुओं के लिए तो खतरा है ही, मानव समाज को भी इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। नदियों को प्रदूषणमुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन धरातल पर उनके सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। आगरा के अधिकारियों ने तो 43 स्थानों से नमूने लेकर यमुना के जल को बैक्टीरियारहित दर्शा दिया था। अधिकरण व अदालतों को गुमराह करने की प्रवृत्ति गलत है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

नदियों के साथ हमारे जीवन का सामाजिक ही नहीं धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध भी है, इन्हें पूर्णतया प्रदूषणमुक्त किया जाना चाहिए

चुनावी चंदे की नई व्यवस्था का सवाल

उमेश चतुर्वेदी

यह प्रश्न अनुत्तरित है कि चुनावी बांड योजना के खारिज होने के बाद राजनीतिक फंडिंग की नई व्यवस्था क्या होगी?

अवधेश राजपूत

राजनीतिक भ्रष्टाचार की चर्चा का एक सिरा चुनाव सुधार पर ही जाकर खत्म होता है। चुनावी फंडिंग भी इसका एक अहम पहलू है। इसी कड़ी में राजनीतिक फंडिंग को सुधारने की दिशा में 2018 में चुनावी बांड को एक बेहतर कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को खत्म कर दिया। चुनावों के ठीक पहले आए सरकार विरोधी फैसले पर विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी बांड की व्यवस्था को खारिज किए जाने के बाद राजनीतिक फंडिंग कैसे होगी? सवाल सिर्फ फंडिंग का नहीं है, बल्कि उसकी पारदर्शी व्यवस्था का भी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनावी बांड को न्यायिक चुनौती देने वाले भी किसी कारगर सुझाव को लेकर सामने नहीं आए हैं। अक्सर ऐसे लोगों की याचिका की पैरवी करने वालों के वकील प्रशांत भूषण भी इसे लेकर स्पष्ट नहीं हैं। हरसंभव मंच पर चुनावी बांड को खत्म किए जाने को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे विपक्षी दलों के पास कोई ठोस वैकल्पिक सुझाव नहीं है।

पारदर्शी फंडिंग व्यवस्था और चुनावी बांड की जरूरत का जवाब बनकर सामने आई है चुनाव आयोग की कार्रवाई से जब्त मोटी रकम। सिर्फ प्रथम चरण के मतदान से पहले यानी 13 अप्रैल तक ही रिकार्ड मात्रा में नकदी, ड्रग्स, शराब और गहने आदि जब्त किए जा चुके हैं। इस दौरान करीब 4,650 करोड़ की नकदी, ड्रग्स, शराब और गहने आदि जब्त होने की सूचना है। 2019 की पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब्ती से यह रकम बहुत ज्यादा है। वर्ष 2019 में करीब 844 करोड़ की नकदी जब्त की गई थी, जबकि इस बार पहले दौर के मतदान के पूर्व तक ही 395 करोड़ की नकदी जब्त की गई है। इसी तरह 2019 में 304 करोड़ मूल्य की शराब की जब्ती हुई थी, जबकि इस बार 13 अप्रैल तक ही 490 करोड़ की शराब जब्त की जा चुकी है। चुनावों में बांटने और रकम आदि जुटाने के लिए ड्रग्स का भी इस्तेमाल इन दिनों बढ़ा है। चुनाव आयोग ने पिछले आम चुनाव में जहां 1,280 करोड़ की ड्रग्स जब्त की थी, वहीं इस बार अभी तक ही यह आंकड़ा 2,068 करोड़ रुपये तक चला गया है। इसी तरह उपहार आदि के रूप में पिछली बार जहां महज 60.15 करोड़ मूल्य के सामान जब्त हुए थे, तो इस बार 1,142 करोड़ के सामान जब्त किए जा चुके हैं। स्पष्ट है कि चुनाव दर चुनाव किस कदर आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ने पर है।

अमेरिका में चुनावी फंडिंग सरकारी और निजी दोनों तरह से जुटाई जा सकती है। हालांकि सरकारी फंडिंग से जुड़े नियम बेहद सख्त और पेचीदा हैं। इसलिए करीब सभी उम्मीदवार निजी फंडिंग का सहारा लेते हैं। वहां निजी फंडिंग की कोई सीमा भी नहीं है। उम्मीदवार अपनी पार्टी के सदस्यों, समर्थकों और कारपोरेट कंपनियों एवं संस्थानों से रकम जुटाते हैं। निजी फंडिंग लेने वाला व्यक्ति कानूनन सरकारी फंडिंग का दावा नहीं कर सकता। अमेरिका में चुनावी खर्च इतना अधिक हो चुका है कि उसकी पूर्ति के लिए सरकारी फंडिंग ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसीलिए उम्मीदवार निजी फंडिंग का सहारा लेते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव के दोनों प्रत्याशी राष्ट्रपति बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप करीब-करीब 600-600 करोड़ डालर की फंडिंग जुटा चुके हैं।

अमेरिका की तरह भारत में भी चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी है, मगर हकीकत में इतने में कोई प्रत्याशी ठीक से विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव में खर्च होने वाली मोटी रकम की कहानी सभी दल जानते हैं। इसलिए अपने हिसाब से नियम की काट खोजते हुए पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लिहाजा सबको भारी फंडिंग की जरूरत होती है। सवाल यह है कि चुनावी बांड को खत्म करने के बाद सरकार पर हमलावर दल क्या यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें मिलने वाला फंड पवित्र और जायज है? चुनावी बांड में बेशक भाजपा को सबसे ज्यादा रकम मिली और उसके सत्तारूढ़ होने के कारण यह बहुत स्वाभाविक भी है, किंतु सवाल उठाने वाले दलों को मिली रकम भी कम नहीं है।

उदारीकरण के बाद से राजनीति में शुचिता का सवाल जितनी तेजी से उठा, सियासी फंडिंग का चलन भी उसी अनुपात में बढ़ा है। चुनावी बांड की व्यवस्था से पहले नियम था कि कंपनियां अपने तीन साल के लाभ का सिर्फ सात प्रतिशत ही दलों को दान कर सकती थीं। चुनावी बांड को खारिज करने का मुख्य आधार गोपनीयता का नियम रहा, जिसके तहत बांड खरीदने वाले की जानकारी हासिल नहीं की जा सकती थी। चुनावी बांड के पहले तक तो यह भी पता नहीं होता था कि किसने, किस दल को, कितनी रकम दी? ज्यादातर रकम नकदी होती थी, जिसका ठोस हिसाब भी नहीं होता था। 1996 के आम चुनावों के ठीक पहले हवाला कांड में जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव पर एक लाख रुपये लेने का आरोप था। तब उन्होंने स्वीकार किया था कि दल चलाने के लिए कब और कहां से पैसे आते हैं, इसका हिसाब नहीं रखा जा सकता। नकदी से मिली बेहिसाब रकम की जब चोरी आदि हो जाती थी, तब भी नेता पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से बचते थे, क्योंकि चोरी में रकम की जानकारी देते तो उसका स्रोत भी बताना पड़ता। कई दल अपने सैकड़ों करोड़ की नकदी को कार्यकर्ताओं और अपने सदस्यों से दान रूप में हासिल करने का झूठा दावा भी इसी वजह से करते रहे।

अब जब चुनावी बांड की व्यवस्था समाप्त हो गई है तो राजनीतिक दल अपने खर्च के लिए येन-केन प्रकारेण पैसे जुटाएंगे। कानूनी प्रविधानों के छिद्रों का इस्तेमाल भी होगा। इस लिहाज से देखें तो चुनावी बांड एक सीमा तक बेहिसाब फंडिंग को हिसाबी दायरे में ही ला रहा था। पारदर्शिता के लिहाज से उसमें सुधार किया जा सकता था। राजनीतिक शुचिता का हिमायती होने का दावा करने वालों को चाहिए कि वे फंडिंग की ऐसी पारदर्शी वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करे, जिसमें संदेह की गुंजाइश न हो। अन्यथा चुनाव सुधार और पारदर्शी फंडिंग का समर्थन भी खोखला ही माना जाएगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक टिप्पणीकार हैं)

response@jagran.com

महिला हितैषी कानूनों का दुरुपयोग

क्षमा शर्मा

जो महिलाएं दहेज प्रताड़ना झेलती हैं, कानून उनकी मदद करे, साथ ही निर्दोषों को फंसाने पर रोक भी लगे

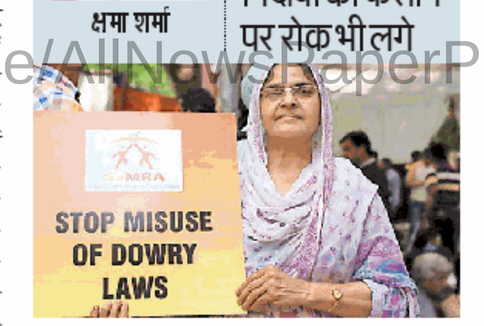

चिंताजनक है कानूनों का एकतरफा झुकाव। फाइल

दहेज अधिनियम और अन्य महिला कानूनों के दुरुपयोग की खबरें लगातार आती रहती हैं। उच्चतम न्यायालय ने ही इसे एक बार 'कानूनी आतंकवाद' कहा था, लेकिन इसके बावजूद इस मोर्चे पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक महिला ने अपने पति से परिवार अदालत में तलाक ले लिया, लेकिन इसके छह महीने बाद उसने दहेज निरोधी अधिनियम के तहत पूर्व पति और उसके घर वालों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर पति को चार्जशीट किया। इस पर उसने उच्च न्यायालय की शरण ली और अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाई समाप्त करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने उसकी अपील निरस्त कर दी। इसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उसके वकील ने उच्चतम न्यायालय में यह भी कहा कि महिला ने पहले भी जब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपील की तो अदालत ने इसे नहीं माना था और महिला ने भी इस मामले को नहीं बढ़ाया था। वकील ने यह तर्क भी दिया कि जब परिवार अदालत द्वारा शादी समाप्त की जा चुकी है तो इस तरह की शिकायत साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनु. 142 के तहत मिले विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए मामले को खारिज कर दिया। उसने यह भी कहा कि तलाक के बाद लोगों को उत्पीड़न से बचाना जरूरी है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति को दस साल तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। इन वर्षों में उसने और उसके परिवार ने कितनी मुसीबत झेली होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सोचिए कि जिनके पास साधन-संसाधन न हों, वे क्या करें?

अदालतें दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के झूठे मामलों में स्त्रियों को फटकार तो लगाती रहती हैं, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग इसलिए नहीं थम रहा, क्योंकि उन्हें झूठा मामला बनाने पर कोई सजा नहीं मिलती। बदले की भावना, पति के परिवार वालों के साथ न रहना, जमीन-जायदाद के मसले, कई बार पुरुष मित्र के साथ जाने की चाहत आदि को लेकर 498-ए का खूब दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे मामलों में आदमी की पहचान भी बार-बार उजागर की जाती है। कई बार उसके फोटो भी छपते हैं। नौकरी चली जाती है। जेल भी जाना पड़ता है। कुछ के तो सारे पैसे और पूरी बचत तक खर्च हो जाती है। यह अफसोस की बात है कि कानूनों ने पुरुषों और उनके परिवार को ऐसे दानवों के रूप में बदल दिया है, जो किसी स्त्री के आरोप लगाते ही अपराधी मान लिए जाते हैं। आरोपित को अपराधी बनाने का चलन हमारे यहां बेहद आम है। मीडिया का एक हिस्सा इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेता है। आखिर यह कैसे मान लिया गया है कि कानून का काम सिर्फ एक पक्ष को न्याय देना है। स्त्री या पुरुष, जो भी अपराधी हो उसे सजा मिले, लेकिन किसी के आरोपित बनते ही उसे अपराधी सिद्ध कर देना कहां का न्याय है?

कायदे से जिस पर आरोप लगा है, वह जब तक अपराधी साबित न हो जाए, तब तक उसकी पहचान उजागर न की जाए। ऐसा करने से बहुत से निरपराधों को बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे नीति-नियंता इन बातों को नहीं जानते, लेकिन नारी हित के नाम पर क्रूर कानून बदलने की कोई कोशिश नहीं की जाती। क्या इसलिए कि उन्हें महिलाओं के वोट चाहिए और जरा सा भी परिवर्तन करेंगे तो महिला हितों के नाम पर दुकानदारी करने वाले शोर मचाएंगे? विकसित देशों में शायद ही कहीं ऐसे कानून हों, जहां एक पक्ष को सत्यवादी मान लिया जाए और दूसरे को बिना प्रमाण अपराधी। आखिर पुरुषों के मानवाधिकारों के बारे में कब सोचा जाएगा या पुरुष होने का मतलब मनुष्य होना नहीं है?

हाल में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी दहेज निरोधी अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की। उसने एक मामले में फैसला दिया कि बहुत बार महिलाएं पति के रिश्तेदारों तक को इस एक्ट में आरोपित बना देती हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं होता। वे अलग भी रहते हैं। जो घटनाएं हुई ही नहीं होतीं, उनका उल्लेख किया जाता है, जिससे 498-ए का केस बनाया जा सके। उक्त मामले में पति के आठ रिश्तेदारों को आरोपित बनाया गया था। न्यायालय ने पति और उसकी मां के खिलाफ मामले को जारी रखा, मगर रिश्तेदारों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।

बीते कुछ समय में तो ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं कि पति के परिवार से भारी-भरकम रकम लेकर मामले को खत्म किया गया। अब जिनके पास पैसे हैं, वे तो ऐसे समझौते कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं, वे क्या करें? कहां जाएं? आखिर उच्चतम न्यायालय तक कितने लोग पहुंच सकते हैं? निःसंदेह महिलाएं और उनके परिवार दहेज से परेशान रहते हैं। जिन महिलाओं को दहेज के चलते तंग किया जाए, कानून उनकी पूरी मदद करे, लेकिन इसके साथ ही निरपराधियों को फंसाने की कोशिश पर रोक लगाई जाए। हरियाणा के एक परिचित ने बताया कि वहां ऐसे गिरोह बन गए हैं, जो महिला कानूनों की आड़ में ब्लैकमेल करके वसूली करते हैं। सरकारों और महिलाओं के लिए काम करने वाले लोगों को इस ओर जरूर सोचना चाहिए। कानूनों का दुरुपयोग उनकी विश्वसनीयता कम करता है। वक्त की मांग यह है कि महिला कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। कानून किसी एक पक्ष को डराने के लिए नहीं, सभी पक्षों को न्याय देने के लिए होते हैं। राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि उनके वोटर पुरुष भी हैं। कहीं यह तो नहीं मान लिया गया कि आखिर वे जाएंगे कहां, इसे या उसे वोट तो देंगे ही? आखिर नेता पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए क्यों कुछ करना नहीं चाहते? राजनीतिक विमर्श में उनसे जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

योग्यता और सम्मान

सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य की होती है। विज्ञानियों के अनुसार जब किसी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है तो उसे प्रसन्नता एवं संतुष्टि की अनुभूति होती है, जिसका सकारात्मक असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, तब उसके भीतर हीनभावना उत्पन्न होती है। वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन की शांति और उत्साह को पूर्णतः खो देता है। अपने अनादर की वजह से जो गहरी चोट उसके दिल पर लगती है, उससे वह असंतोष, घृणा, शत्रुता और प्रतिशोध की नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है।

संसार को व्यवस्थित रखने के लिए प्रकृति ने विनिमय की व्यवस्था बनाई है। इसके अनुसार यदि आप कुछ देते हैं, तभी कुछ प्राप्त कर पाते हैं। मूल्य चुकाए बिना इस संसार में किसी को भी कुछ नहीं मिलता। इस नियम के हिसाब से सीधा उपाय तो यही है कि जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें वैसी योग्यता भी प्राप्त करनी चाहिए। योग्यता अपने आप ही हमें अभीष्ट तक पहुंचा देती है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य सम्मान और प्रशंसा का आकांक्षी हो तो उसके लिए उसे उसी अनुरूप अर्हता भी अर्जित करनी होगी।

कोई धूर्त व्यक्ति अपनी चालाकियों से अस्थायी रूप से सम्मान प्राप्त कर ले तो भी उसे उससे स्थायी संतुष्टि नहीं मिलेगी। उलटे जब उसकी वास्तविकता उजागर होगी तो वह उपहास का पात्र बनेगा। याद रहे कि कागज की नाव बहुत ज्यादा समय तक नहीं तैर सकती और अंततः डूब जाती है। इसीलिए कपट से कुछ प्राप्त करने के बजाय योग्यता और गुणवान बनने पर अपना समय एवं शक्तियां केंद्रित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्थायी सम्मान के पात्र बनेंगे। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। वास्तविकता को सराहते हैं, कृत्रिमता को नहीं।

राजयोगी ब्रह्माकुमार निकुंज जी

मेधा पर हावी कलुषित मानसिकता

सोनम लवंशी

महिलाओं के प्रति हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को अपना सोच बदलना होगा

हाल ही में यूपी बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी किया है। सीतापुर की एक होनहार बेटी प्राची ने पूरे प्रदेश में टाप किया। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों का निकृष्ट सोच का स्तर देखिए कि प्राची के अच्छे स्कोर, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन की सराहना करने के बजाय उसके चेहरे पर दिख रहे बालों का मजाक बनाया। इंटरनेट मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स बनाए गए। जिस कार्य के लिए समाज को उसकी सराहना करनी चाहिए, वह उसके चेहरे पर दिख रहे बालों पर कटाक्ष कर रहा है। क्या आज चेहरे की खूबसूरती ही मायने रखती है? पढ़ाई का खूबसूरती के आगे कोई महत्व नहीं है!

प्राची ने 98.5 प्रतिशत स्कोर के साथ 600 में से 591 अंक प्राप्त किए हैं। जाहिर है कि इसके लिए प्राची ने कड़ी मेहनत की है। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वालों ने उसके चेहरे का मजाक बनाया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चेहरे की सुंदरता शिक्षा से भी बड़ी हो गई है?

वस्तुतः हमारे समाज की यही परेशानी है। कोई किसी की उपलब्धि की सराहना करे या न करे, निंदा करने में कोई पीछे नहीं रहता है। सदियों से महिला को उसके रंग-रूप, चाल-ढाल को लेकर जज किया जाता है। महिला को कुछ लोग केवल उपभोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। महिला यदि खूबसूरत नहीं है तो कुछ लोग उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखते हैं। जबकि सुंदरता अंगों के माप, उसके रंग या उसके भौतिक स्वरूप से नहीं होती है। ऐसे में स्त्री को स्वयं को इन मापदंडों से मुक्त करना होगा।

वैसे यदि प्राची की जगह कोई लड़का टाप करता, तो उसके रंग, रूप या चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं करता। क्यों समाज में स्त्री और पुरुष में इस तरह भेदभाव किया जाता है। सुंदर होना, नहीं होना, यह किसी लड़की के हाथ में नहीं होता है। बावजूद इसके एक लड़की को लेकर हमारा समाज संवेदनहीन हो चला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी स्त्री को उसके रंग रूप या किसी अन्य कारण से उसका मजाक उड़ाया गया हो। यहां तक कि हमारे देश की राष्ट्रपति को भी उनके रंग को लेकर मजाक बनाया गया। कुछ साल पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के रूप-रंग को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने उनके 'लुक्स' को लेकर अपमानजनक बातें कहीं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था, 'हम राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं?'

सोचिए कि जब देश की राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पर बैठी महिला तक को नहीं छोड़ा गया तो फिर एक आम महिला को किस तरह अपमानित किया जाता होगा। महिला कोई वस्तु नहीं है, उसका अपना एक वजूद है। उसे समाज में सम्मान मिलना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भाजपा की संभावनाओं की पड़ताल

'दक्षिण में भाजपा की संभावनाएं' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. एके वर्मा ने दक्षिण भारतीय राज्यों के चुनावी परिदृश्य का गहन विश्लेषण किया है। इसकी शुरुआत उन्होंने कर्नाटक से की है। इस बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दक्षिण के सभी राज्यों में सधी हुई रणनीति अपनाई है। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी से गठबंधन कर जहां सामाजिक आधार का विस्तार किया गया, वहीं आंध्र में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टियों के साथ गठजोड़ को प्राथमिकता दी। तमिलनाडु में वह अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता की विरासत पर दावा ठोकने के प्रयास में है। ऐसे में पूरी संभावना है कि भाजपा इस बार दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। इसके बूते अगर पार्टी को 370 से अधिक सीटें हासिल हो जाएं तब आसानी से राजग 400 का आंकड़ा छू लेगा। दूसरी ओर, विपक्षी दल अपने बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के फेर में वे मजहबी आरक्षण का जो राग अलाप रहे हैं, इसका दुष्परिणाम उन्हें चुनाव परिणाम में देखने को जरूर मिलेगा।

मुकेश कुमार मनन, पटना

नेताओं की अमर्यादित भाषा

लोकसभा चुनाव में नेताओं की भाषण शैली द्वेयम दर्जे की हो चुकी है। मान-मर्यादा तो बहुत दूर की कड़ी हो चुकी है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कुछ नेताओं के भाषणों से परिपक्वता का अभाव स्पष्ट रूप झलकता है। विरासत में मिली राजनीतिक शक्ति का मतलब यह नहीं होता कि अपने से उम्र में बड़े और कद्दावर नेताओं के लिए तू-तड़ाक जैसी भाषा का प्रयोग करें। भारतीय संस्कृति और संस्कार ऐसी भाषा की अनुमति नहीं देते। वैसे भारतीय लोकतंत्र में मतदाता ज्यादा मुखर नहीं होता, लेकिन वोट के माध्यम से अपना आशीर्वाद और देश का नेतृत्व करने का अधिकार राजनीतिक रूप से कुशल, कुशाग्र बुद्धि के धनी, परिपक्व, धैर्यवान और राष्ट्र के प्रति वफादारी निभाने वाले नेता को ही सोच समझ कर सत्ता की चाबी सौंपता है। इसलिए सभी नेताओं को सोच-समझ कर मनभेद से आच्छादित शब्दों को तिलांजलि देकर लोकतंत्र की छवि और मर्यादा को ध्यान में रखकर ही साफ-सुथरी शब्दावली को ही अपनाना चाहिए। अमर्यादित और आक्रोशपूर्ण शब्द जनता-जनार्दन को आकर्षित नहीं करते। इसलिए नेताओं को भाषा की मर्यादाओं को समझना होगा।

दीपक गौतम, सोनीपत

भाजपा का बढ़ता दायरा

दक्षिण में भाजपा की संभावनाएं शीर्षक आलेख में डा. एके वर्मा ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सही लिखा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को लक्ष्य की प्राप्ति कराने में दक्षिण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बेशक पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी मेहनत की है, जिसस कारण दक्षिण में मोदी के प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस चुनाव में भाजपा ने तमिलनाडु में अभूतपूर्व प्रयास किया है। तेलंगाना में भी भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। वर्ष 2019 के संसदीय चुनावों में भाजपा दक्षिण में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, सीटें भी बढ़ेंगी। केरल में पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रति ईसाइयों के बीच असंतोष को उजागर किया। यह अवलोकन राज्य में ईसाई समुदाय से अपील करने के भाजपा के प्रयासों को रेखांकित करता है, जो कई निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनावी प्रभाव रखता है। केरल में ईसाई मतदाताओं को लुभाने पर भाजपा का ध्यान राज्य में अपना समर्थन आधार बढ़ाने के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। केरल के बारे में पीएम मोदी ने कहा है कि जनसंघ के समय से ही वह देश के हर हिस्से में सेवा करना चाहते हैं। जहां राजनीतिक फायदा हो वहां काम करें, जहां फायदा न हो वहां काम न करें, ये हमारे सिद्धांत नहीं हैं।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शनिवार, 27 अप्रैल 2024

ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि यह अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।
-महात्मा गांधी

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल 32 देशों में भूख से जूझते 3.60 करोड़ पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर गंभीरतम होना और करीब ढाई करोड़ बच्चों का भोजन न मिल पाने के कारण कई बीमारियों का शिकार हो जाना वाकई मानवीय विफलताओं का ही प्रतीक है।

भूख और बच्चे

संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य संकट पर जारी वैश्विक रिपोर्ट का यह कहना कि पिछले वर्ष दुनिया के 59 देशों के 28 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से जूझते रहे, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही थे, क्षुब्धकारी तो है ही, आंकड़ों के मायाजाल में उलझी 'विकास' की अवधारणा की भयावह तस्वीर भी पेश करता है। रिपोर्ट में खासकर पांच देशों, यानी फलस्तीन, दक्षिणी सूडान, यमन, सीरिया और हैती की स्थिति बेहद गंभीर बताई गई है, जहां के सात लाख से ज्यादा लोग अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित भूख के पैमाने के उच्चतम स्तर पर हैं, जो 2016, यानी रिपोर्ट आने की शुरुआत से करीब चार गुना ज्यादा है। इस परिमाण में लोगों का भूख से पीड़ित होना, और साल-दर-साल इस संख्या का बढ़ते जाना एक वैश्विक मानवीय त्रासदी को लेकर सामूहिक लापरवाही को दर्शाता है, जिस ओर सभी देशों को ध्यान देना ही चाहिए। अपने सातवें महीने में पहुंच चुके इस्राइल-हमास युद्ध की वजह से गाजा में करीब 11 लाख लोग भूख के पैमाने के पांचवें स्तर पर तो पहुंच ही गए हैं, जुलाई तक वहां अकाल जैसी स्थितियों की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा, 2024 की शुरुआत में अल नीनो के चरम ने पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बाढ़ व अनियमित बारिश और दक्षिणी अफ्रीकी देशों, खासकर मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में सूखे की स्थितियां पैदा की, जिससे पहले से ही अभावग्रस्त इन क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ी ही हैं। अब यहां साल के अंत तक ऐसी ही स्थितियां बनी रहने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, वे चिंतित करने वाली हैं। सूडान हो या सोमालिया लगातार गृहयुद्ध से जूझते अफ्रीकी देशों में भूख व गरीबी वर्षों से चली आ रही है। लेकिन पिछले साल 32 देशों में भूख से जूझते 3.60 करोड़ पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर गंभीरतम होना और करीब ढाई करोड़ बच्चों का भोजन न मिल पाने के कारण कई बीमारियों का शिकार हो जाना वाकई, जैसा संयुक्त राष्ट्र महासचिव कहते हैं, मानवीय विफलताओं का ही प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र हालिया वर्षों में विभिन्न देशों में चलाए जा रहे अपने कार्यक्रमों की विफलताओं का ठीकरा बेशक फंडिंग की कमी पर फोड़े, लेकिन उसके लगातार अप्रासंगिक होते जाने की वजह उसकी वे व्यवस्थाएं ही रही हैं, जिनमें चुनिंदा देशों के हितों को प्राथमिकता मिली। पिछले आठ साल से जारी हो रही इन रिपोर्टों से औपचारिकता की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन अगर वाकई बच्चों को भूखे मरने से बचाना है, तो भोजन की आपूर्ति करने वाली प्रणालियों में सुधार तो लाना ही पड़ेगा, इस गंभीरतम मानवीय संकट से निपटने के लिए सभी देशों को सामूहिक जिम्मेदारी समझते हुए आगे आना होगा।

जंगल की आग का भयावह राग

वनों को आग से बचाने के लिए वन क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य होने चाहिए, ताकि एक तरह की नमी बनी रहे और किन्हीं वजहों से अगर आग लग भी जाए, तो वह ज्यादा फैले नहीं। साथ ही, वन पंचायत और वन विभाग की सार्थक भागीदारी के लिए पहल होनी चाहिए।

उत्तराखंड में जंगल की आग एक बार फिर बड़ा रूप ले चुकी है, जबकि इस बार तो पहले से ही पता था कि जंगल की आग विकराल रूप लेगी। अभी अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ और अब तक करीब 256 हेक्टेयर जंगल में आग लग चुकी है। जंगल में आग लगने की 245 घटनाएं हो चुकी हैं। जाहिर है, आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी। वनों में आग लगने का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन पहले छिटपुट घटनाएं होती थीं, जिन पर तुरंत नियंत्रण पा लिया जाता था, क्योंकि तब न इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती थी और न ही ऐसी ज्वलनशील पादप प्रजातियां थीं। तब वन और जन का रिश्ता अटूट था। पूरे गांव के लोग इस दवानल पर भारी पड़ते थे।

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद

वनाग्नि सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे आग को भड़काने में पूरी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दुनिया का औसत तापमान अगर बढ़ चुका है, तो आग तो पूरी दुनिया के जंगलों में लगेगी ही। कनाडा, कैलिफोर्निया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया इसके ताजा उदाहरण हैं। इन देशों में शीतोष्ण जलवायु है, फिर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण दावानल की घटनाएं होती रहती हैं।

मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक शोध से पता चला है कि आग 2001 से ज्यादा ही कहर ढा रही है। वर्ष 2001 में 30 लाख हेक्टेयर वनों को आग से नुकसान हुआ, तो 2021 में 90 लाख हेक्टेयर वन राख हुए। कनाडा में 2022 में 60 लाख हेक्टेयर वन राख हो गए। रूसी वनों के हालात भी ऐसे ही थे, जहां 2020 की तुलना में 2021 में 31 फीसदी ज्यादा वन जले।

सच तो यह है कि जैसे-जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि 150 वर्षों के अध्ययन से पता चला कि प्रचंड गर्मी की स्थिति आज पांच गुना बढ़ गई है। दुनिया भर में वनाग्नि के बड़े असर होंगे। अंतर बस इतना है कि बेहतर प्रबंधन के कारण विकसित देश ऐसी आपदा से जल्दी निपट लेते हैं, जबकि विकासशील या पिछड़े देशों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।

ग्लोबल वार्मिंग के चलते वनों की आग एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। पृथ्वी पर अब मात्र 31 फीसदी वन बचे हैं। दुनिया में प्रति व्यक्ति 0.61 हेक्टेयर वन क्षेत्र बचे हैं, जबकि अपने देश में यह 0.08 हेक्टेयर है। यह स्वस्थ उपलब्धता नहीं कही जा सकती।

अपने देश की चिंता ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हमारे यहां उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां हैं। शीतकाल में पर्याप्त वर्षा न होने से मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती। इसी वजह से झाड़ ज्यादा होने तथा पत्ते नहीं हटाए जाने से उनमें तुरंत आग पकड़ लेती है, जो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेती। जब शुरू में आग लगती है, तो उसमें एयर पॉकेट आ जाता है, जिसे भरने के लिए हवाएं चलती हैं, जिसके चलते आग तेजी से फैलती है। अन्य कारणों में, शीतकालीन वर्षा का अभाव, पतझड़ लंबा होना तथा गर्मी का लगातार बढ़ना तो है ही।

पिछले कुछ वर्षों से हम लगातार वनों की आग को झेल रहे हैं, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पर्याप्त संसाधनों की कमी। खास तौर से वन विभाग में एक-एक फॉरेस्ट गार्ड के नियंत्रण में करीब डेढ़ सौ से 200 हेक्टेयर वन आते हैं, जो वनों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ने का एक और कारण है कि 1988 से पहले वन गांव वालों की भागीदारी से पनपते थे, लेकिन आज वह कड़ी टूट चुकी है। आज की वन नीति में गांव की भागीदारी चाहे जितनी भी हो, वह प्रभावी नहीं दिखती। इसके अलावा वनों और गांव के बीच दूरी बढ़ गई है। पहले गांव के गांव वनों की आग बुझाने के लिए जुट जाते थे। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। वन विभाग के पास न तो पर्याप्त मैनपावर है और न ही सटीक रणनीति। जंगलों में आग लगने से सिर्फ वनों का नुकसान नहीं होता, बल्कि वन्य जीव भी मारे जाते हैं। खास तौर से छोटे पशु-पक्षी, जिनके जीवन का आधार ही वन है। यही नहीं, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से इस आग से मिट्टी फटने लग जाती है और फिर बारिश में सारी उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है। वनाग्नि से पानी के स्रोत भी सूख जाते हैं।

गंभीर बात यह भी है कि अभी तक हमने इस बात पर नीतिगत विचार नहीं किया है कि हम किस तरह से सामूहिक भागीदारी से वनों को बचा सकते हैं। यह पूरे समाज के लिए एक बड़ा संदेश होना चाहिए कि जलते वन को दूर से देखने का अब समय नहीं है, क्योंकि वनों का योगदान पानी, हवा या अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराने में भी है। इसलिए इसे मात्र विभागों का दायित्व न समझ कर और गांव वालों के ही भरोसे इसका बोझ डालकर छुट्टी नहीं पा लेनी चाहिए, बल्कि सबको मिलकर वनों की रक्षा करनी चाहिए। अगर इन घटते वनों को आग ने लील लिया, तो तापक्रम तो बढ़ेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राण संकट में डाल देगी। इसके अलावा, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि हम वनों को बचाएं।

इसके लिए वन पंचायत को मजबूत कर उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। कम से कम वन पंचायतों को उनके चारों तरफ 100 हेक्टेयर भूमि के वनों की जिम्मेदारी सौंपी जाए और उनसे अपेक्षा की जाए कि वे वनों को अग्नि से बचाएं और बदले में उन्हें वन को अपने लिए उपयोग करने की सुविधा दी जाए। वन पंचायतों की भागीदारी के बिना वन विभाग के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि वह आग पर नियंत्रण पा ले। वनों को आग से बचाने के लिए वन क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य भी होने चाहिए, ताकि एक तरह की नमी बनी रहे और किन्हीं वजहों से अगर आग लग भी जाए, तो वह ज्यादा फैले नहीं। इसके अलावा पतझड़ में जो पत्ते गिरते हैं, उन्हें हटाने एवं उनके उपयोग करने के उपाय करने होंगे। इससे जहां रोजगार उत्पन्न होगा, वहीं वनाग्नि पर भी अंकुश लगेगा। मुख्य बात यही है कि वन पंचायत और वन विभाग की सार्थक भागीदारी के लिए पहल होनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो आग सिर्फ वनों को ही नहीं, बल्कि हमारे संसाधनों और प्राणों को भी लील लेगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

लियो टॉल्सटॉय

जीवन का एकमात्र उद्देश्य नि:स्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करना है। दूसरों की मदद करने के महान कार्य की तुलना में भौतिक धन या व्यक्तिगत खुशी की खोज व्यर्थ है।

खुश रहने की शक्ति तो हमारे भीतर ही छिपी है

यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो खुश रहें। यह खुशी के बारे में एक गहरा सच है। भौतिक संपत्ति की चाह में भाग रही इस दुनिया में असली खुशी की कुंजी हमारे भीतर ही है। खुश रहना चुनकर हम अपनी भलाई के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। वास्तविक खुशी धन, संपत्ति या उपलब्धियों पर ही निर्भर नहीं है और न ही उन तक सीमित है, बल्कि असल खुशी सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और वर्तमान क्षण में संतोष को स्वीकार करने में है। खुशी वास्तव में एक विकल्प है और खुश रहने की शक्ति सिर्फ हमारे भीतर ही निहित है। खुशी कभी भी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे, किस रूप में देखते और लेते हैं। यही वह महत्वपूर्ण पक्ष है, जो खुशी की प्रकृति के बारे में गहन सच्चाई को खूबसूरती से बयां करता है। केवल बाहरी कारक या धन या भौतिक संपत्ति ही खुशी का निर्धारण नहीं करती, बल्कि यह हमारा व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। सच्ची खुशी चीजों पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम उन्हें कैसे संजोते हैं।

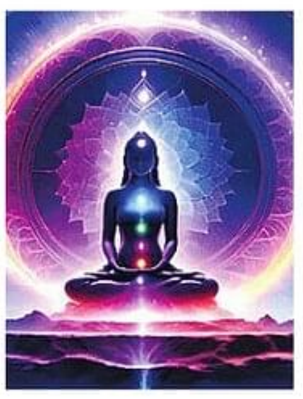

जीवन का एकमात्र उद्देश्य निःस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करना है। दूसरों की मदद करने के महान कार्य की तुलना में भौतिक धन या व्यक्तिगत खुशी की खोज व्यर्थ है। हमारे जीवन को सच्चा अर्थ और पूर्णता तब मिलती है, जब हम अपने साथी मनुष्यों के कल्याण और बेहतरी के लिए खुद को समर्पित करते हैं। मानवता की सेवा में हम करुणा और सहानुभूति की अपनी अंतर्निहित क्षमता का उपयोग करते हैं, पहचान और स्थिति से परे संबंध बनाते हैं। दयालुता, समझ और बलिदान के कार्यों के माध्यम से हम समाज की सामूहिक प्रगति में योगदान करते हैं और इससे एक ऐसा स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, जो हमारे अस्तित्व से कहीं अधिक होता है। इस तरह दूसरों के लिए कुछ अच्छा और कल्याणकारी करने के लिए हम जो अपना जीवन समर्पित करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है।

सबसे बड़ी खुशी दुख के स्रोत को जानना है। अगर हमें अपने दुखों के कारण पता चल जाए, हम उन्हें समझ लें, तो यहीं से हमारे लिए खुशी के दरवाजे खुल जाते हैं। सच्ची खुशी हासिल करने की कुंजी तो संकट के मूल कारण को समझने में ही छिपी है। अगर हमें अपने दुखों, संकट या समस्या का असल कारण पता चल जाता है, तो हम उससे निकलने के रास्ते तलाशने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और सकारात्मक रुख रखते हुए सार्थक बदलाव हासिल करने की शक्ति हमारे भीतर आने लगती है। इसलिए जो लोग अपने दर्द और परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं, वही वास्तविक खुशी और संतुष्टि से भरे जीवन की ओर बढ़ पाने में सक्षम होते हैं।

दुखों का कारण खोजें...

सूत्र

अगर हमें अपने दुखों, संकट या समस्या का असल कारण पता लग जाता है, तो हम उससे निकलने के रास्ते तलाशने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और सकारात्मक रुख रखते हुए सार्थक बदलाव हासिल करने की शक्ति हमारे भीतर आने लगती है।

दूसरा पहलू

जैसे-जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या विकराल होती जा रही है।

चिलचिलाती गर्मी में खारे पानी की सजा

राजस्थान में जैसे-जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। 'पानी के जो स्रोत उपलब्ध हैं, उसमें इतना खारा पानी आता है कि पिया भी नहीं जाता। यदि मजबूरीवश पी लिया, तो पेट में दर्द और दस्त होने लगते हैं। गांव वाले मिलकर पानी का टैंकर मंगवाते हैं, लेकिन स्कूल में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्कूल में खारा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है, इसलिए स्कूल जाने का दिल नहीं करता है।' यह कहना है 9वीं कक्षा की छात्रा 15वर्षीय किशोरी पूजा राजपूत का, जो राजस्थान के बीकानेर स्थित लूणकरणसर ब्लॉक के कालू गांव की रहने वाली है। ब्लॉक मुख्यालय से 20 किलोमीटर और जिला मुख्यालय बीकानेर से 92 किमी दूर आबाद कालू गांव की जनसंख्या लगभग 10,334 है। अनुसूचित जाति बहुल इस गांव के लोगों को पीने के साफ पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। पूरे गांव में समान रूप से सभी घरों में पीने का पानी भी नहीं आता है। गांव की बसावट कुछ इस प्रकार है कि कुछ घर ऊंचाई पर हैं, तो कुछ घर नीचे की तरफ ढलान पर आबाद हैं।

आरती

गांव की बसावट कुछ इस प्रकार है कि कुछ घर ऊंचाई पर हैं, तो कुछ नीचे की तरफ ढलान पर। इसलिए पूरे गांव में समान रूप से सभी घरों में पानी नहीं आता है।

जब मनुष्यों के लिए मुश्किल से पानी इकट्ठा होता है, तो समझा जा सकता है कि पशुओं के लिए पानी का प्रबंध करने में कितनी मुश्किलें होती होंगी।

45 वर्षीय जगदीप कहते हैं कि पहले गांव में बावड़ी समेत पानी के बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, लेकिन बेहतर रखरखाव नहीं होने के कारण या तो वे सभी सूख चुके हैं। एक बार टैंकर मंगवाने पर 1,500 रुपये का खर्च आता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम बार-बार पानी का टैंकर मंगवा सकें।

गांव की महिला कमला देवी का कहना है कि 'कभी-कभी तो एक दिन में पांच से छह बार पानी के लिए हमें तपते रेगिस्तान में मीलों चलना पड़ता है। यही कारण है कि हम कपड़े भी दो या तीन दिनों में एक बार धोते हैं।' वह कहती हैं कि जब मनुष्यों के लिए मुश्किल से पानी इकट्ठा होता है, तो पशुओं के लिए कहां से पानी का प्रबंध कर सकते हैं? इस संबंध में गांव की सरपंच सुगनी देवी का कहना है कि गांव में खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए तीन ट्यूबवेल लगवाए हैं, लेकिन आबादी को देखते हुए वे भी कम हैं। इसलिए पंचायत ने सर्वसम्मति से ब्लॉक अधिकारी के पास अभी एक और बोरवेल लगाने का प्रस्ताव भेजा है।

बहरहाल, जैसे-जैसे तापमान चढ़ेगा, पानी की समस्या भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है कि इंसान और पशुओं सभी के लिए पानी उपलब्ध हो जाए। *(चरखा फीचर)*

आंकड़े

आईबीआरडी से उधार

वर्ष 2023 में विश्व बैंक से संबद्ध आईबीआरडी से कई देशों ने उधार लिया है, जिनमें हमारा देश भारत शीर्ष पर रहा।

दूसरों के कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कार्य में छोटा योगदान भी अमूल्य होता है। साथ ही दूसरों के मजाक उड़ाने पर आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए।

छोटा सहयोग भी अमूल्य

अंतर्यात्रा
संकलित

माता सीता के हरण के बाद लंका तक पहुंचने के लिए भगवान राम की वानर सेना समुद्र के ऊपर पुल बनाने में जुट गई थी। वानर सेना पत्थर पर भगवान श्रीराम का नाम लिखकर समुद्र में पत्थर डालती थी। पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते थे, जिसे देखकर सभी वानर काफी खुश हो रहे थे। भगवान राम भी अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश हो रहे थे।

वहां एक गिलहरी भी थी, जो मुंह से कंकड़ उठाकर पानी में डाल रही थी। उसे ऐसा बार-बार करते हुए एक वानर ने देखा, तो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, 'हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी-सी हो, समुद्र से दूर रहो। कहीं ऐसा न हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ।' दूसरे वानर भी उसका मजाक उड़ाने लगे। बेचारी गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई।

परेशान गिलहरी श्रीराम के पास वानरों की शिकायत लेकर पहुंची। तब भगवान राम खड़े होकर वानरों से बोले, 'अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती, तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर-उधर बिखरे रहते। गिलहरी के द्वारा फेंके गए कंकड़ ही उन पत्थरों को आपस में जोड़े हुए हैं। गिलहरी का योगदान भी अमूल्य है।'

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 14 अप्रैल, 1955

छंटनी के विरोध में सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल

सरकारी सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल

छंटनी का तीव्र विरोध

रॉबर्ट्सगंज, १३ अप्रैल। चुर्क की सीमेंट फैक्टरी के सभी ८०० मजदूरों ने पूरी हड़ताल करदी है। ८२ मजदूरों की छंटनी हुई है, इसी के विरोध में हड़ताल हुई। कल रात तक समझौते की वार्ता चलती रही,

रॉबर्ट्सगंज की सीमेंट फैक्टरी में 82 मजदूरों की छंटनी के विरोध में सभी 800 मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। अभी तक समझौता वार्ता से कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि एक मजदूर नेता ने काफी अनुरोध पर अपना अनशन खत्म कर दिया है।

सिंगापुर से सीखें कचरे की रीसाइक्लिंग

रीसाइक्लिंग न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। अब कचरा प्रबंधन एक बड़ा व्यवसाय बन गया है।

विरंकार सिंह — संभावना

देश में कचरा या अपशिष्ट प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर भी इस समस्या से ग्रस्त हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में कई जगह कूड़े-कचरे के पहाड़ देखे जा सकते हैं। लेकिन यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। अब कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। सिंगापुर और इंदौर जैसे कुछ शहरों में सुनियोजित तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जाता है। दिल्ली सरकार चाहे तो सिंगापुर से कचरा प्रबंधन की सीख ले सकती है।

सिंगापुर जैसे देश में भी कचरा प्रबंधन की चुनौती थी। देश की बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने इस दिशा में मुश्किल खड़ी कर दी थी। वर्ष 2016 में एक दिन में रिकॉर्ड 8,559 टन कचरा इकट्ठा किया गया था। वहीं 2019 में 72 लाख टन से अधिक ठोस कचरा पैदा हुआ। इसमें से 29.5 लाख टन कचरे को रीसाइकल नहीं किया जा सका। यह कचरे की एक बड़ी मात्रा थी, जिसे सावधानीपूर्वक और कुशलता से प्रबंधित करने की जरूरत थी। पर अब सिंगापुर ने इस समस्या को हल करने का एक आसान तरीका खोज लिया है।

सिंगापुर में राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी (एनईए) सभी सामान्य और खतरनाक कचरे की देखरेख करती है। कचरा इकट्ठा करने के बाद उसे एक भस्मीकरण संयंत्र में एक हजार डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाया जाता है। जलने के बाद जो राख बचती है, उसे ऐसे पानी में बहाया जाता है, जो समुद्र में न मिलता हो। इसके अलावा रीसाइक्लिंग का भी विकल्प है, लेकिन सभी सामग्रियों को रीसाइकल नहीं किया जा सकता है, जैसे पॉलीस्टाइनिन। यही बात खाद बनाने पर भी लागू होती है, क्योंकि केवल जैविक सामग्री, जैसे भोजन और पेड़ के स्क्रैप से ही खाद बनाई जा सकती है। इसलिए भस्मीकरण को सबसे अच्छा उपाय माना जाता है।

कचरों को जलाने के क्रम में निकलने वाली जहरीली गैस को वैज्ञानिक तरीके से छान लिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता। कचरे के दहन से उत्पन्न गर्मी का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। यहां के लोग खुद ही कागज, प्लास्टिक और कांच के कचरे को रीसाइकल करते हैं।

भारत में 75 प्रतिशत पुनर्नवीकृत करने योग्य कचरे के केवल 30 प्रतिशत का ही पुनर्नवीनीकरण हो पाता है। इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसाय में विकास की काफी संभावना है। कई उद्यमी कचरे के प्रबंधन और इसे महत्वपूर्ण संसाधनों में बदलने के नए तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। बढ़ते घनत्व और तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण बड़ी मात्रा में जहरीले और गैर-खतरनाक कचरा उत्पन्न होते हैं। कचरे में कई तरह की वस्तुएं होती हैं। इनमें प्लास्टिक से बनी बोतलें, प्लास्टिक से बनी फिल्में, फोम और कठोर प्लास्टिक रेशे तथा अन्य चीजें शामिल हैं। कुछ नगर पालिकाएं और निगम सामान्य उपयोग के लिए लेबल वाले कंटेनरों को खुले में रखकर आवासीय और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए रीसाइक्लिंग डिब्बे उपलब्ध कराकर रीसाइक्लिंग को सरल बनाते हैं। पुनर्चक्रण के अनगिनत फायदे हैं और अधिक से अधिक चीजों को पुनः उपयोग लायक बनाकर हम अपने ग्रह को साफ करने में मदद कर सकते हैं।

रीसाइक्लिंग न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। भारत में सामग्री रिकवरी का बाजार प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और 2024 तक इसके 537.2 लाख डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रीसाइक्लिंग निर्माता उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। देश में इस समय कचरे की रीसाइक्लिंग प्रबंधन की दस कंपनियां हैं। इनकी प्रमुख सेवाओं में अपशिष्ट संग्रह, पुनर्चक्रण, निष्कासन और खतरनाक रसायनों का संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और विनाश, कंटेनर किराये पर लेना और सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। अपशिष्ट संग्रह, छंटाई, निपटान और पुनर्चक्रण को संभालने वाली फर्मों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण हैं कि कचरे का ठीक से निपटान किया जाए।

संग्रहीत कचरे को या तो रीसाइकल किया जाता है या खाद बनाई जाती है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करके पृथ्वी एवं पर्यावरण को बचाता है। कुछ व्यवसाय कचरे को रीसाइकल कर उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं में बदल देते हैं। कुशल अपशिष्ट निपटान पर्यावरण को स्वच्छ रखेगा।

https://t.me/AINewsPaperPdf

कल्पमेधा

जो व्यक्ति सत्य के साथ कर्तव्यपरायणता में समर्पण भाव से लीन है, उसके मार्ग में बाधक होना कोई सरल कार्य नहीं है।

– रवींद्रनाथ ठाकुर

शंका समाधान

एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर नाहक सवाल उठाना उचित नहीं है। इससे शक ही पैदा होता है। अदालत ने ईवीएम संबंधी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल, ईवीएम को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी कि उसे बाहर से नियंत्रित किया और मतों में गड़बड़ी की जा सकती है। अदालत के सामने इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी। इसके पक्ष में कई ऐसे प्रमाण भी दिए गए थे कि कहां-कहां कुल पड़े मतों और मशीनों में पड़े मतों की संख्या में अंतर पाया गया। विपक्षी दल इसे लेकर काफी आक्रामक थे और लगातार आशंका जाहिर कर रहे थे कि सत्तापक्ष मशीनों के जरिए मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसमें कई स्वयंसेवी संगठन और विशेषज्ञ भी शामिल थे, जिनका दावा था कि ईवीएम को बाहर से संचालित किया जा सकता है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग लगातार तर्क दे रहा था कि ईवीएम सौ फीसद सुरक्षित हैं और उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया था कि आम मतदाता के भीतर भी यह भ्रम पैदा हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी करके कोई पार्टी अपने पक्ष में मतों की संख्या बढ़ा सकती है।

ईवीएम पर संदेह जाहिर करते हुए अदालत में गुहार लगाने वालों की मांग थी कि मतदान के बाद जो पर्ची कट कर बक्से में गिरती है उसे मतदाता के हाथ में दिया जाए और वह उसे खुद अलग बक्से में डाले। फिर मशीन के साथ ही उन पर्चियों का मिलान कर अंतिम रूप से मतों की गणना की जाए। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस मांग को खारिज कर दिया। दरअसल, इस तरह मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन होने का खतरा था। मगर इसमें अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह मशीनों में चुनाव चिह्न निर्धारित हो जाने के बाद उन्हें सीलबंद कर दे। उसने एक और रास्ता खोल दिया है कि अगर कोई प्रत्याशी किन्हीं मशीनों के बारे में शिकायत दर्ज कराता है, तो विशेषज्ञों से उनकी जांच कराई जाए। उस जांच का सारा खर्च संबंधित प्रत्याशी को उठाना पड़ेगा। इसे बहुत से लोग बड़ी राहत की बात मान रहे हैं। इस तरह गड़बड़ियों की जांच हो सकेगी। पर अब यह तो तय है कि ईवीएम को लेकर जिस तरह के भ्रम बने हुए थे, वे याचिकाकर्ताओं के मन से काफी हद तक दूर हो चुके होंगे।

हालांकि यह पहला मौका नहीं था, जब ईवीएम पर संदेह जताते हुए अदालत में गुहार लगाई गई थी। इसके पहले भी कई मौकों पर इसे चुनौती दी गई थी। पिछले आम चुनाव के वक्त भी इस मसले को काफी तूल दिया गया था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने बार-बार मशीन की निर्दोषिता सिद्ध करने की कोशिश की थी, पर उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस पर संदेह की कोई गुंजाईश नहीं रह गई है। राजनीतिक दलों को मशीन पर शक करने के बजाय मतदाताओं अधिक भरोसा करने की जरूरत है। मशीन पर शक करने से नाहक मतदाताओं के भीतर भ्रम पैदा हुआ है। हालांकि निर्वाचन आयोग को भी इसे हार-जीत की तरह नहीं लेना चाहिए, उसे ईवीएम को विश्वसनीय बनाए रखने के जो भी उपाय हो सकते हैं, उन्हें अपनाने में उसे गुरेज नहीं होना चाहिए।

नाहक दखल

भारतीय समाज में इतनी विविधता और कई मायनों में जटिलता है कि उसमें अक्सर टकराव जैसे हालात बन जाते हैं। मगर सरकार बिगड़े हालात को संभालने, शांति कायम करने का हर प्रयास करती है। कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं स्थितियां इतनी खराब हो जाएं कि उन्हें ठीक करने में वक्त लगे। भारत सरकार अपनी जवाबदेही को समझती है। अपने संप्रभु क्षेत्र में अराजकता पर काबू पाने और लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। मगर कुछ खास मामलों को आधार बना कर अगर किसी अन्य देश का कोई समूह मानवाधिकार हनन के लिए भारत को कठघरे में खड़ा करता है, तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश विभाग की एक रपट में दावा किया गया है कि भारत में मणिपुर सहित अन्य इलाकों में मानवाधिकार हनन के मामले बढ़े हैं।

कुछ गिने-चुने मामलों को आधार बना कर किसी देश की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वह भी तब, जब भारत सरकार हिंसा से प्रभावित तबकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाती है। इस तरह नाहक दखलअंदाजी की वजह से अगर भारत की छवि पर असर पड़ता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? यह बेवजह नहीं है कि गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी रपट को 'बेहद पक्षपातपूर्ण' करार दिया और कहा कि इसके जरिए देश की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है और यह भारत के प्रति खराब समझ को दर्शाता है। विचित्र है कि दुनिया भर में इस तरह की आवाजें उठती रही हैं कि अमेरिकी नीतियों की वजह से कई देशों में मानवाधिकारों को काफी नुकसान पहुंचा है। मगर आए दिन किसी अमेरिकी समूह की ओर से मानवाधिकारों का सवाल उठा कर विकासशील देशों को कठघरे में खड़ा किया जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, कुछ जटिल स्थितियां पैदा होती हैं, तो उन पर काबू पाने और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार बातचीत सहित अन्य जरूरी तौर-तरीके अपना कर समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। भारत अपनी मुश्किलों को दूर करने में सक्षम है और यहां लोकतंत्र की जड़ें इसीलिए गहरी हैं।

विकसित देश बनने की चुनौतियां

भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बन गई है। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं।

जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें भारत के 2047 तक विकसित देश बनने के संकल्प पर लगी हुई हैं। दरअसल, आने वाले तेईस वर्षों में भारत को विकसित देश बनाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इस समय दुनिया में चालीस ही देश विकसित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से औद्योगिक रूप से विकसित यूरोपीय देश हैं। भारत अभी विकासशील देश है। इसे विकसित देश बनाने के लिए लगातार आठ से नौ फीसद वार्षिक विकास दर प्राप्त करना जरूरी है। देश की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय, जो करीब 2600 डालर है, उसे करीब 12 हजार डालर तक पहुंचाने, मजबूत आर्थिक सुधारों, कृषि एवं श्रम सुधारों, अधिक पूंजीगत व्यय, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, राजकोषीय आदर्श, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के मूल्य, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अधिक गुणवत्तापूर्ण विकास तथा गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की राह पर रणनीतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ना प्रमुख चुनौतियां है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाओं के कई आधार हैं। भारत दुनिया में वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास की डगर पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्तवर्ष 2024-2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर सात फीसद कर दिया। उसने पहले 6.7 फीसद वृद्धि का अनुमान लगाया था। उसने कहा कि सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर परिदृश्य और सेवा क्षेत्र की मजबूत स्थिति को देखते हुए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत निवेश और निजी कंपनियों के निवेश बढ़ने, सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन तथा उपभोक्ता के आत्मविश्वास में सुधार की बदौलत वित्तवर्ष 2024-25 में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

वस्तुओं के निर्यात में सुधार और विनिर्माण तथा कृषि उत्पादन बढ़ने से वित्तवर्ष 2025-26 में भी वृद्धि दर बढ़ेगी। एडीबी का संशोधित अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा चालू वित्तवर्ष के लिए लगाए गए सात फीसद वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है। आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति ने कहा है कि इस वर्ष 2024 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के अच्छा रहने की उम्मीद है, जिससे कृषि गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके साथ ही शहरों में मांग बनी रहने और ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ने से निजी खपत में भी तेजी आएगी। तमाम बाजार संकेतक सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। इससे विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। दुनिया की प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजंसियों ने कहा है कि विनिर्माण, निवेश और निर्यात के मद्देनजर भारत में स्थितियां उपयुक्त हैं। भारत में कई अहम आर्थिक सुधार हुए और उनका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआइ प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है। भारत ने एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में आधार तैयार किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बन गई है। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत दी जा रही है। भारत वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के कारण भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) बढ़ रहे हैं। प्रवासी भारतीय लगातार अधिक विदेशी धन भेज रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमता, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा तथा नए तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास को गति मिल रही है। चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरकर सामने आया है।

> हालांकि पिछले दस वर्षों में बहुआयामी गरीबी में बड़ी कमी आई है, लेकिन अब बकाया पंद्रह करोड़ से अधिक गरीबों को नई मुस्कुराहट देने का जोरदार अभियान आगे बढ़ाना होगा। कृषि, श्रमिक, भूमि और अन्य सुधारों की जरूरत बनी हुई है। जीडीपी के अनुपात में हमारा शोध एवं विकास क्षेत्र पर कुल व्यय केवल 0.64 फीसद है। यह 2.71 फीसद के वैश्विक स्तर से बेहद कम है। देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कराने के साथ ही शांति कायम रखने और सुरक्षा चाक-चौबंद रखने के जरूरी ऊंचे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा।

भारत द्वारा 2023 में आयोजित की गई जी-20 की सफल अध्यक्षता से नए आर्थिक लाभों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस समय भारत जीडीपी के मद्देनजर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान हैं। जापान की अर्थव्यवस्था से इसी साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था आगे निकल सकती है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजंसी क्रिसिल ने अपनी नई रपट में कहा कि भारत आर्थिक वित्तीय तथा संरचनात्मक सुधारों के कारण वर्ष 2031 तक निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। इन आधारों की बुनियाद के साथ भारत 2047 तक विकसित देश की संभावनाएं रखता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मकसद से देश के प्रमुख सरकारी विभागों ने अभी से अगले पांच साल के लिए विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इनमें खासतौर से कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिलाओं का उत्थान, गरीबी में कमी लाने, संतुलित क्षेत्रीय विकास, प्रभावी न्याय व्यवस्था, दुनिया में भारत की नई भूमिका जैसे विकसित राष्ट्र बनने के प्रमुख विषय शामिल हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों के विकास की लंबी अवधि की रणनीति से भारत द्वारा वर्ष 2047 तक तीस लाख करोड़ डालर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संभावनाओं के बीच यह भी ध्यान देना होगा कि विकसित देश बनने की विभिन्न चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त की जाए। अब लगातार देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ प्रतिव्यक्ति आय और आम आदमी की खुशहाली पर ध्यान देना होगा।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई मानव विकास सूचकांक (एचडीआइ) रपट में भारत 193 में से 134वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रपट 2024 में 143 देशों में भारत को 126वां स्थान दिया गया है। हालांकि पिछले दस वर्षों में बहुआयामी गरीबों में बड़ी कमी आई है, लेकिन अब बकाया पंद्रह करोड़ से अधिक गरीबों को नई मुस्कुराहट देने का जोरदार अभियान आगे बढ़ाना होगा। कृषि, श्रमिक, भूमि और अन्य सुधारों की जरूरत बनी हुई है। जीडीपी के अनुपात में हमारा शोध एवं विकास क्षेत्र पर कुल व्यय केवल 0.64 फीसद है। यह 2.71 फीसद के वैश्विक स्तर से बेहद कम है। देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कराने के साथ ही शांति कायम रखने और सुरक्षा चाक-चौबंद रखने के जरूरी ऊंचे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। देश में उन्नीस करोड़ से अधिक महिलाओं को सवैतनिक श्रमशक्ति में शामिल करने की रणनीति को अमलीजामा पहनाना होगा। हमारे शक्तिशाली सेवा क्षेत्र के जरिए विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के समक्ष दिखाई दे रही चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होगा।

अपना कोना

मेघा राठी

संसार गतिमान है और उससे भी अधिक गतिमान है मानव का मन, जो विविध क्रियाकलापों में, अलग-अलग संदर्भों में उपजे विचारों में संलग्न रहता है। एक पल में एक स्थान पर है और दूसरे ही पल सुदूर यात्रा कर आता है। इस यात्रा के दौरान वह न जाने कितने ही ताने-बाने बुन लेता है। जबकि किसी छोटी-सी बात पर तो कई बार बड़ी-बड़ी बातों से प्रभावहीन रहता है। सूर्य की पहली किरण निकलने से लेकर रात्रि में नींद में डूब जाने से पहले तक मन न जाने कितनी ही घटनाओं और वास्तविक वार्ताओं में सम्मिलित होता है और उनका प्रभाव या कुप्रभाव भी झेलता है। कई बार इन दोनों ही परिणामों का सामना तो लोग करते हैं, मगर इनके कारणों या स्रोत पर गौर करना या तो जरूरी नहीं समझते या फिर कारण खोज नहीं पाते। नतीजतन, हर अगली बार वैसी ही परिस्थितियां होने पर परिणाम भी लगभग वही होता है।

मन मनुष्य की जीवनशैली और व्यवहार को निर्धारित करता है। मन अच्छा और शांत होगा तो निर्णय लेने की क्षमता भी दृढ़ होगी। उचित और अनुचित का विचार कर, उसमें फर्क कर पाना और उसके मुताबिक निर्णय लेना आसान हो सकेगा। मन की मजबूती और निर्मलता व्यक्ति के प्रभामंडल पर भी अपना असर डालती है, जिसके कारण किसी व्यक्ति के 'औरा' यानी आभामंडल के संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके प्रति आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कर पाते हैं। ऐसे उदाहरण अक्सर देखने को मिल जा सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति, दृढ़ विचार के साथ भरोसे से भरा होता है और उसकी बातें अन्य लोगों पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

सवाल है कि मन को स्वस्थ और सकारात्मक कैसे रखा जाए? अच्छा अध्ययन और चिंतन मन को सबल बनाता है और इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य के पास एक स्थान, एक कोना उसका अपना हो, ताकि उस स्थान पर वह शांत मन से बैठ सके, बिना किसी अन्य बातों की फिक्र किए... अपने विचार में किसी भी अन्य के दखल से अलग। ऐसी जगह, जहां व्यक्ति की अपनी जरूरत के मुताबिक तय वक्त में अनावश्यक ही कोई उसके एकांत में प्रवेश न कर सके। जरूरी नहीं कि इस तरह का कोना किसी विशेष स्थान पर हो। यह कोना कहीं भी हो सकता है, घर में, किसी तालाब किनारे, किसी बाग में। जहां भी हृदय सारी आशंकाओं या बाधाओं से मुक्त होकर अपने आप से बात कर सके। ऐसी ही जगह मन को सबल बनाने के लिए उचित है। अपने उस कोने में व्यक्ति आत्मचिंतन करे, किताबें पढ़े या फिर खुद से बातें करे। अपने दिमाग में आए प्रश्नों या समस्याओं पर विचार करे, कोई समाधान निकाले। या फिर अपने अच्छे बुरे पलों को याद करे, उससे मिले सबक के आधार पर जीवन में आगे के सफर की दिशा तय करे। हालांकि कुछ भी करना व्यक्ति की मनःस्थिति और इच्छा पर निर्भर है, मगर उस कोने में व्यक्ति खुद के साथ थोड़ा ऐसा समय व्यतीत कर पाता है, जो उसे परिपक्व बनाने में सहायता करता है, बशर्ते उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो। ऐसी स्थिति में वह अपने लिए ही एक अच्छा सलाहकार बन कर अपनी या अपने मन की मदद कर सकता है।

जब व्यक्ति का स्वयं का एक कोना होता है, तब वह उस एकांत में खुद को पूर्ण रूप से प्रकट या अभिव्यक्त कर पाता है। किसी मौके पर दबाई गई भावनाओं के बरक्स अकेले में वह खुलकर रो या चिल्ला सकता है, ताकि मन का गुबार निकल जाए और हल्का होकर नई राह की तलाश की जा सके। यह छिपा नहीं है कि अपने परिजनों या मित्रों के सामने किसी भी कारणवश व्यक्ति कई बार अपनी भावनाएं उजागर नहीं कर पाता, लेकिन यह मनोविज्ञान का तंत्र है कि वे भावनाएं मन में फांस बनकर चुभती हैं, जिसका असर संबंधों और व्यवहार पर भी पड़ता है। जबकि अपने कोने में व्यक्ति आत्मविश्लेषण कर पाता है, क्योंकि यहां उसे कोई भय नहीं होता कि इस रूप में देखकर कोई उसके विषय में क्या सोचेगा! ऐसे कोने में अगर किसी बात पर उसकी आंखें भर जाएं तो उसे अपने आंसू किसी से छिपाने की आवश्यकता नहीं होती।

शुरुआत में दुख, क्रोध, विद्वेष के भाव बादलों की तरह उमड़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वे पूर्ण रूप से बरस चुके होते हैं और मन हल्का अनुभव करने लगता है, तब बुद्धि जाग्रत होती है और मन को आलंबन देती है। विवेक शक्ति देता है निर्णय लेने और उचित-अनुचित के अंतर को समझने की।

व्यक्ति का अपना कोना उसका सृजन स्थल होता है जो उसका सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। व्यक्तित्व विकास और मानसिक विकास के साथ-साथ व्यक्ति का सामाजिक विकास करने में भी उसका अपना कोना सहायता करता है। अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने, अपनी रुचियां परिष्कृत करने और मनन के लिए अपने एक कोने की जरूरत बहुत सारे लोगों को महसूस होती है, जहां संसार से कुछ देर के लिए दूर होकर आत्मिक उन्नति का आधार ढूंढ़ा और अपने मन को शांत, उसकी थकावट दूर की जा सके। अगर किसी के पास वह कोना है, तो बेहतर। अगर नहीं है तो इसे खोजने की जरूरत है और अपने क्लांत मन को सुकून से भरने का प्रयास हर रोज करना चाहिए। व्यक्ति का कोना मात्र एक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र है जो उसे ऊर्जावान रख कर जीवन की विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने का साहस देता है।

दुनिया मेरे आगे

> अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने, अपनी रुचियां परिष्कृत करने और मनन के लिए अपने एक कोने की जरूरत बहुत सारे लोगों को महसूस होती है, जहां संसार से कुछ देर के लिए दूर होकर आत्मिक उन्नति का आधार ढूंढ़ा और अपने मन को शांत, उसकी थकावट दूर की जा सके।

समानता के बजाय

सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना है जो न्यायसंगत हो, विविधता को महत्त्व देता हो, अपने सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करता हो और संसाधनों का उचित बंटवारा और समर्थन सुनिश्चित करता हो। शिक्षा, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक संबद्धता, विश्वास या अन्य विशेषताओं सहित कई विविध कारकों में अगर ईमानदारी न बरती जाए, तो ये भेदभावपूर्ण व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। खासकर उन लोगों द्वारा जिनके हाथों में कुछ हद तक शक्ति हो सकती है। वर्तमान समय हमारे समाज की जो स्थिति है उसमें लोगों के साथ बर्ताव कई बार उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए किया जाता है। सभ्य कहा जाने वाला मानव समाज आदमी की स्थिति को देखते हुए उनसे संवाद और व्यवहार के तौर-तरीके तय करता है। अगर कोई व्यक्ति योग्यता में आगे है लेकिन वह धनाढ्य नहीं है तो उसे बेवकूफ समझकर उसका समाज में तिरस्कार ही किया जाता है। यह सरासर गलत है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धनाढ्य और रुतबे को देखकर नहीं, उसकी योग्यता को प्राथमिकता देकर उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

– योगेंद्र गौतम, उन्नाव

स्वाद और रुचि

'अस्वाद का आस्वाद' (21 अप्रैल) पढ़ा। हम खाने और सोचने का कार्य करने में बाहरी प्रभावों की वजह से एक आदत बना बैठे हैं। बचपन से हम जो खा रहे हैं, वह जीभ ने सत्य मान लिया। जीभ उसी स्वाद की मांग बार-बार करती है। मसलन, केरल के लोगों का नारियल, डोसा का स्वाद, बंगाल के लोगों का चावल का स्वाद, मराठी लोगों का बड़ा पाव का स्वाद, उत्तर प्रदेश के लोगों का छोले-पूड़ी, बिहार का बाटी-चोखा आदि। ये सब हमने अपनी रुचि के साथ विकसित किया है और अब कई बार यह हमें आदत-सी बन गई लगती है। अब एक नई बात अस्वाद की करनी होगी। इसी से भोजन, मन और समाज ठीक रहेगा। अस्वाद दरअसल, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति से मुक्ति है। इससे न केवल खानपान संबंधी रूढ़िबद्धता से मुक्ति मिलती, बल्कि जीवन में किसी भी चीज के प्रति असक्ति से विरक्ति का भाव पैदा होता है।

– वेदसिंह यादव, लखनऊ

बाजार बनाम प्रकृति

हाल ही में पूरे विश्व में 22 अप्रैल को 'पृथ्वी दिवस' मनाया गया, लेकिन इससे आगे हम इस पृथ्वी को बचाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? जब से वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है, पूरा विश्व बाजार में बदल गया। सबको विकास की मनगढ़ंत धारणा से प्रेरित करके उसकी आड़ में प्रकृति से छेड़छाड़ की गई। बाजारवाद ने देशों और उनकी कंपनियों के बीच स्पर्धा को जन्म दिया, जिससे प्रकृति को बिना ध्यान में रखे मनुष्यों ने इस तरह प्रकृति का दोहन किया कि उसका खमियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। प्लास्टिक के प्रयोग को रोका नहीं जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में मनुष्य के हस्तक्षेपों के चलते आए दिन आपदाओं का कहर बरप रहा है। जलवायु परिवर्तन से पहाड़ी इलाकों के निवासियों में पीने का पानी तक प्राप्त करना दुर्लभ होता जा रहा है। यह आपदा दरअसल हम मनुष्यों की ही देन है। अगर प्रकृति ने अपना प्रभाव दिखाना और तेज किया तो सब आविष्कार धरा का धरा रह जाएगा।

– करुणा नयन चतुर्वेदी, दिल्ली विवि

युद्ध का हासिल

ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी, तभी से विश्व के विकसित देश दो खेमों में बंट कर युद्ध को रुकवाने के बजाय भड़काने में लग गए। उनकी नीयत से यह स्पष्ट हो रहा है कि वे विश्व को तीसरे विश्वयुद्ध की विभीषिका में धकेलना चाहते हैं। अगर विश्वयुद्ध होता है तो विकासशील देशों की बर्बादी का सबब बन जाएगा। विश्व की महाशक्तियां चाहती हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, व्यापार चलता रहे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विश्व कल्याण की बात करने वाले देश घर वापसी के बाद अपने स्वर बदल लेते हैं। अगर अत्याधुनिक हथियारों के इस दौर में विश्व युद्ध होता है, तो यह दुनिया के हर प्राणी के लिए महाविनाशक साबित होगा और इससे हासिल कुछ नहीं होगा। अंत में रास्ता आपसी समझ तथा बातचीत से ही निकलेगा। फिर क्यों न कट्टरपन को त्याग कर युद्ध को टालने के प्रयास किए जाएं?

– हुकुम सिंह पंवार, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

www.readwhere.com

चिंतन

ईवीएम की विश्वसनीयता पर बेवजह सवाल सही नहीं

देश में जारी आम चुनाव के दौरान वीवीपैट से जुड़ीं सभी याचिकाएं खारिज कर सौ फीसदी वीवीपैट से मिलान की मांग का फिलहाल पटाक्षेप हो गया है। ईवीएम को लेकर जारी बहस पर भी विराम लग गया है। देश में ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, मतपत्र की ओर लौटने की किसी भी संभावना का अंत हो गया है। चुनाव की मौजूदा व्यवस्था चलती रहेगी। अभी ईवीएम से चुनाव होते हैं और चुनिंदा सेंटरों पर वीवीपैट से मिलान की व्यवस्था है। ईवीएम से चुनाव में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी की आशंकाओं को निर्वाचन आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से डाले गए वोट का 'वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (वीवीपैट) के साथ मिलान कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए अहम बात कही कि तंत्र के किसी भी पहलू पर ''आंख मूंद कर अविश्वास करना'' बिना वजह संदेह पैदा कर सकता है। पीठ ने मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया पुनः अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी खारिज कर दिया है। दरअसल, लोकतंत्र का अर्थ सद्भाव और सभी संस्थाओं में भरोसा बनाए रखने का प्रयास करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी दिया है कि उम्मीदवार की शिकायत पर ईवीएम की जांच हो सकती है। ईवीएम के 42 वर्ष के इतिहास में ऐसा प्रावधान पहली बार किया गया है। अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले को किसी प्रकार का शक है तो वे 7 दिनों के भीतर शिकायत कर सकते हैं। इस जांच का खर्च प्रत्याशी को उठाना होगा। जांच के बाद अगर ये साबित होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले उम्मीदवार को जांच का पूरा खर्च लौटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी तीन निर्देश दिए हैं। चुनाव चिन्ह लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इस यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण किया जाय। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग यह भी देखे कि चुनाव चिन्ह के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है क्या? दिलचस्प है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को अदालत ने अब तक 40 बार खारिज की है। 24 अप्रैल को 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में शामिल न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने एक महत्वपूर्ण बात भी की है कि केवल अटकल के आधार पर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दे सकते। यह उन याचिकाकर्ताओं को आईना दिखाना है, जो बार-बार इस मुद्दे को अदालत लेकर गए हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, याचिकाकर्ता न तो कभी यह दिखा पाए कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के सिद्धांत का कैसे उल्लंघन करता है और न ही डाले गए सभी वोट से वीवीपैट पर्चियों के शत प्रतिशत मिलान के अधिकार को साबित कर सके। चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करीब 11 वर्ष पहले शुरू किया गया था। समय के साथ ईवीएम खरी उतरी हैं और मतदान प्रतिशत में वृद्धि इस बात को मानने का पर्याप्त कारण है कि मतदाताओं ने मौजूदा प्रणाली में विश्वास व्यक्त किया है। देश को पिछले 70 वर्ष से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर गर्व रहा है, जिसका श्रेय काफी हद तक निर्वाचन आयोग और जनता द्वारा उस पर जताए गए विश्वास को दिया जा सकता है।

चुनाव
अखिलेश आर्येंदु

राजनीतिक मूल्यों को न भूलें दल

> लोकतंत्र के इस उत्सव में जब चुनाव की गहमागहमी का मकसद येन केन प्रकारेण महज सत्ता हासिल करने तक ही सीमित हो गया हो तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। मूल्य पतन और विचारहीनता सत्ता पाने की ललक भले ही पूरी करती हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए यह सुखद स्थिति नहीं है। लोकतंत्र का शासन सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय के लिए जाना जाता है। लोकतंत्र की गहराई को लेकर यकीन भी होता है कि जिस लोकतंत्र के पहरुए डॉ. लोहिया, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, वहां राजनीतिक मूल्यहीनता और भ्रष्टाचार का बढ़ना और भी चिंताजनक है।

बदलते जमाने ने हमें यह सिखा दिया है कि हवाओं के साथ बहना ही अच्छा है। कविता की ये पंक्तियां आज के राजनीतिक माहौल को बयां करने के लिए काफी हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव में जब चुनाव की गहमागहमी का मकसद येन केन प्रकारेण महज सत्ता हासिल करने तक ही सीमित हो गया हो तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। जाहिर तौर पर लोकतंत्र का शासन सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय के लिए जाना जाता है। लोकतंत्र की गहराई को लेकर यकीन भी होता है कि जिस लोकतंत्र के पहरुए डॉ. लोहिया, नेहरू, आचार्य नरेंद्रदेव, लाल बहादुर शास्त्री, जेपी. कामराज, कर्पूरी ठाकुर व चौधरी चरण सिंह रहे हों, वहां राजनीतिक मूल्यहीनता और भ्रष्टाचार का बढ़ना और भी चिंताजनक है।

इस चुनाव को देखकर स्वामी विवेकानंद का वह वाक्य भी याद आता है कि राजनीति एक खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग दिनभर चर्चा करते हैं। चुनाव में चर्चाओं का दौर दिनभर चलता है। ये चर्चाएं हिंसक, अहिंसक, व्यर्थ और काम की भी हुआ करती हैं। कहते हैं लोकतंत्र में चर्चाएं चुनाव के वक्त हवा बनाने या हवा का रुख बदलने का कार्य किया करती हैं, लेकिन ये चर्चाएं वाद-विवाद झगड़े और हिंसा की वजह बन जाएं तो यह सेहतमंद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जाहिर तौर पर आम चुनाव लोकतंत्र का जिंदा रहने का सबूत और यकीन भी है, लेकिन आम चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक मूल्यों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रति आशंका भी पैदा कर रहा है। इसके लिए महज राजनेता ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि देश का सारा तंत्र कमोवेश जिम्मेदार है। दो चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण में पिछले आम चुनाव से कम मत पड़े हैं। इसकी तमाम वजह बताई जा रही हैं, लेकिन उन तमाम वजहों में एक बड़ी वजह मतदाताओं का चुनाव के प्रति उदासीन होना बताया जा रहा है। चुनाव आयोग की तमाम कवायदों के बावजूद यदि मत प्रतिशत कम है तो इसकी वजह तो यह भी हो सकती है कि लोगों के सामने कोई पार्टी या नेता के रूप में कोई ऐसा विकल्प नहीं दिख रहा है जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता हो। गौरतलब है आजादी के सात दशक बाद भी करोड़ों लोगों के सामने यदि समस्याओं का अम्बार लगा मिले और आम आदमी खुद को उन समस्याओं को कम या हल करने में अक्षम पा रहा हो तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता ही है। इसके लिए भले ही किसी एक पार्टी को जिम्मेदार न मानें, लेकिन सबसे लम्बे समय तक देश पर शासन करने वाली पार्टी की नाकामी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बार के आम चुनाव में भी एक बार फिर राजनीतिक दलों में सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक मूल्यों की परवाह न करते हुए वे सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो राजनीतिक मूल्यों और लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह जायज नहीं ठहराए जा सकते हैं। विडम्बना ही कही जाएगी कि सत्ता पाने के लिए वे दल भी इस चुनावी समर में दंडबैठक कर रहे हैं जिनका न जनाधार है और न ही

कोई बेहतर दूरदर्शी राजनीतिक सोच ही है। जाहिर तौर पर राजनीतिक गठजोड़ व दबाव की राजनीति के बूते सत्ता हथियाने की सारी तरकीबें इस चुनाव में देखी जा सकती है। यह देखते हुए अच्छे, निष्ठावान, मूल्यों को संरक्षित करने वाले ईमानदार व सक्षम जननायक लोकतंत्र के इस समर में कूदने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास के लिए स्वदेशी का आधार, सतत आर्थिक व सामाजिक विकास, पशुधन व पर्यावरण सुरक्षा, सुशासन, स्वावलम्बन, हिंसा व भ्रष्टाचार मुक्त समाज, हर हाथ को काम व उसका उचित दाम और मूलभूत आवश्यकताएं मसलन सड़क, बेहतर यातायात के साधन, कृषि और कृषकों की खुशहाली, सब को बिजली, सबके लिए समान अधिकार व कानून, राजनीतिक व सामाजिक आचार संहिता का पालन, भारतीय शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में ही सुनिश्चित करने की गारंटी, सबको पीने योग्य पानी, प्राकृतिक व मानव संसाधन का जरूरत के मुताबिक वितरण, सबको फ्री चिकित्सा, गरीब व मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए ठोस नीतियां, आधुनिक सूचना तंत्र को और बेहतर बनाने की योजनाएं, बढ़ती गैर बराबरी को खत्म करने के लिए ठोस आर्थिक नीति, महिलाओं की सुरक्षा व खुशहाली, युवा वर्ग की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल जैसे जनहितकारी और राष्ट्रीय मुद्दों की जगह लोक लुभावने वादे, नारे और भाषणों की भरमार किस लोकतंत्र के हिस्से कहे जाएंगे! राजनीति के केंद्र में जो वादे या घोषणाएं होनी चाहिए उनकी जगह तुष्टिकरण, लोक लुभावने वादे, राजनीति कर सत्ता पर काबिज होने का चलन का लगातार बढ़ते जाना सुखद लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, यह सच्चाई यदि किसी दल को याद नहीं है तो इससे न तो संविधान की रक्षा हो सकती है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों और शक्तियों को सुरक्षित करना ही सुनिश्चित हो सकता है। भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि दूसरे मुल्क भी भारत के मूल्याधारित लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र कह कर इसकी सराहना करते। आज भारत के इस लोकतंत्र के उत्सव पर विश्व मीडिया की बारीक नजर लगी हुई है। वे इस उत्सव के अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षक बने हुए हैं, इसलिए आम चुनाव महज भारतीय लोकतंत्र के लिए ही महत्वपूर्ण नही है बल्कि दुनिया में तेजी से भारत की बढ़ती साख के नजरिये से भी महत्वपूर्ण है। जिस लोकतंत्र के स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखे थे उन स्वप्नों को पंख देने की दृढ़ इच्छा शक्ति किसी दल में दिखाई नहीं दे रही है। शायद इसलिए मतदाता इस बार खामोश है। उसकी उदासीनता यह बताती है कि कोई भी सत्ता में आए उसकी रोजमर्रा की समस्याएं जस की तस रहने वाली हैं।

भारत के कई राज्यों में लम्बे समय से अराजकता का माहौल देखने को मिलता रहा है। बाहुबलियों और माफियाओं ने अपना दबदबा शासन तक बना रखा था। लोकतंत्र का क्षरण और लोकतंत्र को बंधक बनाने वाली प्रथम चरण में देश के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें लोकतंत्र के इस उत्सव को क्या दागदार नहीं बनाती! राष्ट्रीय हितों की कीमत पर मूल्य पतन और विचारहीनता सत्ता पाने की ललक भले ही पूरी करती हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए यह सुखद स्थिति नहीं है। आम आदमी को चाहिए कि वह जात पात, क्षेत्रवाद और निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर केवल ऐसी पार्टियों और नेताओं का बहिष्कार ही न करे वरन, अपने बहुमूल्य मत का इस्तेमाल करते हुए देशहित में निर्णय लें। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, सबका साथ लेते हुए सबका विकास और आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए जो पार्टी कटिबद्ध दिखे उसे ही अपना बहुमूल्य मत दें। नोटा की बटन भी इसमें से कोई नहीं के तौर पर विकल्प के रूप में मौजूद है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

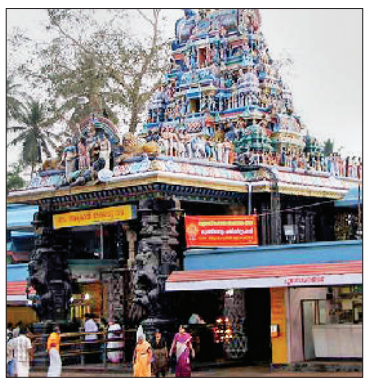

अट्टुकल भगवती मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित बहुत ही आकर्षक मंदिर है। अट्टुकल भगवती मंदिर माँ देवी भगवती को समर्पित एक धार्मिक मंदिर है। इसे महिलाओं की सबरीमाला के रूप में जाना जाता है और अपने वार्षिक अट्टुकल पोंगल उत्सव के लिए बड़ी संख्या में महिला भक्तों को आकर्षित करती है।

व्यक्ति को कैसे मिल सकती है दुखों से मुक्ति

संकलित
दर्शन

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण विश्व दर्शन के नए क्षितिज स्पर्श कर रहा था। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से, ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में पाइथागोरस नए तर्क गढ़ रहे थे तो भारत में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध वैदिक दर्शन को नया आयाम देने में लगे थे। गौतम बुद्ध ने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन दुखमय है। मृत्यु भी दुख का अंत नहीं है, बल्कि नए दुख का आरंभ है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म होता है। उनका मानना था कि प्राणी की इच्छा अपूर्ण रहती है तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध अनात्मवादी और अनीश्वरवादी तो थे, किंतु भौतिकवादी नहीं थे। उनका मत है कि सृष्टि में जो कुछ है वह क्षणिक है, परिवर्तनशील है। द्वितीय आर्य सत्य है कि प्रत्येक कार्य का कारण अवश्य होता है, जिसे बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद कहा। इस दुख के कारणता सिद्धांत को द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। इस दुख का मूलभूत कारण अविद्या है। अविद्या से संस्कार या पूर्व में किए गए कर्मों की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, नामरूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति या जन्म से जरा-मरण का दुख भोगना पड़ता है। बौद्ध दर्शन का तृतीय आर्यसत्य दुख-निरोध है। दुखों के मूल कारण अविद्या को दूर करके इसी जीवन में दुखों का अंत किया जा सकता है। दुखों का निरोध ही निर्वाण है।

https://t.me/AllNewsPaid

क्या भगवान का अस्तित्व है?

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने गया। तभी नाई ने कहाः मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता और इसीलिए तुम मुझे नास्तिक भी कह सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो व्यक्ति ने पूछा। नाई ने कहाः बाहर जब तुम सड़क पर जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अगर भगवान होते, तो क्या इतने सारे लोग भूखे मरते? क्या इतने सारे लोग बीमार होते? व्यक्ति ने थोड़ा सोचा लेकिन वह वाद-विवाद नहीं करना चाहता था। नाई ने अपना काम खत्म किया और वह व्यक्ति नाई को पैसे देकर दुकान से बाहर आ गया। वह जैसे ही नाई की दुकान से निकला, उसने सड़क पर एक लम्बे-घने बालों वाले एक व्यक्ति को देखा जिसकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी और ऐसा लगता था शायद उसने कई महीनों तक अपने बाल नहीं कटवाए थे। वह व्यक्ति वापस मुड़कर नाई की दुकान में दुबारा घुसा और उसने नाई से कहाः क्या तुम्हें पता है? नाइयों का अस्तित्व नहीं होता। नाई ने कहाः तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो? क्या तुम्हे मैं दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ हूँ और मैं एक नाई हूँ। और मैंने अभी अभी तुम्हारे बाल काटे है। व्यक्ति ने कहाः नहीं! नाई नहीं होते हैं। अगर होते तो क्या बाहर उस व्यक्ति के जैसे कोई भी लम्बे बाल व बढ़ी हुई दाढ़ी वाला होता? नाई ने कहाः अगर वह व्यक्ति किसी नाई के पास बाल कटवाने जाएगा ही नहीं तो नाई कैसे उसके बाल काटेगा?

दरकार
सोनम लववंशी

मेधा का सम्मान करना सीखें

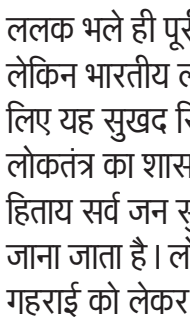

बीते दिनों यूपी बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ। सीतापुर की प्राची निगम ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, लेकिन हमारे समाज की निकृष्ट सोच का स्तर देखिए प्राची के अच्छे स्कोर, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन की सराहना करना तो दूर पर प्राची के चेहरे पर दिख रहे बालों का मजाक बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोचिए उसके बाल मन पर क्या बीत रही होगी। जिस कार्य के लिए समाज को उसकी सराहना करनी चाहिए, उसके बजाय किस चीज पर बात कर रहे हैं। क्या आज के समय में चेहरे की खूबसूरती ही मायने रखती है? पढ़ाई लिखाई का खूबसूरती के आगे कोई महत्व नहीं है! प्राची ने 98.50 प्रतिशत के उत्कृष्ट स्कोर के साथ 600 में से 591 अंक प्राप्त किए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए प्राची ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन विकृत मानसिकता वाले उसकी उपलब्धि को तरजीह न देकर उसकी शक्ल-सूरत को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। हमारे समाज में अक्सर एक लड़की को उसके रंग रूप को लेकर जज किया जाता है, पर सवाल तो यह है कि, क्या बिना शिक्षा के समाज चल पाएगा? अगर बिना पढ़े-लिखे सिर्फ सुंदर दिखने और फैशन से ही देश चल सकता है, तो फिर देश में एजुकेशन सिस्टम का क्या महत्व है? देश में शिक्षण संस्थानों की जगह सौंदर्य प्रसाधन केंद्र ही खोल दिए जाने चाहिए। दरअसल हमारे समाज की यही परेशानी है। कोई किसी की उपलब्धि की सराहना करे या न करे, निंदा करने में कोई पीछे नहीं रहता है। सदियों से महिला को केवल उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है जहां उसकी बाहरी खूबसूरती पितृसत्तात्मक समाज के लिए ज़रूरी हो जाती है। महिला खूबसूरत नहीं है तो उसे समाज में सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता है। स्त्री को स्वयं को इन मापदंडों से मुक्त करना होगा। यूं तो सोशल मीडिया के बढ़ते चलन ने भले ही सामाजिक दायरे को काफ़ी बढ़ा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ़ ट्रोल गैंग जैसी विकृत मानसिकता एक्टिव हो गई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कौन है। उसे क्या परेशानी है। बस अपने मज़े के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अनाप शनाप लिखना होता है। प्राची को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नामक बीमारी है। इस बीमारी में मेटाबॉलिज्म और हॉर्मोनल इंबैलेंस ज्यादा होता है। यहां तक कि पीरियड्स की भी समस्या रहती है। सोचिए कि जिस मासूम को दुनियादारी की परवाह तक नहीं है उसे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, बावजूद इसके ट्रोल गैंग उसे निशाना बना रहा है। एक ग़रीब ठेकेदार की बेटी की कामयाबी भी सभ्य समाज से देखी नहीं गई। वैसे अगर प्राची की जगह कोई लड़का टॉप करता तब उसके रंग रूप या चहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं करता। क्यों समाज में स्त्री और पुरुषों में इस तरह भेदभाव किया जाता है। लड़की को लेकर समाज इतना संवेदनहीन हो चला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी स्त्री को उसके रंग रूप या किसी अन्य कारण से अपमानित किया गया हो। यहां तक कि हमारे देश की राष्ट्रपति तक को उनके रंग को लेकर मज़ाक बनाया गया। हमारे समाज को महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। महिला कोई वस्तु नहीं है, उसका अपना एक वजूद है। उसे समाज में सम्मान मिलना चाहिए।

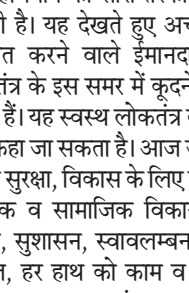

(लेखिका फ्रीलांसर एवं शोधार्थी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतर्मन

आज की पाती

इलाज पर भरोसा बना रहना चाहिए

पतंजलि के कुछेक उत्पादों का मामला सुर्खियों में है। वैसे भ्रामक विज्ञापन किन्हीं एक या दो कंपनियों के ही नहीं होते, लगभग हर कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा करती है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों की सुनवाई के साथ-साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उच्चतम न्यायालय ने जो भी सवाल पूछे, उनके संबंधित संस्थाओं को साफ-साफ उत्तर देने चाहिए और सबकी निष्पक्ष और उचित जांच भी होनी चाहिए। इसका सारा सच आमजन के सामने मीडिया के जरिए भी आना चाहिए। दूसरी चीज आयुर्वेद की या अंग्रेजी दवाएं हों, इनकी कीमत इतनी निर्धारित होनी चाहिए कि ये गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हों। - **वीरेंद्र कश्यप**, दुर्ग

करंट अफेयर

श्रीलंका के मटाला हवाई अड्डे की जिम्मेदारी भारत-रूस को

श्रीलंका के हम्बनटोटा स्थित मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत और रूस की कंपनी को संयुक्त रूप से दी गई है। सरकार के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस हवाई अड्डे का निर्माण 20.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर में किया गया है और एक समय उड़ानों की कमी की वजह से इसे 'दुनिया का सबसे सुनसान हवाई अड्डा' करार दिया गया था। सरकारी प्रवक्ता और मंत्री बांदुला गुणवर्धने ने कहा कि श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने नौ जनवरी को संभावित पक्षकारों से रुचि पत्र आमंत्रित करने की मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए और कैबिनेट द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति ने भारत की शौर्य एयरोनॉटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्षों के लिए एक प्रबंधन अनुबंध देने का निर्णय लिया। गुणवर्धने ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन और हवाई अड्डा सेवा मंत्री की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मटाला हवाई अड्डे का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। महिंदा राजपक्षे के करीब एक दशक के शासन में कई विशाल आधारभूत संरचना परियोजनाएं शुरू की गई जिनमें से यह एक है।

ऑफ बीट

आपका भोजन आने वाली नस्लों को बदल सकता है

पिछली शताब्दी के दौरान, आनुवंशिकी के बारे में शोधकर्ताओं की समझ में गहरा परिवर्तन आया है। जीन, डीएनए के क्षेत्र जो हमारी शारीरिक विशेषताओं के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, 1865 में जीवविज्ञानी ग्रेगर मेंडल द्वारा शुरू किए गए आनुवंशिकी के मूल मॉडल के तहत अपरिवर्तनीय माने जाते थे। यानी, जीन को किसी व्यक्ति के पर्यावरण से काफी हद तक अप्रभावित माना जाता था। 1942 में एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र के उद्भव ने इस धारणा को तोड़ दिया। एपिजेनेटिक्स जीन अभिव्यक्ति में बदलाव को संदर्भित करता है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव के बिना होता है। कुछ एपिजेनेटिक परिवर्तन कोशिका कार्य का एक पहलू हैं, जैसे कि उम्र बढ़ने से जुड़े परिवर्तन। हालाँकि, पर्यावरणीय कारक भी जीन के कार्यों को प्रभावित करते हैं, जिसका अर्थ है कि लोगों का व्यवहार उनके आनुवंशिकी को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक जैसे जुड़वाँ बच्चे एक ही निषेचित अंडे से विकसित होते हैं और परिणामस्वरूप, उनमें आनुवंशिक संरचना समान होती है। हालाँकि, जैसे-जैसे जुड़वा बच्चों की उम्र बढ़ती है, अलग-अलग पर्यावरणीय जोखिमों के कारण उनकी शक्ल-सूरत अलग-अलग हो सकती है।

ट्रेंड

कल्याण के लिए काम करेंगे

प्रेरक! यही एकमात्र शब्द है जो पूरे मालदा के माहौल का वर्णन कर सकता है। चिलचिलाती गर्मी हमें आशीर्वाद देने आए समर्थन के सागर को रोकने में असमर्थ थी। मैं इस स्नेह के लिए लोगों को धन्यवाद देता हू और विश्वास दिलाता हू कि हम हमेशा उनके कल्याण के लिए काम करेंगे।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मानव होने का स्वभाव

यदि आपकी मानवता पूर्ण प्रवाह में है, तो आप अपने आस-पास के जीवन तक पहुंच जाएंगे। यह नैतिकता नहीं है- मानव होने का स्वभाव है। केवल आपके भौतिक शरीर को एक सीमा की जरूरत है। आपके बारे में बाकी सब कुछ सार्वभौमिक हो सकता है।
-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

यह सामान्य चुनाव नहीं

मतदान का बटन दबाने से पहले, 'हम, भारत के लोग' - भारत के संविधान की यह आत्मा, आपके दिल और दिमाग में गूंजनी चाहिए। यह मत भूलिए कि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है।' यह लोकतंत्र को तानाशाही के चंगुल से बचाने का चुनाव है।
-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

अच्छी आदतों से आता स्वास्थ्य

प्यार दीर्घकालिक रिश्तों से आता है। स्वास्थ्य दीर्घकालिक अच्छी आदतों से आता है। धन लंबी अवधि के निवेश से आता है। शांति दीर्घकालिक आत्म-चिंतन से आती है। प्रतिभा दीर्घकालिक केंद्रित प्रयासों से आती है।
-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।